तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था

परन्तु

मध्यममार्ग दृष्टिकोण एक व्यवहारिक समाधान है

केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन

हिन्दी अनुवादः सतीश धर

प्रकाशक :

भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच–10, द्वितीय तल,
लाजपत नगर–3, नई दिल्ली–110024
फोन : 011–29830578
टैलीफैक्स : 011–29840968
ई–मेल : indiatibet7@gmail.com
वैबसाईट : www.indiatibet.com

©DIIR

प्रथम संस्करणः मई 2019
500 प्रतियां

मुद्रक : वी एन प्रिन्ट–ओ–पेक, नई दिल्ली–110020
ई–मेल : vnprints@gmail.com

विषय-सूची

प्रस्तावना 5

अध्याय एकः
सुलगता तिब्बत : तिब्बत में आत्मदाह द्वारा विरोध..... 8

अध्याय दोः
तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति 40

अध्याय तीनः
तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति 68

अध्याय चारः
तिब्बत में सांस्कृतिक नरसंहार 103

अध्याय पाँचः
तिब्बतीय पठार और इसका बिगड़ता पर्यावरण 128

अध्याय छहः
तिब्बत में आर्थिक विकास का वास्तविक स्वरूप 150

अध्याय सातः
तिब्बत में चीन का शहरीकरण 172

अध्याय आठः
तिब्बत के लिए चीन का मास्टर प्लान 185

अध्याय नौः
मध्यम मार्ग दृष्टिकोणः आगे का रास्ता 208

प्रस्तावना

तिब्बतियों के लिए, जानकारी एक कीमती वस्तु है। निरन्तर दुष्प्रचार अभियान सहित अभिव्यक्ति पर गंभीर प्रतिबंध तथ्यों, ज्ञान और सच्चाई को अनमोल बनने के लिए प्रेरित करते हैं। लंबे समय से तिब्बत का यही हाल रहा है।

इस रिपोर्ट के प्रकाशन के समय, तिब्बत पर पूरी तरह से चीनी लोक गणराज्य (People Republic of China) का कब्ज़ा है, जो केवल साठ वर्षों के लज्जाजनक पाँच मास से कम है। जैसा कि चीन ने तिब्बत को कई तरीकों से बडे पैमाने पर आर्थिक रूप से चीनी क्षेत्रों में विकसित करने का प्रयास किया है, सूचना के प्रवाह पर इसके जुनूनी प्रतिबंध अधिक तीव्र हो गए है। इस बीच, पीआरसी के पास पहले से ही मध्ययुगीन इतिहास या वर्तमान विकास के रुझान पर अपनी जानकारी की कमी, बाधाओं से निर्मित अंतराल को भरने के लिए उत्तर तैयार हैं। तथ्यों के ये सरकारी संस्करण देश की आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ने के साथ–साथ और अधिक मजबूती से समर्थित हैं। तिब्बतियों के लिए, ये घटनाक्रम हमारे राष्ट्र–हमारे इतिहास, हमारी पहचान, हमारी समृद्धि और हमारे अधिकारों की सच्चाई को खतरे में डालते हैं। पीआरसी की इन अवधारणाओं में से प्रत्येक की अपनी निर्मित प्रस्तुतियां हैं। यदि उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो वे चीनी लोगों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यहां तक कि तिब्बतियों की भावी पीढ़ियों के मन में वास्तविकता को दबाने का जोखिम उठा सकते हैं।

यह रिपोर्ट तिब्बत पर दुष्प्रचार के खिलाफ चुनौती को मजबूत करने के लिए एक उपकरण प्रदान करना चाहती है। तिब्बती लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (Central Tibetan Administration) को अपने मंच का जब भी और जहाँ भी संभव हो, रिकॉर्ड को सीधे व्यवस्थित करने के लिए उपयोग करना चाहिए। स्त्रोत जैसा कि यह प्रकाशन है, एक महत्वपूर्ण साधन हैं। यह सीटीए द्वारा पूर्व के कार्यों पर निर्भर करता है और दुनिया भर के अन्य सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और विद्वानों के स्रोतों से भी जुड़ा है जो तिब्बत में वर्तमान परिस्थितियों को उद्धाटित करने से कतराते नहीं हैं। ये स्रोत तिब्बत के अंदर तिब्बतियों पर

निरपवाद रूप से भरोसा करते हैं जो बाहरी दुनिया को जानकारी प्रकट करने के लिए अपने जीवन और आजीविका को जोखिम में डालते हैं।

तथ्यों का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने से अधिक, यह रिपोर्ट यहां चर्चा किए गए विषयों के बारे में किसी भी प्रकार के भ्रम को मिटाने का प्रयास करती है। तिब्बत में तिब्बतियों के लिए, अधिकारों के उल्लंघन और यहां वर्णित अन्य कठिनाइयों के प्रभाव प्रत्यक्ष और गंभीर हैं। इसका प्रमाण तिब्बतियों में अप्रत्याशित और अत्यंत दुखद रूप से बढ़ती आत्म–दाह की संख्या है। आगामी अध्यायों में शामिल प्रत्येक विषय कम से कम एक आत्म–दाह के लिए या आधिकांश आत्म–दाह के लिए प्रेरक कारण रहा है। हमने इन आत्म–दाहों की चर्चा न केवल दस्तवेज़ीकरण के लिए की है बल्कि यह दर्शान के लिए भी की है कि तिब्बती लोगों के प्रति पीआरसी की ज्यादतियां आज भी भयावह रूप से जारी हैं परिणामतः 152 से आधिक तिब्बतियों ने विरोध–प्रदर्शन के इस कृत्य को अपनाया।

यह रिपोर्ट नौ अध्यायों में व्यवस्थित की गई है, जिसमें आत्म–दाह, तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति, मानवाधिकार, सांस्कृतिक नरसंहार, पर्यावरण, आर्थिक विकास, शहरीकरण, परमपावन दलाई लामा के पुनर्जन्म, और मध्यम मार्ग नीति शामिल हैं। अध्याय का उद्देश्य व्यापक लेकिन ग्राध्य होना है। यह देखते हुए कि प्रत्येक विषय स्वयं में पुस्तक हो सकता है–और वास्तव में इस विषयों पर बहुत सी पुस्तके लिखी भी गयी है। यह रिपोर्ट तिब्बत के मामले में रुचि रखने वालों के लिए तिब्बत में सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों के अवलोकन के रूप में प्रस्तुत की गई है।

इस प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत सामान्य दावा यह नहीं है कि आज के तिब्बत में बिताये जाने वाला जीवन शर्त्रिया नारकीय जीवन में से एक है। या यह कि पीआरसी द्वारा बोला या जारी किया गया प्रत्येक शब्द एक झूठ है। इसका आशय यह है कि जो भी सकारात्मक, या आमतौर पर, तिब्बती भलाई के सबसे अच्छे, अप्रभावी तत्व आधुनिक तिब्बत में मौजूद हैं, वे आर्थिक भेदभाव, तिब्बती भाषा, संस्कृति और धर्म के प्रति अनादर, तिब्बती इतिहास के उन्मूलन और मानवाधिकारों के उल्लंघन को नही रोक सकते जो आज क्षेत्र में व्याप्त है। कुल मिलाकर, ये अन्याय प्रदर्शित करते हैं, कि उनके व्यापक पैमाने और गंभीरता के कारण पीआरसी 2018 में तिब्बत के वैध प्रतिनिधि होने के करीब नहीं है, जैसा कि वह 1959 में थी।

लेकिन पीआरसी के तहत तिब्बत की दयनीय स्थिति को चित्रित करने से अधिक, यह इन मुद्दों के समाधानों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए सीटीए की भूमिका भी है। तीस साल पहले 15 जून 1988 को फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद के संबोधन में परमपावन दलाई लामा ने आधिकारिक तौर पर मध्यम मार्ग नीति की घोषणा की जो तिब्बत में तिब्बतियों के लिए स्वतंत्रता बहाल करने के लिए सीटीए का दृष्टिकोण बनी हुई है। वर्तमान वातावरण में, तिब्बत में वास्तविक स्वायत्तता के लिए पीआरसी के साथ बातचीत एक संकल्प प्राप्त करने के लिए सीटीए के लिए सबसे व्यवहार्य विकल्प है। दुर्भाग्य से, यह दृष्टिकोण खुद चीनी सरकार द्वारा झूठी सूचना का शिकार रहा है, इसलिए इस रिपोर्ट में मध्यम मार्ग नीति पर एक अध्याय शामिल है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि इसका आशय क्या है।

भले ही पीआरसी तिब्बत के बारे में दुनिया के दृष्टिकोण को बदलने का कितना प्रयास करे, जब तक कि तिब्बती और उनके समर्थक इस क्षेत्र में जो कुछ भी चल रहा है उसकी सच्चाई को उजागर करने वाली जानकारी प्रकाशित और प्रोत्साहित करते रहेंगे, तिब्बतियों के अधिकारों के लिए दबाब जारी रहेगा। यह रिपोर्ट इस प्रयास में सीटीए के वर्तमान योगदान को चिह्नित करती है।

डॉ. लोबसांग सांगे
अध्यक्ष
केंद्रीय तिब्बती प्रशासन
अक्टूबर, 2018

अध्याय एक

सुलगता तिब्बत : तिब्बत में आत्मदाह द्वारा विरोध

23 दिसंबर, 2017 को, जब दुनिया का अधिकांश हिस्सा क्रिसमस उत्सव के जश्न की तैयारी में था, तिब्बती पठार के किसी उत्तर–पूर्व कोने में, एक 30 वर्षीय पूर्व बौद्ध भिक्षु कोंपे ने तिब्बत के भीतर स्वतन्त्रता और परमपावन दलाई लामा की तिब्बत वापसी की मांग पर खुद को आग लगा दी। एक दिन बाद, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, उसने दम तोड़ दिया। कोंपे तिब्बत में चीनी शासन के विरोध में आत्मदाह करने वाले 151 वें तिब्बती बन गए। वह आत्म–दाह से मरने वाले 129वें तिब्बती बन गए।

पिछले नौ वर्षों से दुनिया की छत जल रही है।

तिब्बती आत्म-दाह क्यों करते हैं?

आत्म–दाह स्वयं को आग लगाने का कृत्य है और ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग वियतनाम और अरब दुनिया जैसे अन्य देशों में राजनीतिक प्रतिरोध के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया है।

आत्म–दाह एक सचेत प्रयास और एक विशिष्ट लक्ष्य के साथ किया जाता है और इसलिए आत्म–दाह के निर्णय की पूरी प्रक्रिया, कार्य को पूरा करना और किसी की मृत्यु सुनिश्चित करना पूरी तरह से व्यर्थ नहीं जाता है। आत्म–दाह करने वालों द्वारा अपने कार्य के दौरान या उससे पहले अपनी मांगों को व्यक्त करने के लिए सचेत प्रयास करते हैंः आत्म–दाह करने वालों द्वारा किए गए सचेत प्रयास; अपने आप को जलाने का उनका कार्य उनके लक्ष्यों को पूरा करता है और परमपावन दलाई लामा की तिब्बत की वापसी के प्रतीक तिब्बत में बेहतर मानवाधिकारों और राजनीतिक सुधार के लिए एक स्पष्ट आह्वान करता है।

आत्मदाह की यह श्रृंखला इस तथ्य को उजागर करती है कि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र तिब्बत पर, चीन का कब्जा अवैध है। यह तिब्बत को ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र की स्थिति से जोड़ता है। तिब्बत में

बिगड़ते मानवाधिकारों की स्थिति के कारण सांस्कृतिक नरसंहार और शहरीकरण, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास जैसी विकास नीतियों की आड़ में अधिकारों का दमन और धार्मिक नेताओं के पुनर्जन्म के लिए पवित्र संस्था का राजनीतिकरण हुआ है। तिब्बत में इन ख़राब स्थितियों ने तिब्बतियों को राजनीतिक विरोध के ऐसे चरम पग उठाने के लिए बाध्य किया है। स्वयं को आग लगाने वालों ने सार्वजनिक स्थानों पर आत्म–दाह का कार्य करके और दो अलग–अलग तरीकों के माध्यम से अपने संदेश दो निरंतर नारोंः हम स्वतंत्रता चाहते हैं और परमपावन दलाई लामा की तिब्बत वापसी चाहते है, को तैयार करके अपने लक्ष्य को व्यक्त किया है। इसके बदलें में, इन दोनों नारों का दो दृष्टियों मे विश्लेषण किया जा सकता है। स्वतंत्रता का आह्वान मानव की बेहतर मानवाधिकार परिस्थितियों के लिए एक पुकार है। परमपावन दलाई लामा की तिब्बत में वापसी का आह्वान भी एक राजनीतिक आह्वान है जिससे दलाई लामा के क्रमिक पुर्नअवतार (5वें से 14वें), जिन्होंने 376 वर्षों के लिए तिब्बती राजनीतिक प्रतिष्ठान का नेतृत्व किया है। और जो तिब्बत में राजनैतिक सुधारों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं भी शामिल है।

आत्म-दाह का कार्य

चीन के खिलाफ 2008 के राष्ट्रव्यापी विद्रोह के बाद 2009 में आत्म–दाह की व्यापक लहर शुरू हुई। तब से तिब्बत में कम से कम 152 आत्मदाह हुए हैं। इन आत्म–दाह करने वालों में से[1] 126 पुरुष और 26 महिलाएँ थीं। जलती हुई आग ने 130 लोगों की जिन्दगियां लील लीं।

लगभग एक–तिहाई तिब्बती जिन्होंने आत्म–दाह द्वारा विरोध प्रदर्शन किया भिक्षु और भिक्षुणियाँ[2] थे। शेष जीवन के सभी क्षेत्रों और विभिन्न प्रान्तों से साधारण लोग थेः छात्र, किसान, शिक्षक, युवा माता–पिता, दादा–दादी और कई बच्चों की माताएं।

आत्म–दाह विरोध प्रदर्शन करते समय, आत्म–दाहक अपने शरीर पर केरोसीन/पेट्रोल डालते हैं और स्वयं को अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर

1 इसके अतिरिक्त, दस आत्मदाह तिब्बत से बाहर हुए, अधिकाँश भारत और नेपाल में।

2 केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन, फरवरी 2009 के बाद से तिब्बत में आत्मदाह विरोध की तथ्य शीट।" http://tibet.net/important-issues/factsheet-immolation-2011-2018/.

आग लगाते हैं। तिब्बत से आये फोटो और आत्म–दाह पर वीडियो रिकॉर्डिंग में आत्म–दाह करने वालों को हाथ जोड़कर खड़े हुए या प्रतिबंधित तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज उठाये हुए सावधान की मुद्रा में दिखाया है। इन रिकॉर्ड किए गए उदाहरणों में से किसी में भी प्रदर्शनकारियों ने अन्य लोगों या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे जीवित नहीं रहेंगे, और चीनी अधिकारियों के हाथों में फंसने से बचने के लिए, कई आत्म–दाह करने वाले व्यक्तियों ने केरोसिन पीया और अपने शरीर के चारों ओर कांटेदार तारों को लपेटा हैं।[3] यदि वे आत्म–दाह विरोध से बच जाते हैं तो प्रत्याशित परिणाम से भी अधिक भयानक होते हैंः कारावास, यातना और अन्य अमानवीय व्यवहार। 2017 की फ्रीडम हाउस की विशेष रिपोर्ट में कहा गया है कि "तिब्बती क्षेत्रों में चीनी सुरक्षा बल त्वरित कदम उठाने के लिए बाध्य हैं .... जिनमें निहत्थे नागरिकों के खिलाफ गोला बारूद का उपयोग भी शामिल है।"[4]

आत्म–दाह विरोध के तुरंत बाद, पुलिस विरोध स्थल को घेर लेती है और इस क्षेत्र में एक गहन सुरक्षा बना लेती है, जिसमें सूचना के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं अवरुद्ध कर दी जाती हैं।

तिब्बती आत्म-दाह के प्रमुख तथ्य

2012 में आत्म–दाह की लहर अपने चरम पर पहुंच गई जब 85 तिब्बतियों ने विभिन्न स्थानों पर आत्म–विसर्जन किया। चीन पर कार्यकारी आयोग की महासभा (CECC) ने उस वर्ष में "तिब्बती आत्म–दाह विरोध की आवृत्ति, भौगोलिक प्रसार, और विविधता में वृद्धि देखी, और यह भी उल्लेख किया कि" आत्म–दाह के रूप में वृद्धि हुई है और भौगोलिक रूप से फैल गई है, इसमें साधारण जनता ने बडी भूमिका निभाई है। "तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह की निरंतरता, तिब्बतियों के लिए भेदभावपूर्ण चीनी नीतियों के खिलाफ पठार भर में तिब्बतियों की शिकायतें और आक्रोश महामारी की

3 अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन फॉर तिब्बत, "आत्म–दाह से बचे तिब्बतीः दमन तथा गुमशुदगी", 19 मार्च 2015, http://www.savetibet.org/newsroom/tibetan-survivors-of-self-immolation-repression-and-disappearance/..

4 सारा कुक, "चीन की स्वभाव के लिए लड़ाईः धार्मिक पुनरुद्धार, दमन और प्रतिरोध के तहत शी जिम्पिंग", फ्रीडम हाउस 2017 https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_ChinasSprit2016_FULL_FINAL_140pages_compressed.pdf.

तरह फैलने का संकेत देती है। आत्म–दाह विरोध 2018 में तब फैला जब नाबा से 44 वर्ष आयु के त्सेखो तुगचाक ने आत्म–दाह किया और तिब्बत के भीतर आत्म–दाह करने वाला उस वर्ष में पहला तिब्बती बना और रिपोर्ट लिखने तक वह कुल 152वां तिब्बती था।[5]

वर्ष	आत्म–दाहों की संख्या	ज्ञात मौतें	वर्तमान स्थिति अज्ञात	अन्य (सीएलयू: वर्तमान ठिकाना अज्ञात)
2009	1	0	0	गहरे जलने के घावों के बावजूद जीवित लेकिन ठिकाना अज्ञात
2011	12	8	0	दो अंग–विच्छेद,1 को पांच वर्ष की सज़ा (दोनों का ठिकाना अज्ञात)
2012	85	74	9	दो अंग–विच्छेद,1 को पांच वर्ष की सज़ा (दोनों के ठिकाना अज्ञात)
2013	26	25	1	
2014	11	9	1	एक गंभीर रूप से घायल व ठिकाना अस्पताल में भर्ती (अज्ञात)
2015	7	7	0	
2016	3	3	0	
2017	6	3	3	
2018	1	1		

चित्र 1 सीटीए के आंकड़ों के आधार पर वर्षा–अनुसार तिब्बत में आत्म–दाहों की संख्या दर्शाता है [6]

5 केंद्रीय तिब्बती प्रशासनः फरवरी 2009 के बाद से तिब्बत में आत्मदाह विरोधों की संख्या पर तथ्य शीट।"

6 वही

फैलगया आत्म–दाह करने वालों की आयु 15 से 65 वर्ष की थी। सबसे अधिक आयु, अमदो चेंत्सा प्रांत के एक 64 वर्षीय तमडींग थार व्यक्ति थे, जबकि सबसे छोटे, 15 वर्षीय दोरजी गोमोंग कस्बे के नाबा त्सोगड्रुग गांव से था। तमदींग थार और दोरजी दोनों का क्रमशः 15 जून और 7 नवंबर 2012 को विरोध प्रदर्शन के बाद निधन हो गया। आत्म–दाह करने वाले अधिकांश तिब्बती विरोध प्रदर्शन के समय बीस वर्ष की आयु में थे और उनकी औसत आयु 27 वर्ष के आसपास थी। ये तथ्य चीन की नीतियों की विफलता और तिब्बत पर कब्जे के बारे में छह दशकों की कहानी कह रहे थे। ल्हासा में 1959 के तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह ने परमपावन दलाई लामा और हजारों तिब्बतियों को अपने देश से भागने और पड़ोसी भारत में शरण लेने को बाध्य किया। तब से, परमपावन दलाई लामा निर्वासित तिब्बती समुदाय के कई सदस्यों के साथ उत्तरी भारत के धर्मशाला में वास कर रहे हैं। तिब्बत में 1959 के बाद जन्मी पीढ़ी ने परमपावन दलाई लामा को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है और उनकी जीवन की इच्छा महामना के दर्शन पाने की है। उनकी श्रद्धा चीनी सरकार की कठोर नीतियों से निर्लिप्त है, जिसका उद्देश्य परमपावन दलाई लामा को निराश करना है। तिब्बत में महामना की वापसी के लिए आह्वान आत्म–दाह करने वालों की इस श्रद्धा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।

तिब्बतियों के आत्म-दाह का उद्भव

वर्ष 1998 में भारत में पहला तिब्बती आत्मदाह हुआ था, जब भारतीय पुलिस द्वारा जबरदस्ती 'आमरण अनशन' मुहीम को हटाए जाने के बाद, 27 अप्रैल को एक प्रदर्शनकारी, शहीद (तिब्बती में पावो) थुपतेन नोडुप ने खुद को आग लगा कर आत्म–दाह किया था। तिब्बती युवा कांग्रेस द्वारा नई दिल्ली में उच्च स्तरीय चीनी अधिकारियों की यात्रा का विरोध करने के लिए यह भूख हड़ताल/प्रदर्शन आयोजित किया गया था। थुपतेन नोडुप भूख हड़ताल विरोध में एक स्वयं–सेवक था। आत्मदाह के विरोध के दो दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई।

तिब्बत में पहला आत्मदाह 27 फरवरी, 2009 को शुरू हुआ, जब बीस वर्षीय टैपे[7], एक भिक्षु, जो कि अमडो नाबा में कीर्ति मठ से थे, ने स्थानीय

7 तिब्बती मानवाधिकार और लोकतंत्र केंद्र, तिब्बती आत्मदाह करने वाले को अपने पैरों को विच्छिन्न करने को कहा, 13 मार्च 2019 http://tchrd.org/self-immolated-man-asked-to-amputate-his-legs/..

अधिकारियों द्वारा उनके मठ में प्रार्थना समारोह रद्द करने के बाद खुद को आग लगा ली। उसके कृत्य का उल्लेख करते हुए, तिब्बत के एक प्रसिद्ध लेखक त्सेंरिंग वोसेर ने लिखा है:–

फरवरी 27, 2009 को तिब्बती नव वर्ष लोसर का तीसरा दिन था। यह वह दिन भी था जब तिब्बत में आत्म–दाह ने प्रवेश किया था। अधिकारियों ने सिर्फ एक महान प्रार्थना महोत्सव (मोनालाम) को रद्द कर दिया था, जो कि 2008 में सरकार के शोषण के पीड़ितों की स्मृति में आयोजित किया गया था। तापे नामक एक भिक्षु कीर्ति मठ से बाहर निकले और नाबा की गलियों मे अपने शरीर को आग लगा दी। तिब्बत का यह क्षेत्र अमदो के नाम से जाना जाता है, जो महान धार्मिक श्रद्धा का स्थान है और चीन के सिचुआन प्रांत का हिस्सा है।

टेपे के विरोध के बाद, तिब्बत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ–साथ भारत और नेपाल के पड़ोसी देशों में, जहां निर्वासित तिब्बती रहते हैं, आत्म–दाह की लहर चल पड़ी। कम से कम 130 तिब्बतियों को आत्म–दाह विरोध के कारण प्राण गवांने पड़े। इस विरोध के बाद केवल मुट्ठी भर जीवित आत्म–दाह करने वालों की स्थिति और ठिकाने ज्ञात हैं। लोबसांग केलसांग, लोबसांग कुंचोक और सोनम रबांग को अंग–विच्छेद करवाना पडा, जबकि केसांग वांगचुक को स्थायी रूप से रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद लकवा मार गया। दावा त्सेरिंग को आखिरी बार अपने घर पर जले की चोटों से ठीक होते हुए सुना गया था और कुंचोक को गंभीर चोटों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आत्म–दाह करने वाले एक दर्ज़न से अधिक व्यक्तियों की वर्तमान स्थिति और ठिकाने अज्ञात हैं।

इस बात पर फिर से ध्यान देना आवश्यक है कि बहुसंख्यक आत्म–दाह करने वाले युवा तिब्बती थे जो तिब्बत पर चीन के आक्रमण के बाद पैदा हुए थे। वे उस पीढ़ी से सम्बन्धित थे जिन्होंने परमपावन दलाई लामा को कभी नहीं देखा था, फिर भी उनके अंतिम संदेशों ने उनकी तिब्बत वापसी के लिए प्रार्थना की थी। वास्तव में, प्रदर्शनकारियों में से एक तिहाई अपनी किशोरावस्था में थे। 2012 में चीन पर कार्यकारी आयोग की महासभा द्वारा चीन पर जारी रिपोर्ट में, तिब्बत में आत्म–दाह विरोध प्रदर्शनों की "बढ़ती आवृत्ति, व्यापक प्रसार और आधिक विविधता" के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी।

इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि "मार्च 2008 में शुरू हुए तिब्बती राजनीतिक विरोध के बाद कई कारण और रुझान विकसित हुए या बिगड़

गए होंगे, जिन्होंने आत्म–दाह के निर्णय को प्रभावित करने वाले वातावरण को बनाने में योगदान दिया हो।"[8] अपनी माँगों को व्यक्त करने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं होने के कारण, तिब्बती लोग तिब्बत में स्वतंत्रता के लिए, और भाषा और सांस्कृतिक संरक्षण के अधिकार के लिए आह्वान करते हुए परम पावन दलाई लामा की तिब्बत वापसी के लिए आत्म–दाह का कदम उठा रहे थे।

तिब्बत क्यों सुलग रहा है ?

तिब्बत में अपने कब्जे और उसके बाद के शासन का सामना करने वाली मूलभूत समस्या को हल करने में चीन की विफलता चीनी कम्युनिस्ट प्रतिष्ठान के भीतर काम कर रहे प्रख्यात तिब्बती नेताओं द्वारा तिब्बत में चीनी शासन के शुरुआती दिनों में ही भांप ली थी। 1960 के दशक की शुरुआत में, तिब्बती नेताओं ने चीनी कम्युनिस्ट शासन की निंदा की। अदम्य साहस और निर्भीकता के एक कार्य में, 10वें स्वर्गीय पंचम लामा ने शीर्ष चीनी नेताओं को संबोधित एक 70,000 शब्दों की एक याचिका प्रस्तुत की, जिसे हालांकि कूटनीतिक रूप से लिखा गया था, इसमें चीन पर तिब्बत में सांस्कृतिक नरसंहार करने का आरोप लगाया गया था। तिब्बत में चीनी शासन की इस प्रवृत्ति की तीखी आलोचना पंचेम लामा को महंगी पड़ी। माओत्से तुंग ने तिब्बती नेता को "हमारे वर्ग का शत्रु" कहा और उनकी 70,000 शब्दों की याचिका को "जहरीला तीर" बता कर निंदा की। उनके साथ "जोर जबरदस्ती" की गयी कभी–कभी हिंसक तरीके से भी, और कई वर्षों तक कारावास और एकांत कारावास में रखा गया था। जब वह माओत्से तुंग की मृत्यु के बाद कारावास से रिहा हुए, तो 1989 में पंचेन लामा ने कहा कि तिब्बत ने चीनी कम्युनिस्ट शासन के तहत कुछ प्राप्त करने की तुलना में बहुत अधिक खो दिया है। उन्होंने यह टिप्पणी अपनी रहस्यमय और असामयिक मृत्यु के कुछ दिन पहले ही की थीं।

तिब्बत में कम्युनिस्ट प्रतिष्ठान में काम करने वाले कई तिब्बती बुद्धिजीवी और लेखकों ने इन शब्दों में चीनी कम्युनिस्ट शासन के विषय में अपना निर्णय दिया हैः "पहले 10 वर्षों (1950–60) में हमने अपनी जमीन खो दी

8 अमेरिकी कांग्रेस, चीन पर कार्यकारी समिति की महासभा "विशेष रिपोर्टः तिब्बतियों का आत्म–दाहः बढ़ती आवृत्ति, व्यापक प्रसार, अधिक विविधता," 22 अगस्त 2012, https://www.cecc.gov/publications/issue-papers/special-report-tibetan-self-immolation-rising-frequency-wider-spread.

(यानी कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया)। दूसरे 10 साल में (1960–70) हमने राजनीतिक शक्ति खो दी (पुराने तिब्बत की सरकार को कम्युनिस्ट प्रतिष्ठान में बदल दिया गया)। तीसरे 10 वर्षों (1970–80) में हमने अपनी संस्कृति खो दी (सांस्कृतिक क्रांति ने तिब्बत की पारंपरिक आस्थाओं को नष्ट कर दिया)। चौथे 10 वर्ष (1980–90) में हमने अपनी अर्थव्यवस्था खो दी (चीनी उपनिवेशवादियों ने तिब्बत में रोजग़ार के बाजार को संभाला)।"[9]

तिब्बत में चीनी शासन का कड़ा मूल्यांकन का यह उल्लेख करता है कि तिब्बत में इतने सारे युवा तिब्बती आत्मदाह करने के लिए क्यों प्रेरित हुए। वे प्रतिदिन तिब्बती बौद्ध सभ्यता, तिब्बती भाषा और उनकी अपनी पहचान पर चीन के निरंतर हमले को देखते और अनुभव करते थे। वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अपने अध्यात्मिक जीवन में सक्रिय दखल को लेकर कड़ी नाराजगी जताते थे, जिसमें तिब्बती अध्यात्मिक नेताओं को नियुक्त करने का प्रयास भी शामिल है। वे मूलतः नाराज हैं, चीन द्वारा परमपावन दलाई लामा छवि धुमिल करने और भिक्षुओं और भिक्षुणियों को बलपूर्वक दलाई लामा को नहीं मानने की नीति पर जोर देने की निंदा करते हैं। तिब्बत के लोग चीनी उपनिवेशवादियों को भय और खतरे के पूर्व संकेत के रूप देखते थे क्योंकि उन्होंने तिब्बतियों की नौकरियां, ज़मीन और उनका भविष्य पूरी तरह से छीन लिया था और इस प्रक्रिया में, तिब्बत के शहरों को चीन के नगरों में बदल दिया। वे चरागाहों से खानाबदोशों को बलपूर्वक हटाने, उनके अपने पशु–धन और आय के जानवरों के झुंड और आजीविका के स्रोत से दूर करने और उन्हें स्थायी आवास संरचनाओं में फिर से बसाने के लिए जहां से कोई आय नहीं है, और पूर्व आत्मनिर्भर परिवारों को अस्थाई परिवारों में परिवर्तित करने का विरोध कर रहे थे। उसी समय, तिब्बती लोग अपनी भूमि पर किए गए बड़े पैमाने पर विकास गतिविधियों को देखते हैं जो उनके लिए बहुत कम या कोई लाभ नहीं लाते हैं और इसके बजाय, तिब्बती प्राकृतिक संसाधनों से को संसाधनों के भूखे चीन को सौंपते हैं। पिछले कुछ वर्षों में तिब्बत के चीनीकरण ने तिब्बती नागरिकों को अपनी मातृभूमि में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है।

चीन द्वारा तिब्बती लोगों पर लगातार हमला, और उन्हें एक अलग दुनिया में

9 तिब्बत नीति संस्थान, क्यों तिब्बत जल रहा है? (धर्मशालाः तिब्बत नीति संस्थान प्रकाशन, 2013) http://tibet.net/wp-content/uploads/2014/12/Why-Tibet-is-Burning...pdf.

धकेलने को विद्वान डेविड स्नेलग्रोव और ह्यूग रिचर्डसन ने अपनी पुस्तक ए कल्चरल हिस्ट्री ऑफ़ तिब्बत[10] में व्यक्त किया है। पुस्तक लिखने के उद्देश्य को बताते हुए उन्होंने लिखा हैः

> *हमने इस समय स्वयं को पुस्तक को लिखने के लिए इसलिए चुना है क्योंकि तिब्बती लोगों की सभ्यता हमारी आंखों के सामने से गायब हो रही है, और केवल इधर–उधर कुछ शालीन विरोधों के अतिरिक्त इसे समस्त दुनिया में बिना टिप्पणी के और खेद के जाने दिया जा रहा है। अतीत में कई सभ्यताओं में गिरावट और विघटन हुआ है, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि किसी को इस तरह की घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती हो।*

नारे, अंतिम शब्द और ईच्छा–पत्र

अपने शरीर को आग की भेंट करते समय आत्म–दाह करने वालों ने "हम तिब्बत के अंदर आजादी चाहते हैं" और "हम दलाई लामा की तिब्बत में वापसी चाहते हैं" के नारे लगाए हैं। लगभग सभी आत्म–दाह करने वालों ने नारे लगाए और कुछ ने लिखित नोट्स और रिकार्ड किए गए संदेश रखे जो यह दर्शाते हैं कि उनकी आत्महत्याएं चीनी सरकार की "दमनकारी नीतियों" का विरोध करती हैं, जो तिब्बती पहचान, धर्म और भाषा को खतरा पैदा करती हैं, और वे परमपावन दलाई लामा की तिब्बत वापसी का आह्वान करते हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि उनका इरादा अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, जैसा कि वीडियोक्लिप और तस्वीरों में देखा गया है जो चीनी सेंसरशिप से बच कर बाहरी दुनिया में पहुंच गई।

16 मार्च, 2011 को आत्म–दाह करने वाले कीर्ति मठ के 21 वर्षीय भिक्षु फुंटशोक ने साथी भिक्षुओं को मरते समय बतायाः "छह मिलियन तिब्बतियों केलिए मेरा अंतिम संदेश एकजुट रहें, जैसे कि माला {प्रार्थना माला} के मनके एक ही धागे में होते हैं, हर तिब्बती को इसी प्रकार जुड़ना है। तिब्बती लोगों को जितना हो सके, अपने उद्देश्य के लिए मिलकर काम करना चाहिए।"[11]

---

10 डेविड एल स्नेलग्रोव एवं हुयग रिजर्डसान, तिब्बत की संस्कृतिक इतिहास। (कोलारेडोः शामबाला, 1980)

11 चरागाहों में तूफानः तिब्बत में आत्मदाह और चीनी नीति, अंतरर्राष्ट्रीय कैंपेन फॉर तिब्बत, दिसम्बर 2012 https://www.savetibet.org/wp-content/uploads/2013/06/storminthegrassland-FINAL-HR.pdf..

22 वर्षीय न्गावांग नोर्फ़ेल, जिन्होंने ड्रिदू (चीनीः चेंग्दू) में 20 जून 2012 को तेनजिन खेडुप के साथ मिलकर आत्मदाह किया था। युसु तिब्बती स्वायत्त प्रान्त किंग्हाई, आत्म–दाह के बाद फिलमाए गए एक विड़ियो में तिब्बती भाषा और स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। उन्हें यह कहते सुना गया हैः

मेरे लोगों को भाषा की स्वतंत्रता नहीं है। प्रत्येक तिब्बती को चीनी से मिला रहा है। जैसा हो सकता है वैसा बनो, मेरा धन ले लो। मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मेरे बर्फ की धरती को क्या हो गया? {यह} तिब्बत के लिए है। हम बर्फ की भूमि में हैं। यदि हमारे पास हमारी स्वतंत्रता, सांस्कृतिक परंपराएं और भाषा नहीं है, तो यह हमारे लिए बेहद शर्मनाक होगा। इसलिए हमें उन्हें सीखना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्रीयता को स्वतंत्रता, भाषा और परंपरा की आवश्यकता है। भाषा के बिना, हमारी राष्ट्रीयता क्या होगी? {क्या हमें तब} खुद को चीनी कहना चाहिए या तिब्बती?[12]

आत्म–दाह विरोध स्थलों का महत्व

आत्म–दाह विरोध स्थलों का स्थान और निकटता विरोध के महत्व को बढ़ाते हैं। कुछ तिब्बतियों ने चीन के सरकारी भवनों, खनन स्थलों, पुलिस स्टेशनों और सैन्य शिविरों के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करना चुना जबकि अन्यों ने सार्वजनिक स्थलों और उल्लेखनीय गलियों में आत्म–दाह किया। कम से कम दो आत्म–दाह की घटनाएं खनन स्थलों के पास हुईं। 20 नवम्बर, 2012 को 34 वर्षीय त्सेरिंग धोंदुप ने उत्तर–पूर्वी तिब्बत के कनलोह, के संगचू प्रांत में अमचोक खनन क्षेत्र के प्रवेश–द्वार पर खुद को आग लगा कर प्राण–त्याग दिए।[13] इसी खनन क्षेत्र स्थल पर दूसरा आत्मदाह विरोध एक सप्ताह बाद देखा गया जब 26 नवम्बर 2012 को 18 वर्षीय कुञ्चोक त्सेरिंग ने आत्म–दाह विरोध किया।[14]

26 अक्तूबर 2012 को एक 24 वर्षीय किसान ल्हामो त्सेतेन ने कंलोह के संगचू प्रांत के अमचोक कस्बे में सरकारी कार्यालय और सेना बेस के सामने खुद को आग लगा कर प्राण त्याग दिया।[15]

12 वही

13 ऑमदो स्थित ऑमछोक शहर में एक तिब्बती ने आत्मदाह किया। वायस ऑफ अमेरिका, 20 नवम्बर 2012 https://www.voatibetanenglish.com/a/1549512.html.

14 केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, "तीन और तिब्बती आत्मदाह से मरे, संख्या 85 तक पहुंची, 27 नवम्बर 2012 http://tibet.net/2012/11/two-more-tibetans-die-of-self-immolations-tollreaches-84/.

15 "चीनी शासन के विरोध में तिब्बती किसान ने खुद को आग लगाई," दी गार्डियन, 26 अक्तूबर 2012, https://www.theguardian.com/world/2012/oct/26/tibet-farmer-fire-protest.

4 मार्च 2012 को आमदो नाबा पुलिस स्टेशन के सामने एक तिब्बती मां रिनचेन ने आत्म–दाह किया और विरोध–स्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हुई। 15 जून को, आमदो चेंत्सा के 64 वर्षीय तामदिंग थार ने भी चेंत्सा मालहो के स्थानीय पुलिस स्टेशन के सामने खुद को आग लगा ली। 57 वर्षीय दोरजे रिंचेन ने भी इसी प्रकार का विरोध–कनलोह के सांगचू प्रांत में स्थानीय पुलिस स्टेशन के सामने खुद को मौत के हवाले कर विरोध प्रदर्शित किया। 17 फरवरी 2013 को सांगचू प्रान्त, कांलहो के सैनिक पुलिस स्टेशन के सामने 49 वर्षीय नमल्हा त्सेरिंग की आत्मदाह के बाद मृत्यु हो गई। गोलोग में गाड़े प्रान्त के खोर कस्बे के 42 वर्षीय कुञ्चोक ने 16 सितंबर 2014 को त्सांग खोर कस्बे के स्थानीय पुलिस स्टेशन के सामने आत्म–दाह किया और अंतिम जानकारी के अनुसार उसे गम्भीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी तरह 16 दिसम्बर 2014 को 33 वर्षीय संगेय खार, ने खुद को कनलोह के सांगचू प्रांत के अमचोक कस्बे में, पुलिस स्टेशन के सामने आग लगा दी, लेकिन जीवित नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद, 23 दिसंबर, 2014 को, तावून यित्सो मठ के एक भिक्षु केलसांग यशी ने अपने मठ के निकट तावू प्रांत, कर्दज़े में पुलिस स्टेशन के सामने आत्म–दाह किया। केलसांग यशी की उसी दिन निधन हो गया।

चीनी सरकार की आत्म-दाह पर प्रतिक्रिया

चीनी सरकार का "तिब्बती बौद्ध सभ्यता,तिब्बती भाषा और उनकी अपनी पहचान पर निरंतर हमला," और चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा उनके आध्यात्मिक जीवन में सक्रिय हस्तक्षेप, जिसमें तिब्बती आध्यात्मिक नेताओं को नियुक्त करने के प्रयासभी शामिल हैं, "वे कारण हैं जिन्होंने तिब्बत में कुछ युवा तिब्बतियों को आत्म–दाह की ओर प्रेरित किया है।"[16] प्रदर्शनकारियों की शिकायतों को दूर करने की अपेक्षा, चीन सरकार ने तिब्बती आत्म–दाहों का जवाब उन क्षेत्रों मेंगंभीर प्रतिबंधों से दिया है जहाँ आत्म–दाह हुआ था। आत्म–दाह करने वालों को अपराधी घोषित करने वाले नए नियम लागू किए गए और कार्यान्वित किये गए थे। आत्म–दाह करने वाले परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मठों और आत्म–दाह जुड़े गांवों पर सामूहिक दंड लगाया गया।

16 "चरागाहों में तूफान" अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन फॉर तिब्बत (2012) ।

चीन की सरकार ने आत्म–दाह को "घरेलू समस्याएँ,"[17] बता कर इसे बदनाम और हतोत्साहित किया और आत्म–दाह करने वालों को "निर्वासित दलाई लामा द्वारा प्रेरित बहिष्कृत, अपराधी और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों" के रूप में आरोपित किया।[18] चीनी अधिकारी और मीडिया ने भी आत्म–दाह करने वालों और उनकी मृत्यु को आतंकवादी और.... नकलची–बिल्ली जैसे अपमानित शब्दों का प्रयोग कर उल्लेख किया। "उन्होंने कुछ पर चोरी करने के आरोप भी लगाए और संकेत दिए कि" तनाव "और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के कारण ये "आत्म–हत्याएं" हुई हैं।" उन्होंने कहा, "वे आवेगी हैं और उनमें आत्म–विश्वास की कमी है।"[19]

"पीआरसी के अधिकारियों ने आत्म–दाह करने वालों को हिंसक कह कर कड़ी आलोचना की है।"[20]

हिंसक कार्रवाई और आत्म-दाह विरोधों का अपराधीकरण

आत्मदाह विरोध तिब्बती लोगों की आवाज़ का विस्तार भी है जो चीनी सरकार से उनके साथ मानवीयता और गरिमा के साथ व्यवहार करने का आग्रह करता है। आत्म–दाह करने वाले पीड़ा की चरम सीमा तक पहुंच कर अपने शरीर को आग लगा देते हैं और अकल्पनीय निर्दयता की भेंट हो जाते हैं। प्रत्येक आत्म–दाह विरोध के बाद, चीनी अधिकारियों ने हिंसक तनातनी और तिब्बती क्षेत्रों में पहले से ही दमनकारी माहौल को "आत्म–दाह करने वालों से "सम्बद्ध" लोगों को दंडित कर तेज कर दिया, इसमें मित्र, परिवार

---

17 तानिया बर्निगन, "चीन की पुलिस द्वारा हाल के आत्मदाह विरोध की आड़ में एक तिब्बती को अपनी पत्नी की हत्या का आरोप", दी गार्डियन, 19 मार्च 2013, https://www.theguardian.com/world/2013/mar/19/china-accuses-tibetan-self-immolation.

18 चीन का दावा है कि "तिब्बत के आत्मदाह करने वाले बहिष्कृत, अपराधी और मानसिक रोगी हैं, "दी गार्डियन, 7 मार्च 2012 https://www.theguardian.com/world/2012/mar/07/tibetan-immolators-outcasts-criminals-china.

19 CECC विशेष रिपोर्टः तिब्बती आत्मदाह" (2012)।

20 जॉन सोबोसलाई, हिंसक रूप से शांतिपूर्णः तिब्बतियों के आत्मदाह और अलगाव और गैर/हिंसा की दोहरी समस्या, खुला धर्मशास्त्र 1, संख्या 1(2015) 146–159, https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/opth.2014.1.issue-1/opth-2015-0004/opth-2015-0004.pdf.

और पूरा समुदाय भी शामिल था।[21] और विभिन्न दांव–पेचों के माध्यम से, कुछ आत्म–दाह करने वाले भी जो विरोध के बाद जीवित रहे।

पहला आत्म–दाह करने वाले तापेय के मामले में, उसे पास में तैनात एक पीपुल्स सशस्त्र पुलिस कर्मी ने गोली मार दी थी, जबकि उसके शरीर में पहले से ही आग लगी हुई थी।[22] प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तापेय, जो घर पर बनाया हुआ, तिब्बती ध्वज, जिसके बीच में परम पावन दलाई लामा का चित्र था हाथ में लिए हुए था। वह फिर जमीन पर गिर गया और पुलिस कर्मियों द्वारा एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया।

एक अन्य घटना में, सुरक्षा कर्मियों ने निहत्थे तिब्बतियों पर गोलियां चलाईं, जिन्होंने आत्मदाह के विरोध के बाद अधिकारियों को भिक्षु कलसांग यशे के शरीर को ले जाने से रोकने की कोशिश की। दो तिब्बतियों को गोली मार दी गई और कई अन्य घायल हो गए, जब चीनी पुलिस ने तिब्बतियों के एक समूह पर गोलियां चला दीं,जो पुलिस से केलसंग येशी के शव को वापिस मांग रहे थे। केलसांग येशी की रक्षा के लिए इकट्ठा हुई भीड़ जो केलसंग येशी की अधिकारियों से सुरक्षा के लिए एकत्रित हुए थे को हटाने की कोशिश में भी पुलिस ने भीड़ पर चेतावनी–गोली चलाई थी जबकि भिक्षु आग की लपटों में घिर गए थे।

मीडिया रिपोर्ट में इस क्षेत्र से जुड़े सूत्रों के हवाले से लिखाः "मृतक के दो परिवार के सदस्यों को बंदूक की नोक पर रखा गया था और बंदूक की नोक पर ही नदी में अवशेष फेंकने के लिए मजबूर किया गया था। और जो लोग घायल हुए वे गिरफ्तार होने के डर से अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं थे।"[23]

सरकार द्वारा आत्म–दाह की प्रमुखता को कम करने के लिए इस विरोध

---

21 महत्वपूर्ण बुराई के कृत्यः तिब्बती आत्म–दाहों का अपराधीकरण", तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान 2014 https://savetibet.de/fileadmin/user_upload/content/berichte/Acts-of-significant-evil-073114.pdf.

22 "तिब्बत में भिक्षु ने खुद को आग लगाई, विरोध के दौरान पुलिस द्वारा गोली, तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान, 27 फरवरी, 2009, https://www.savetibet.org/monk-in-tibet-sets-himself-on-fireshot-by-police-during-protest/.

23 केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, "आत्मदाह करने वाले के शव की वापिसी की कोशिश पर तिब्बतियों पर गोलियां बरसायीं।" 26 दिसंबर 2014 http://tibet.net/2014/12/tibetans-shot-trying-to-reclaim-self-immolators-body/.

को "आतंकवाद का कृत्य" कह कर जानबूझ कर बदनाम करने का प्रयास किया और यहाँ तक कि "निवारक" उपाय के रूप में आत्म–दाह करने वालों के सहयोगियों, मित्रों और रिश्तेदारों के भी अपराधीकरण में शामिल होने की बात की। चीनी सरकार ने दावा किया कि "बाहरी ताकतों" ने आत्म–दाह को उकसाया है। प्रसिद्ध तिब्बती लेखक त्सेरिंग वोसर ने चीन द्वारा अपने मुखपत्रों, शिन्हुआ समाचार एजेंसी, सिन्हुआ.नेट, और चीन सेंट्रल टेलीविज़न (सीसीटीवी) के माध्यम से "आत्म–दाह करने वालों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने" के लिए चीन के प्रयास का भंडाफोड़ किया है। "अपनी किताब तिब्बत ऑन फायरः सेल्फ इमोलेशन्स अगेंस्ट चायनीज़ रूल में लेखिका ने लिखा है:)

> *इन मीडिया केंद्रों द्वारा लगाए गए विचित्र आरोपों के बीच यह दावा किया गया कि आत्म–दाह करने वालों को मिर्गी का दौरा पड़ता था, 'मानसिक समस्याएं 'थीं, वे चोर थे, या मद्यपान के दुरुपयोग, लड़ाई और जुए में लिप्त थे। अन्य लोगों ने आरोप लगाया, वे नियमित रूप से वेश्याओं के पास जाते थे, यौन संचारित रोगों से ग्रसित थे। {....} उनकी दूसरों के साथ महत्वपूर्ण असहमति थी, उन्हें प्रेमी–जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ा, या उनके स्कूल के ग्रेड में भी अचानक गिरावट आई, जिसने उन्हें किसी तरह आत्म–दाह करने के लिए प्रेरित किया।*

यह "सिद्ध" करने के लिए चीन सेंट्रल टेलीविजन द्वारा आरोपों को प्रमाण प्रदान करने के लिए "पांच प्रचार विशेष" कार्यक्रमों का निर्माण किया।[24] सीसीटीवी में "सात आत्म–दाह करने वालों के चित्र दिखाए गए" जिनके परिवार और दोस्तों को उनके विषय में आज तक कोई जानकारी नहीं है।[25]

तिब्बत एक बौद्ध राष्ट्र है जिसमें मृत लोगों के लिए पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के लिए बहुत सम्मान है। स्थानीय अधिकारियों ने अनैतिक प्रथाओं को लागू किया, जिसमें आत्म–दाह करने वालों के शरीर को जिन्होंने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया, नहीं सौंपना भी शामिल हैं ताकि, शोक संतप्त परिवार दिवंगत के अंतिम अनुष्ठानों से वंचित हो और भिक्षुओं को आत्मदाह करने वालों के लिए अंतिम संस्कार करने से रोका जाए। प्रार्थना सेवाएं प्रदान करने वाले भिक्षुओं को हिरासत में लिया गया था। कई बार, अधिकारियों द्वारा गुप्त दाह संस्कार करने के बाद अवशेष परिवारों को

---

24 त्सेरिंग वोसेर, जलता तिब्बतः चीनी शासन के विरोध में आत्मदाह। (London: Verso Books, 2016), 47

25 वही–51 ।

वापस कर दिए गए। "जो कोई भी आत्म–दाह करने वालों की प्रशंसा करता है, उनके कार्यों के लिए सहानुभूति व्यक्त करता है, या उनके परिवारों को दान की पेशकश करता है"।[26] उनके लिए कनलोह और माल्हो जैसे प्रांतीय स्तर के अधिकारियों ने आत्म–दाह पर रोक लगाने वाले कड़े आदेशों के साथ आपातकालीन निर्देश जारी किए। माल्हो सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने सात निषिद्ध गतिविधियों को सूचीबद्ध किया, जिसे "सात निषेध"[27] के रूप में जाना जाता है।

1. किसी के घर में दलाई लामा के चित्र को प्रदर्शित नहीं करना।

2. दलाई लामा गुट के शब्दों और दृष्टिकोण को फैलाना नहीं।

3. पार्टी और सरकार के बारे में कोई शिकायत या अफवाह न फैलाएं।

4. कोई आयोजन, योजना, उकसाना, जबरदस्ती, प्रलोभन, आत्म–दाह के लिए उकसाना और दूसरों की आत्म–दाह में सहायता न करना।

5. आत्म–दाह न देखना, अंतिम संस्कार नहीं करना या इसमें शामिल लोगों को दान नही देना।

6. अवैध मार्च या अन्य जलसों में कोई भागीदारी नहीं।

7. सामाजिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली कोई भी घटना, सार्वजनिक स्थानों पर गड़बड़ी या यातायात को बाधित न करें।

आत्म–दाह को रोकने के इन उपायों की विफलता स्पष्ट हैः आत्म–दाह के मना करने के निर्देशों को ज़ारी करने के बाद भी, आत्म–दाह जारी रहे। वास्तव में, इस तरह के निर्देशों के बाद आत्म–दाह विरोध प्रदर्शनों की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। उदाहरण के लिए, 21 अक्तूबर 2012 में कनलोह तिब्बती स्वायत्त प्रान्त के अधिकारियों ने आत्म–दाह के पीछे "काले हाथों" की जानकारी देने वालों के लिए एक नोटिस जारी किया जिसमें जानकारी देने वालों के लिए 50,000–200,000 येन का पुरस्कार देने का वादा किया गया था, जबकि इस क्षेत्र में कई अतिरिक्त निगरानी कैमरा लगाए गए थे।[28] वॅइसर ने खुलासा किया कि 'इस दस्तावेज़ के जारी होने से पहले के छह महीनों में, छह तिब्बतियों ने कनलोह में आत्मदाह कर

26 वही–80

27 वही–82

28 वही–

लिया था। लेकिन इन उपायों के कार्यान्वयन के बाद एक संक्षिप्त महीने में, कनलोह ने कुल चौदह आत्म–दाह देखे।"[29]

सामूहिक सजा

आत्म–दाह विरोध प्रदर्शनों की लहर के साथ आत्म–दाह करने वालों के परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी, हिरासत, यातना बढने लगी।

24 दिसंबर 2017 को, एक और तिब्बती ने अपने आत्म–दाह विरोध प्रदर्शन के बाद जलने के धावों की ताब न सहकर दम तोड़ दिया। कोंपे ने 23 दिसंबर 2017 को चीनी सरकार की नीतियों के विरोध में खुद को नागबा प्रांत में आग के हवाले कर दिया। वह लगभग 30 साल का था और उसने एक साल पहले ही शादी की थी। उसके विरोध के तुरंत बाद, पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और उसे साथ ले गई। भारत में सूत्रों के अनुसार, आत्मदाह विरोध के 12 घंटे के भीतर, कोंपे की अस्पताल में मृत्यु हो गई। कोंपे के पिता,ग्याक्याब को अपने बेटे के आत्म–दाह के बाद हिरासत में लिया गया था, और ग्याक्याब के वर्तमान ठिकाने और हालत की जानकारी अज्ञात थी।

आत्म–दाह के कृत्य का अपराधीकरण और सामूहिक सजा को लागू करना चीन सरकार द्वारा अपनाया गया सामान्य घिनौना तरीका है। आत्म–दाह करने वालों के गाँव और मठों को दंडित किया जाता है, और क्षेत्र के प्रभारी अधिकारियों को भी ऐसे विरोध प्रदर्शनों की सजा दी जाती है।[30]

चीनी अधिकारियों ने आत्म–दाह को "दलाई गुट" (दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन) द्वारा उकसाए गए आतंकवाद के रूप में प्रतिक्रिया दी है। अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों और आत्म–दाह करने वालों के रिश्तेदारों को निशाना बनाते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश तिब्बती आत्म–दाह करने वालों के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को तीन साल तक विदेश यात्रा या "तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र" में यात्रा करने पर रोक लगाते हैं। वे आत्म–दाह करने वालों के परिवार के सदस्यों को चीनी सरकार या सेना में रोजगार के लिए आवेदन करने से रोकते हैं, और घटना के बाद

29 वही–

30 वर्षीक रिपोर्ट 2014: तिब्बत में मानवाधिकारो की स्थिति, तिब्बती मानवाधिकार और लोकतंत्र केंद्र, 2015 http://tchrd.org/annual-report-2014-human-rights-situation-in-tibet/.

तीन वर्षों में ऋण या व्यावसायिक लाइसेंस के लिए आवेदन को स्वतः ही अस्वीकार कर देते हैं। दिशानिर्देशों का यह भी अर्थ है कि आत्म–दाह करने वाले के परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले खेत को जबरन सरकार को वापस कर दिये जाएंगे, और संभावित आत्म–दाह विरोध(धों) के विषय में जानकारी के लिए नकद पुरस्कार की पेशकश की जाएगी।

ज़ोगे, नाबा स्वायत्त प्रान्त में अप्रैल 2013 में, अधिकारियों का नए नियम ज़ारी किये गए जिसमें आत्म–दाह करने वाले के परिवार के सदस्यों, साथी ग्रामीणों, और मठों को आपराधिक दंड देने का प्रावधान था। जारी किए गए दस्तावेज़ में 16 धाराएं हैंः आत्म–दाह करने वाले के परिवार के सदस्यों को काली–सूची में रखना (अनुच्छेद 16), राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना (अनुच्छेद 2), सरकारी रोजगार से वंचित करना (अनुच्छेद 1), सभी कल्याण ाकारी लाभों से तीन साल के लिए बहिष्कार (अनुच्छेद 4), भूमि और घरों के स्वामित्व से इनकार (अनुच्छेद 10), व्यवसाय शुरू करने से रोक (अनुच्छेद 10), ल्हासा और विदेशी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध, (अनुच्छेद 11), वित्तीय सहायता से वंचित (अनुच्छेद 5), और ग्रामीणों, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए "कानूनी शिक्षा" अभियान (अनुच्छेद 13)[31]

इसके अतिरिक्त नियमानुसार गाँव तथा मठों को 10,000 से 50,000 येन भी जमा करवाने पड़ते थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई आत्म–दाह ना हो। यदि आत्म–दाह होता है तो जमा–राशि ज़ब्त हो जाएगी और नई राशि जमा करवानी पड़ेगी (अनुच्छेद 7)।[32]

नए दिशा निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित समुदाय को राष्ट्रीय निवेश परियोजनाओं तथा समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं से एक वर्ष के लिए निरस्त अथवा अयोग्य घोषित किया जायेगा।

ज़ोगे प्रान्त द्वारा ज़ारी दिशा–निर्देश

5 दिसंबर 2012 को, डोज़े प्रांत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशानिर्देश जारी किया जिसमें घोषणा की गई कि जो कोई भी तिब्बती लोगों को

31 "चीन ने तिब्बत के ज़ोगे प्रांत में आत्मदाह रोकने के लिए अनपेक्षित कड़े उपायों की घोषणा की, "तिब्बती मानवअधिकार और लोकतंत्र केंद्र," फरवरी 14, 2014 http://tchrd.org/china-announces-unprecedented-harsh-measures-to-deter-self-immolations-in-tibets-dzoege-county/.

32 –वही–

आत्म–दाह के लिए समर्थन या प्रोत्साहित करेगा उन पर "जानबूझकर हत्या" का आरोप लगाया जाएगा।[33]

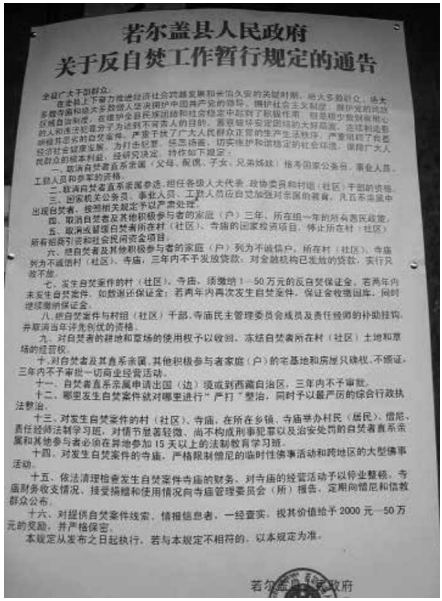

若尔盖县人民政府
关于反自焚工作暂行规定的通告

一、取消自焚者直系亲属（父母、配偶、子女、兄弟姊妹）报考国家公务员、事业人员、工勤人员和参军的资格。

二、取消自焚者直系亲属参选、担任各级人大代表、政协委员和村组（社区）干部的资格。

三、国家机关公务员、事业人员、工勤人员应自觉加强对亲属的教育，凡直系亲属中出现自焚者，按照相关规定予以严肃处理。

四、取消自焚者及其他积极参与者的家庭（户）三年、所在组一年的所有惠民政策。

五、取消或暂缓自焚者所在村（社区）、寺庙的国家投资项目，停止所在村（社区）所有招商引资和社会民间资金项目。

六、将自焚者及其他积极参与者的家庭（户）列为不诚信户，所在村（社区）、寺庙列为不诚信村（社区）、寺庙，三年内不予发放贷款，对金融机构已发放的贷款，实行只收不放。

七、发生自焚案件的村（社区）、寺庙，须缴纳1—50万元的反自焚保证金，若两年内未发生自焚案件，如数退还保证金；若两年内再次发生自焚案件，保证金收缴国库，同时继续缴纳保证金。

八、把自焚案件与村组（社区）干部、寺庙民主管理委员会成员及责任经师的补助挂钩，并取消当年评先创优的资格。

九、对自焚者的耕地和草场的使用权予以收回，冻结自焚者所在村（社区）土地和草场的经营权。

十、对自焚者及其直系亲属、其他积极参与者家庭（户）的宅基地和房屋只确权，不颁证，三年内不予审批一切商业经营活动。

十一、自焚者直系亲属申请出国（边）境或到西藏自治区，三年内不予审批。

十二、哪里发生自焚案件就对哪里进行"严打"整治，同时予以最严厉的综合行政执法整治。

十三、对发生自焚案件的村（社区）、寺庙，在所在乡镇、寺庙举办村民（居民）、僧尼、责任经师法制学习班，对情节显著轻微、尚不构成刑事犯罪以及治安处罚的自焚者直系亲属和其他参与者必须在异地参加15天以上的法制教育学习班。

十四、对发生自焚案件的寺庙，严格限制僧尼的临时性佛事活动和跨地区的大型佛事活动。

十五、依法清理检查发生自焚案件寺庙的财务，对寺庙的经营活动予以停业整顿，寺庙财务收支情况、接受捐赠和使用情况向寺庙管理委员会（所）报告，定期向僧尼和信教群众公布。

十六、对提供自焚案件线索、情报信息者，一经查实，视其价值给予2000元—50万元的奖励，并严格保密。

本规定从发布之日起执行，若与本规定不相符的，以本规定为准。

若尔盖县人民政府

ज़ोगे प्रान्त द्वारा ज़ारी दिशा–निर्देशों का अनुवाद

आत्म–दाह के विरुद्ध काम के लिए अनंतिम नियम पर अधिसूचना

डोज़े प्रान्त की जनता सरकार द्वारा जारी

इस देश के सभी सरकारी कर्मचारियों और लोगों के लिए:

इस महत्वपूर्ण क्षण में जब पूरे देश ने अर्थव्यवस्था के विस्तार और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में अत्यधिक प्रयास किया है, जनता का बहुमत, मठ, और भिक्षु चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व का कड़ाई से पालन करते हैं, समाजवादी व्यवस्था का पालन करते हैं, और अल्पसंख्यक क्षेत्रीय स्वायत्तता की प्रणाली का पालन करते हैं। पूरे प्रांत में, वे राष्ट्रीय एकीकरण और सामाजिक स्थिरता की सुरक्षा में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। फिर भी, अराजक अपराधियों का एक छोटा अल्पसंख्यक समूह, अपने बुरे इरादों को पूरा करने के निहित स्वार्थों के साथ समग्र स्थिरता

33 "ज़ोगे प्रांतः 'सद्भाव और स्थिरता बनाए रखना," तिब्बत वॉच, अक्तूबर 2013, http://www.tibetwatch.org/uploads/2/4/3/4/24348968/dzoege_county_thematic_report.pdf.

और एकता को नष्ट कर रहा है। आम जनता का जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है। समाज और अर्थव्यवस्था का स्वस्थ विकास नहीं हो पाता। अपराध को रोकने के लिए, गुणी की प्रशंसा और दोषी को दंडित करने के लिए, स्थिरता और सामाजिक सदभाव को बनाए रखने के लिए, और जनता के मौलिक हितों की रक्षा के लिए, इन नियमों को विशेष रूप से सावधानीपूर्वक विचार–विमर्श के बाद तैयार किया जाता है।

1. आत्म–दाह करने वाले व्यक्ति के निकटस्थ रक्त–सम्बन्धियों (माता–पिता, पति, बच्चे, चचेरे भाई) को राष्ट्रीय लोक सेवक के पद, उद्दयम स्टाफ, वर्कर, यूनिट क्लर्क और सेना में भर्ती होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

2. निकटस्थ रक्त–सम्बन्धियों को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में प्रतिनियुक्ति से, चीनी राजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन से, और गांव समूह (समुदाय) की स्टाफ सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है।

3. राज्य के प्रतिष्ठानों के सरकारी कर्मचारियों, उद्यम कर्मचारियों और श्रमिकों को जानबूझकर अपने रिश्तेदारों की शिक्षा को मजबूत करना चाहिए। एक बार यदि उनके तत्काल रिश्तेदारों के बीच आत्म–दाह होता है, व्यक्ति (नोटः संदर्भ में उल्लेखित सरकारी कर्मचारी) से सम्बन्धित नियमों के अनुरूप गंभीरता से निपटा जाना चाहिए।

4. तीन साल के लिए लोगों को लाभान्वित करने वाली नीतियों से आत्म–दाह करने वाले के परिवार को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, और जो ग्रामीण समूह जिसमें आत्म–दाह करने वाला रहता था, उन्हें तीन साल के लिए लोगों को लाभान्वित करने वाली नीतियों से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।

5. गाँव (समुदाय) और मठ, जहाँ पर आत्म–दाह करने वाला रहता था, को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या राष्ट्रीय निवेश परियोजनाओं से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। निवेश आकर्षण की सभी परियोजनाएं, सभी सामाजिक और ग्रामीण पूंजीगत परियोजनाओं को उस गाँव (समुदाय) से काट दिया जाना चाहिए जिसमें आत्म–दाह करने वाला रहता था।

6. आत्म–दाह करने वाला या अन्य सक्रिय प्रतिभागियों के परिवार (घर)

को बेईमान परिवार के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। गाँव (समुदाय) और मठ जिसमें आत्म–दाह करने वाला रहता था, को बेईमान मठ के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। तीन साल के लिए उन्हें ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। वित्तीय संस्थानों द्वारा पहले से दिए गए ऋणों को केवल वापिस लिया जाना चाहिए और उन्हें कोई नया ऋण नहीं दिया जाएगा।

7. गाँव (समुदाय) या मठ जहाँ पर आत्मदाह हुआ हो, आत्मदाह का प्रतिकार करने के लिए जमानत राशि के रूप में 10,000 से 50,000 युआन का भुगतान करना चाहिए। अगर दो साल तक कोई आत्मदाह नहीं होता है तो प्रतिभूति राशि पूरी लौटा दी जायेगी। यदि कोई आत्म–दाह फिर से होता है, तो प्रतिभूति राशि को जब्त कर राज्य के खजाने के जमा कर दिया जाएगा और साथ ही और प्रतिभूति राशि जमा करवानी पड़ेगी।

8.आत्म–दाह मामलों को ग्राम समूह (समुदाय) के कैडरों की सब्सिडी से, मठ की लोकतांत्रिक प्रबंधन समिति के सदस्य और भिक्षु शिक्षकों की मान्यता से जोड़ा जाना चाहिए। उन्हें वर्ष के पुरस्कारों के लिए चयन से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

9. भूमि की खेती और चरागाह के अधिकारों को आत्म–दाह करने वाले से वापस ले लेना चाहिए। जमीन और चरागाह का प्रबंधन अधिकार उस गाँव (समुदाय) के लिए बंद कर देना चाहिए जहाँ आत्म–दाह करने वाला व्यक्ति रहता था।

10. आत्म–दाह करने वाले व्यक्ति की केवल आवासीय संपत्तियों और, तत्काल रिश्तेदारों और अन्य सक्रिय प्रतिभागियों से संबंधित घर को स्वामित्व की पुष्टि की जा सकती है। लेकिन उनकी आवासीय संपत्ति और घर को प्रमाणीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनकी सभी वाणिज्यिक परिचालन गतिविधियों को तीन साल के लिए मंजूरी नहीं मिलेगी।

11. देश से बाहर निकलने (सीमा) या तिब्बत स्वायत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवेदन, जो कि आत्म–दाह करने वाले के तत्काल रिश्तेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, को तीन साल के लिए मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए।

12. जहाँ आत्म–दाह का मामला होता है, वहाँ "कठोर कार्रवाई" और सज़ा

होनी चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें व्यापक प्रशासनिक कानून के प्रवर्तन से भी गुजरना होगा।

13. जहां आत्म–दाह हुआ हो वहां के ग्रामीणों, भिक्षुओं, भिक्षुणियों, जो समुदाय से जुड़े हों, के लिए कानूनी पाठ्यक्रमों के लिए सत्र शुरू किया जाना चाहिए। यदि आत्म–दाह का मामला सार्वजनिक सुरक्षा को भंग करने और आपराधिक दंड का नहीं बनता, तो आत्म–दाह करने वाले के निकटस्थ रिश्तेदारों और अन्य सक्रिय प्रतिभागियों को 15 दिनों से अधिक कानूनी शिक्षा सत्रों में भाग लेना चाहिए।

14. मठ में जहां आत्म–दाह होता है, धार्मिक गतिविधियों और अंतर–क्षेत्रीय बौद्ध कार्यक्रमों को गंभीरता से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

15. कानून के अनुसार, उन वित्तीय सौदों का निरीक्षण किया जाएगा जहां आत्म–दाह होता है। वित्तीय आय और व्यय, प्राप्त और उपयोग किए गए दान का विवरण, मठ प्रबंधन समिति को सूचित किया जाना चाहिए और समय–समय पर भिक्षुओं, भिक्षुणियों और भक्तों को घोषित किया जाना चाहिए।

16. यदि कोई आत्म–दाह की की खुफिया रिपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है और यदि जानकारी की पुष्टि हो जाती है, तो सूचना देने वाले को 2,000 से 500,000 युआन का इनाम दिया जाएगा। प्रक्रिया को कड़ाई से गोपनीय रखा जाना चाहिए।

इस नियम को इसकी घोषणा के दिन से लागू किया जाना चाहिए। इस नियम की विसंगति में किसी भी अन्य नियम के स्थान पर इस नियम को अंतिम और आधिकारिक माना जाना चाहिए।

सील से ज़ारी
पीपुल्स गवर्नमेंट ऑफ ज़ोगे प्रांत
दिनांकः 8 अप्रैल, 2013

"आत्म-दाह को उकसाने" के लिए तिब्बतियों को सज़ा

लगभग एक सौ तिब्बती को हिरासत में लिया गया है और उन्हें आत्म–दाह विरोध के साथ सम्बन्ध के अनुसार मनमाने ढंग से विभिन्न अवधि की

सज़ा सुनाई गयी। आत्म–दाह प्रदर्शनों के जवाब में चीन द्वारा तिब्बतियों पर मुकदमा चलाना, जिसे चीन आत्म–विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए एक निवारक उपाय मानता है, वास्तव में आत्म–दाह सहित अधिक दुखद विरोध–प्रदर्शनों को बढ़ावा देता है।

28 मार्च 2018 को, पीपुल्स कोर्ट ऑफ बरखम, नगाबा ने एक गुप्त मुकद्दमें में, आत्म–दाह विरोध से संबंधित आरोपों पर 36 वर्षीय लोबसांग सांगये को 5 वर्ष की सजा सुनाई।[34] यद्यपि आत्म–दाह विरोध की जानकारी कड़ी निगरानी और इंटरनेट सेंसरशिप के कारण कम मिल पाती है, यह ज्ञात हुआ है कि कोर्बी मठ के भिक्षु लोबसांग सांगेय को अगस्त 2012 में लंबे समय तक भीख मांगने के लिए हिरासत में लिया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था। उसे पांच साल बाद अगस्त, 2017 में पुनः गिरफ़्तार किया गया और तब से एकांत वास में रखा गया है। उसके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को उसके मुकद्दमें की या सज़ा की कोई खबर नहीं दी गयी।

जब 39 वर्षीय वांगचुक त्सेतेन ने 15 अप्रैल 2017 को आत्मदाह कर लिया, तो न्यारोंग प्रांत के तीन तिब्बतियों को वांगचुक त्सेतान के "मोबाइल फोन रखने के आरोप में" गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर अत्याचार और गंभीर पिटाई की गई। अन्य पांच तिब्बतियों को आत्म–दाह विरोध का वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 39 वर्षीय कुंचोंक त्सेरिंग को आत्म–दाह विरोध की वीडियो रिकॉर्डिंग के आरोप में हिरासत में लिया गया और शक है उसकी अत्यधिक पिटाई के कारण हिरासत के दौरान ही मृत्यु हो गयी।[35]

कई मामलों में, आत्म–दाह से सम्बद्ध तिब्बतियों को मृत्यु–दंड और लम्बी अवधि की जेल की सजाएं सुनाई गयीं। आत्म–दाह करने वाली 29 वर्षीय कुंचोक वांगमो के 32 वर्षीय पति डोलमा क्याब को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में 15 अगस्त 2013 को मृत्युदंड सुनाया गया। पांच मास पहले

---

34 "तिब्बती भिक्षु को 'आत्मदाह से सम्बन्धित' विरोध के आरोप में पांच साल जेल की सज़ा, "रेडियो फ्री एशिया, 30 मार्च 2018 http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=38940&t=1.

35 तेनज़िन धारपो, "5 तिब्बतियों को कद्र्ज़े में एक तिब्बती की आत्मदाह के बाद से गिरफ्तार किया गया", फायुल 19 अप्रैल 2017, http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=38940&t=1.

उसकी पत्नी ने खुद को आग लगा ली थी और उसका पति दजोएगे प्रांत के चीनी अधिकारियों द्वारा कुंचोक वांगमो के खुद के आत्म–दाह के एक दिन बाद गिरफ़्तार किया गया था।" डोलमा क्याब को घरेलू समस्याओं के आधार पर अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए आधिकारिक आदेशों को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद हिरासत में लिया गया था।[36]

इसी तरह, 31 जनवरी 2013 को, इंटरमिडिएट पीपुल्स कोर्ट ऑफ़ नाबा (चीनीःअबा) और कियान स्वायत्त प्रान्त ने दो तिब्बतियोंः लोबसांग कुंचोक, 40, और लोबसांग त्सेरिंग, 31, को आठ आत्म–दाह मामलों में "जानबूझ कर हत्या" के आरोप में लम्बी जेल की सजा सुनाई। चीनी सरकार की स्वामित्व वाली समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, लोब्सांग कुंचोक को दो साल की सजा के साथ मृत्यु दंड दिया गया, जबकि उनके भतीजे लोबसांग त्सेरिंग को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई।[37] उन दोनों को अगस्त 2017 में हिरासत में लिया गया था, लेकिन उनकी हिरासत और पुलिस के आरोपों की घोषणा दिसंबर 2012 में ही की गई थी। आत्म–दाह विरोध प्रदर्शनों से संबंधित जानकारी का प्रसार करना समान कठोरता के साथ नियंत्रित किया जाता है। युशु तिब्बती स्वायत्त प्रान्त, में दो साल पहले रिकार्ड किए गए आत्म–दाह विरोध प्रदर्शनों के वीडियो बनाने और साझा करने के आरोप में अक्टूबर 2017, में चीन ने त्रिडू (चीनीःचेंगदू) प्रांत में सात तिब्बतियों को हिरासत में लिया। रेडियो फ्री एशिया ने बताया कि "चीनी अधिकारियों ने उन तिब्बतियों पर इंटरनेट के माध्यम से तिब्बत के बाहर संपर्क बनाने का आरोप लगाया, और कई गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया।"[38]

3 नवंबर 2014 को, नगाबा में इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने एक वाहन पर आत्म–दाह करने वाले कुंचोक त्सेतन के जले शरीर को उठाने की कोशिश

---

36 केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, "चीन ने तिब्बतियों को आत्मदाह पर मौत की सजा दी," 19 अगस्त 2013, http://tibet.net/2013/08/china-sentences-tibetan-to-death-over-self-immolations/

37 "तिब्बतियों को आत्म–दाह का विरोध करने के लिए प्रदर्शन मुकद्दमें में 'हत्या' की सज़ा सुनाई गई।" तिब्बती मानवाधिकार और लोकतंत्र केंद्र 1 फरवरी 2013, http://tchrd.org/tibetans-sentenced-for-murder-at-show-trial-to-discredit-self-immolation-protests/.

38 चीन ने आत्मदाह विडियो पर युसूल में सात तिब्बतियों को हिरासत में लिया "रेडियो फ्री एशिया, 23 अक्टूबर 2017 https://www.rfa.org/english/news/tibet/yushul-detentions-10232017164043.html.

करने के लिए डोलमा त्सो को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसी मामले में, सात अन्य तिब्बतियों को कुंचोक त्सेतन को आत्म–दाह में सहायता करने के आरोप में 5 वर्ष जेल की सज़ा सुनाई गयी। कोनमे को 3 साल कैद और पांच अन्य अज्ञात तिब्बतियों को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी।

29 अगस्त 2011 को नगबा की अदालत ने 46 वर्षीय लोबसांग त्सुन्दुए को 11 वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार 29 अगस्त 2011 को "लोबसांग त्सुन्दुए को फुंत्सोक द्वारा खुद को आग लगाने के बाद छिपाने और उपचार लेने से रोकने के आरोप में "जानबूझ कर मानव–वध" के अंतर्गत सज़ा सुनाई गई। लोबसांग त्सुन्डुए कीर्ति मठ के मृतक फुंत्सोक का चाचा और अध्यापक था जिसने 16 मार्च 2011 को आत्म–दाह किया था।[39]

30 अगस्त, 2011 को नगबा की अदालत ने लोबसांग तेंजिन को 13 वर्ष की और लोबसांग तेंजिन (नकतें) को "फुंत्सोक को आत्म–दाह के लिये" तैयार करने, उकसाने और सहायता करने" के आरोप में 10 वर्ष की सज़ा सुनाई।[40]

5 सितंबर को, लोबसांग धारग्याल, 22 (आत्म–दाह करने वाले फुंत्सोक का भाई), तथा 30 वर्षीय त्सोको, को अप्रैल के प्रारम्भ में गिरफ्तार किया गया और फुंत्सोक के आत्म–दाह में संदिग्ध भूमिका के आरोप में प्रत्येक को 3 वर्ष की सज़ा सुनाई गयी। 26 सितंबर 2011को फुंत्सोक के भाई लोबसांग धारग्याल तथा चाचा लोबसांग त्सोन्दुए की गिरफ्तार करने के बाद फुंत्सोक के छोटे भाई ने भी आत्म–दाह कर विरोध प्रदर्शन किया। उसके परिवार के चार बेटों में से दो ने खुद को आग लगा ली थी और उनके बड़े बेटे को तीन साल की सज़ा हुई, और चाचा त्सोन्दुए को 11 साल की सज़ा सुनाई गई थी। यह भी कहा जाता है कि पिता तथा उसका एक मात्र शारीरिक रूप से अक्षम बेटा, उसके बाद कहीं भी दिखाई नहीं दिए।

---

39 "आत्मदाह मामले में तिब्बती भिक्षु को 11 वर्ष की सज़ा," तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र 29 अगस्त 2011 http://tchrd.org/tibetan-monk-sentenced-to-11-yrs-termin-immolation-case/.

40 "चीनः मठों पर कार्रवाई समाप्त हो, "ह्यूमन राइट्स वॉच, 12 अक्तूबर 2011 https://www.hrw.org/news/2011/10/12/china-end-crackdown-tibetan-monasteries

31 जनवरी, 2013 को संगचू (चीनी:ज़िआहे) प्रांत के गनसू क्षेत्र के कनलोह (चीनी:गन्नान) प्रदेश की जन अदालत ने छः तिब्बतियों को 58 वर्षीय दोरजी रिनचें, जिसने 23 अक्तूबर, 2012[41] को आत्म–दाह किया था, के आत्मदाह में सहयोग के आरोप में 3 से 12 वर्ष की सज़ा सुनाई । छः तिब्बती हैं: पेमा धौंदुप (12 वर्ष की सज़ा), केलसांग ग्यात्सो (11 वर्ष), पेमा त्सो (8 वर्ष), लाहमो धौंदुप (7 वर्ष), धुकर ग्याल (4 वर्ष) तथा यांगमो कयई (3 वर्ष)।[42]

28 फरवरी, 2013 को, बीजिंग की सत्ता को चुनौती देते" आत्म–दाह को उकसाने" के आरोप में 9 तिब्बतियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। गनसु क्षेत्र के कनलोह प्रांत (चीनी:गन्नान) में लुचू (चीनी:लुकू) की अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच सुनवाई हुई और किसी भी सम्बन्धी तथा तिब्बती को कान्शो (चीनी: गन्नान) प्रांत की लुचु (चीनी: ल्यूक) काउंटी में अदालत की सुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच रिश्तेदारों और तिब्बतियों को अदालत परिसर के पास आने की अनुमति नहीं दी गयी। आरोपियों की शिनाख्त ज़ामसा दोंगसुक मठ के भिक्षु, केलसंग समड्रुब, केलसंग क्याब, केलसंग सोनम, त्सेसुंग, दोरजे दोंगद्रुब, केलसंग नामड्रोन, सोनम क्यी, ल्हमो दोरजी तथा निमा के रूप में हुई है। वे सभी लुचू में ज़ामसा लोटसो गाँव से हैं।[43]

2 मार्च, 2013 को पूर्वी तिब्बत की एक चीनी अदालत ने चालू आत्म–दाह की लहर से सम्बंधित "अपराधों" के लिए तीन तिब्बतियों को 15 वर्ष तक की भारी जेल अवधि की सज़ा सुनाई। कनलोह क्षेत्र के एक सरकारी चीनी समाचार पत्र ने बताया है कि लुचू की एक अदालत ने यह निर्णय दिया है। अदालत ने दोरजी को 15 साल जेल की सज़ा, कलसंग सोनम को 11 साल, और त्सेनक्याब को 10 वर्ष की सज़ा 'जानबूझ कर हत्या' के आरोपों

---

41 वही–

42 "चीन द्वारा आत्मदाहों पर अन्य छह तिब्बतियों को सज़ा," ज़िन्हुआ, 31 जनवरी 2013 http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-01/31/c_132142496.htm.; ''आत्मदाह मामले में 6 तिब्बतियों को 12 वर्ष की सज़ा,'', "तिब्बती मानवाधिकार और लोकतंत्र केंद्र, 1 फरवरी 2013 http://www.tchrd.org/2013/02/six-tibetans-sentenced-up-to-12-yrs-over-selfimmolation/.

43 "आत्मदाह विरोधों पर 9 तिब्बतियों पर मुकद्दमा," रेडियो फ्री एशिया, 28 फरवरी 2013 http://www.rfa.org/english/news/tibet/court-02282013202705.html.

की सज़ा सुनाई।[44]

2 मार्च, 2013 को येरशोंग मठ के एक भिक्षु यारफेल, 42 को एक साल तीन मासकी सज़ा सुनाई गई। यारफेल एक आत्म–दाह करने वाले का चाचा है और इस आरोप पर उसे सज़ा दी गयी कि उसने अपने भतीजे की अस्थियां रोंगवो मठ में अपने भतीजे के घर से 2012 में किंगहाई क्षेत्र के तिब्बत स्वायत्त प्रांत के मालहो (चीनीः हुंगनान) की रेबकोंग (चीनीः तोंगरेन) में एक जलूस के दौरान उठायी थीं।

18 अप्रैल, 2013 को किंगहाई प्रदेश के त्सोशार (चीनीःहैदोंग) प्रांत में याज़ी (चीनीःजुन्हुआ) की जन–अदालत ने बेउड़ो (चीनीःवेन्दु) में स्थित बेउड़ो मठ से दो भिक्षुओं, लगभग 27 वर्षीय त्सोन्दुए और लगभग 30 वर्षीय गेदूँ त्सुत्रीम को तीन वर्ष जेल की सज़ा सुनाई। उन पर किंगहाई प्रांत[45] के त्सोशार (चीनीः हैदोंग) प्रांत में याज़ी (चीनीः शुन्हुआ) सालार स्वायत्त प्रांत के कंगत्सा कस्बे में 19 नवम्बर 2012 को आत्म–दाह विरोध से मरने वाले वांगचेन नोरबू के लिए धार्मिक–अनुष्ठान और प्रार्थना–सेवाएं आयोजित करने का आरोप था। दोनों भिक्षुओं को 21 नवम्बर 2012 को गिरफ्तार किया गया था जब वे वांगचेन नोरबू [46] के घर पूजा करने जा रहे थे।

14 मई 2013 को किंगहाई प्रदेश के मालहो (चीनीः हुआँगन) तिब्बती स्वायत्त प्रांत में त्सेखोग (चीनीः जेकोग) प्रांत की जन अदालत ने लेखक और भिक्षु 36 वर्षीय गरत्से जिग्मे को आत्म–दाह विरोधों सहित तिब्बत के मामले पर

---

44 "आत्मदाह 'अपराधों' के लिए चीन द्वारा 3 तिब्बतियों को 15 वर्ष तक की सज़ा" फायूल, 2 मार्च 2013 http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=33116&article=China+sen-%20tences+three+Tibetans+up+to+15+years+for+self-immolation+%E2%80%9Ccrimes-%E2%80%9D.

45 "आत्मदाह करने वालों के लिये प्रार्थना आयोजित करने पर दो भिक्षुओं को तीन वर्ष की सज़ा, "तिब्बती मानवाधिकार और लोकतंत्र केंद्र, 5 जून 2013 http://www.tchrd.org/2013/06/two-monks-sentenced-to-3-yrs-in-prison-for-holding-prayers-for-self-immolator/.

46 "आत्म–दाह करने वाले के लिए प्रार्थना आयोजित करने पर दो भिक्षुओं को तीन वर्ष की सज़ा" तिब्बत के लिए अंतरर्राष्ट्रीय अभियान। https://www.savetibet.org/two-monks-imprisonedfor-three-years-after-prayers-for-a-tibetan-self-immolator/.

पुस्तक लिखने के आरोप में 5 वर्ष कारागार की सज़ा सुनाई।[47]

अक्तूबर 2013 की समाचार रिपोर्ट के अनुसार किंगहाई प्रदेश के हुजहोय (सीलिंग के पास) में चीनी अदालत ने गोलोग पेरमा प्रांत में डुंगड़ा कस्बे के रहने वाले 51 वर्षीय वाशुल दोतटरक को 10 वर्ष कारागार की सज़ा सुनाई। यद्यपि आरोप और सज़ा की तारीख अस्पष्ट है, ऐसा माना जाता है कि उसे 3 दिसम्बर 2012 को लोबसांग गेदुन के आत्म–दाह विरोध में "संलग्नता" के आरोप में हिरासत में लिया गया।[48]

लाबरंग मठ के दो भिक्षु 39 वर्षीय जिनपा ग्यात्सो और 37 वर्षीय केलसांग मोनलम को संगचू प्रांत की एक चीनी अदालत ने 27 मई 2015 कोसां गयेत्सो के आत्म–दाह विरोध में "संलग्नता" के कारण सज़ा सुनाई। दोनों भिक्षुओं को जून 2015 को हिरासत में लिया गया था और आधिकारियों ने उनके माता–पिता तथा रिश्तेदारों को उनके विरुद्ध आरोपों के बारे में कुछ नहीं बताया। जिंपा और केलसांग को संगोत्सो के आत्म–दाह विरोध से सम्बंधित सूचना और फ़ोटो "ऑनलाइन साझा करने के आरोप में सज़ा सुनाई गई।[49]

आत्म–दाह से सम्बंधित तिब्बतियों की गिरफ्तारी, हिरासत, प्रताड़ना और सज़ा का कुल लेखा अधिक विस्तृत नहीं है। संचार शिंकजों और सख्ती के कारण, तिब्बतियों की हिरासत, गिरफ्तारी और सजा की सूचना नहीं होना कोई असामान्य बात नहीं है; तिब्बत के बाहर पहुंची जानकारी तिब्बतियों को गिरफ्तारी और उनके जीवन को खतरे में डाल सकती है।

अंतरराष्ट्रीय अधिकार समूहों ने चीनी अधिकारियों की आत्म–दाह से सम्बंधित तथाकथित मामलों में तिब्बतियों को कड़ी जेल की सज़ा सुनाने

---

47 "तिब्बती लेखक को आत्म–दाह पर किताब लेखने पर पांच वर्ष की सजा सुनाई गई" तिब्बती मानवाधिकार और लोकतंत्र केंद्र, 21 मई 2013, http://tchrd.org/tibetan-writersentenced-to-5-yrs-in-prison-for-writing-book-on-self-immolation/.

48 "तिब्बती को आत्मदाह के समर्थन पर 10 वर्ष की सज़ा," रेडियो फ्री एशिया, 10 अक्तूबर 2013 https://www.rfa.org/english/news/tibet/term-10102013140812.html.

49 "एक गुप्त मुकदमें में आत्मदाह से सम्बंधित दो तिब्बती भिक्षुओं को सज़ा," रेडियो फ्री एशिया, 20 सितंबर 2016 https://www.rfa.org/english/news/tibet/sentenced-09202016135125.html.

की आलोचना की है। चीन के ह्यूमन राइटस वॉच के निदेशक सोफिया रिचर्डसन ने इन सज़ाओं को विश्वसनीयता की कमी कहा है। "चीन की सरकार सम्भवतः यह सोचती है कि किसी को भी सज़ा सुना कर जो आत्म–दाह की बात करता है चीन की सरकार आत्म–दाह को रोक सकती है। पर इन "उकसाने" वाले मामलों पर कार्यवाही करके, सरकार आत्महत्या प्रदर्शनों की त्रासदी बढ़ा रही है।"[50]

आत्म-दाहों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

तिब्बत में आत्म–दाह और इसके लिए तिब्बत में आवाह्न को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, तिब्बत के सक्रिय समुहों, अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार समुहों और एडवोकेसी ग्रुप द्वारा प्रचार किया गया, सभी ने विश्व की सरकारों से चीन की सरकार से बात करने और मामले के समाधान के लिए विभिन्न कूटनीतिक हस्तक्षेप का आग्रह किया।

वर्ष 2012 की चीन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य मानवाधिकार विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें हांगकांग, चीन, मकाऊ और तिब्बत भी सम्मिलित है, में कहा गया है कि तिब्बत में बिगड़ते मानव अधिकारों को चीन की भेदभावपूर्ण प्रथाओं और दमनकारी नीतियों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है जिसमें "घातक बल प्रयोग, शांतिपूर्ण तिब्बती प्रदर्शनकारियों की अंधाधुंध गोलीबारी, इकट्ठे होने पर प्रतिबंध, (और) दलाई लामा पर विश्वास व्यक्त करने वाले तिब्बतियों की मनमानी गिरफ्तारियाँ सम्मिलित हैं।[51] वर्ष 2011 में अत्याचार पर संयुक्त राष्ट्र की समिति ने चीन की नीतियों की निंदा की जो तिब्बती भाषा की क्षति को प्रोत्साहित करती है और धार्मिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करती है। 2008 में महिला अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने तिब्बत में तिब्बती महिलाओं के जबरन गर्भपात और बंध्याकरण की सूचना दी। 2010 में खाद्य पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषदूत ने तिब्बत में "कृषि योग्य भूमि को जब्त करने" और "तिब्बत की चरागाहों से तिब्बती खानाबदोशों के जबरन निष्कासन," जिससे अत्यधिक हानिकारक और अनियंत्रित खनन द्वारा चिह्नित विकास परियोजनाओं के लिए रास्ता प्रशस्त

50 "तिब्बतियों को आत्मदाह "उकसाने" के लिए सज़ा रोकेः चीन," ह्यूमन राइट्स वॅच, 1 फरवरी 2013 https://www.hrw.org/news/2013/02/01/china-stop-sentencing-tibetans-inciting-immolations.

51 "यू एस स्टेट डिपार्टमेंट," चीनः 2012 मानवाधिकार रिपोर्ट,"2013 https://www.state.gov/documents/organization/204405.pdf.2013

हो सके की रिपोर्ट दी।[52]

2 नवंबर 2012 को, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त नवी पिल्ले ने तिब्बती आत्म–दाह पर अपना पहला सार्वजनिक बयान जारी किया, जिसमें चीन सरकार से तिब्बतियों के अधिकारों का सम्मान करने और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और विदेशी मीडिया को तिब्बती क्षेत्रों तक पहुंचने की अनुमति देने का आग्रह किया गया।[53] 1 जून 2013 को जब संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार पर उच्चायुक्त से विशेष तौर से अप्रत्याशित संख्या में आत्म–दाह मामलों के दृष्टिगत तिब्बत के कष्ट पर संयुक्त राष्ट्र की चीन से बातचीत ना होने पर उन्होंने कहा," तिब्बत को अब राजनैतिक समाधान की आवश्यकता है, और तिब्बत के लोगों की पीड़ा को ध्यान में रखना होगा और अब बिना ध्यान दिए और दबा कर नहीं रखी जा सकती। [54] 28 से अधिक राष्ट्रीय सरकारों ने आत्म–दाह पर वक्तव्य दिये हैं।

2009 के बाद से, इस मुद्दे के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की संलग्नता अन्य सरकारों के बयानों की तुलना में सबसे अधिक मुखर और सुसंगत रही है। यू.एस. कांग्रेसी जिम मैकगवर्न की आधिकारिक वेबसाइट ने 13 अगस्त 2012 को मैकगवर्न के स्वयं का और कांग्रेस मैन फ्रैंक आर. वुल्फ का एक वक्तव्य पोस्ट किया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सरकार से तिब्बत के संकट और तिब्बत पर बहु पक्षीय संलग्नताओं की आवश्यकता पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आग्रह किया है।[55] उन्होंने अमेरिकी राज्य विभाग से आग्रह किया कि "तिब्बत में संकट को पलटने के लिए अधिक सुदृढ़ अधिक समन्वित, दृश्यमान, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक कदमों को प्रारम्भ किया जाए।"[56]

52 केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, "संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विशेष दूत ने चीन की बलात पुनर्वास नीति को चुनौती दी," 7 मई 2012 http://tibet.net/2012/03/un-special-rapporteur-challenges-chinas-forced-resettlement-policy-in-tibet/.

53 अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन फॉर तिब्बत," संयुक्त राष्ट्र अधिकार आयुक्त ने तिब्बत पर पहला कड़ा बयान दिया," 2 नवम्बर 2012 https://www.savetibet.org/un-rights-commissioner-makes-strongfirst-statement-on-tibet/.

54 "तिब्बत में तिब्बतियों की शिकायतें दूर करें: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने चीन से कहा" दी तिब्बत पोस्ट इंटरनेशनल, 1 जुलाई 2013 http://www.thetibetpost.com/en/news/internation-%20al/3499-address-grievances-of-.

55 जेम्स पी मैकगवर्न व फ्रैंक आर वुल्फ, अमेरिकन कांग्रेस के सदस्य," लेटर टू हिलेरी क्लिंटन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट,," 13 अगस्त 2012 https://mcgovern.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=396454.

56 वही–

जिनहुआनेट.कॉम के अनुसार, चीन की सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से एकजुटता की कोई अभिव्यक्ति देखी है और तिब्बती अलगाव के लिए "मध्यस्थता" के रूप में चिंता की और चीन के आंतरिक मामलों में "हस्तक्षेप"[57] और नकारात्मक परिणामों की चेतावनी दी है।

निष्कर्ष

तिब्बती, युवा और बूढ़े, खुद को आग लगाने का रास्ता क्यों चुनते हैं, बहुमूल्य जीवन और अपने परिवारों और समुदाय की सुरक्षा के लिए जोखिम और बलिदान क्यों करते हैं?

चीन की सरकार ने परमपावन दलाई लामा तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन पर आत्म–दाह करने का "साजिश" और "उकसाने" का आरोप लगाया है।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष डॉ0 लोबसांग सांगे ने चीनी सरकार की तिब्बत के प्रति दमनकारी नीतियों के लिए तिब्बती आत्म–दाह की उत्पत्ति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आत्मदाह तिब्बती लोगों द्व ारा तिब्बती लोगों के चीन के कब्जे की निंदा व्यक्त करना एक राजनीतिक संदेश के रूप में काम करता है जो तिब्बत में बदलाव और तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है।

धार्मिक दमन, सामाजिक हाशिए पर, अपनी ही भूमि में दूसरी श्रेणी की नागरिकता, गरीबों का शोषण और पर्यावरण, तिब्बती भाषा को कमजोर करने वाली भेदभावपूर्ण नीतियां–ये तिब्बत में चीन के छह–दशक के शासन के मुख्य पहलू हैं। बार–बार, परिणामस्वरूप विफल नीतियां तिब्बती लोगों की वैध आकांक्षाओं के लिए चीन की उपेक्षा को उजागर करती हैं। उनकी नीतियां तिब्बत पर चीन के साम्राज्यवादी हत्यकंड़ों को प्रदर्शित करती हैं और औपनिवेशिक गुरु के रूप में अपना स्थान स्थापित करती हैं।

लेकिन चीन की सरकार के कठोर शासन के बावजूद, तिब्बती लोगों ने शासन का विरोध और अवेहलना की। उन्होंने परमपावन दलाई लामा पर अटुट विश्वास व्यक्त किया है और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रति निष्ठा, जो तिब्बत के भीतर और बाहर तिब्बती लोगों के नैतिक और वैध प्रतिनिधि हैं।

---

57 "चीन द्वारा तिब्बत पर अमेरिका के प्रस्ताव का विरोध," ह्सिन्हुआ नेट, 28 अप्रैल 2018

चीन ने परमपावन दलाई लामा की छवि घूमिल करने और तिब्बती लोगों को उनका अपमान करने के लिए मजबूर करने के लिए कई अभियान चलाए हैं। लेकिन इन प्रयासों ने तिब्बतियों को केवल परम पावन की अनुपस्थिति के साथ तिब्बत में शून्य को महसूस करने और उनकी वापसी के लिए अपनी आकांक्षा व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक स्वयं सेवक ने उन नारों का इस्तेमाल किया है जो परम पावन की वापसी और तिब्बत के अंदर स्वतंत्रता के लिए कहते हैं।

तिब्बत के अंदर तिब्बतियों के लिए, परमपावन उनकी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षक और तिब्बत में स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। उनके प्रति उनकी उदात्त निष्ठा निराधार है। इसके अलावा, चीनी सरकार ने तिब्बतियों को मुख्यधारा की चीनी संस्कृति में आत्मसात करने और तिब्बती भाषा और सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति को कम करने का प्रयास किया है, तिब्बती लोगों का चीनी अधिकारियों के प्रति गहरा अविश्वास है। तिब्बत में चीनी लोगों के बड़े पैमाने पर प्रवासन ने प्रभावी ढंग से तिब्बतियों को अपनी भूमि में अल्पसंख्यक बना दिया है। तिब्बती लोगों को निराश करते हुए लगभग सभी क्षेत्रों में बेदखल और हाशिये पर रखा गया है। शिक्षा के महत्वपूर्ण दायरे में, तिब्बती छात्र निषेधात्मक और भेदभावपूर्ण शुल्क के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से अपर्याप्त सुविधाओं का खामियाजा भुगत रहे हैं।

तिब्बत में चीनी शासन के शिकंजे ने तिब्बतियों को आत्म–दाह जैसे चरम उपायों के लिए मजबूर करता है, ताकि उनकी पहचान और संस्कृति के विनाश की नीतियों और प्रथाओं का विरोध किया जा सके। उसी समय, तिब्बत के पारंपरिक नेता–इसके लामा और चंचल शिक्षक मानव जीवन और पर्यावरण की देखभाल के लिए सरल जीवन और देखभाल का उपदेश देते हैं, जबरदस्त अनिश्चितता और भटकाव के समय में तिब्बती पहचान, एकता और आध्यात्मिकता जुड़ाव की भावना प्रदान करते हैं।

और यह चीनी सरकार की वास्तविक दुविधा हैः यद्यपि यह तिब्बत पर शासन करती है, लेकिन यह तिब्बती लोगों के दिलों और दिमागों को नहीं जीत सकी। आत्म–दाह विरोध यह स्पष्ट संदेश को देते हैं। कई कारणों से चीनी सरकार आत्म–दाह विरोधों को नियंत्रित करना चाहती है। यह पूरी तरह से सेंसरशिप और आत्म–दाह करने वालों के अपराधीकरण को लागू करता है, लेकिन इन विरोधों के लिए सरकार की प्रतिक्रिया की गंभीरता और क्रूरता ने स्थिति को बदतर कर दिया है।

तिब्बत में आत्म–दाह की संख्या कम नहीं हुई है। पिछले नौ वर्षों में तिब्बत को घेरने वाली लाल और पीली लपटों की ज्वलंत छवियों ने दुनिया की आँखों और कानों पर कब्जा कर लिया है।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मानना है कि आत्म–दाह विरोधों को रोकने का एकमात्र तरीका चीनी अधिकारियों के लिए तिब्बत के भीतर तिब्बती लोगों की वास्तविक और वैध शिकायतों का समाधान करना है। तिब्बती लोगों के लिए स्वतंत्रता की मांग, और परमपावन दलाई लामा की यथोचित वापसी की गूंज तिब्बत के प्रत्येक आत्म–दाह करने वाले ने अपने शरीर को जलाते हुए अंतिम सांस तक, जब तक शरीर राख में नहीं हुआ है।

अध्याय दो

तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति

परिचय

वर्ष 1949/50 में जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की टुकड़ियों ने हमला किया था, तब तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य था। चीनी सैन्य के अधिग्रहण का अर्थ एक सम्पूर्ण–प्रभुत्व सम्पन्न राज्य पर हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। आज चीन द्वारा तिब्बत पर कई सौ हजार सैनिकों की मदद से कब्जा कर लिया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और तिब्बती लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

चीनी साम्यवादी सरकार तिब्बत पर "स्वामित्व" के अधिकार का दावा करती है। यह 1949/1950 में अपनी सैनिक विजय या 1959 के राष्ट्रीय जन आंदोलन के बाद से तिब्बत पर उसके कथित नियंत्रण के आधार पर इस अधिकार का दावा नहीं करती है। चीन सरकार 1951 से तिब्बत में लागू "तिब्बत की शांति पूर्वक आज़ादी" के लिए लागू "सतरह सूत्रीय समझौते" को भी "स्वामित्व" के दावे का आधार नहीं मानती। चीन का यह तथाकथित वैधानिक दावा चीन के मंगोल या मांचू शासकों के तिब्बती लामों के साथ ऐतिहासिक सम्बन्धों और कुछ हद तक चीनी शासकों के तिब्बती लोगों के साथ संबंधो पर मूलतः आधारित था। प्राथमिक घटनाएं जिनका चीन सरकार हवाला देती है सदियों पहले मंगोल साम्राज्य के विस्तार के दौरान हुई हैं। उस समय, विशेष रूप से अठारहवीं शताब्दी में, मांचू सम्राटों ने चीन पर शासन किया और पूर्वी यूरोप और तिब्बत सहित पूरे पूर्वी और मध्य एशिया में अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार किया।

यह विवादित नहीं है कि अपने लंबे इतिहास के विभिन्न कालखंडों में, तिब्बत विभिन्न विदेशी शासकोंः मंगोल, नेपाल के गोरखा, चीन के मांचू सम्राट और भारत के ब्रिटिश शासकों के प्रभाव में रहा। शेष समय में तिब्बत के इतिहास में, यह तिब्बत ही था जिसने चीन सहित अपने पड़ोसियों पर शक्ति और प्रभाव का प्रयोग किया। दुनिया के कुछ राज्य अपने इतिहास के किसी भी काल में विदेशी प्रभुत्व या प्रभाव के अधीन नहीं रहे हैं। तिब्बत

के मामले में, विदेशी प्रभाव और हस्तक्षेप की मात्रा और अवधि काफी सीमित है। इसके अलावा, जहां तक राजनीतिक महत्व था, मंगोल, चीनी और मांचू शासकों के साथ उनके संबंध प्रकृति में व्यक्तिगत थे और जो किसी भी समय तिब्बती राज्य का चीनी राज्य के साथ एक संघ या एकीकरण के अर्थ के रूप में नहीं लिए जा सकते।

हालाँकि, तिब्बत का प्राचीन इतिहास कितना भी आकर्षक क्यों न हो, चीनी आक्रमण के समय इसकी स्थिति निश्चित रूप से आधुनिक इतिहास के आधार पर आंकी जानी चाहिए, विशेष रूप से 1911 के बाद चीन से इसके सम्बन्धों को ले कर, जब चीन विदेशी मांचू शासन को हटा कर स्वयं अपने ही देश का स्वामी बन गया था। प्रत्येक देश अपने पड़ोसी राज्यों के साथ प्रादेशिक दावों को सही ठहराने के लिए इतिहास के किसी न किसी दौर में लौट सकता है–लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय कानून और व्यवहार के तहत अस्वीकार्य दावा है।

न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग की तिब्बत पर कानूनी जांच समिति ने तिब्बत की वैधानिक स्थिति पर अपने अध्ययन में प्रतिवेदित किया है:

> *तिब्बत ने 1913 से 1950 तक सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत स्वीकार्य राज्यत्व की स्थितियों को दर्शाया है। वर्ष 1950 में एक व्यक्ति और एक क्षेत्र था, और एक सरकार थी जो उस क्षेत्र में कार्य करती थी, किसी भी बाहरी अधिकारी से मुक्त अपने घरेलू मामलों का संचालन करती थी। 1913 से 1950 तक तिब्बत के विदेशी संबंधों को तिब्बत सरकार द्वारा विशेष रूप से संचालित किया जाता था, और जिन देशों के साथ तिब्बत के विदेशी संबंध थे, उन्हें आधिकारिक दस्तावेजों द्वारा तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में माना था।*[58]

स्वतंत्रता के चालीस साल स्पष्ट रूप से एक देश के लिए अंतराष्ट्रीय समुदाय द्वारा उसे देश के रूप में स्वीकार करने के लिए पर्याप्त अवधि है। आज संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्यों ने इस अवधि के समान, या उससे भी कम समय तक स्वतंत्रता का आनंद लिया है। लेकिन तिब्बत के मामले में, यहां तक कि इसके प्राचीन इतिहास को "स्वामित्व" के अपने दावे का बचाव करने के उद्देश्य से चीन की सरकार ने चुनिंदा रूप से पुनः लिखा है।

---

58 तिब्बत पर कानूनी जाँच कमेटी, न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग, "तिब्बत और चीन लोक गणराज्य" (जिनेवाः इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ ज्यूरिस्ट्स 1960), 5,6.

प्राचीन इतिहास

तिब्बती के पूर्व वृतांतों के अनुसार, तिब्बत के पहले राजा ने 127 ईसा पूर्व से शासन किया था, लेकिन यह सातवीं शताब्दी ईस्वी में ही था कि तिब्बत का सम्राट सोंगत्सेन गैम्पो के शासनकाल में एकीकृत राज्य और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उदभव हुआ। उसके शासन काल में, राजनीतिक और सैनिक वर्चस्व और क्षेत्रीय विस्तार का युग शुरू हुआ जो तीन शताब्दियों तक चला। नेपाल के राजा और चीन के सम्राट ने अपनी बेटियों की शादी तिब्बती सम्राट से की थी, और ये विवाह विशेष महत्व के थे क्योंकि उन्होंने तिब्बत में बौद्धधर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चीनी प्रचार में हमेशा सोंगत्सेन गैम्पो के राज्य को चीन के राजनैतिक हितों के लिए चीन की साम्राज्यवादी राजकुमारी वेन चेंग के साथ संदर्भित करता है, तिब्बती शासक की अन्य रानियों, विशेष रूप से उनकी नेपाली दुल्हन को अनदेखा करके, जिसका प्रभाव उनकी चीनी समकक्ष से अधिक था।

तिब्बती सम्राट त्रिसोंग देतसन (शासनकालः 755–797) ने चीन के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके तिब्बती साम्राज्य का विस्तार किया। 763 में तिब्बत ने तांग चीन की राजधानी, चांगान (वर्तमान जियान) पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, और तांग साम्राज्य को तिब्बत को वार्षिक हर्जाना देना पड़ता था। 783 में, एक संधि हुई जिसके अंतर्गत तिब्बतऔर चीन के बीच की सीमाओं को निर्धारित किया गया; ल्हासा में पोटाला महल के तल पर एक स्तंभ शिलालेख इनमें से कुछ एक विजय–अभियानों का साक्षी है।

ल्हासा के जोखांग में एक स्तम्भ पर उकेरे गए वर्णन के अनुसार 821 में तिब्बत और चीन के बीच एक नई शांति–सन्धि हुई जिसके तहत दोनों देशों के मध्य सीमाएं निर्धारित की गईं। इस महत्वपूर्ण संधि में एशिया की दो महान शक्तियों के मध्य सम्बन्धों का वर्णन मिलता है। विवरण, तीन पत्थर के स्तम्भों पर तिब्बती और चीनी दोनों भाषाओं में अंकित किया गया थाः एक गुंगु मेरु में है। दो राष्ट्रों के बीच की सीमाओं का सीमांकन करता है, दूसरा ल्हासा में जहां यह अभी भी खड़ा है, और चांगआन की साम्राज्यवादी राजधानी तांग में तीसरा है। इसमें लिखा हैः "तिब्बत और चीन उन सीमाओं का पालन करेंगे जो उनके अब कब्जे में हैं। पूर्व का सभी महान चीन का देश है, और पश्चिम में सभी, बिना किसी सवाल के, महान तिब्बत का देश है। अतः दोनों ओर न तो युद्ध होगा और न ही सीमा को जब्त किया

जाएगा।"

चीन इन घटनाओं की व्याख्या यह दिखाने के लिए करता है कि "तिब्बती और चीन ने शाही परिवारों के बीच विवाह के माध्यम से और गठजोड़ के लिए बैठकों से एकता और राजनीतिक दोस्ती को मज़बूत किया और निकटस्थ आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाये जिससे अंततः एकीकृत राष्ट्र की नींव तैयार हुई।" वास्तव में, दोनों चीनी और तिब्बती ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस तरह की व्याख्या का खंडन करते हैं, और इसकी अपेक्षा अलग–अलग शक्तिशाली साम्राज्यों को संदर्भित करते हैं। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष स्वर्गीय नगाबो नगवांग जिग्मे ने अपने 1989 के भाषण में कहाः

> *कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का हिस्सा था, कुछ अन्य लोग दावा करते हैं कि तिब्बती राजा सोंगत्सेन गम्पो के समय से जब उनकी शादी चीनी राजकुमारी से हुई थी यह चीन का हिस्सा बना। मैं इन दोनों विचारों से सहमत नहीं हूं। जब आप पुरातनता के बारे में बात करते हैं, तो कोई समय रेखा नहीं होती है या अगर यह सोंगत्सेन गम्पो के विवाह से ही जोड़ा जाए तो हम सब जाने हैं सोंगत्सेन गम्पो की पहली पत्नी नेपाल की राजकुमारी थी, तो तिब्बत को नेपाल का हिस्सा होना चाहिए। हम इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं?*

वर्ष 2007 में चीन की समीक्षा लिखते हुए शिंघाई में फुंदान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी जियानशियोंग ने लिखा हैः" चीन (जहोंग्गुओ) केवल आधिकारिक तौर पर 1912 में चीन गणराज्य की स्थापना के साथ हमारे देश का नाम बन गया। इससे पहले चीन के विचार (जहोंग्गुओ) की अवधारणा स्पष्ट रूप से नहीं की गयी थी। उन्होंने कहा "टुबो/तुफान (तिब्बती साम्राज्य) तांग राजवंश का एक संप्रभु/स्वतंत्र राज्य था।"

नौवीं शताब्दी के मध्य में, तिब्बती राज्य कई रियासतों में खंडित हो गया। इसने भारत और नेपाल पर ध्यान केंद्रित किया और इन क्षेत्रों के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभावों ने तिब्बत में एक प्रमुख अध्यात्मिक और बौद्धिक पुनर्जागरण लाया।

मंगोल सम्राटों के साथ संबंध (1240–1350)

मंगोल शासक चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों ने एशिया और यूरोप के कई विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जिससे विश्व में अब तक ज्ञात

सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण हुआ, जो प्रशांत से पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था। 1207 में, तिब्बत के उत्तर में स्थित थांगुट साम्राज्य, ने मंगोलों के घुटने टेक दिए, और 1271 में, मंगोलों ने साम्राज्य के पूर्वी भाग पर शासन करने के लिए मंगोल युआन राजवंश की स्थापना की घोषणा की। 1279 में, दक्षिण चीन में चीन की स्यंग राजवंश ने अग्रिम सेनाओं के समक्ष घुटने टेक दिए और मंगोलों ने चीन पर अपनी जीत पूरी की। अब, चीन युआन राजवंश को अपना वंश होने का दावा करता है, और ऐसा करके, वह मंगोलों की पूरी जीत में से कम से कम आधे पूर्वी भाग पर अपना दावा जतलाते हैं।

1240 में चंगेज खान के पोते राजकुमार गोदेन खान ने तिब्बत के लिए एक अभियान भेजा और तिब्बत के वरीयता में प्रमुख धार्मिक गुरुओं में से एक, शाक्य पंडिता कुंगा ग्यालत्सेन (1182–1251) को अपने दरबार में आमंत्रित कर अन्ततः एक स्थायी तिब्बती–मंगोल संबंध स्थापित किया। यहाँ से अद्वितीय चो–योन (पुजारी–संरक्षक) सम्बन्ध प्रारम्भ हुआ। कुबलाई खान, जो गोदेन खान के उत्तराधिकारी बने,ने तिब्बती बौद्धधर्म अपनाया और अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में शाक्य पंडिता के भतीजे दुर्जन चोग्याल फाग्पा को अपनाया।

इस चो–योन संबंध के परिणामस्वरूप कुबलई ने अपने साम्राज्य के राजधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया, और फगपा इसके सर्वोच्च आध्यात्मिक अधिकारी बन गये। कृतज्ञता की अभिव्यक्ति में, 1254 में कुबलाई खान ने अपने तिब्बती लामा को समस्त तिब्बत के राजनीतिक अधिकारी की पेशकश की, और उन्हें विभिन्न सम्मानों से अलंकृत किया।

मंगोलियाई राजकुमार और तिब्बती कुलीन परिवारों और तिब्बती लामाओं के मध्य बाद में शुरुआती चो–योन संबंधों के अतिरिक्त कई अन्य समान रिश्ते थे। मध्य एशिया में एक अद्वितीय संबंध बनाने के अलावा, इसने मांचू सम्राटों और उत्तराधिकारी दलाई लामाओं के बीच बाद के संबंधों को भी आधार बनाया। चो–योन संबंध स्वयं विशुद्ध रूप से पुजारियों के संरक्षक रूप में धार्मिक समर्पण से उत्पन्न एक निजी सम्बन्ध था, और जो संरक्षक की राजनीतिक स्थिति बदल जाने के बावजूद भी ज़ारी रहता था। मंगोल–तिब्बत संबंधों में यह स्पष्ट था, जो युआन राजवंश के पतन के बाद भी जारी रहा।

चो–योन संबंधों का एक अनिवार्य तत्व संरक्षण था, उनकी निष्ठा नहीं, जो संरक्षक ने अपने धार्मिक शिक्षण के बदले में लामा को प्रदान किया था। हालांकि, कुछ चो–योन संबंधों ने महत्वपूर्ण राजनीतिक आयाम हासिल किए, जहां संरक्षक को लामा और उनके शिक्षण या चर्च की रक्षा के लिए सैन्य सहायता प्रदान करने की उम्मीद थी। संरक्षक की श्रेष्ठता लागू नहीं की जाती थी, क्योंकि अबोध संरक्षक भी लामा के छात्र और उपासक थे।

जिस समय बौद्ध धर्म मंगोल साम्राज्य के पूर्वी भाग में राजकीय धर्म और शाक्या लामा (फगपा) उच्चतम आध्यात्मिक अधिकारी बन गया, उस समय पारस्परिक–निर्भरता के संदर्भ में मंगोल–तिब्बती संबंध अच्छी तरह से उल्लेखित किया गया है। इस अवधारणा ने समानता और अन्योन्याश्रय के आधार पर विश्व सम्राट और आध्यात्मिक नेता के दोहरे राजनीतिक और धार्मिक वर्चस्व को परिभाषित किया। जबकि आध्यात्मिक नेता, सत्तारूढ़ तिब्बत में संरक्षण और समर्थन के लिए सम्राट पर निर्भर थे, सम्राट ने लामा पर निर्भर होकर मंगोल साम्राज्य के अपने शासन को वैधता प्रदान की।

यह नकारा नहीं जा सकता कि मंगोल के राजाओं ने तिब्बत पर अपना प्रभाव फैलाया लेकिन किसी भी मंगोल शासक ने तिब्बत पर सीधे शासन करने का कोई प्रयास नहीं किया। तिब्बत ने मंगोल साम्राज्य को कर का भुगतान नहीं किया था, और निश्चित रूप से इसे मंगोल सम्राटों द्वारा कभी भी चीन का हिस्सा नहीं माना गया था।

1350 में तिब्बतियों ने मंगोलों के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को तोड़ दिया जब तिब्बती राजा चांगचूब ग्यालत्सेन, (1350–1364से शासन) ने तिब्बत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में शाक्य लामाओं की जगह ली। चंगचूब ग्यालत्सेन ने तिब्बती प्रशासन प्रणाली में मंगोल प्रभाव को दूर किया और एक नया और विशिष्ट रूप से तिब्बती प्रशासन प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने राज्य में न्याय के प्रशासन के लिए (त्रिमयीग शेल्छेह चोंगा, 15–अनुच्छेद संहिता) नई कानून सहिंता भी बनाई। चीन ने मंगोल शासकों से पुनः अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली थी और 18 वर्ष बाद मिंग राजवंश की स्थापना की।

मिंग सम्राटों के साथ संबंध (1368-1644)

मंगोल खानों या सम्राटों और तिब्बती लामाओं के बीच संबंध चीन पर मंगोल

विजय से पहले के हैं। इसी प्रकार, चीन से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने से पहले तिब्बत ने मंगोल सम्राटों से नाता तोड़ लिया। चीन के मिंग सम्राटों को विरासत में मंगोलों से कोई संबंध नहीं मिला। फिर भी मोंगोल के खानों ने तिब्बतियों के साथ गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तें प्रायः चो–योन रिश्तों के रूप में, बनाए रखे।

तिब्बत और मिंग चीन के बीच संपर्क अरुचिकर थे और काफी हद तक विभिन्न, कभी–कभी प्रतिद्वंद्वी मठों के व्यक्तिगत लामाओं द्वारा चीन के दौरे और चीनी सम्राट द्वारा उन्हें सम्मानजनक शाही पदवियां या उपहार देने तक सीमित थे। ये दौरे तिब्बत के पंद्रहवीं से सत्रहवीं सदी के इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन तिब्बत या इसके शासकों की चीन या मिंग राजाओं से राजनीतिक अधीनता का कोई सबूत नहीं है।

इंडियाना यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूरेशियन स्ट्डीज के प्रोफेसर स्वर्गीय इलियट स्पर्लिंग ने बताया है, "इन उपाधियों की प्रस्तुति के इर्द–गिर्द होने वाली घटनाओं के परीक्षण से स्पष्टता दृष्टव्य है कि प्राप्तकर्ता तिब्बत में यह उपाधियां प्राप्त करने से पूर्व सत्तासीन थे या काफी प्रभाव रखते थे। इस प्रकार, इन उपाधियों ने शक्ति ही प्रदान नहीं की, बल्कि इसे स्वीकार किया, और उनके प्रदान करने को सम्मान, उपाधियों, या पुरस्कारों की एक असामान्य प्रस्तुति के रूप में एक देश से दूसरे देश के नागरिकों के लिए नहीं देखा जाना चाहिए।"[59]

1350 से, तिब्बत पर फागमद्रु राजकुमारों ने राज किया और फिर 1481 तक, रिम्पुंग राजवंश का शासन था। 1406 में, सत्तारूढ़ फागमद्रु राजकुमार, दाकपा ग्यालत्सेन ने चीन के दौरे का शाही निमंत्रण ठुकरा दिया था। इससे उस समय तिब्बती शासकों के प्रभुत्व का स्पष्ट पता चलता है। लगभग 1565 से लेकर 1642 में पाँचवें दलाई लामा के सत्ता में आने तक (मिंग राजवंश के पतन से दो साल पहले), त्सांग के राजाओं ने तिब्बत पर शासन किया। इनमें से कुछ शासकों और मिंग सम्राटों के बीच अरुचिकर कूटनीतिक सम्बम्धों के संकेत है लेकिन मिंग सम्राटों ने न तो अधिकार का प्रयोग किया और न ही उन पर प्रभाव डाला।

1644 में, मिंग राजवंश को विदेशी विजेताओं द्वारा उखाड़ फेंका गया था।

---

59 ऐनी–मैरी ब्लोंड्यू और काटिया बफेट्रिल, इडीएस, ऑथेंटिकिंग तिब्बतः चाइना के 100 सवालों के जवाब, (बर्कलेः कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, प्रेस, 2008)।

मंचू अपने स्वयं के शाही राजवंश की स्थापना करने में सफल रहे, जिसने एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया, जिसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चीन था। उन्होंने इसे ख्यिंग राजवंश कहा।

मंचुओं के साथ संबंध (1639–1911)

1642 में, महान पांचवें दलाई लामा, अपने मंगोल संरक्षक गुशरी खान की मदद से, एकीकृत तिब्बत के सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक शासक बन गए। तब से, तिब्बती उन्हें अपना सर्वोच्च संप्रभुता गोंगसा छेन्पो मानते थे, और उनके सम्मान को तिब्बत की सीमाओं के बाहर भी स्वीकारा जाता था। पांचवें दलाईलामा ने न केवल मंगोलों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा, बल्कि मांचू शासकों के साथ भी अंतरंग संबंध विकसित किए।

1639 में, दलाई लामा ने सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली थी और चीन की मांचू विजय और किंग राजवंश की स्थापना से पहले, मांचू सम्राट ताई तुंग ने दलाई लामा को अपनी राजधानी, मुकदेन (वर्तमान शेनयांग) में आमंत्रित किया था। निजी रूप से निमंत्रण स्वीकार करने में असमर्थ, दलाई लामा ने अपने दूत को भेजा, जिसे सम्राट द्वारा बहुत सम्मान प्रदान किया गया था। इस प्रकार दलाई लामा और मंचू शासकों के बीच चो–योन संबंध स्थापित हुआ।

जैसा कि मंगोल सम्राटों के साथ तिब्बती संबंध के बारे में सच था, तिब्बतियों और मांचू सम्राटों के बीच विकसित सम्बन्धों में चीन शामिल नहीं था। जैसा कि ओवेन लटिमोर किंग राजवंश के संदर्भ में बताते हैं, "वास्तव में जो अस्तित्व में था वह मांचू साम्राज्य था, जिसका चीन केवल एक हिस्सा था।"[60]

चीन पर विजय प्राप्त करने और इसे मांचू साम्राज्य के साथ जोड़ने के बाद, सम्राट शुनजी ने 1653 में पांचवें दलाई लामा को शाही राजधानी की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया। सम्मान के एक अप्रत्याशित संकेत में, मांचू सम्राट ने तिब्बती सम्प्रभुता और मध्य एशियाई बौद्धों के अग्रणी आध्यात्मिक नेता के स्वागत के लिए अपनी राजधानी (पीकिंग) से बाहर चार दिवसीय यात्रा की। दलाई लामा की यात्रा पर टिप्पणी करते

60 ओवेन लट्टीमोर, स्टडीज इन फ्रंटियर हिस्ट्री कलेक्टेड पेपर्स 1928–1958 (ऑक्सफोर्डः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1962)।

हुए, चीन में एक अमेरिकी विद्वान और राजनयिक, डब्ल्यू रॉकहिल ने लिखा हैः (दलाई लामा) का सभी रीतियों से स्वागत किया गया जिसे किसी भी स्वतंत्र सम्प्रभुता को प्रदान किया जा सकता था, और चीनी कार्यों में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे यह पता चले कि किसी अन्य दृष्टि से इसे देखा गया था; तिब्बत के साथ चीन के संबंधों की इस अवधि में, लामा की लौकिक शक्ति, गुशरी खान द्वारा समर्थित थी और सभी मंगोलिया की भक्ति पर, चीन के सम्राट के द्वारा प्रश्न उठाने की कोई बात नहीं थी।"[61]

इस अवसर पर, पांचवें दलाई लामा और मांचू सम्राट ने एक दूसरे को अभूतपूर्व उच्च मानार्थ खिताब दिए, और चो–येन रिश्ते की फिर से पुष्टि की गई। किंग राजवंश के दौरान, तिब्बत और मांचू सम्राटों के बीच संबंधों की पुनः पुष्टि हुई। किंग राजवंश के दौरान, तिब्बत और मांचू सम्राटों के बीच संबंध औपचारिक रूप से चो–योन संबंधों पर आधारित रहे। मांचू सम्राट ने आक्रमणकारी दज़ुंगर मंगोलों को खदेड़ने और 1720 में तिब्बती राजधानी में नए खोजे गए सातवें दलाई लामा को लाने के लिए अपील का तत्परता से जवाब दिया।

मांचू सेना ने अठारहवीं शताब्दी में तीन अन्य अवसरों पर तिब्बत में प्रवेश कियाः एक बार नेपाल (1792) से गोरखा बलों पर आक्रमण करने के खिलाफ तिब्बत की रक्षा करने के लिए, और दो बार गृह युद्धों (1728–1751) के बाद आदेश को बहाल करने के लिए। हर बार वे तिब्बतियों के अनुरोध पर आए, हर बार चो–योन सम्बन्धों को लागू किया। हालांकि इस संकट के समय में मांचू तिब्बत में कुछ हद तक प्रभाव स्थापित करने में सफल रहे, लेकिन उनके प्रभाव में तेजी से गिरावट आई, जिससे उन्हें कोई भी भूमिका निभाने में असमर्थता हुई जब तिब्बत ने जम्मू (1841–1842), नेपाल (1855–56) और ब्रिटिश भारत (1903–1904) आक्रमणकारियों के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ा। मध्य–उन्नीसवीं शताब्दी तक, मांचू सम्राट की भूमिका (और अम्बन की संबंधित भूमिका) केवल नाममात्र की थी।

आज तक, चीन ने सम्राट कियानलॉन्ग के तथाकथित उन्नतीस सूत्रीय अध्यादेश या तिब्बत से सम्बंधित 1793 के नियमों पर, और राजदूतों की नियुक्तियों पर काफी ध्यान देता था, जैसे कि ये "नियम" एक शाही आदेश

61 रोकहील डब्लू. डब्लू. "ल्हासा की दलाई लामा और चीन के मांचू सम्राटों के साथ उनके संबंध। 1644–1908," टोंग पाओ सेकेंड सीरीज 11, संख्या 1(1910): 1–104, 37, http://www.jstor.org/stable/4526129.

हों तिब्बत में मांचू के व्यापक अधिकारों को सिद्द करता हो। वास्तव में, उन्नतीस सूत्र सम्राट द्वारा नेपाल के साथ अपने युद्ध के बाद तिब्बत की सरकार को विचार करने के लिए दिए गए सुझाव थे। दूत वाइसराय या प्रशासक नहीं थे, लेकिन अनिवार्य रूप से मांचू के हितों की देखभाल करने और सम्राट की ओर से दलाई लामा की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे।

1792 में, तिब्बत और नेपाल के बीच विवाद के बाद, नेपाल के गोरखाओं ने तिब्बत पर आक्रमण किया और दलाई लामा ने मांचू से मदद की अपील की। सम्राट ने एक बड़ी सेना भेजी जिसने तिब्बत से गोरखाओं को बाहर निकालने में मदद की, और फिर तिब्बत और नेपाल के बीच शांति संधि की मध्यस्थता की। चूंकि यह चौथी बार था जब बादशाह को तिब्बती सरकार की ओर से लड़ने के लिए सैनिकों को भेजने के लिए कहा गया था, वह तिब्बती मामलों में कुछ दखल चाहता था ताकि तिब्बतियों को संघर्षों में शामिल होने से रोका जा सके जो पुनःमांचू अदालत की सैन्य भागीदारी के लिए अनुरोधों को तेज़ कर सकता है।

"नियम" एक शासक द्वारा उसकी प्रजा को आदेश के बजाय, सम्राट की रक्षक भूमिका के संदर्भ में दिए गए सुझाव थे। यह मांचू सेना के शाही दूत और कमांडर जनरल फू कंग–ए से आठवें दलाई लामा के लिए दिए गए बयान से स्पष्ट रूप से उभरता हैः

> *सम्राट ने मुझे व्यापक निर्देश दिए, महान योद्धा ने सभी बिंदुओं पर एक–एक करके चर्चा की, और विस्तृत निर्देश जारी किए। यह सम्राट की इस चिंता को प्रदर्शित करता है कि तिब्बतियों को कोई नुकसान नहीं हो और उनका कल्याण सदा के लिए सुनिश्चित हो जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दलाई लामा, सम्राट के प्रति अपने आभार को स्वीकार करते हुए विस्तृत चर्चा के बाद सहमति के पश्चात स्वीकार करेंगे। हालांकि अगर तिब्बती अपनी सदियों पुरानी आदतों को अपनाने पर जोर देते हैं, तो बादशाह सैनिक टुकड़ियों को खदेड़ने के बाद अम्बानों और गैरिसन को वापस ले लेंगे। फिर भी अगर भविष्य में इसी तरह की घटनाएं होती हैं, तो सम्राट का उनसे कोई लेना–देना नहीं होगा। इसलिए तिब्बती अपने लिए यह तय कर सकते हैं कि उनके पक्ष में क्या है और क्या नहीं है या क्या गम्भीर है और क्या सुगम है, और वे स्वयं इसका चयन करें।*[62]

सम्राट के सभी सुझावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के बजाय, तिब्बतियों ने उन उन्नतीस बिंदुओं को अपनाया जो उनके लिए लाभकारी

62 या हानजांगः दलाई लामा की जीवनी, भोड़ की लो ग्युस राग रीम्स जू यी फेंगबा 2, (1991): 316 (ल्हासाः तिब्बत का सामाजिक विज्ञान संस्थान, 1991).

माने जाते थे और उन विचारों की अवेहलना की जो प्रतिकूल थे। नौवें पंचम लामा के रूपमें, थुबतेन चोकेई न्यिमा ने कहा था, "जहां चीनी नीति उनके अपने विचारों के अनुरूप थी, तिब्बती लोग अम्बान की सलाह को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन ... अगर यह सलाह उनके राष्ट्रीय पूर्वाग्रहों के संबंध में किसी भी तरह से विरोध करती, तो चीनी सम्राट स्वयं भी उन्हें प्रभावित करने के लिए शक्तिहीन होंगे।"[63]

इस उन्नतीस सूत्रीय अध्यादेश के महत्वपूर्ण सुझावों में दलाई लामा और पंचेन लामा सहित महान अवतार लामाओं के चयन के लिए सम्राट का प्रस्ताव था, जिसमें एक स्वर्ण कलश से नाम निकालना भी सम्मिलित था। हालांकि, यह महत्वपूर्ण कार्य तिब्बती सरकार और उच्च लामाओं की जिम्मेदारी बन गया, जो धार्मिक परंपराओं के अनुसार पुनर्जन्म का चयन करते रहे। इसकी शुरूआत के बाद, स्वर्णकलश का उपयोग कभी–कभी चयन के एक भाग के रूप में किया जाता था, जैसे कि 11वें दलाई लामा के साथ, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता था, जैसे कि 9 वें दलाईलामा के समय। पारंपरिक तरीकों से अभी भी प्रक्रिया चलाई जाती है।

इस "अध्यादेश "का एक और महत्वपूर्ण बिंदु दूतों की भूमिका थी। कई बार, यह एक राजदूत की तरह दिखता था, और कई बार एक अति उत्कृष्ट रक्षात्मक संबंधों के रूप में। इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या 1903 में अंबुद यू ताई द्वारा भारत सरकार के विदेश सचिव, मोरटीमेर डुरंड को दी गयी थी (जैसा कि उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है): "वह केवल ल्हासा में एक अतिथि थे–एक मास्टर नहीं–और वह वास्तविक स्वामी को अलग नहीं रख सकते थे, और क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कोई शक्ति नहीं थी।"[64]

इसी तरह, उन्नीसवीं सदी के मध्य में दो ज़ारिस्ट मिशनरियों, ह्यूक औरगैबेट, जो ल्हासा में थे, ने इन दूतों की स्थिति इस प्रकार से वर्णित की है : "तिब्बत की सरकार पोप के समान है और चीनी राजदूत की स्थिति वैसी ही है जैसे रोम में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत की।"[65]

---

63 कैप्टन ओ कोनोर की डायरीः सितंबर 4, 1903।

64 सर पर्सी सयक्स, सर मोर्टिमर डुरंडः ए बायोग्राफी (लंदनः कासेल एंड कंपनी, 1926) 166.

65 हूक पी, डेकोवेरते दू तिबेट, 1845–1845– लेस बोनस लेकचर (ली–लीवरीःफलेमैरोन, 1933), 50

"चीनी राजदूतों" का संदर्भ एक सामान्य मिथ्या नाम है, क्योंकि मंचू सम्राट केवल चीनी दूतों को नियुक्त करने के लिएही सावधानी नही बरतते थे बल्कि मंगोलियाई और मंचुओं की नियुक्ति में भी सतर्क रहते थे ,यह तथ्य इस बात पर बल देता था कि अम्बन की नियुक्ति चो–योन संबंधों में संरक्षक की भूमिका का विस्तार थी, एक ऐसा संबंध जिससे चीनियों को बाहर रखा गया था।

1908 में मांचू सैनिकों द्वारा तिब्बत पर अप्रत्याशित आक्रमण से तिब्बत और मांचू सम्राट के मध्य संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। पिछला शाही सैनिक अभियान दलाई लामा या तिब्बती सरकार की सहायता के लिए उनके निमंत्रण पर आया था। लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर तिब्बत में ब्रिटिश प्रभाव को हटाने के लिए, मांचू सम्राट ने तिब्बत में अपने अधिकार को बलपूर्वक स्थापित करने का प्रयास किया। दो साल बाद, तेरहवें दलाई लामा पड़ोसी देश भारत भाग गए। हालाँकि, तिब्बत पर कब्ज़ा अल्पकालिक था। 1910 में जब मांचू सम्राट ने दलाई लामा को "पदच्युत" करने की कोशिश की, तो दलाई लामा ने छो–योन संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की। संरक्षक ने अपने लामा पर हमला किया था और इस तरह उनके रिश्ते की नींव का उल्लंघन किया।

आक्रमण का प्रतिरोध तब सफल हुआ जब 1912 में मांचू सम्राट का पतन हो गया और तिब्बतियों ने कब्जा करने वाली सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। उन गर्मियों में, तिब्बत और चीन के बीच नेपाल की मध्यस्थता से "तीन सूत्रीय समझौते" के समापन के परिणाम स्वरूप औपचारिक आत्मसमर्पण हुआ और सभी शेष बचे शाही सैनिकों का निष्कासन हुआ। 14 फ़रवरी 1913 को ल्हासा लौटने के बाद, तेरहवें दलाईलामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की पुष्टि करते हुए एक घोषणा जारी की।

चीन गणराज्य के साथ संबंध (1912–1949)

इस अवधि के दौरान चीन की स्थिति अस्पष्ट थी। एक ओर, राष्ट्रवादी सरकार ने अपने संविधान में और अन्य देशों से पत्र व्यवहार में एकतरफा घोषणा की कि तिब्बत चीन गणराज्य का एक प्रांत था (गणतंत्र की "पाँच जातियों में से एक")। दूसरी ओर, तिब्बत सरकार के साथ पत्र–व्यवहार में उन्होंने यह माना कि तिब्बत चीन गणराज्य का हिस्सा नहीं थाः चीन के

राष्ट्रपति ने दलाई लामा और तिब्बती सरकार को बार–बार पत्र और दूतों को भेजा और तिब्बत सरकार को चीन गणराज्य में "शामिल" होने के लिए कहा। इसी प्रकार के संदेश चीन ने नेपाल सरकार को भेजे थे। तिब्बत और नेपाल दोनों ने लगातार चीन में शामिल होने से इनकार कर दिया।

चीनी राष्ट्रपति युआन शिकाई से प्राप्त पहले पत्र के जवाब में, तेरहवें दलाई लामा ने शिष्टता से समझाते हुए गणतंत्र में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि तिब्बतियों ने अतीत के अन्याय के कारण चीनी सरकार का "अनुमोदन नहीं किया" और कहाः

> *गणतंत्र केवल अभी घोषित किया गया है और राष्ट्रीय नींव मजबूत नहीं हुई है। यह अभी राष्ट्रपति को आदेश के अनुरक्षण के लिए अपनी शक्ति इस्तेमाल करने के योग्य बनाता है। जहां तक तिब्बत का प्रश्न है, तिब्बती अपने अस्तित्व को बरकरार रखने में काफी सक्षम हैं और राष्ट्रपति को इसके लिए खुद को दूर–दूर तक चिंतित करने या विचलित होने की जरूरत नहीं है।*[66]

तिब्बत की स्वतंत्रता और सीमा–क्षेत्रों पर तिब्बत चीन से वापस होना चाहता था, दलाई लामा ने कहाः "अब तक प्रदान किए गए पुजारी–संरक्षक संबंध के तहत, तिब्बत ने व्यापक स्वतंत्रता का आनंद लिया है। हम इसे संरक्षित करने की इच्छा रखते हैं। हमें लगता है कि यदि सीमाएं जो हमने बाहरी लोगों से खो दी हैं यदि वापिस कर दी जाएँ तो दीर्घकालीन स्थायित्व वापिस आ सकता है।"[67]

तिब्बत में चीनी दूतों, जैसे कि जनरल हुआंग मुसुंग (1934) और वू झोंगक्सिन (1940) को भी तिब्बती सरकार द्वारा कोई अनिश्चित शब्दों में नहीं बताया गया था कि तिब्बत स्वतंत्र था, और स्वतंत्र रहने की कामना करता था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि तेरहवें दलाई लामा की 1933 में मृत्यु के बाद रीजेंट के रूप में रेतिंग रिनपोछे की नियुक्ति में चीन की सरकार और न ही उसके "विशेष दूत" (हुआंग मुसुंग) की कोई भूमिका थी। यद्यपि वह 1911 के बाद तिब्बत में सरकारी अधिकारी के रूप में प्रवेश करने वाला पहला चीनी अधिकारी था जिसे तिब्बत में प्रवेश की अनुमति दी गयी थी, तिब्बतियों ने उसे अनुमति देने से मना नहीं किया क्योंकि वह स्वर्गीय दलाई लामा को धार्मिक श्रद्धांजलि देने आ रहा था–यह ऐसा कृत्य

66 गुओमिन गोंगबाओ, 6 जनवरी 1913

67 तेहरवें दलाई लामा के पत्र व्यवहार का रिकार्ड, दिनांक तिब्बती चौथे महीने का पन्द्रहवा दिन आयरन हॉर्स ईयर, 1930।

था जिसे तिब्बती शायद ही किसी को अनुमति देने से मना कर सकें। हालांकि अप्रैल 1934 में रेतिंग रिनपोछे रीजेंट बनने के तीन महीने बाद हुआंग मुसुंग ल्हासा पहुंचे।

चीन का दावा है कि तिब्बती सरकार के अधिकारियों को चीन के नेशनल असेंबली सत्र में 1931 और 1946 में नानजिंग, चीन में भाग लेने के लिए भेजा गया था। वास्तव में, 1931 में, खेंपो कुंचुक जुंगनी को दलाई लामा ने नानजिंग, चीन में एक अस्थायी सम्पर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए और चीन सरकार से सम्पर्क स्थापित करने के लिए नियुक्त किया था। इसी तरह, 1946 में दूसरे विश्व युद्ध में मित्र देशों की जीत पर ब्रिटेन, अमेरिका और चीन को बधाई देने के लिए एक तिब्बती मिशन को दिल्ली और नानजिंग भेजा गया था। चीनी राष्ट्रीय असेंबली में भाग लेने के लिए उनके पास कोई निर्देश या अधिकार नहीं था। 29 अगस्त 1959 को इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट लीगल इंक्वायरी कमेटी के अंतर्राष्ट्रीय आयोग से इस विषय में बात करते हुए, चौदहवें दलाई लामा ने कहा, "उनका (नानजिंग में तिब्बती प्रतिनिधि) असेंबली में कोई आधिकारिक भागीदारी नहीं थी। जब यह दुष्प्रचार हमारी सरकार के संज्ञान में आया, तब तार द्वारा उन्हें भाग नहीं लेने के निर्देश दिए गए थे।"

1911 और 1952 के बीच तिब्बत की स्वतंत्रता की स्थिति ल्हासा में चीनी मिशन के अंतिम प्रमुख, शेन सुन्निलन द्वारा प्रमाणित की गई थी। 1948 में देश छोड़ने के बाद, उन्होंने लिखा, "1911 से ल्हासा (अर्थात ल्हासा में तिब्बत की सरकार) को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है।"[68]

ब्रिटिश भारत के साथ संबंध (1857-1947)

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में, ब्रिटेन ने तिब्बत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने में गहरी रुचि दिखलाई। सभी हिमालयी राज्यों को ल्हासा से निकटता से जोड़ा गया था, और चूंकि वे सभी धीरे–धीरे संधियों और अन्य समझौतों के द्वारा ब्रिटिश भारत से बंधे हुए थे, तिब्बत को डर था कि अगर यह तिब्बत तक पहुंच हासिल करने के लिए ब्रिटिश के प्रयासों का विरोध नहीं करता तो यह अपनी स्वतंत्रता भी खो देगा। तेरहवें दलाई

68 त्सुंग–लियन शेन और शेन–छी लियू, तिब्बत और तिब्बती (स्टैनफोर्ड, कैलीफॉर्नियाः स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1973) 62

लामा ने तिब्बत को स्वतंत्रता के पथ पर अग्रसर किया। इस नीति ने अंग्रेजों को निराश किया, जिन्होंने इस बात से ज्यादा आशंका जताई कि तिब्बत में रूसी घुसपैठ से मध्य एशिया में शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तिब्बत के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में असमर्थ, ब्रिटेन ने तिब्बत को सहयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए मांचू अदालत का दरवाजा खटखटाया। 'तिब्बत के संरक्षण या ज्ञान के बिना, इसने ब्रिटेन और चीन के बीच दो संधियों (1890 और 1893) को जन्म दिया, जिसमें तिब्बत के संबंध में प्रावधान शामिल थे। तिब्बती सरकार ने इन संधियों को अत्यधिक अधीनता के रूप में खारिज कर दिया, और इस पर 1903 में तिब्बत पर ब्रिटिश ने आक्रमण कर दिया। मांचू सम्राट तब तिब्बत की सहायता के लिए नहीं आया था और जैसा कि अम्बान यू ताई ने कहा था, कि तिब्बतियों की किसी भी कार्रवाई की जिम्मेवारी से खुद को अलग कर लिया था स एक वर्ष के भीतर, तिब्बत सरकार के साथ, ल्हासा सम्मेलन के समापन के बाद, एक द्विपक्षीय संधि के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने ल्हासा छोड़ दिया।

ल्हासा कन्वेंशन के प्रावधानों में आंतरिक और बाह्य मामलों में तिब्बत की अप्रतिबंधित संप्रभुता को पहले से माना गया है अन्यथा तिब्बत वैध रूप से ब्रिटेन को संधि में निर्दिष्ट शक्तियों को हस्तांतरित नहीं कर सकता था। ल्हासा सम्मेलन ने मांचू सम्राटों और तिब्बत के बीच किसी विशेष संबंध के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। इस सम्मेलन के समापन ने ब्रिटेन द्वारा तिब्बत को एक राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करने का कार्य किया, ताकि किसी भी बाहरी शक्ति से परामर्श करने की आवश्यकता के बिना अपनी ओर से संधियों को लागू करने में सक्षम हो सके।

चीन को सहयोग देने के लिए राजी करने के प्रयास में, ब्रिटेन ने चीनी नेताओं को 1906 में एक बार फिर तिब्बती अधिकारियों की भागीदारी या ज्ञान के बिना आसंजन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया। यह समझौता, और ब्रिटेन और रूस के बीच 1907 में संपन्न हुआ समझौता, तिब्बत में ब्रिटिश प्रभाव के एक क्षेत्र की मौजूदगी की पुष्टि करता है और तिब्बत पर चीनी "आधिपत्य" की अवधारणा को प्रस्तुत करता है–एक अवधारणा जो न ही तिब्बत और न ही मांचू अदालत द्वारा स्वीकार की गई थी।

1908 में, तिब्बत पर मांचू सेना के छोटे आक्रमण के दौरान, ब्रिटेन ने

फिर से मांचू के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि ने तिब्बत के साथ व्यापार की बात की लेकिन फिर से, इसमें स्वतंत्र तिब्बत की कोई भागीदारी नहीं थी।

भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने आधिपत्य पर ब्रिटिश अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहाः "तिब्बत पर चीन का अधिपत्य एक संवैधानिक परिकल्पना है एक राजनीतिक स्नेह जो केवल दोनों पक्षों को अपनी सुविधा के कारण बनाए रखा गया है .... वास्तव में ल्हासा में दो चीनी (यानी मांचू) दूत वाइसराय के रूप में नहीं, बल्कि राजदूतों के रूप में हैं।[69]

कूटनीतिक गतिविधि और सैन्य खतरे

1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उसने ल्हासा में ब्रिटिश राजनयिक मिशन पर कब्जा कर लिया और तिब्बत के साथ ब्रिटेन के संधि संबंधों को विरासत में प्राप्त किया। तिब्बत की मान्यता को भारत सरकार द्वारा तिब्बती विदेश कार्यालय कोभेजे गए आधिकारिक पत्र व्यवहार से स्पष्ट थाः

> *भारत सरकार को यह आश्वासन देते हुए खुशी होगी कि तिब्बती सरकार की यह मंशा है कि मौजूदा आधार पर संबंधों को तब तक जारी रखा जाए, जब तक कि दोनों में से कोई भी पक्ष मामलों पर नई व्यवस्था नहीं कर लेता। यह प्रक्रिया सभी अन्य देशों द्वारा अपनाई गई है। जिनके साथ भारत को संधि के संबंध विरासत में महामहिम की सरकार से मिले हैं।"*[70]

राष्ट्रवादी चीनियों पर साम्यवादियों की जीत के बाद और 1 अक्तूबर,1949 को पीआरसी की स्थापना के बाद, रेडियो बीजिंग ने यह घोषणा करनी प्रारम्भ कर दी कि "लोगों की मुक्ति सेना को तिब्बत, शिनजियांग, हसन और ताइवान सहित सभी चीनी क्षेत्रों को मुक्त करना होगा।" आंशिक रूप से इस खतरे के जवाब में, और चीन के साथ लंबे समय से चल रहे सीमा विवादों को हल करने के लिए, नवंबर 2, 1949 को, तिब्बती सरकार के विदेशी कार्यालय ने माओ त्से तुंग को सभी क्षेत्रीय विवादों को निपटाने के लिए बातचीत के प्रस्ताव के विषय में लिखा। पत्र की प्रतियां भारत, ग्रेट ब्रिटेन, और संयुक्त राज्य अमेरिका के भेजी गयी थीं। हालाँकि इन तीनों

---

69 एकांउड्स एंड पेपर्स, सीडी, 1920 (1904) {तिब्बत से संबंधित कागजात, नंबर 66}

70 भारत–विदेश मंत्रालय, नोट्स, ज्ञापन और पत्र का आदान–प्रदान और समझौते भारत सरकार और चीन के बीच हस्ताक्षीतः श्वेत पत्र (नई दिल्लीः विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, 1959), 39.

सरकारों ने साम्यवाद के प्रसार को दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरा माना, लेकिन उन्होंने तिब्बती सरकार को चीन सरकार के साथ सीधी बातचीत करने की सलाह दी क्योंकि कोई भी अन्य कार्रवाई सैन्य प्रतिशोध को भड़काने वाली हो सकती है।

तिब्बती सरकार ने तीसरे वरिष्ठ देश, संभवतः यूएसएसआर, सिंगापुर के हांगकांग में पीआरसी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों, त्सेपोन शाकबपा और त्सेचंग थूबतेन ग्यालपो को भेजने का निर्णय लिया।

इन अधिकारियों ने चीनी सरकार के साथ चेयरमैन माओ ज़ेडॉन्ग को तिब्बती विदेश कार्यालय के पत्र की सामग्री और चीनी रेडियो "तिब्बत की मुक्ति" निकटस्थ घोषणाओं की धमकी के मामले उठाने थे। उन्होंने एक आश्वासन प्राप्त करना था कि तिब्बत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और तिब्बत किसी भी तरह के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा।

जब तिब्बती प्रतिनिधियों ने दिल्ली में हांगकांग के लिए वीजा हेतु आवेदन किया था, तो चीनियों ने उन्हें बताया कि भारत में नए चीनी राजदूत शीघ्र ही राजधानी आने वाले थे और बातचीत उनके माध्यम से प्रारम्भ की जानी चाहिए। इन वार्ताओं के दौरान, चीनी राजदूत युआन झोंग जियान ने मांग की कि तिब्बती प्रतिनिधिमंडल एक दो सूत्री प्रस्ताव स्वीकार करेः 1) तिब्बती राष्ट्रीय सुरक्षा चीन द्वारा सम्भाली जायेगीः और 2) तिब्बत को चीन के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। फिर उनको समझौते की पुष्टि के लिए चीन जाना होगा।

चीन की मांगों की जानकारी होने पर, तिब्बती सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्देश दिया। फिर बातचीत को निरस्त कर दिया गया।

7 अक्टूबर, 1950 को पॉलिटिकल कमिसार, वांग क्युमी के तहत 40,000 चीनी सैनिकों ने आठ दिशाओं से तिब्बत की प्रांतीय राजधानी चमदो पर हमला किया। 8,000 सैनिकों और नागरिक–सेना से युक्त छोटे तिब्बती बल को हराया गया था। दो दिनों के बाद, चमदो को कब्ज़े में ले लिया गया और क्षेत्रीय गवर्नर कालोन (मंत्री) नगपा न्गवांग जिग्मे को पकड़ लिया

गया। 4000 से अधिक तिब्बती लड़ाके मारे गए।

चीनी आक्रमण भारत के लिए एक झटका था। 26 अक्तूबर, 1950 को बीजिंग को एक कड़ी टिप्पणी में, भारतीय विदेश मंत्रालय ने लिखाः

> *अब जब चीनी सरकार द्वारा तिब्बत पर आक्रमण का आदेश दिया गया है, तो शांतिपूर्ण वार्ता शायद ही इसके साथ जुड़ सकती है और स्वाभाविक रूप से तिब्बतियों को भय होगा कि वार्ता संदेह के दायरे में होगी। विश्व की घटनाओं के वर्तमान संदर्भ में, चीनी सैनिकों द्वारा तिब्बत के आक्रमण को खेदजनक नहीं माना जा सकता है और भारत सरकार के विचारित निर्णय में, चीन या शांति के हित में नहीं माना जा सकता।*

अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने आक्रामकता पर भारतीय स्थिति के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

नवंबर, 1950 में, तिब्बती नेशनल असेंबली ने एक आपातकालीन सत्र बुलाया और दलाई लामा से जो उस समय केवल पंद्रह साल के थे, अनुरोध किया कि वे राज्याध्यक्ष रूप में पूर्ण अधिकार ग्रहण करें। तब दलाई लामा से व्यक्तिगत क्षति से बचने के लिए ल्हासा को छोड़ कर भारतीय सीमा के पास ड्रोमो (यतुंग) जाने का अनुरोध किया गया था। उसी समय, तिब्बती विदेश कार्यालय ने निम्नलिखित बयान जारी कियाः "तिब्बत दलाई लामा के पीछे एकजुट है, जिन्होंने पूरी शक्तियां संभाली हैं ... हमने दुनिया से शांतिपूर्ण हस्तक्षेप के लिए अपील की है (इस के दृष्टिगत) यह स्पष्ट असुरक्षित आक्रमण का मामला है।"

7 नवम्बर 1950 को तिब्बती सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को पत्र लिखकर विश्व निकाय से हस्तक्षेप करने की अपील की। पत्र में कहा गया हैः" तिब्बत मानता है कि यह चीन के इस कृत्य का विरोध करने की स्थिति नहीं है। अतः यह चीनी सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण शर्तों पर बातचीत करने के लिए सहमत हुआ है ... हालांकि इस बात की उम्मीद कम ही है कि कोई राष्ट्र शांति के लिए समर्पित हो पाएगा युद्ध के लिए प्रशिक्षित पुरुषों के क्रूर प्रयास का विरोध करने के लिए, हम समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने जहां भी आक्रमण हुआ है, उसे रोकने का फैसला किया है। "17 नवंबर, 1950 को, ईआई सल्वाडोर की सरकार ने औपचारिक रूप से पूछा कि तिब्बत के खिलाफ आक्रामकता को जनरल काउंसिल की कार्यसूची में रखा जाए। हालाँकि, भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा

में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई थी लेकिन इसमें कहा गया था कि एक शांतिपूर्ण समाधान जो तिब्बत, भारत और चीन के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद हो, संबंधित पक्षों के बीच हो सकता है। दिसंबर 2018–19 को संयुक्त राष्ट्र में तिब्बती प्रतिनिधिमंडल के दूसरे पत्र ने भी स्थिति को नहीं बदला।

पूर्वी और उत्तरी तिब्बत के सैन्य कब्जे का सामना, अपनी छोटी सेना की अवहेलना और विनाश, केंद्रीय तिब्बत की ओर हजारों पीएलए सैनिकों का बढना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सक्रिय सहयोग की कमी के कारण, दलाई लामा और तिब्बत की सरकार ने नए चीनी नेतृत्व के साथ वार्ता के लिए बीजिंग में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया।

सत्रह-सूत्रीय समझौता

अप्रैल 1951 में, तिब्बती सरकार ने कलोन न्गापो न्गावांग जिग्मे के नेतृत्व में बीजिंग में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजा। तिब्बती सरकार ने तिब्बती स्थिति को आगे बढ़ाने और चीनियों की बात सुनने के लिए अपने प्रतिनिधिमंडल को अधिकृत किया। चीनी के दावों के विपरीत कि प्रतिनिधिमंडल के पास "पूर्ण शक्तियां" थीं, इसे कुछ भी निर्णय लेने का अधिकार नही दिया गया। इसके विपरीत इन्हें सभी महत्वपूर्ण मामलों को सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया था।

29 अप्रैल, को चीन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा "समझौते"के एक प्रारुप की प्रस्तुति के साथ वार्ता प्रारम्भ की गई। तिब्बत के प्रतिनिधिमंडल ने चीन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसके बाद चीन ने संशोधित प्रारूप प्रस्तुत किया वह प्रारूप भी तिब्बती प्रतिनिधि मंडल को अस्वीकार्य था। इस स्थिति में चीन के प्रतिनिधियों ली वेइहेन और ज़हांग ने स्पष्ट किया कि शर्तें जैसी हैं अंतिम हैं और इसके बाद केवल अल्टीमेटम ही दिया जाएगा। तिब्बती प्रतिनिधिमंडल को तीखे और अपमानजनक ढंग से संम्बोधित किया गया, उन्हें शारीरिक हिंसा की धमकी दी गई और वस्तुतः बंदी बना लिया गया। उन्हें आगे विचार–विमर्श की अनुमति नहीं दी गयी, चीन के दावों के विपरीत तिब्बती प्रतिनिधिमंडल को अपनी सरकार से निर्देशों के लिए सम्पर्क की भी अनुमति नहीं दी गई। इसकी बजाय उन्हें या तो समझौते पर हस्ताक्षर करने का विकल्प दिया गया या फिर ल्हासा पर तुरत आक्रमण का दायित्व स्वीकार करने को कहा।

चीनी प्रतिनिधिमंडल के भारी दबाव के बाद 23 मई,1951 को तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने "सेंट्रल पीपलज़ गवर्नमेंट और स्थानीय तिब्बत सरकार के साथ तिब्बत की शांतिपूर्वक मुक्ति के उपायों पर समझौते" पर बिना तिब्बत सरकार को सूचित किये हस्ताक्षर कर दिए। प्रतिनिधिमंडल ने चीन को चेतावनी दी कि वे केवल अपनी निजी हैसियत में हस्ताक्षर कर रहे हैं और दलाई लामा या तिब्बत सरकार पर इस "समझौते" की कोई बाध्यता नहीं होगी। इनमें से कुछ भी चीन सरकार को हस्ताक्षर समारोह आयोजित करने और विश्व को यह घोषित करने में कि "तिब्बत की शांतिपूर्वक मुक्ति" के लिए "समझौता" सम्पन्न हो गया है नहीं रोक पाया। यहां तक कि चीन सरकार ने दस्तावेज़ पर लगाई जाने वाली मोहरें भी नकली लगायीं ताकि इन्हें आवश्यक पुष्टि का स्वरूप दिया जा सके ।

अन्य मदों के साथ "समझौते"के सत्रह अनुच्छेदों में, चीनी सेनाओं का तिब्बत में प्रवेश और तिब्बत के विदेश मामलों का चीन सरकार द्वारा प्रबंध के लिए प्राधिकृत करना भी शामिल था। इसके साथ ही यह समझौता आश्वासन देता था कि चीन सरकार तिब्बत में वर्तमान राजनैतिक प्रणाली को ना तो बदलेगी और ना ही परमपावन दलाई लामा या पंचेन लामा के संस्थागत स्तर, कार्य या शक्तियों में कोई हस्तक्षेप करेगी। तिब्बत के लोगों को क्षेत्रीय स्वायत्तता होगी और उनके धार्मिक आस्थाओं व प्रथाओं का सम्मान किया जाएगा। तिब्बत में आंतरिक सुधार अग्रणी तिब्बतियों के परामर्श के बिना किसी विवशता के लागू किये जायेंगे।

"सत्रह सूत्रीय समझौते" का पूरा पाठ 27 मई,1951 को रेडियो बीजिंग द्वारा प्रसारित किया गया था। यह पहली बार थी जब दलाई लामा और तिब्बत सरकार ने इस विनाशकारी दस्तावेज के बारे में सुना था। दोरमो(जहां दलाई लामा उस समय रूके पड़े थे) और ल्हासा में प्रतिक्रिया सदमे और अविश्वास की थी।

बीजिंग में प्रतिनिधियों को तुरंत एक सन्देश भेजा गया जिसमें सरकार के निर्देशों के बिना "समझौते" पर हस्ताक्षर करने की कड़ी निंदा की गई। प्रतिनिधिमंडल को जिस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं उसकी सामग्री भेजने के लिये कहा गया और आगामी निर्देशों तक बीजिंग में ही प्रतीक्षा करने को कहा गया। इसी बीच, प्रतिनिधिमंडल की ओर से तार द्वारा एक सन्देश प्राप्त हुआ कि चीन सरकार का प्रतिनिधि जनरल ज़हांग जिनवू

भारत के रास्ते दोरमो के लिए प्रस्थान कर चुका हैं। सन्देश में यह भी बताया गया कि प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्य भारत के रास्ते वापिस आ रहे हैं और प्रतिनिधिमंडल के नेता सीधे ल्हासा वापिस आएंगे।

दलाई लामा और तिब्बत की सरकार ने" समझौते" के प्रति जनता के रोष को रोक दिया था। दलाई लामा ल्हासा 17 अगस्त 1951 को इस आशा से वापिस लौट आये थे कि चीनियों के साथ अधिक अनुकूल सन्धि पर पुनः वार्ता होगी।

9 सितंबर 1951 को अनुमानतः 3000 चीनी सेना की टुकड़ियां ल्हासा की ओर निकल पड़ीं। इसके बाद लगभग और 20,000 पूर्वी तिब्बत से और उत्तर में पूर्वी तुर्किस्तान (शिनजियांग) से आने लगे। जन मुक्ति सेना (पीएलए) ने रूथोक तथा गरतोक के प्रमुख शहरों पर कब्ज़ा करने के बाद ज्ञानग्त्से और शिगत्से पर कब्ज़ा कर लिया।

तिब्बत के सभी प्रमुख शहरों पर कब्ज़ा करने के बाद और सैनिकों का पूर्वी और पश्चिमी तिब्बत पर अधिक केंद्रित होने के कारण तिब्बत पर सैनिक नियंत्रण वास्तव में पूर्ण हो चुका था। इस स्थिति में, चीन ने पुनः वार्ता से इंकार कर दिया और दलाई लामा किसी भी तिब्बत–चीन "समझौते" को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने की योग्यता खो चुके थे। फिर भी उन्होंने पहली बार 20 जून 1959 को भारत की विमान–यात्रा के बाद खुले तौर से स्वयं को व्यक्त किया, दलाई लामा ने औपचारिक रूप से "सत्रह सूत्रीय समझौते" की निंदा करते हुए इसे "तिब्बत की सरकार और लोगों पर हथियारों के बल पर थोंपा हुआ" कहा।

तिब्बत के लिए शांतिपूर्ण मुक्ति के लिए उपायों पर सत्रह सूत्रीय समझौते" और तिब्बत की संलग्नता के मूल्यांकन में दो तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला, तिब्बत की ओर पीपलज़ लिबरेशन आर्मी की बढ़त में चीन द्वारा किस मात्रा तक अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया और "समझौते" पर हस्ताक्षर के दूरगामी प्रभाव।

संधियों को कार्यान्वित करने वाले कानून सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों पर आधारित होते हैं कि परंपरागत बाध्यताओं की नींव समझौता करने वाले पक्षों की स्वतंत्र और परस्पर सहमति पर आधारित है और इसके विपरीत, समझौते की वैद्यता के लिए सहमति की स्वतंत्रता आवश्यक है।

धमकियों से या बल प्रयोग कर लाई गई सन्धियाँ, कानूनी वैद्यता नही रखतीं, विशेष तौर से जब देश या सम्बन्धित सरकार पर आपसी बातचीत के स्थान पर बल प्रयोग किया जाए। चीन द्वारा तिब्बत के अधिकांश भाग पर कब्ज़ा करना और सन्धि हस्ताक्षर नही करने पर ल्हासा पर सैनिक कार्यवाही की खुलेआम धमकी से, समझौता प्रारम्भ से ही अवैध था और ये बाद में भी तिब्बत सरकार की रज़ामन्दी से वैध नहीं बनाया जा सकता था। चीन के दावों के विपरीत, दलाई लामा या तिब्बत की सरकार ने स्वेच्छा से "समझौते" पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। वास्तव में, तिब्बत में हमारे कार्य पर चीन के साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के 6 अप्रैल 1952 को ज़ारी निर्देशों में माओ त्सेतुंग ने स्वयं स्वीकारा था किः "केवल दो सीलोन (अर्थात प्रधानमंत्री) ही (न)हीं पर दलाई लामा और उसके गुट के बहुत से लोग समझौते को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे और इसे लागू करने के इच्छुक नही हैं.... क्योंकि अभी हमारे पास समझौते को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए सामग्री का आधार नहीं है और नही हमारे पास इस उद्देश्यार्थ जनता या ऊपर के वर्ग का समर्थन है।[71]

राष्ट्रीय विद्रोह

चीनियों के प्रति विरोध का तिब्बती आंदोलन 1950 में आक्रमण के साथ शुरू हो गया था, इससे पहले कभी भी चीन में लोकप्रिय विद्रोह नहीं हुआ था, पूर्वी तिब्बत के खाम और अमदो प्रान्तों में खुली लड़ाइयां हो रहीं थीं। तीन वर्षों के बाद विद्रोह ने राष्ट्रीय रूप ले लिया और मार्च,1959 में ल्हासा में भारी प्रदर्शन हुआ और दलाई लामा 80,000 तिब्बतियों के साथ पड़ोसी देश को भाग गए। 10,000 से अधिक तिब्बती विद्रोहों के दौरान पीएलए द्वारा मार दिए गए।

चीन की सरकार ने इस लोकप्रिय प्रतिरोध को अपने शासन में कुछ सिरफिरे धनाढ्यों का कार्य बताया जो तिब्बती लोगों के दमन और शोषण की प्राचीन पद्दति ज़ारी रखना चाहते थे।

इसमें 95 प्रतिशत तिब्बतियों को कुछ धनाढ्यों और लामाओं द्वारा बुरी तरह से दमन किये गए कृषि– मजदूर दर्शाया गया था। चीन इस बात की कभी भी व्याख्या नहीं कर पाया कि ये तथाकथित शोषित लोग अपने मालिकों के

71 माउ त्सेतुंग, माउ त्सेतुंग के कुछ चुने हुए कार्य (पेकिंगः विदेशी भाषा प्रेस, 1977) वो.5, 75

खिलाफ क्यों खड़े नहीं हुए जबकि उनके देश में कभी भी राष्ट्रीय पुलिस बल नहीं रहा और इतिहास में कभी भी यहाँ मजबूत सेना नहीं रही। फिर भी वही तिब्बती उठ खड़े हुए और आज भी भारी सुरक्षा प्रबंधों और सेना के विरूद्ध आवाज बुलुंद कर रहे हैं यह जान कर भी कि इस विरोध में भारी खतरा हो सकता है।

यदि हम 1959 में प्रारम्भ हुए प्रदर्शनों और विद्रोहों में, जो अभी तक ज़ारी हैं, शामिल तिब्बतियों की सामाजिक संरचना पर ध्यान दें तो अधिकाँश धनाढ्य या उच्च लामा नहीं हैं। कम से कम 85 प्रतिशत से अधिक तिब्बती जो निर्वासन में हैं न तो "कृषि–मजदूर वर्ग" से हैं और न ही समाज के उच्च वर्ग से हैं जैसा कि चीन दावा करता है।

1959 के विद्रोह की घटनाएं

चीनी सेनाओं के ल्हासा में प्रवेश के बाद, तिब्बत सरकार की सम्प्रभुता को कम करने और चीनी की सत्ता को थोंपने का प्रयास किया गया। यह तीन तरीकों से कार्यान्वित किया गया। पहला, बांटों और राज करों नीति के अंतर्गत तिब्बतियों में राजनैतिक और क्षेत्रीय मंडल बनाये गए। दूसरे, तिब्बतियों की इच्छा के विरूद्ध विभिन्न सुनियोजित सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू किये गए ताकि तिब्बती समाज का ढांचा बदला जा सके। तीसरे, वर्तमान तिब्बती संस्थानों के साथ–साथ चीन सरकार के विभिन्न संस्थान और निकाय स्थापित किये गए।

24 नवम्बर, 1950 से 19 अक्तूबर,1953 के बीच चीन ने खाम प्रांत के अधिकांश हिस्से को पड़ोसी चीन प्रांत के सिचुआन में मिला दिया। खाम को दो स्वायत्त तिब्बती प्रान्तों और एक तिब्बती जिला में विभाजित कर दिया गया। 13 सितम्बर 1957 को दक्षिण खाम के एक भाग का नाम देचेन तिब्बती स्वायत प्रांत रखा गया और इसे यूननान प्रांत के अधीन कर दिया गया।

अमदोह का बहुत सारा भाग और खाम का कुछ हिस्से को मिला कर किंघाई नाम से चीनी प्रांत बना दिया गया। अमदोह के एक हिस्से को नग्पा तिब्बती स्वायत्त प्रांत का नाम दिया गया और उसे सिचुआन प्रांत के साथ मिला दिया गया। अमदोह के शेष भाग को पुनः तिंजहू तिब्बती स्वायत्त जिला (6 मई,1950) और गनल्हो तिब्बती स्वायत्त प्रांत (1 अक्तूबर 1953) में विभाजित

कर चीन के गान्सू प्रांत के साथ मिला दिया।

9 सितम्बर 1965 को चीन ने औपचारिक रूप से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रीय सरकार की स्थापना की और इसके अंतर्गत समस्त यू–त्सांग और खाम के कुछ क्षेत्र का प्रशासन रख दिया गया।

इस बीच, चीन ने बहुत से तिब्बतियों की जातीय पहचान, जैसे शेरपा, मोनपा, तेंगपा, जंगपा आदि छीन लिए, भले ही वे खुद को तिब्बती मानते थे, उन्हें अलग चीनी अल्पसंख्यकों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया। उसी अवधि में, पीपुल्स लिबरेटियन आर्मी द्वारा हजारों टन जौ और अन्य खाद्य सामग्री इधर–उधर कर दी जिसने तिब्बतियों को इतिहास में पहली बार अकाल के कगार पर धकेल दिया और ल्हासा में विरोध सभाओं के लिए प्रोत्साहित किया।

पहला प्रमुख लोकप्रिय प्रतिरोध समूह, मिमांग त्संगदू (पीपुल्स असेंबली), जिसे अनायास ही प्रतिबंधित कर दिया गया था, ने चीनी सैन्य कमान को एक याचिका सौंपी जिसमें पीएलए की वापसी की मांग की गयी थी और तिब्बत के मामलों में चीनी हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए कहा गया था। चीनी की प्रतिक्रिया त्वरित थीः दो तिब्बती प्रधान मंत्री लुखंगवा और वेन. लोबसांग ताशी, जिन्होंने चीनी शासन के विरुद्ध अपने विरोध का कोई रहस्य नहीं रखा था और "सत्रह सूत्रीय समझौते" का विरोध किया था, को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था और मिमांग त्संगदू के पांच नेताओं को जेल में डाल दिया गया था जिसके कारण संगठन भूमिगत हो गया।

1954 में चीन के निमन्त्रण पर दलाई लामा ने बीजिंग का दौरा किया स उस समय, "सत्रह सूत्रीय समझौते" में वर्णित तिब्बत की "विशेष" स्वायत्त स्थिति को चीन की जन कांग्रेस के नये संविधान को स्वीकार कर औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद "तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र के लिए तैयारी समिति (पीसीएआरटी) की स्थापना का प्रस्ताव" रखा गया जो तिब्बत के प्रशासन को पीआरसी में मिलाने की और एक कदम था। तैयारी समिति ने तिब्बत के केन्द्रीय प्रशासन के रूप में कार्य करना था। दलाई लामा को इसका अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन बिना किसी अधिकार के।

दलाई लामा ने अपनी आत्मकथा में इसकी व्याख्या की है :

समिति शक्तिहीन थी –तिब्बती प्रतिनिधित्व मात्र दिखावा था जिसके पीछे सभी प्रभावी शक्तियाँ चीनियों द्वारा प्रयोग की जाती थीं। वास्तव में, सभी आधारभूत नीति पर निर्णय तिब्बत में चीन के साम्यवादी दल कहलाने वाली संस्था द्वारा लिया जाता था, जिसमें कोई भी तिब्बती सदस्य नहीं था।[72]

1956 में पीसीएआरटी कार्यान्वित की गयी और उत्तरी तिब्बत में चमदोह के गवर्नर –जनरल (तिब्बत सरकार द्वारा नियुक्त) की सीमा–क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रो सहित तशिल्हुनपो एस्टेट को ल्हासा में तिब्बत सरकार की सीमा–क्षेत्र से अलग कर दिया गया। उनके प्रशासनिक ढांचे को तिब्बत सरकार के समक्ष दर्जा प्रदान किया गया, इस प्रकार तिब्बत सरकार का अधिकार कम कर दिया गया। अमदोह और खाम में सामाजिक, राजनीतिक और कृषि सुधार चीन सरकार द्वारा लागू किए गए थे जबकि देश के शेष हिस्सों में अपेक्षाकृत कम थे। धार्मिक व्यक्तियों और मठों पर लगातार हमले किए गए। चीनी सरकार की इन सभी नीतियों और कार्यों के कारण तिब्बती लोगों की हिंसक प्रतिक्रियाएँ बढती गयीं।

"सत्रह–सूत्रीय समझौता" यह सुनिश्चित करता था कि कोई भी साम्यवादी सरकार तिब्बत पर सुधारों को बलपूर्वक लागू नहीं करेगी। लेकिन पूर्वी तिब्बत में, वे एक दम लागू कर दिये गए। चीनी प्रशासकों की बढ़ती बेचैनी और भावनाओं ने हिसंक प्रतिक्रियाओं को उकसाया जो तेज़ी से समस्त पूर्वी तिब्बत के खाम और अमदोह प्रान्त में सैनिक दमन और प्रतिशोध की आग के रूप में फैल गया। जैसे ही हिंसा तिब्बत के अन्य क्षेत्रों में फैली, 1956 की गर्मियों में पूर्ण रूप से गुरिल्ला युद्द प्रारम्भ हो गया। पूर्वी और उत्तरी पूर्वी तिब्बत से भारी मात्रा में शरणार्थी ल्हासा पहुंचने शुरू हो गए। एक वर्ष के भीतर, विद्रोह केंद्रीय तिब्बत में फैल गया, और 1958 में मिमांग त्सो गन्दू और चुशी गंगदरुक (चार नदियां छह श्रृंखलायें) संगठनों ने मिल कर तेनसुंग धनगलांग मागर (सुरक्षा और विश्वास के लिए एक स्वैच्छिक बल) की नींव रखी। उस वर्ष के पतझड़ तक इस लोकप्रिय प्रतिरोध बल का दक्षिणी तिब्बत के कई ज़िलों और पूर्वी तिब्बत के हिस्सों पर नियंत्रण था।

दलाई लामा ने अपने लोगों को शांत करने के लिए खूब प्रयास किया ताकि खून–खराबा रोका जा सके। पर फिर भी तिब्बत में स्थिति तेज़ी से ख़राब होने लगी जब 1956 में दलाई लामा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर बुद्द जयंती समारोह में भाग लेने भारत के

72 दलाई लामाः मेरे देश और मेरे लोग (न्यू यॉर्कः ग्रान्ड सेन्ट्रल पब्लिशींग, 1962) 133

दौरे पर आये। दिल्ली में नेहरू और चाउ एन लाई की एक बैठक में दलाई लामा ने अपनी मातृभूमि में विस्फोटक स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और स्वीकार किया कि वह भारत में राजनैतिक शरण लेने पर विचार कर रहे हैं। नेहरू ने दलाई लामा को यह नहीं करने का परामर्श दिया।

दलाई लामा की घर वापसी के लिए प्रलोभन के लिए चीन की सरकार ने तुरत घोषणा कर तिब्बत में "सामाजिक तथा प्रजातांत्रिक सुधारों" को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। इस पर भी सहमति व्यक्त की गई कि चीनी नागरिक कर्मिकों को वापिस बुला लिया जाएगा और पीसीएआरटी के विभाग आधे कर दिए जाएंगे। बाद की घटनाओं में इन वायदों को झूठा पाया गया। आने वाले वर्षों में चीन ने समाजवादी अभियान तेज़ कर तिब्बतियों के विरुद्ध प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया और तिब्बत में भारी मात्रा में सैनिक बल भेजा, चीनियों की पहले की तुलना में कमी के स्थान पर वृद्धि होने लगी।

राष्ट्रीय जनक्रांति और परम पावन दलाई लामा का पलायन

मार्च, 1959 में एक अपरिहार्य प्रदर्शन हुआ। तब तक यह भ्रम फैल चुका था कि चीनी अधिकारी दलाई लामा का अपहरण कर उन्हें बीजिंग ले जाने की योजना बना रहे हैं।ये भय दलाई लामा की सुरक्षा के लिये और भी ज़्यादा हो गया जब 10 मार्च को चीनी सेना कमांड ने तिब्बती नेता को सैनिक बैरकों में नाटक देखने के लिये आमंत्रित किया। तिब्बतियों को इससे पूर्व खाम और अमदोह में कटु अनुभव हो चुका था जहां महत्वपूर्ण लामा और तिब्बती नेता चीनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य समारोहों में आमंत्रित किये जाने के बाद रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। तिब्बतियों का संदेह और अधिक बढ़ गया जबकि चीनियों ने उनके साथ अंगरक्षकों को नहीं भेजने पर ज़ोर दिया जोकि परंपरा के अनुरूप था। ल्हासा के लोग दलाई लामा को चीनी छल में फंसने की अनुमति नहीं दे सकते थे। 10 मार्च 1959 को उन्होंने एक भारी प्रदर्शन किया और हज़ारों की संख्या में एकत्रित लोगों ने दलाई लामा के ग्रीष्मकालीन महल, नोरबूलिंगका को घेर लिया ताकि चीनी समारोह में भाग लेने से रोका जाए। आगामी दिनों में तिब्बतियों ने ल्हासा में नागरिकों के साथ बैठकें कीं और चीन से तिब्बत छोड़ कर देश की पूर्ण आज़ादी बहाल करने की मांग की। दलाई लामा ने इन सामूहिक प्रदर्शनों के खतरनाक परिणामों से डर कर भारी भीड़ को नोरबूलिंगका के

नज़दीक से चले जाने के लिए कहा। उन्होंने चीन को तस्सली देने और वर्तमान हिंसा को टालने के प्रयास में प्रमुख चीनी जनरल तान गुणसान को तीन पत्र लिखे। दलाई लामा अपनी आत्मकथा में लिखते हैंः

> *मैंने समय लेने के लिए उनके सभी पत्रों के जवाब दिये–दोनों ओर से गुस्से को शांत करने के लिए समय और ल्हासा के लोगों से संयम का आग्रह करने का समय..... उस क्षण में मेरा सबसे ज़रूरी नैतिक कर्तव्य अपने निहत्थे लोगों और चीन के सेना के बीच पूर्णतया विनाशकारी संघर्ष को रोकना था।*[३]

लेकिन दलाई लामा के प्रयासों के बावजूद, इसके एकदम बाद ल्हासा में खुले आम लड़ाई प्रारम्भ हो गयी, जिसके परिणाम तिब्बतियों के लिए विनाशकारी होते। यह देख कर कि खुली लड़ाई और खून खराबे को रोकने के सभी प्रयास अंततः असफल हो गए हैं और चीन के अधिकारियों के साथ दमन को कम करने में सहयोग अब सम्भव नहीं है, दलाई लामा ने भारत भागने का फैसला किया ताकि अपने लोगों को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अपील की जा सके। उन्होंने ल्हासा 17 मार्च 1959 की रात को छोड़ दिया।

28 मार्च 1959 को चीन के प्रीमियर चाउ–एनलाई ने स्टेट कॉउंसिल का तिब्बत सरकार को "भंग" करने का आदेश ज़ारी किया। दलाई लामा और उनके मंत्रियों ने भारत की ओर आते हुए रास्ते में ही तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए घोषणा कि ल्हासा में नए चीनी प्रशासन को तिब्बत के लोग कभी भी मान्यता नहीं देंगे। भारत पहुंचने पर दलाई लामा ने पुनः तिब्बती प्रशासन स्थापित किया और सार्वजनिक रूप से घोषणा कीः "जब भी मैं अपनी सरकार के साथ होता हूँ तिब्बत के लोग हमें तिब्बत की सरकार के रूप में मान्यता देते हैं।" कुछ ही महीनों में, लगभग 80,000 तिब्बती भाग निकले और भारत, नेपाल और भूटान की सीमाओं पर पहुंच गए। कुछ और सीमा तक भी नहीं पहुंच पाए।

चीन की सरकार ने इन घटनाओं को कुछ मुट्ठी भर तिब्बती प्रतिक्रियावादियों के कार्य के रूप में प्रतिबिंबित किया जिन्होंने सीआईए की सहायता से सशस्त्र "विद्रोही" तैयार किये हैं और जिनका लोगों ने "सख्ती" से विरोध किया है। चीनियों ने यह भी दावा किया कि दलाई लामा को "दबाव के अंतर्गत" भारत ले जाया गया। चीन ने यह भी दावा किया कि दलाई लामा

---

73 वही–187

को "दबाव के अंतर्गत" भारत ले जाया गया। चीन ने यह भी दावा किया कि प्रतिरोध करने वाले "विद्रोही" 7000 से अधिक नही थे और प्रतिरोध दो दिनों में कुचल दिया गया। यह दृष्टिकोण कठिनतया से विश्वसनीय है और स्वयं भी चीनी अधिकारियों ने इसका प्रतिकार किया हैः चीनी सेना के खुफिया विभाग की रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि पीएलए ने ल्हासा और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से 87,000 तिब्बती सदस्यों को केवल मार्च से अक्तूबर,1959 तक खत्म कर दिया।[74] सीआईए की अनमने मन से सहायता वास्तव में विद्रोह के बाद ही शुरू हुई थी जिसका तिब्बतियों ने स्वागत किया था लेकिन यह मात्रा में कम थी।

सभी प्रमाण इस बात को दर्शाते हैं कि विद्रोह भारी, लोकप्रिय तथा सर्वत्र फैला हुआ था। तिब्बत के सभी क्षेत्रों में किया जाने वाला क्रूर दमन इस वास्तविकता की पुष्टि करता है।

74 पीएलए के जिलों के सेना राजनीतिक रिपोर्ट, 1960 Xizang Xingshi he Renwu Jiaoyu de Jiben Jiaocai,

अध्याय तीन

तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति

परिचय

यह अध्याय चीन सरकार के अधीन तिब्बत में निरंतर सिलसिलेवार और गम्भीर मानवाधिकारों के उल्लंघन का दस्तावेज़ है। उपलब्ध सभी प्रमाण यह दर्शाते हैं कि चीन अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित सभ्य आचरण के सभी मानकों का परवाह किये बिना उल्लंघन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्व ारा मानवअधिकारों पर सर्वभौमिक घोषणा में निहित सबसे बुनियादी और मौलिक मानवाधिकारों से तिब्बत में तिब्बतियों को वंचित रखा गया है। वास्तव में कोई भी एकल कृत्य या मात्र विचार जो चीन की सरकार को पसंद नहीं है पर कठोर परिणाम या दण्ड मिल सकता है।

तिब्बतियों को अपने आत्म–निर्धारण अधिकार से भी वंचित रखा गया है, प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक नियम है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर[75] सहित अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों की एक श्रेणी में परिलक्षित होता है।

जब तक तिब्बत में, मानवाधिकारों का सर्वाधिक दुरुपयोग रोका नहीं जाता, चीन सरकार का दावा कि वे तिब्बत में उचित सत्ताधारी सरकार अवैध हैं। स्थिति के सत्य को स्वीकार करने और कम से कम उल्लंघनों को रोकना, तिब्बत मामले में शांतिपूर्वक प्रस्ताव और तिब्बत को वास्तव में स्वायत्त क्षेत्र बनाने की ओर पहला कदम होगा।

तिब्बत का विनाश (1949-1979)

1993 में, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की प्रकाशित एक रिपोर्ट, तिब्बतः तथ्यों से सत्य को सिद्द करना,[76] जिसमें यह दस्तावेज़ीकृत किया गया था कि 1949

---

75 यूएन चार्टर, अध्यादेश 55, UN Charter, http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-ix/index.html

76 केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग, तिब्बतः प्रुविंग ट्रूथ फ्रोम फैक्ट (धर्मशलाः सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, 1996) http://tibet.net/1996/01/tibet-proving-truth-from-facts-1996/.

से 1979 तक चीनी हमले के दृष्टिगत और तिब्बत पर कब्ज़े के फलस्वरूप 1.2 मिलियन तिब्बती मारे गए। आज तिब्बत का शायद ही कोई परिवार होगा जिसका एक सदस्य चीनी सत्ता द्वारा या तो कैद ना किया गया हो या फिर मार डाला गया हो।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की सूचना पर आधारित निम्न तालिका 1.1 दर्शाती है कि तिब्बत के तीन प्रान्तों में किस तरह 1.2 मिलियन तिब्बती मारे गए ।

चित्र 1.1

मृत्यु का कारण	यू–त्सांग	खाम	अमदोह	कुल
कैद में प्रताड़ना	93,560	64,877	14784	173,221
संक्षिप्त सज़ा	28,267	32,266	96,225	156,758
लड़ाई में मौत	143,253	240,410	49042	432,705
भोजन ना देने से मौत	131,072	89,916	121982	342970
आत्महत्या	3,375	3,952	1,675	9002
संघर्ष सत्र	27,951	48,840	15,940	92,731
कुल	427,478	480,261	299,648	1,207,387

'संघर्ष सत्र के दौरान (तिब्बतीःथामजिंग) तिब्बतियों को सार्वजनिक रूप से एक–दूसरे को गाली–गलौच,आलोचना और पीटने के लिए बाध्य किया जाता था। कोई भी तिब्बती जिसने स्वतंत्र तिब्बत की सरकार में कार्य किया है या समृद्दि अथवा उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त किया था उसे ब्लैक बेल्ट के अंतर्गत "भूस्वामी,साहूकार,कृषि–मज़दूर"आदि वर्गीकृत करके प्रताड़ित किया जाता था।

नरसंहारों, प्रताड़नाओं, हत्याओं और बौद्ध–विहारों पर बम्ब गिराने की घटनाओं और सभी खानाबदोश शिविरों की तबाही के लेखों को अच्छी तरह से दस्तावेज़ किया गया है। इन में से बहुत से प्रतिवेदन न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट 1960 में दस्तावेज़ किये हैं।

एक चीनी स्त्रोत ने बताया है कि पीपलज़ लिबरेशन आर्मी ने 7 अक्तूबर से 24 अक्तूबर 1950 तक पूर्वी तिब्बत के विभिन्न क्षेत्रों में 5000 सैनिकों को

"तबाह" कर दिया और 2,000 को बंदी बना लिया।[77] अन्य गोपनीय चीनी सैनिक दस्तावेज़ के अनुसार पीएलए ने 1952–58 तक कानलोह, अमदोह में 996 विद्रोहियों को खत्म कर दिया, और 10,000 तिब्बती मार डाले।[78] इसी प्रकार अमदोह क्षेत्र के गोलोक की जनसंख्या 1956 की 1,30,000 की तुलना में 1963 में घट कर 60,000 रह गई।[79]

28 मार्च, 1987 को तिब्बत की स्थिति पर बीजिंग में नेशनल पीपलज़ कांग्रेस की उप–समिति में अपना वक्तव्य देते हुए स्वर्गीय दसवें पंचेन लामा ने कहा था:

> *यदि किंगहाई प्रान्त में किये जाने वाले सभी अत्याचारों की फ़िल्म बनाई जाए तो यह दर्शकों को सदमा देगी..... सैनिकों ने मृतकों के परिवार के सदस्यों और सम्बन्धियों को कहते थे कि उन्हें जश्न मनाना चाहिए क्योंकि विद्रोहियों का सफाया किया जा चुका है। उन्हें बलपूर्वक लाशों पर नाचने के लिये कहा जाता था और उसके एक दम बाद उन्हें भी मशीन–गनों से मार दिया जाता था।*[80]

उन्होंने आगे कहा:" अमदोह और खाम में, लोगों पर अकथनीय अत्याचार किये गए। उन पर दस अथवा बीस के समूहों में गोलियां चलाई जाती थीं. .... इन कृत्यों ने लोगों के मन में गहरे घाव कर दिए थे।"[81]

10 मार्च 1959 को ल्हासा में आयोजित जन आंदोलन के दृष्टिगत धर पकड़ अभियान में तीन दिनों के भीतर 10,000 से 15,000 तक तिब्बती मारे गए। सन 1961 के पीपल्स लिबिरेशन आर्मी के सैनिक जिला राजनीतिक विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मार्च एवं अक्तूबर 1959 के बीच 8700 तिब्बती केवल मध्य तिब्बत में ही मारे गए।[82]

कैदियों को सताया जाता था और बुरा व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण वे जेलों और श्रम–शिविरों में भर जाते थे। कारागारों और श्रम–शिविरों

---

77 तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का सर्वेक्षण, तिब्बत पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, 1984

78 11वें पीएलए डिवीजन की कार्य रिपोर्ट, 1952–1958

79 चाइना स्प्रिंग, जून 1986

80 सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विभाग, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, पंचेन लामा बोलता है। (धर्मशाला: सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, 1991) 12

81 वही–12.

82 पीएलए की जिलों का सेना राजनीतिक रिपोर्ट, 1960 Xizang Xingshi he Renwu Jiaoyu de Jiben Jiaocai,

की स्थिति का 1962 में दस्तावेज़ीकरण करते हुए पंचेन लामा ने लिखा है:

> *गार्ड और सिपाही कैदियों को क्रूर, निर्मम और निंदनीय शब्दों से धमकाते हैं, और उनकी जमकर और बेईमानी से पिटाई करते हैं ..... (कैदियों के) .... कपड़े और रज़ाईयां उनके शरीर को गर्म नहीं रख सकती थी, उनके टेंट और इमारतें उन्हें हवा और बारिश से नहीं बचा पाते थे और भोजन उनका पेट नहीं भरता था। उनका जीवन दुखों और अभावों से भरा था, उन्हें काम के लिए जल्दी उठना पड़ता था और अपने कामों से देर से लौटना पड़ता था; यही नहीं इन लोगों को भारी और अत्यंत मुश्किल कार्य दिया जाता था.... इसके अतिरिक्त उनको कई रोग लग गए, उन्हें पर्याप्त आराम नहीं मिलता था, चिकित्सा उपचार खराब था, जिसके कारण कई कैदी असामान्य कारणों से मर जाते थे।*[83]

कारागारों और श्रम–शिविरों से बच कर आये कैदियों के ब्यानों के अनुसार तिब्बत में इन कारागारों और शिविरों के 70 प्रतिशत कैदी मर गए थे। उदाहरण के लिए उत्तरी तिब्बत के जंगल में झंग त्सालखा के पांच कारागारों में 10,000 से अधिक कैदियों को रखा गया था और उन्हें खदान और बोरेक्स परिवहन के लिए मजबूर किया गया था। इन शिविरों से बच कर आने वालों के अनुसार यहां हर दिन 10 से 30 तक कैदी भूख, पिटाई व ज़्यादा कार्य करने से मर जाते थे। पूर्वी तिब्बत के न्यारोग, खाम के पूर्व कैदी, आधी तापोनत्संग के अनुसार 1960 से 1962 तक ज़िला दरत्सेदो लीड़ खान पर 12,019 कैदी मारे गए थे।[84]

सामुहिक विरोध-प्रदर्शनों में वृद्धि (1980-1990 तक)

सितंबर 1976 में माओ–त्से–तुंग की मृत्यु के बाद चीन की नीतियों में बदलाव आया जिसके बाद आर्थिक उदारीकरण तथा खुलापन अपनाया गया। फिर भी उदारीकरण और खुलेपन ने तिब्बत में राजनैतिक स्वतन्त्रता के प्रति व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया। मई 1982 में 115 तिब्बती राजनैतिक कार्यकर्ता गिरफ़्तार किये गए थे और उन्हें "अपराधी" और "काला बाज़ारिया" कहा गया। बहुत सी गिरफ्तारियां और सार्वजनिक प्राण–दंड दिए जाते थे और केवल ल्हासा में ही 750 राजनैतिक कार्यकर्ताओं को जेल

83 केल ज़न शीह, ए पॉइज़न एरोः द सीक्रेट रिपोर्ट ऑफ द 10 पंचेन लामा (लांडनः तिब्बत सूचना नेटवर्क, 1997). पुस्तक में 10वीं पंचेन लामा द्वारा माओ त्सेतुंग और चाउ एनलाई को 1962 में प्रस्तुत 70,000 चरित्र याचिका का पूरा पाठ शामिल है।

84 सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विभाग, केंद्रीय तिब्बती प्रशासनः तिब्बतः तथ्यों से सत्य साबित, 1996

डाल दिया गया।

1987 का विरोध प्रदर्शनः 1987 के पतझड़ में, तिब्बतियों ने ल्हासा में तीन प्रमुख प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों के बाद धर पकड़ में चीनी पुलिस ने गोलियां चलाईं, कइयों को मार दिया था और गम्भीर रूप से घायल कर दिया था और निहत्थे प्रदर्शनकारियों को कारागार में बंद कर दिया था।

पहला प्रदर्शन 27 सितंबर,1987 को उसी दिन हुआ जिस दिन दलाई लामा की संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस के साथ बैठक थी और उन्हें तिब्बत मामले के समाधान के लिए पांच–सूत्रीय शांति योजना की घोषणा करनी थी। 200 से अधिक तिब्बतियों ने चीनी अधिकारियों द्वारा दलाई लामा की निंदा के मीडिया अभियान के खिलाफ प्रदर्शन किया। ल्हासा में स्थानीय टेलिविज़न ने दलाई लामा के अमेरिका दौरे की खबर दिखा कर, दौरे की निंदा की और दलाई लामा के खिलाफ प्रदर्शनों को प्रोत्साहित किया।

प्रदर्शन 21 भिक्षुओं के समूह ने किया था जिसमें बाद में 100 तिब्बतियों भी आ गए थे। प्रदर्शनकारियों के हाथ मे तिब्बत का प्रतिबंधित राष्ट्रीय झंडा था तथा हाथ से बनाये बैनर थे जो दलाई लामा के प्रति समर्थन व्यक्त कर रहे थे और वे "तिब्बत आज़ाद है" और "दलाई लामा दस हज़ार वर्षों तक जियें" नारे लगा रहे थे। चीनी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धरपकड़ की और सभी भिक्षुओं और पांच प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया।

दूसरा प्रदर्शन 1 अक्तूबर को चीन के राष्ट्रीय दिवस पर हुआ, सेरा मठ से 23 भिक्षुओं,[85] नेचुंग मठ[86] से 3 भिक्षुओं तथा जोखांग मंदिर से 8 भिक्षुओ सहित 34 भिक्षुओं ने ल्हासा में जोखांग मंदिर के गिर्द गलियों में बरखोर की ओर से प्रदर्शन किया। उन्होंने तिब्बत का प्रतिबंधित राष्ट्रीय झंडा लहराया और तिब्बत की आज़ादी के लिए नारे लगाए।

चीन के सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों की पिटाई की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2000 से 3000 तिब्बतियों की भीड़ पुलिस स्टेशन पर एकत्रित हुई और सभी प्रदर्शनकारियों की तुरंत रिहाई की मांग करने लगी। इसके एक दम बाद पुलिस अहाते की छत्त से चीन की पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी जिसमें 8 तिब्बती मारे गए और दर्ज़नों घायल हो गए।

---

85 ल्हासा से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर ।

86 ड्रेपुंग मठ के निकट (ल्हासा से 8 किलोमीटर दूर)

अगले कई सप्ताहों में लगभग 600 तिब्बती गिरफ्तार किए गए जिनमें से अधिकांश रात को 11.00 बज़े से 2.00 बजे सुबह तक गिरफ्तार किए गए थे। एक अमेरिकन पर्यटक जिसे केवल प्रदर्शन के फोटो लेने के लिए हिरासत में लिया गया था, ने बताया कि उसने पुलिस–स्टेशन के भीतर पुलिस कर्मियों को कुछ भिक्षुओं के सिर पर बेलचा मारते हुए देखा था।[87]

6 अक्तूबर को, ड्रेपुंग मठ के 50 भिक्षुओं ने ड्रेपुंग मठ के 21 भिक्षुओं की लगातार हिरासत पर जिन्हें 27 सितंबर के प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किया गया था, तीसरा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी भिक्षु, हिरासत में लिए गए भिक्षुओं को शीघ्र छोड़ने और तिब्बत की आज़ादी की मांग कर रहे थे। लगभग 250 सशस्त्र पुलिस बल एकदम पहुंचा और सभी भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें हिंसक रूप से बेल्टों, छड़ियों और लोहे की छड़ों से पीटा गया।

1988 का विरोध प्रदर्शनः कड़ी सजा और व्यवधानों जैसे कठोर उपायों के बावजूद 1987 के बाद पूरे तिब्बत में प्रदर्शन जारी रहे। जुलाई 1988 में, चीन के सुरक्षा प्रमुख, कइओ शी जब "तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र" (टीएआर) के दौरे पर आये तो उन्होंने तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर "निर्दयी दमन" की घोषणा की।[88] यह नीति स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत लागू कर दी थी।

एक पाश्चात्य पत्रकार के अनुसार जोखांग मन्दिर में 10 दिसम्बर 1988 को एक प्रदर्शन के दौरान एक अधिकारी को अपने आदमियों को "तिब्बतियों को मार डालो" का आदेश देते सुना गया था। एक भिक्षु जिसने प्रदर्शन को भी देखा था ने बतायाः

> *चीनी सैनिकों ने मन्दिर को घेर लिया था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अंदर बहुत सारे भिक्षु फंसे हुए थे। बाहर निकलना मुश्किल था क्योंकि वे अश्रु–गैस के गोले दाग रहे थे। सैनिक मन्दिर के भीतर आ गए और भिक्षुओं को अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया।*[89]

87 रोनल्ड डी. शवर्तज, सर्किल ऑफ प्रोटेस्टः तिब्बती विद्रोह में राजनीतिक अनुष्ठान (लंदनः हरत्स और कोंपनी, 1994)

88 जेन मैकार्टनी, "डिटैनी बीट की शिकायत", यूपीई 20 जुलाई 1988 https://www.upi.com/Archives/1988/07/20/Detainee-complains-of-beatings/5300585374400/.

89 रोनल्ड डी. श्वरत्स, सर्किल ऑफ प्रोटेस्टः तिब्बती विद्रोह में राजनीतिक अनुष्ठान (लंदनः हरत्स और कोंपनी, 1994), 81.

उस दिन कम से कम 15 तिब्बती मारे गए थे, और 150 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए थे और बहुत सारे गिरफ्तार किये गए थे।

सेरा, द्रेपुंग तथा गांदेन मठों के भिक्षुओं ने सामूहिक रूप से वार्षिक मोनलाम समारोह का बहिष्कार करने का निर्णय लिया जो तिब्बती बौद्ध उत्सवों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भिक्षुओं का मानना था कि मोनलाम पूजा का आयोजन तब तक अस्वीकार्य है जब तक 1987 के विरोध प्रदर्शनों में संलग्न भिक्षु हिरासत में हैं।

फिर भी भिक्षुओं को मोनालाम उत्सव में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया ताकि तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता के चीनी सरकार के प्रयासों के समर्थन का प्रदर्शन हो सके। भाग नहीं लेने पर मठ से निष्कासन सहित कई अन्य गंभीर परिणामों की घोषणा की गयी। जोखिमों के बावजूद, त्यौहार के आखिरी दिन जैसे ही पार्टी के अधिकारी समापन समारोह में भाग ले रहे थे गांदेन मठ के भिक्षुओं ने हिरासत में लिए गए तिब्बतियों की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया।

चीन के सैनिकों ने 15 भिक्षुओं को गोलियों से भुन दिया। अन्य सैनिक ट्रकों में भर दिए गए और बहुतों को बेहोशी की हालत में ही घसीटा गया।

इस समय तक तिब्बत में व्यापक गिरफ्तारी,रात्रि–छापे, यातना और पूछताछ एक सामान्य प्रथा बन गई थी।

1989-1990 के प्रदर्शनः तिब्बती चीन की साम्यवादी दल की सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते रहे और ल्हासा के इर्द–गिर्द चीन की स्वतन्त्रता की मांग के पोस्टर दिखाई देने लगे। 7 फरवरी, 1989 को जो तिब्बतियों के नये साल (लोसर) के शुरुआत का दिन था, ल्हासा में जोखांग मन्दिर के सामने प्रतिबंधित तिब्बती झंडा दिखाई दिया जो कई घंटों तक लगा रहा जब तक कि चीनी अधिकारियों ने उसे हटा नहीं दिया।

तिब्बतियों ने तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम के स्मरण का आह्वान करते हुए पर्चे बाँटना भी शुरू कर दिया था। 17 फरवरी को लगभग 1700 पीपल्ज़ सशस्त्र पुलिस कर्मी ल्हासा पहुंचे और बारखोर में प्रवेश के लिए जांच–स्थल स्थापित किये। 10–12 सैनिकों के दल ने क्षेत्र में प्रवेश चाहने वाले सभी तिब्बतियों की जांच की।

बढ़ती सैनिक उपस्थिति के बावजूद, मार्च 5, 1989 में तीन दिनों तक ल्हासा में प्रदर्शनकारियों द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय झंडे सहित तिब्बत की स्वतन्त्रता के नारों के साथ फिर अशांति थी। पुलिस की कार्यवाही के दौरान, स्व–चलित हथियारों से गोलियां चलाई गयीं जो निकटवर्ती घरों में आ कर लगीं। अनुमानतः मरने वालों की संख्या 80–400 तक थी। सरकारी चीनी आंकड़े केवल ग्यारह ही थे। एक चीनी पत्रकार, टंग डक्सियन जो इस अवधि में ल्हासा में था, के अनुसार कोई चार सौ तिब्बतियों को मौत के घाट उतारा गया और कई हजार घायल हुए व तीन हजार तिब्बतियों को जेल में बंद किया गया।[90]

7 मार्च 1989 की मध्य रात्रि में, ल्हासा में औपचारिक रूप से मार्शल ला लगा दिया गया। तिब्बत में मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और नजरबंदी मानदंड बन गए थे।

तिब्बतियों पर जलसों और जूलुसों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

एक वर्ष से भी कम समय में, 1 मई 1990 को चीन ने मार्शल लॉ हटाने की घोषणा की। हालांकि पहले आस्ट्रेलियाई मानवाधिकार प्रतिनिधि ने, जिन्होंने जुलाई 1991 में चीन और तिब्बत का दौरा किया था, पाया किः "मार्शल लॉ 1 मई 1990 से हटाने की घोषणा की गई है जो नाममात्र है, मार्शल लॉ अभी भी जारी है।" एमनेस्टी इन्टरनेशनल ने अपनी 1991 की रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की है और कहा है, "पुलीस और सुरक्षा बलों ने बिना मुकद्दमें के मनमानी गिरफतारी और नज़रबंदी की व्यापक शक्तियां बरकरार रखी हैं।"[91]

चीन ने तिब्बत के सम्मिलित होने की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, 10 अप्रैल 1991 को 146 "अपराधियों" को गिरफ्तार किया था, इसके बाद सार्वजनिक सजा रैलियों में अधिक गिरफ्तारियों की घोषणा की गई थी। समारोह के दिन, पूरे ल्हासा को कर्फ्यू के अधीन रखा गया था।

फरवरी 1992 के प्रारंभ में अचानक एक कार्यवाही में दस चीनी कार्मिकों के दलों द्वारा ल्हासा में तिब्बतियों के घरों पर छापे मारे गए और जिनके

90 तांग डैक्सियन, ल्हासा में घटनाएं, 2–10 मार्च 1980

91 एमनेस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट 1991, एमनेस्ट्री इंटरनेशनल 1992,64

पास कुछ भी विनाशकारी, जिसमें परमपावन दलाई लामा के फोटोग्राफ, भाषणों और उपदेशों के टेप और किताबें भी सम्मिलित थीं, पाया गया उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। दो सौ से अधिक तिब्बती गिरफ़्तार किये गए।

उपलब्ध रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि 27 सितम्बर,1987 से 1993 के अंत तक समस्त तिब्बत में विभिन्न आकारों के 200 से अधिक प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। मार्च, 1989 में चीन की खूनी कार्यवाही के बावजूद भी 24 मार्च 1993 को बहुत सारे तिब्बती दुबारा गलियों में निकल आये। प्रत्यक्षदर्शियों जिसमें पर्यटक भी शामिल थे, के अनुसार, प्रदर्शनकारियों की संख्या 10,000 से अधिक थी। प्रदर्शन जो पूरे दिन जारी रहा शाम को जब प्रदर्शनकारी घर जा रहे थे क्रूर बल से कुचल दिया गया।

बीजिंग ओलम्पिक्स और तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति (2008) के दौरान व्यापक अशांति

वर्ष 2008 तिब्बत के लिए ऐतिहासिक वर्ष था। आगामी 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के कारण चीन अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहने के साथ ही, 10 मार्च 2008 को तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की 49वीं वर्षगांठ पर ल्हासा में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन के कारण भी विश्व का ध्यान चीन द्वारा तिब्बत के भीतर होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन और तिब्बती लोगों के न्याय के लिए संघर्ष की ओर आकर्षित हुआ।

2008 के विद्रोह व्यापक थे जो ल्हासा से बाहर तक केंद्रीय तिब्बत के बाहरी तिब्बती क्षेत्रों तक फैल चुके थे। अनुमान लगाया जाता है कि इस समयावधि में 300 प्रदर्शन हुए जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों से तिब्बतियों ने भाग लिया जिसमें आम आदमी, किसान, खानाबदोश तथा छात्र भी शामिल थे।

10 मार्च को द्रेपुंग मठ के 300 भिक्षुओं ने ल्हासा में बारखोर की ओर स्मृति प्रदर्शन की अगुवाई की। वे तिब्बत की आज़ादी और उन सभी भिक्षुओं की तत्काल रिहाई की मांग कर रहे थे जिन्हें मनमाने ढंग से नज़रबंद किया है। जब प्रदर्शनकारियों को पीपलज़ सशस्त्र पुलिस की भारी टुकड़ी ने रोका तो प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए और परमपावन दलाई लामा की दीर्घायु के लिए प्रार्थनाएं करने लगे। लगभग आधे घण्टे के बाद सेरा मठ के भिक्षुओं ने भी प्रदर्शन किया और तिब्बत की आज़ादी के लिए पर्चियां बांटने लगे और उनके हाथों में तिब्बत का प्रतिबंधित राष्ट्रीय ध्वज था। इन तीनों प्रदर्शनों

के बाद, "ल्हासा में तीन अति लोकप्रिय मठ–द्रेपुंग, सेरा और गंदेन तथा ल्हासा के मध्य में स्थित जोखांग और रामोचे मंदिर सील कर दिए गए। इसी प्रकार मठों में सभी धार्मिक पढ़ाई बलपूर्वक बंद कर दी गयी।"[92]

10 मार्च को विरोध के फैलने के बाद वर्ष 2008 में अनुमानतः 344 विभिन्न आकार के विरोध [93] प्रदर्शन हुए। कम से कम 6,500 तिब्बती गिरफ्तार किये गए और जानकारी के अनुसार 190 तिब्बतियों को नौ मास से आजीवन कारावास तक की सज़ा सुनाई गई। अधिकांश को सज़ा "राज्य की सुरक्षा को खतरा" के आरोपों में सुनाई गई। 30 वर्ष से कम आयु के सात तिब्बतियों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। लोबसांग ग्यालत्सेन तथा लोयक को 20 अक्तूबर 2009 को सज़ा सुनाई गई और अन्य पांच तिब्बतियों–तेज़िन फुंत्सोक, कंगत्सुक, पेंकयी, पेमा येशी तथा सोनम त्सेरिंग को दो साल की सज़ा के साथ मौत की सज़ा सुनाई गई। अनैच्छिक या बलपूर्वक गायब होने के एक हज़ार से अधिक मामले दर्ज किए गए।[94]

14 मार्च 2008 को चीनी सशस्त्र बल ने प्रदर्शनकारी तिब्बतियों पर गोलियां चलाईं जिससे 80 तिब्बती मारे गए।[95] उसी वर्ष 3 अप्रैल को 14 तिब्बती गोली लगने से मारे गए जब कारदेंज़ प्रांत में त्सोनगखोर मठ के निकट तिब्बती प्रदर्शनकारियों पर सशस्त्र सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध गोलियां चलायीं।[96] 16 मार्च 2008 को चीनी सुरक्षा बलों की नगबा प्रान्त में एक विरोध प्रदर्शन जिसमें हज़ारों तिब्बती शामिल हुए थे, की जवाबी कार्यवाही में आठ तिब्बती मारे गए थे।[97] मरने वालों में सबसे कम उम्र की 16 वर्षीय तिब्बती स्कूली

---

92 त्सेरिंग वोसेर, "तिब्बत अपडेट्स 2: 2–16 अप्रैल 2008" https://chinadigitaltimes.net/2008/04/tibet-update-2/.

93 सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध विभाग, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, 2008 में तिब्बत विद्रोहः कालक्रम और विश्लेषण, (धर्मशालाः सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध विभाग, 2010), 167

94 तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र, 2008 में तिब्बत का मानवाधिकार वर्षीक रिपोर्ट (धर्मशालाः तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र, 2009),5

95 "तिब्बती विद्रोह में अस्सी मारे गए", बीबीसी, 16 मार्च 2008, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7299212.stm.

96 तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र, 3 अप्रैल 2008 को चीनी सेना द्वारा तिब्बतीयों को गोली मारकर हत्या", फयूल, 17 अप्रैल 2008 http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=20724&t=1.

97 16 मार्च 2008 को सिचुआन प्रांत के नाबा काउंटी में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनो पर खूनी खराबा का फोटोग्राफिक साक्ष्य", तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र का प्रेस विज्ञाप्ति

छात्रा लहुंदुप त्सो थी।[98]

चीनी अधिकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सशस्त्र बल का उपयोग किया जिसके बाद दुनिया भर में तिब्बतियों के मूल अधिकारों के चीन द्वारा व्यापक उल्लंघन की निंदा हुई।

अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की समिति ने अपनी 4वीं आवधिक रिपोर्ट में मार्च 2008 के प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए तिब्बतियों के बारे में चीनी सरकार द्वारा सूचना प्रदान करने में विफलता पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस रिपोर्ट में ल्हासा, कार्देज़ प्रान्त और नगबा प्रांत में बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की भीड़ में पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी के कारण हुई मौतों की रिपोर्टिंग के अभाव की भी आलोचना की। इसके अलावा, अप्रैल 2008 में, सात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जनादेश धारकों के एक समूह ने चीन से "पत्रकारों और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के लिए संबंधित क्षेत्रों में अधिक से अधिक पहुंच" का भी अनुरोध किया।

आत्म-दाह विरोध प्रदर्शन

तिब्बती लोगों द्वारा बार–बार अवज्ञा दिखाने, और इन कई दशकों से अधिकारों की मांग के बावजूद तिब्बत में चीनी सरकार की भारी–भरकम नीतियां जारी हैं। वास्तव में, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पहले कार्यकाल में चीन की दमनकारी नीतियां कई तरह और अधिक खराब रहीं। फ्रीडम हाउस की 2017 की रिपोर्ट *बैटल फ़ॉर चाइनाज़ स्पिरिटः रिलीजियस रिवाइवल, रिप्रेशन एंड रेजिस्टेंस अंडर शि जिनपिंग* में कहा गया है कि" नए उपायों में आत्मदाह करने वालों को दंडित करने, पहले से मनाए जाने वाले त्योहारों की अनुमति को रद्द करने, निजी धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप कर प्रतिबंधों को बढ़ाने और अधिक सक्रिय हो कर तिब्बती बौद्ध सिद्धान्तों में जोड़तोड़ करने और धार्मिक नेताओं के चयन" सहित अन्य उपायों को अपनाया गया है,जो तिब्बत में मानवाधिकारों स्थिति और खराब कर रहे हैं।

चीन सरकार उस विचार की अभिव्यक्ति को दबा देती है जो वह है कि साम्यवादी दल के प्रतिकूल है। शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारी, चाहे वे समूह में हों या अकेले, नज़रबन्दी, बलात गुमशुदगी, हिरासत, प्रताड़ना तथा कैद प्राप्त

98 "16 मार्च 2008 को सिचुआन क्षेत्र के नाबा प्रान्त में माध्यमिक विद्यालय की छात्रा को गोली मारी," तिब्बती मानवाधिकर एवं लोकतंत्र केंद्र, 20 मार्च 2008, http://tchrd.org/middle-school-student-shot-dead-in-ngaba-county/.

करते हैं। इस दमन का एक परिणाम यह हुआ कि कुछ तिब्बतियों ने अपनी बात सुनाने के लिए खतरनाक कदम उठाए। 2009 में आत्म–दाह विरोधों की एक लहर तिब्बत में चली जो आज तक जारी है। कम से कम 152 तिब्बतियों ने तिब्बत के भीतर तिब्बत में चीनी राज के खिलाफ विरोध स्वरूप खुद को आग लगा दी। आत्म–दाह करने वाले तिब्बत की आज़ादी और परमपावन दलाई लामा की वापसी की मांग करते थे। लेकिन इन मांगों के बदले अपराधीकरण, गिरफ्तारी और आत्म–दाह करने वालों उनके परिवारों और दोस्तों को जेल मिलती है। आत्म–दाह विरोध प्रदर्शनों को रोकने के प्रयासों में विभिन्न नियमों को जारी किया गया है।

इस रिपोर्ट के पहले अध्याय में स्वतंत्रता के लिए परम पुकार का विवरण दिया गया है।

तिब्बत के राजनैतिक कैदी

चीन के संविधान तथा आपराधिक कानून में गैरकानूनी तलाशी, मनमाने ढंग से नज़रबन्दी, और नागरिकों की गिरफ्तारी निषिद्ध है। उदाहरण के लिए संविधान की धारा 37 में कहा गया है" गैरकानूनी नज़रबन्दी या अन्य तरीकों से व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करने या उस पर प्रतिबंध निषिद्ध है, और किसी नागरिक या व्यक्ति की गैरकानूनी तलाशी प्रतिबंधित है।" फिर भी चीन की सरकार ने "सामाजिक व्यवस्था" बनाये रखने की आड़ में इन संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों के उल्लंघन के लिए कई तरीके लागू किये हैं।

2016 की मानवाधिकार वॉच रिपोर्ट *रेलेंटलेसः डिटेंशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ तिबेतन्स अंडर चाइनीज़ "स्टेबिलिटी मेन्टेन्स" कैंपेन* के अनुसार उन्होंने 500 मामलों का विश्लेषण किया,"2013–2015 से तिब्बतियों की नज़रबन्दी या मुकदमों के सभी मामले राजनैतिक अभिव्यक्ति या सरकारी नीतियों की आलोचना–'राजनैतिक अपराध' के थे। तिब्बतियों को प्रायः "राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने" या"राष्ट्र के स्थायित्व को खतरा पहुंचाने के अभियान के अंतर्गत इन आरोपों में गिरफ्तार कर सज़ा दी जाती है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि 2008 से 2012 तक, औसत रूप से प्रति वर्ष 61 गिरफ्तारियां की गयीं, कुल मिला कर "राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा" के अपराध में तार और

किंगहाई में औपचारिक रूप से 304 गिरफ्तारियां की गईं।[99]

इसके अतिरिक्त, यातना को कैदियों के लिए पूछताछ की प्राथमिक विधि माना जाता है। चीन द्वारा यातना के विरुद्ध संयुक्तराष्ट्र की सन्धि के अनुसमर्थन ने भी इस वास्तविकता को नहीं बदला। "2015 में अत्याचारों पर चीन के रिकॉर्ड की समीक्षा में, संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर ने अपनी जेलों में यातना के बड़े पैमाने पर उपयोग को समाप्त करने के लिए और सभी गुप्त जेलों को बंद करने का चीन से आग्रह किया; उन्होंने भारी संख्या में जेलों में होने वाली मौतों की पर भी गहरी चिंता व्यक्त की।

चीन किसी भी राजनीतिक कैदियों को पकड़े रखने या प्रचुर मात्र में प्रमाण के बावजूद यातनाओं के आरोपों का खंडन करता रहा है। चीनी अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अत्याचार और घिनौने तरीकों और उपकरणों का वर्णन उनके बहुत सारे पूर्व कैदियों द्वारा किया गया है। यातना के इन साधनों में बिजली के डंडों के साथ झटके; लोहे की छड़ों से पिटाई;राइफल के पिछले भाग और कील लगी छड़ों से पिटाई, लाल–गर्म फावड़ियों से शरीर गोदना; कैदियों के ऊपर उबलता हुआ पानी डालना,;कैदियों को उल्टा लटकाना या अंगूठे बांध कर छत से टांगना; जूतों से मारना, कैदियों पर क्रूर कुत्ते छोड़ना; अत्यधिक तापमान के संपर्क में रखना; नींद, भोजन और पानी की कमी; लंबे समय तक ज़ोरदार" थकान भरा कार्य"; दीर्घकालीन एकान्त कारावास; यौन हिंसा और उत्पीडन और अत्याचार तथा मृत्यु की धमकी सम्मिलित है।

2018 में[100] तिब्बत से मनमानी गिरफ्तारियों, नजरबंदी तथा अत्याचार की रिपोर्ट आती रही।

इस वर्ष 20 सितम्बर को, 41 वर्षीय शोनू पाल्देन की लम्बी बीमारी के बाद मृत्यु हो गयी जो कारावास के दौरान निरंतर अत्याचार का परिणाम थी। शोनू को 18 जून 2012 को 2008 के सामूहिक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।

---

99 अथकः चीन के स्थिरता मेंटेनेंस अभियान के तहत तिब्बतीयों का अवरोध और अभियोजन करना", ह्यूमन राइट्स वॉच, 22 मई 2016 https://www.hrw.org/report/2016/05/22/relentless/detention-and-prosecution-tibetans-under-chinas-stability-maintenance.

100 लिखने के समय, 16 अक्टूबर 2018

उसे दो महीने से अधिक समय तक, कनलो (चीनीःगन्नन) तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र, गांसु प्रांत, जो पारंपरिक रूप से तिब्बत के अमदो क्षेत्र का हिस्सा रहा था, के मांडू प्रांत में अवैध रूप से नज़रबंद रखा गया था। उसे बाद में मार्च 2008 में मांचू प्रान्त में विरोध प्रदर्शनों को फैलाने की सज़ा के रूप में दो वर्ष और नौ मास के कारावास की सज़ा सुनाई गई लेकिन 24 जुलाई 2013 को विभिन्न बीमारियों के कारण सज़ा पूरी करने से पहले ही उसे छोड़ दिया गया।

27 जनवरी 2018 को एक 51 वर्षीय भिक्षुणी तथा एक भूतपूर्व राजनैतिक कैदी जेल में अत्याचार के कारण बीमारियों से मृत्यु को प्राप्त हुए। भिक्षुणी की 1993 में ल्हासा में एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन में भाग लेने पर सात वर्ष के कारावास के दौरान भारी सिरदर्द सहित कई और बीमारियां हो गईं थीं। कारावास में, नगवांग त्सोमो के साथ अत्याचार और अभद्र व्यवहार किया गया और उसकी रिहाई के बाद उसे ठीक तरह से उपचार प्राप्त नहीं हुआ। उसका स्वास्थ्य पिछले साल और अधिक खराब हो गया, नगवांग त्सोमो फेनपो लहुंदरुब प्रान्त, ल्हासा के अस्पताल में उपचार की प्रतीक्षा में अस्पताल के कॉरिडोर में मृत्यु को प्राप्त हुई। रेडियो फ्री एशिया (आरएफए) की रिपोर्ट के अनुसार 28 जनवरी 2018 को तिब्बत की राजधानी ल्हासा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद लोद्रो ग्यात्सो, अका सोगकर लोद्रो" पुनः पुलिस हिरासत से लापता"हो गए। लोद्रो ग्यात्सो के परिवार वालों को शक था कि उसे पुनः विरोध प्रदर्शन के बाद चीन के अधिकारियों द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया होगा। इससे पहले भी उसे आत्महत्या और राजनैतिक सक्रियता के आरोप में बीस साल से अधिक के लिए जेल में रखा गया था। एक वर्ष तक एकांत में रखने के बाद,10 जनवरी,2018 को किंगहाई, सीलिंग में त्सोजंग इंटरमीडिएट कोर्ट ने, 55 वर्षीय पत्रकार और पूर्व राजनैतिक कैदी त्सेगोन ग्यात्सो को" अलगाववाद" उकसाने के आरोप में तीन साल की सज़ा सुनाई। मानवाधिकारों और प्रजातंत्र पर तिब्बती केंद्र (टी सीएच आर डी) ने रिपोर्ट की थी कि त्सेगों ग्याल को कोई भी कानूनी सहायता या निष्पक्ष मुकदमें तक पहुंच प्रदान नहीं की गई। मनमानी नज़रबन्दी पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यदल ने उसकी नज़रबन्दी पर सवाल उठाए लेकिन उन्हें चीन की सरकार से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

द्रागो मठ के एक भूतपूर्व भिक्षु, गेशे त्सेवांग नामग्याल को जिसे राजनैतिक विरोध प्रदर्शनों के लिए छः वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी, जेल में पिटाई

के बाद टांगों में स्थायी चोटों के कारण रिहा कर दिया गया था। उसे 24 जनवरी 2018 को रिहा किया गया था परन्तु सूत्रों के अनुसार वह अब टांगों में चोटों के कारण सामान्य रूप से चलने में असमर्थ है। उसे जनवरी 2012 में द्रागो प्रान्त में एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन में भाग लेने पर गिरफ़्तार किया गया था।

धर्मशाला में स्थित तिब्बती पत्र तिब्बत टाइम्स के अनुसार इस वर्ष 28 मार्च को कीर्ति मठ के 36 वर्षीय भिक्षु को पांच वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई गई। उसे राजनैतिक और आत्म–दाह से सम्बंधित मामलों के आरोपों में नगबा प्रांत की बरखम (चीनीः माइरकांग) पीपलज़ कोर्ट ने सज़ा सुनाई। लोबसांग सांगये 14 अगस्त 2012 को गिरफ्तार किया गया था। और उसके तीन दिन बाद मठ में उसके साथ कमरे में रहने वाले लोबसांग कुञ्चोक को भी गिरफ्तार किया गया था।

अप्रैल 2018 में पवित्र पर्वत, सेबतरा जागयें क्षेत्र में एक चीनी खनन परियोजना के विरोध के बाद ग्रामीण नेता के "लापता" होने के बाद तिब्बत के दरिरु प्रान्त से लगभग 30 तिब्बतियों को नज़रबन्द किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, चीन के अधिकारियों ने फरवरी 2018 में पवित्र पर्वत में"स्थानीय अधिकारियों को खनन कार्यों की अनुमति देने वाले उस दस्तावेज़ पर मारकोर, व्थानग, तथा गोचु (गांव) के सभी निवासियों को बलात हस्ताक्षर करने के लिए विवश करने वाले सरकारी आदेशों को चुनौती देने पर" मारकोर गांव के मुखिया करमा को नज़रबंद किया था।[101] सरकारी अधिकारियों से बहस के दौरान उसने खनन परियोजना का पार्टी नेताओं से अनुमोदन का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा था जिसके बाद वह लापता हो गया था। बाद में जब करमा के नज़रबंद होने की ख़बर तिब्बत से बाहर फैली तो स्थानीय चीनी अधिकारियों ने मारकोर, व्थानग तथा शाकचु कस्बे के गोचु गांव के तिब्बती ग्रामीणों को नागचु प्रान्त तार के दरीरु में तत्काल बैठक के लिए बुलाया। 2 अप्रैल 2018 को बैठक के दौरान, तिब्बतियों पर करमा के लापता होने की खबर निर्वासित तिब्बती समुदाय तक पहुंचाने का शक किया गया और उन्हें "पीटा और नज़रबंद" किया गया था।

---

101 "ग्रामीण मुखिया सहित 31 तिब्बतियों को पवित्र पर्वत पर खनन के विरोध में नज़रबंद किया गया," तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र, http://tchrd.org/ village-leaderamong-31-tibetans-detained-for-opposing-mining-at-sacred-mountain/

चीन की पुलिस ने दो अन्य मामलों में कर्दज़े तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र, सरशूल प्रांत के वोपो मठ से दो भिक्षुओं को नज़रबंद किया था। लोबसांग लहुंदरुब को 9 मार्च 2018 को गिरफ्तार किया गया था जिसके विषय मे अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं, जबकि छोएचोक को 25 दिसम्बर 2017 को भी अज्ञात कारणों से गिरफ़्तार किया गया था।

टीसीएचआरडी के अनुसार, 16 अप्रैल 2018 को चीनी अधिकारियों द्वारा किंगहाई प्रान्त के तसोल्हो तिब्बती क्षेत्र के त्सांग मठ में दो तिब्बती भिक्षुओं को वी चैट (चीनी सोशल मीडिया एप्प) पर "संवेदनशील चित्र और लेख" पोस्ट करने के आरोप में नजरबंद किया गया। प्रान्त की पुलिस ने वॉइचुंग ग्यात्सो तथा एक अज्ञात भिक्षु को नज़रबंद रखा।

रेडियो फ्री एशिया के अनुसार, गनसु क्षेत्र के सांगचु प्रांत के लबरंग मठ का एक भिक्षु जिनपा ग्यात्सो 27 मार्च,2018 को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद "लापता" हो गया। "चीन राज्य के सुरक्षा अधिकारी ने जब वह लापता हुआ उसी दिन फोन पर उसे बुलाया था और उसने अपने दोस्त से कहा था कि उसे फोन आया था" एक अनाम स्त्रोत ने रेडियो फ्री एशिया को इस आशय की जानकारी दी। जिंपा ग्यात्सो को 10 दिन गुप्त नज़रबन्दी के बाद रिहा कर दिया गया था उसे उसकी गिरफ्तारी की कोई भी "वज़ह" नही बताई गई।

रेडियो फ्री एशिया के सूत्रों के अनुसार, इस वर्ष अप्रैल में 60 वर्षीय तिब्बती महिला लाहमो डोलकर, लापता हो गयी। वह कई अन्य सम्बन्धियों के साथ ल्हासा में तीर्थाटन के लिए जा रही थी और बहुत सारे' "सादे कपड़ों में सुरक्षा एजेंट"उसे पूछताछ के लिए अज्ञात स्थान पर ले गए जहां से वह गुम हो गयी। लापता होने की इस घटना की पुष्टि करते हुए, तिब्बती संसद के सदस्य नगवांग थारपा ने कहा," तब से, उसके बारे में कोई पता नहीं है, और वह लापता हो गयी है।"[102]

यू.के. आधारित फ्री तिब्बत ने रिपोर्ट दी है कि इस वर्ष 8 मई को प्रातः सोग प्रांत के त्रिदो कस्बे के 50 वर्षीय तिब्बती गांगेय को इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि चीन के पुलिस कर्मियों ने उसके पास "दलाई लामा की पुस्तकें

102 "ल्हासा जा रही तिब्बती महिला तीर्थ यात्री, चीन की पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद लापता।" रेडियो फ्री एशिया, 13 अप्रैल 2018, https://www.rfa.org/english/news/tibet/pilgrim-missing-04132018160220.html.

और कालचक्र दीक्षा की सीडी प्राप्त की थी" जो कि तिब्बत में प्रतिबंधित है।

पिछले वर्ष भी, मनमानी नजरबंदी और गिरफ्तारी के विभिन्न मामले सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन तरीकों से सामने आये। चीनी संविधान की धारा 35 यद्यपि "अभिव्यक्ति, प्रेस, इकट्ठे होने, जुलुस और जलसों की स्वतन्त्रता" प्रदान करता है, तिब्बती जो शांतिपूर्वक ढंग से अकेले प्रदर्शन कर तिब्बत की स्वतन्त्रता के लिए और परमपावन दलाई लामा की वापसी की मांग करते हैं, उन्हें यह संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं। इन प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे अज्ञात स्थानों पर हिरासत में हैं; उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को उनके बारे में उनकी चिकित्सा–स्थिति के विषय में कोई जानकारी नहीं है।

5 जनवरी 2017 को सिचुआन के सेरथर प्रांत में एक युवा तिब्बती सोनम ताशी ने अकेले विरोध प्रदर्शन किया। उसे हवा में पर्चियां उछालते तिब्बत की आज़ादी और परमपावन दलाई लामा की दीर्घायु की कामना करते हुए गलियों में घूमते देखा गया। सोनम ताशी को सेरथर प्रांत की पुलिस ले गयी और तब से उसकी कोई भी जानकारी नहीं है।

इसी प्रकार, नागबा की कीर्ति मठ के भिक्षु लोबसांग त्सुलत्रिम के बारे में भी तब से कोई जानकारी नहीं जब उसे सुरक्षा अधिकारियों ने 25 फरवरी 2017 को तिब्बत की आज़ादी के लिए एकल विरोध प्रदर्शन पर हिरासत में लिया था।

27 फरवरी 2017 को मुरा मठ अस्पताल के प्रमुख और वरिष्ठ भिक्षु 50 वर्षीय खेदुप को दूसरी बार नजरबंद किया गया। दलाई लामा तथा मानवाधिकारों पर लिखने के आरोप में उसे सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारियों ने हिरासत में लिया था।

16 मार्च 2017 को कीर्ति मठ का भिक्षु लोबसांग दारगेय तिब्बत की स्वतन्त्रता और परमपावन दलाई लामा की वापसी के लिए एकल विरोध प्रदर्शन के बाद लापता हो गया। प्रारम्भ में, लोबसांग दारगेय के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी परन्तु कई लोगों के प्रयासों के फलस्वरूप उसे नगाबा प्रांत के नवनिर्मित सेना शिविर में पाया गया। लोबसांग दारगेय पर कड़े अत्याचार किये गए। उसके परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों को संदेह है कि वह नजरबंदी के दौरान पिटाई के कारण मर गया होगा।

18 मार्च 2017 को दुकपे नाम की तिब्बती महिला को नगबा कस्बे में एकल विरोध प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया गया था। उसके वर्तमान ठिकाना अज्ञात है।

रेडियो फ्री एशिया के अनुसार 4 मई,2017 को पुलिस ने पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में कद्र्ज़े क्षेत्र के नगाग्रोंग प्रांत में ओएफुंग मठ से एक 43 वर्षीय भिक्षु को नजरबंद कर दिया। उस पर तिब्बत से बाहर अपने सम्पर्को में हाल के आत्म–दाह विरोध प्रदर्शनों की खबरें फ़ैलाने का शक था।

टीसीएचआरडी के अनुसार, जुलाई 2017 को एक भिक्षु जिसको लगभग चार मास के लिए चीन के नागचू क्षेत्र के सोग प्रान्त के "पुनः शिक्षा केन्द्र" में नजरबंद रखा गया था ने बताया कि अत्याचार और यौन–उत्पीड़न"इन पुनः शिक्षा केंद्रों"में काफी मात्रा में हैं। भिक्षु जिसकी पहचान सुरक्षा कारण ों से छिपाई गयी है, बताया कि अधेड़ भिक्षु और भिक्षुणियां, विशेष रूप से भिक्षुणियाँ, जेल अधिकारियों का निशाना बने।

कर्दज़े प्रान्त के बोरोए मठ के एक अन्यभिक्षु तुल्कु लोबसांग को 21 जुलाई 2017 को बिना कोई कारण बताए स्थानीय पुलिस द्वारा बुलाया गया। तब से तुलकु लोबसांग के ठिकाने और उसके कुशल–क्षेम के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

उसी मास 30 वर्षीय जाम्पा छोग्याल को मनमाने ढंग से नज़रबंद कर भारत में रह रहे अपने सम्बन्धी नवांग जाम्पा, जो चीनी अधिकारियों के अनुसार "दलाई गुट" का सदस्य था, के साथ सम्पर्क साधने के आरोप में पूछताछ की गई।

जून 2016 में युदरुक नियमा, नामक 40 वर्षीय तिब्बती व्यक्ति को पुलिस हिरासत में पीट कर मार डाला गया। नियमा की नज़रबन्दी का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं। वो जिन्हें रिहा कर दिया गया है उनकी औसत जीवन–अवधि भी खतरनाक रूप से कम हो गयी है। औसतन, तिब्बत का राजनैतिक कैदी रिहा होने के तीन वर्ष के भीतर जेल के दौरान गहरी चोटों और दुर्व्यवहार के कारण प्राण त्याग देता है।

रेडियो फ्री एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 21 नवम्बर 2016 को 37 वर्षीय ताशी छोयिंग "पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद गायब हो गया।"

ताशी चोएयिंग चीन द्वारा ज़ारी यात्रा–परमिट के बाद तिब्बत में अपने परिवार से मिलने जा रहा था। 2017 के अंत तक उसके परिवार और सम्बन्धियों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें रिहा किये गए साथी कैदी से मालूम हुआ कि ताशी चोएयिंग को अज्ञात आरोपों के कारण छः वर्ष की सज़ा सुनाई गई है।

दिसम्बर 2011 में, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने चीनी पुलिस तथा अर्ध–सैनिक बलों द्वारा 2008 में ल्हासा के निकट ग्रामीण घरों में सुबह के समय छापों की वीडियो फुटेज ज़ारी की। इस वीडियो फुटेज में चीनी बलों द्वारा आठ तिब्बतियों को सुबह नींद से जगा कर नज़रबन्दी के लिए पकड़ा गया है और इसमें से एक के हाथ पीठ के पीछे बांध कर उसे पीटा जा रहा है। गिरफ्तारियां 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान सामुहिक विरोध प्रदर्शनों के सम्बन्ध में की गईं।

लगभग 40 वर्ष की आयु के तिब्बती भिक्षु खेनराब थरचिन को 2008 में इसलिये पांच वर्ष की सज़ा सुनाई गई क्योंकि उसने "देशभक्ति पूर्ण पुनर्शिक्षा" सत्र में भाग लेने से इनकार कर दिया था। उन्हें 2013 में सज़ा पूरी करने पर कमज़ोरी की हालत में रिहा किया गया था। 8 अगस्त 2016 को थरचिन कारावास के दौरान जख्मों का ताब न सहते हुए अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गए थे।

हाल ही के वर्षों में तिब्बतियों द्वारा शांतिपूर्वक एकल विरोध प्रदर्शन अपेक्षाकृत बढ़ा है। इन प्रदर्शनकारियों को प्रायः परमपावन दलाई लामा के चित्र को हाथों में ले कर उनके तिब्बत वापसी की मांग या प्रार्थना मुद्रा में हाथ जोड़ कर तिब्बत की आज़ादी के लिए नारे लगाते हुए देखा गया है। कुछ मामलों में अकेले प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उनके बारे में दुबारा कुछ भी सुना नही जाता जिससे उनके सगे–सम्बन्धियों के पास उनके ठिकाने अथवा कुशल–क्षेम की जांच करने का कोई तरीका नहीं रहता। 7 जून 2016 को कीर्ति मठ के 20 वर्षीय भिक्षु लोबसांग त्सेरिंग को पूर्वी तिब्बत के नगबा प्रांत में हीरो रोड पर एकल विरोध प्रदर्शन के एकदम बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। त्सेरिंग को परमपावन दलाई लामा का चित्र अपने सिर पर उठा कर गलियों में चलते हुए देखा गया था। उसे बुरी तरह से पीटा गया था और पुलिस द्वारा अज्ञात ठिकाने पर ले जाया गया और उसकी स्थिति तथा पता ठिकाना

आज तक अज्ञात है। दुर्भाग्य से,त्सेरिंग का मामला तिब्बत में उत्पीड़न का मात्र एक उदाहरण है।

ऊंचे दर्जे के राजनैतिक कैदी : पंचेन गेदुन छोएक्यी निमा

14 मई 1995 को ही दलाई लामा ने गेधुन चोएकयी नईमा को 11वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता प्रदान की,जो दलाई लामा के उत्तराधिकारी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। घोषणा के तीन दिन के बाद चीन की सरकार ने बच्चे और उसके परिवार के सदस्यों को अगुवा कर लिया।

संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य बहुत से अवसरों पर चीन ने पंचेन लामा को नज़रबंद करना स्वीकार किया है। 20 वर्षों से अधिक तक, तिब्बतियों, उनके समर्थकों तथा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दलों ने जिसमें अत्याचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समिति, बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति, धर्म और आस्थाओं पर विशेष राजदूत और बलात गुमशुदगी पर कार्यदल सम्मिलित है, ने पंचेन लामा के ठिकाने और कुशल–क्षेम पर जानकारी मांगी पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया। पंचेन लामा विश्व के सबसे लम्बी अवधि के राजनैतिक कैदी रहे हैं।

नवम्बर 2017 में, कनेडा के विदेश मामलों के मंत्री, क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने चीन से मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त तथा धर्म और आस्था पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत को गेदुन छोक्यी नीमा को मिलने की अनुमति मांगी। मंत्री फ्रीलैंड ने चीन से "गेदुन छोक्यी नीमा तथा उसके माता–पिता के ठिकाने, शिक्षा का स्तर जो उसने पूरा किया है,तथा माता–पिता सहित वापिसी की सम्भावित तिथि" की जानकारी भी मांगी ।

गेदुन छोक्यी नीमा की 29वीं जन्मतिथि के अवसर पर तथा लापता होने की उसकी 23वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमेरिका राज्य विभाग ने 26 अप्रैल 2018 को एक वक्तव्य ज़ारी कर उसकी तत्काल रिहाई की मांग की।[103] विभागीय प्रवक्ता हीथर नौरट की 26 अप्रैल को जारी वक्तव्यः

> *25 अप्रैल को, हम 11वें पंचेन लामा, गेदुन छोक्यी नीमा का जन्मदिन मनाते हैं, जो बीस वर्ष पूर्व छः वर्ष की आयु में चीन की सरकार द्वारा अगुआ कर लिए गए थे और आज तक सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुए। अमेरिका*

103 अमिरिकी राज्य विभाग, गायब पंचेन लामा के जन्मदिन की बधाई, 26 अप्रैल 2018 https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/04/281248.htm.

की सरकार इस बात से चिंतित है कि चीनी अधिकारी तिब्बतियों की धार्मिक, भाषायी तथा सांस्कृतिक पहचान समाप्त करने के लिए लगातार कदम उठा रही है जिसमें पूजा के समुदायों, जैसे कि लारउँग ग़ार तथा याचेन ग़ार मठ, की तबाही शामिल है। हम चीन से गेदुन छोक्यी नीमा की तुरंत रिहाई की मांग करते हैं और सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को बनाये रखेंगे।[104]

अंतर्राष्ट्रीय विकास तथा विदेशी मामलों की केनेडा के सांसदों की उपसमिति ने 8 मई 2018 को हुई एक सुनवाई में केनेडा के सांसदों ने "तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र"[105] के तथाकथित प्रतिनिधिमंडल और पंचेन लामा की स्थिति पर सवाल उठाए। केनेडा के सांसद गार्नेट जीनियस की 11वें पंचेन लामा गेदुन छोक्यी नीमा के स्तर तथा तिब्बत तक अंतर्राष्ट्रीय पहुंच पर उठाई चिंताओं के उत्तर में चीन सरकार द्वारा–नियुक्त प्रतिनिधि ने उन्हीं जवाबों को दोहराया जो सरकार ने वर्षों से तैयार कर रखे थेः" (गेदुन छोक्यी नीमा) ने पहले ही वर्तमान शिक्षा प्राप्त कर ली है और वह तथा उसके परिवार वाले बाहर के वातावरण का व्यवधान नहीं चाहते। मेरा विचार है यदि कभी भी अवसर मिला, आप देखेंगे कि उसका जीवन अब अति श्रेष्ठ है।

प्रतिनिधिमंडल, गेदुन छोक्यी नीमा जो 1995 में छः वर्ष की आयु में परिवार के साथ अगुवा किये गए थे और तब से अज्ञातवास में रखे गए हैं, का ठिकाना बताने में असफल रहा।

अ) ताशी वांगचुक

तिब्बती भाषा अधिकारों के अधिवक्ता ताशी वांगचुक को 2015 में *दी न्यू यॉर्क टाइम्स* द्वारा तैयार की गई एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री में भाग लेने पर जनवरी 2016 में नजरबंद किया गया। *डॉक्यूमेंट्रीः ए तिबेतन्स जर्नी फ़ॉर जस्टिस* में, ताशी वांगचुक इस आशा से बीजिंग की यात्रा करते हैं कि वे स्थानीय युशु सरकार के अधिकारियों के खिलाफ स्कूलों में तिब्बती भाषा की कमी कर और चीनी भाषा को पढ़ाई का माध्यम बनाने पर जबकि अधिकांश छात्र तिब्बती हैं, मुकदमा दायर करेंगे। वीडियो में दिखाया गया है कोई भी

---

104 वही–

105 केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, "चीन द्वारा तिब्बत में नियुक्त' 'प्रतिनिधि' पंचेन लामा के ठिकाने की पुष्टि करने में असफल रहा, पहुंच भी अस्वीकारी," 12 मई 2018, http://tibet.net/2018/05/chinese-appointed-delegation-from-tibet-fails-to-confirm-panchen-lamas-whereabouts-denies-access/.

कानूनी–फर्म यह मुकदमा लेने की इच्छुक नही थी।

सूत्रों के अनुसार, इस वर्ष 4 जनवरी को मुकदमे की सुनवाई जो चार घण्टे चली, के दौरान, अदालत ने कहा कि ताशी वांगचुक ने "जातीय संस्कृति की हत्या" और "लिखित और बोली जाने वाली भाषा को नष्ट करने", और "तिब्बती लोगों की तिब्बती नैतिक संस्कृति के वास्तविक उपयोग को नियंत्रित करने और "कड़ी निगरानी" व किसी भी कारण "मनमानी गिरफ्तारी" पर सरकार को दोषी ठहराया और बदनाम किया है। अदालत ने घोषणा की कि ऐसे कृत्य पीआरसी के आपराधिक कानून के अनुच्छेद103 की धारा 2 के विरुद्ध हैं (.....) और उसने अलगाववाद को उकसाया है।" वांगचुक ने "अलगाववाद उकसाने" के आरोप के विरुद्ध वकालत की।

पूर्वी तिब्बत में यूलशुल (चीनीःयुशू) प्रांत की इंटरमीडिएट पीपलज़ कोर्ट में हुए 32 वर्ष पुराने मुकदमे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हुआ लेकिन कोर्ट ने अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, जर्मनी या कनाडा के कूटनीतिज्ञों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी।

ताशी वांगचुक के वकील लिआंग ज़िओजुन, के अनुसार अभियोजन पक्ष ने उनके मुवक्किल "अलगाववाद' को उकसाने के कृत्य में जानबूझ कर संलग्न थे यह सिद्ध करने के लिए *दी न्यू यार्क टाइम्स* की डॉक्यूमेंट्री को महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया। फिर भी, ताशी वांगचुक का कहना था कि वह केवल यह सुनिश्चित करना चाहता था कि तिब्बती बच्चों की मतृभाषा तक पहुंच हो, उसने तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग नही की है।

पीठासीन न्यायाधीश ने अदालत को बताया कि फैसला बाद में किसी दिन सुनाया जायेगा। चीन के वामपंथी दल द्वारा नियंत्रित अदालतों में सज़ा–दर 99 प्रतिशत से अधिक है, विशेष तौर से राजनैतिक तौर से विवादित मुकदमों में। 22 मई 2018 को उसे पांच वर्ष की सज़ा सुनाई गई।

अदालत का फैसला सुनाने के बाद केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष, डॉ. लोबसांग सांगये ने कहा," यह उनके लिये दुख भरा दिन है जो क़ानून के राज में विश्वास करते हैं, लेकिन हम उसकी रिहाई के लिए निरन्तर पैरवी करते रहेंगे।" डॉ सांगे ने पुष्टि की कि सजा अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानकों का पालन करने के चीन के दावों के भ्रम को उजागर करती है।

इस वर्ष 23 अगस्त को ताशी वांगचुक की सज़ा के खिलाफ एक अपील अदालत द्वारा रद्द कर दी गयी थी और अदालत ने सज़ा बरकरार रखी।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं ने ताशी वांगचुक की सज़ा को "घोर अन्याय" "झूठा अलगाववाद का आरोप" कह कर अस्वीकृत कर दिया और इस जनवरी के अभियोग को "राजनैतिक रूप से प्रेरित अभियोग" का नाम दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच चीन के निदेशक सोफी रिचर्डसन ने कहाः "ताशी वांगचुक का "अपराध" केवल यही था कि वह शांतिपूर्वक अल्पसंख्यक लोगों द्वारा अपनी भाषा को प्रयोग करने के अधिकार की मांग कर रहा था–एक कृत्य जिसे चीन के संविधान तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के कानूनों के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है।" इस दोष–सिद्धि पर अपने वक्तव्य में एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्वी एशिया के शोध निदेशक, जोशुआ रोसेंजवैग ने कहा," ताशी वांगचुक के खिलाफ आज का निर्णय घोर अन्याय है। उसे तिब्बती संस्कृति के व्यवस्थित ह्रास की ओर ध्यान दिलाने के लिये क्रूरता से दंडित किया जा रहा है।"[106]

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चीन को बार–बार आग्रह करके ताशी वांगचुक को पांच साल की सजा की निंदा की है। "यह अत्यंत चिंता का विषय है कि यह सजा तब सुनाई गई जब हमने दो संयुक्त पत्र उसकी तत्काल रिहाई के लिए और सभी आरोपों को रद्द करने की मांग के ज़ारी किये हैं," मानवाधिकार वेबसाइट पर उच्चायुक्त के कार्यालय की एक प्रकाशित प्रेस वक्तव्य की रिपोर्ट।[107] विभिन्न विदेशी कूटनीतिज्ञों और सांसदों ने ताशी वांगचुक की सज़ा पर गहरी चिंता जताई है। अदालत के निर्णय के बाद, यूरोपियन संसद के अध्यक्ष, केनेडा सरकार, अमेरिका राज्य विभाग, जर्मन संसद तथा फ्रांस की सीनेट ने तत्काल आवाज़ उठाई, जिसमें से कुछ ने अदालत के निर्णय की निंदा कर ताशी वांगचुक की रिहाई की मांग की। इससे पूर्व इस वर्ष, यूरोपियन संसद ने भी तत्काल प्रस्तावों को स्वीकार

106 चीनः तिब्बती कार्यकर्ता ने न्यूयॉर्क टाइम्स विडियो की विशेषता के बाद 5 साल की जेल की सजा काट दी", एमनेस्ट्री इंटरनेशनल, 22 मई 2018 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/china-tibetan-activist-unjust-sentence-nyt-video/.

107 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चाधिकारी कार्यालय, "चीनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ तिब्बती कार्यकर्ता के लिए 5 साल की जेल की सजा", 1 जून 2018 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23176.

करके चीन से ताशी वांगचुक को रिहा करने की मांग की जबकि लाटविया संसद तथा फ्रांस की सीनेट ने तिब्बती भाषा वकील के लिए" निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रिया" अपनाने का आग्रह किया।

ब) शोकजंग

द्रुकलो, एक प्रमुख तिब्बती लेखक तथा ब्लॉगर जिनका शोकजंग उपनाम था,को मार्च 2015 में राष्ट्रीय सुरक्षा पुलिस अधिकारियों ने पूर्वी तिब्बत के रेबकोंग प्रान्त के एक होटल में नज़रबंद कर लिया था। तब 17 फरवरी 2016 को उसे "अलगावाद उकसाने" पर तीन वर्ष की सज़ा सुनाई गई। उसे 19 मार्च 2018 को रिहा किया गया। शोकजंग तिब्बत की वर्तमान स्थिति पर अपने आलोचनात्मक लेखों के कारण जाने जाते थे, इनमें 2008 के विद्रोह और तिब्बती खानाबदोशों का बलात पुनर्वास भी शामिल है।

स) तेंजिन देलेक रिनपोछे

"विस्फोटों के कारण" और "राज्य को अलग करने के लिए उकसाने" के आरोपों में एक प्रमुख 65 वर्षीय तिब्बती धर्मगुरु, तेंजिम डेलेक रिनपोछे को 2002 में निलंबित मौत की सजा मिली, जिसे 2005 में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। ये आरोप सिचुआन की राजधानी चेंगदू में एक बम्ब विस्फोट से सम्बन्धित थे। तेंजिन डेलेक के कथित सह–साजिशकर्ता, लोबसांग डोनड्रुप को भी दोषी पाया गया और 26 जनवरी 2003 को उसे मार दिया गया।

ह्यूमन राइट्स वाच ने तेंजिन डेलेक रिनपोछे की गिरफ्तारी और मुकदमें से सम्बन्धित परिस्थितियों का विस्तृत विवरण प्रदान किया है, और कहा है यह अनियमितताओं से भरा हुआ था और इसमें रिनपोछे के खिलाफ किसी भी विश्वसनीय सबूत का अभाव था। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया," अदालत के निष्कर्षों और समीक्षा अदालतों या अदालतों में से जो मूल सज़ा को बरकरार रखने के मामले पर सवालों के लिए कई कारण बने हुए हैं। मुकदमा प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण था। अदालत न तो स्वतंत्र थी और न ही निष्पक्ष थी, और प्रतिवादियों को स्वतंत्र वकील तक पहुंच से भी वंचित रखा गया था। तेनज़िन डेलेक के परिवार के सदस्यों द्वारा चुने गए वकीलों को उनकी अपील पर सुनवाई में बचाव करने की अनुमति नहीं थी। यह दावा करते हुए कि राज्य के रहस्य इसमें शामिल थे, चीनी

अधिकारियों ने अभी भी मुकदमें में प्रस्तुत किए गए किसी भी साक्ष्य को जारी करने से मना कर दिया।[108]

अमेरिका, यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों सभी ने रिनपोछे की सजा की आलोचना की और उसकी तत्काल रिहाई के लिए कहा।

जनता के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता और परमपावन दलाई लामा के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए तेंजिन डेलेक रिनपोछे के मामले को व्यापक रूप से राजनीति से प्रेरित और उन्हें खामोश करने के प्रयास के रूप में देखा गया था। स्थानीय तिब्बती लोग तेंजिन डेलेक रिनपोछे को तिब्बती लोगों के आर्थिक, सांस्कृतिक धार्मिक और पर्यावरणीय अधिकारों के लिए एक पैरोकर के रूप में देखते थे।

13 साल जेल में गुजारने के बाद तेनज़ीन डेलेक की 13 जुलाई, 2015 को रहस्यमय परिस्थितियों में हिरासत में मौत हो गई। चीनी सरकार ने दावा किया कि रिनपोछे की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई है। हालांकि, तेंजिन डेलेक की भतीजी नियमा ल्हामो, जो बाद में भारत भाग गई थी, ने आधिकारिक स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया था। उसने मानवाधिकार और प्रजातंत्र पर 9वें जिनेवा शिखर सम्मेलन में गवाही देते हुए कहा था कि रिनपोछे को यातना दी गई थी और उसे जहर देकर मार दिया गया था। नियमा ल्हामो ने खुलासा किया कि अंततः जब परिवार को रिनपोछे के पार्थिव शरीर को देखने की अनुमति दी गई, तो उन्होंने देखा कि उसके होंठ काले थे। स्थानीय तिब्बतियों और अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों चीख–चिल्लाहट के बावजूद भी न तो तेंजिन डेलेक रिनपोछे के शरीर और न ही उनकी राख को उनके परिवार को बौद्धों के अंतिम संस्कारों के लिए वापस लौटाया गया था।

इ) येशी छोएडोन

तिब्बत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद मार्च, 2008 में एक सेवानिवृत्त मेडिकल डॉक्टर और दो बच्चों की मां, येशी चेओड्रोन को ल्हासा

108 मिकी स्पीगल, ट्रायल्स ऑफ ए तिब्बतन मांकः द केस ऑफ तेनजिन देलेक", ह्यूमन राइट्स वॉच, 8 फरवरी 2004 https://www.hrw.org/report/2004/02/08/trials-tibetan-monk/case-tenzindelek.

में गिरफ्तार किया गया था। उन पर कार्रवाई की सूचना साझा करने का आरोप था और उन्हें धर्मशाला में "दलाई गुट के सुरक्षा विभाग" को "खुफ़िया जानकारी" प्रदान करने के जुर्म में "जासूसी" का आरोप लगाया गया था।[109] 7 नवम्बर 2008 को ल्हासा इंटरमीडिएट पीपलज़ कोर्ट ने 52 वर्षीय ल्हासा में रामोचे के निवासी को दोषी ठहराया था और 15 वर्ष जेल की सज़ा सुनाई थी।[110] अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार जेल में आठ वर्ष बिताने के बाद, 2016 में येशी चेओद्रोन को जेल की यातनाओं के कारण बिगड़ते स्वास्थ्य की स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

आवाजाही की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध

देश के भीतर आवाजाही

> *"हवाई जहाज, ट्रेन, बस और मोटर साइकिलों पर चीनी लोग तिब्बत में तथा तिब्बत से बाहर हजारों की तादाद में घूम रहे हैं। तिब्बती खुद अपनी भूमि पर बाहरी बन गए हैं, हर मोड़ पर रोका जाता हैं।"—चीनी लेखक और विद्वान वेंग लिश्योंग।*

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 13 के प्रमुख उल्लंघन में, चीन ने तिब्बतियों के लिए अपने स्वयं के देश में स्वतंत्र आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाले नियमों की श्रृंखलाओं को सुदृढ़ किया है। तिब्बतियों को एक विशेष स्थान पर पंजीकृत होना पड़ता है और वे केवल एक विशेष स्थान पर राशन का भोजन खरीदने और निवास के हकदार होते हैं। किसी भी उद्देश्य के लिए दूसरे स्थान पर जाने से, यहां तक कि एक छोटी अवधि के लिए भी, उन्हें आधिकारिक अनुमति की आवश्यकता होती है।

पीपुल्स सशस्त्र पुलिस (पीएपी) और स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने शहरों के बाहरी इलाकों में और उनके साथ प्रमुख सड़कों और मठों पर बाधाओं और चौकियों को स्थापित किया है। इन जांच चौकियों पर, तिब्बतियों की किसी भी "अवैध" या "अलगाववादी" समझी जाने वाली वस्तु के लिए अच्छी तरह से जांच की जाती है,जिनमे परमपावन दलाई लामा के चित्र, तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज, या अन्य निषिद्ध सामग्री सम्मिलित है।

---

109 सोफी रिचार्डसन एड, "'मैने अपने आंखो से देखा', चीनी सुरक्षा बलों द्वारा तिब्बत में दुर्व्यवहार, 2008–2010", ह्यूमन रईट्स वॉच, 21 जुलाई 2010 https://www.hrw.org/report/2010/07/21/i-saw-it-my-own-eyes/abuses-chinese-security-forces-tibet-2008-2010.

110 वही –

ल्हासा रेलवे स्टेशन पर, तिब्बतियों के लिए गंभीर रूप से प्रतिबंधात्मक प्रवेश आवश्यकताओं से गुजरना अनिवार्य है। तिब्बती यात्रियों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहां उनमें से प्रत्येक को स्थानीय गारंटर प्रस्तुत करना पड़ता है, यह नियम गैर–तिब्बती यात्रीके लिए लागू नहीं होता है, जो ट्रेन स्टेशन से अपने वांछित गंतव्यों के लिए स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। ल्हासा की अपनी यात्रा के दौरान, बीजिंग–की लेखिका वोएसर ने बताया कि चीनी अधिकारी तिब्बतियों के पहचान पत्रों की जांच कर रहे थे, जो उसके साथ एक ही ट्रेन में आए थे, जबकि चीनी आगंतुकों को उसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना था। पहचान–पत्र बाद में भी ल्हासा के आसपास के सभी जांच–केंद्रों पर स्कैन किए जाते हैं ताकि तिब्बती यात्रियों पर नजर रखी जा सके और शहर के कुछ भागों तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित किया जा सके।

कुछ मामलों में, तिब्बतियों को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से आने–जाने के लिए कई सरकारी कार्यालयों से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। कई तिब्बती ऐसे परमिट प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करने की शिकायत करते हैं। इससे न केवल तिब्बतियों के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में पवित्र धार्मिक स्थलों के लिए तीर्थयात्रा करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि नेपाल के रास्ते से भारत के लिए सड़क–यात्रा में भी बाधा पहुंचती है जिस पर विस्तार से आगे चर्चा की गई है। इसके अलावा, ल्हासा की यात्रा करने वाले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बाहर के तिब्बतियों ने यह भी रिपोर्ट किया कि वहां के अधिकारियों ने उन्हें अपने राष्ट्रीय पहचान पत्रों को जमा करने और अपनी योजनाओं को दैनिक आधार पर अधिकारियों को विस्तार से सूचित करना आवश्यक बताया है। ल्हासा के पोटाला महल में तीर्थयात्रा के बाद, एक अनाम व्यक्ति ने अपने अनुभव का वर्णन करते हुए कहा, "खिड़कियों की तुलना में अधिक निगरानी कैमरे हैं, लामाओं से अधिक सैनिक,और बोधिसत्वों से अधिक चूहे।"[111]

विदेश यात्रा

"एक तिब्बती के लिए स्वर्ग में जाने की तुलना में पासपोर्ट प्राप्त करना कठिन

111 त्सेरिंग वोसेरः भारत में बौद्ध शिक्षाओं में भाग लेने के बाद ल्हासा में तिब्बतीयों का सोच बदलना। हइस पीक्स एंड प्युअर अर्थ, 28 मई 2012 https://highpeakspureearth.com/2012/brainwashed-in-lhasa-after-attending-buddhist-teachings-in-india-by-woeser/.

है। यह उन" तरजीही नीतियों "में से एक है जो हमें तिब्बतियों को (चीन की) केंद्र सरकार द्वारा दी गई है।" एक तिब्बती ब्लॉगर द्वारा चीनी भाषा–वेबसाइट पर पोस्ट किया है।

इन वर्षों में, ह्यूमन राइट्स वॉच (एच आर डैब्ल्यू) ने विस्तृत जानकारी प्रदान की है कि कैसे तिब्बती लोग अन्य चीजों के साथ–साथ पासपोर्ट प्राप्त करने में कड़े भेदभावपूर्ण उपायों सहित आवाजाही की बुनियादी स्वतंत्रता पर नियमित रूप से इंकार प्राप्त करते हैं। एचआरडब्लू की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, चमदोह प्रान्त में, जिसकी आबादी 650,000 है, वर्ष 2012 में केवल दो पासपोर्ट जारी किए गए थे।[112] रिपोर्ट *वन पासपोर्ट, टू सिस्टम* में आगे बताया गया है कि एक 2012 के बाद से, चीनी अधिकारियों ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पंजीकृत निवासियों के बिना बदले सभी साधारण पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं–जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक तिब्बती हैं।[113]

कई तिब्बती नए पासपोर्ट प्राप्त करने या वर्तमान पासपोर्टों को नवीनीकृत करने में कठिनाइयों की निरन्तर रिपोर्ट कर रहे हैं। सूत्रों की रिपोर्ट है कि तिब्बती और अन्य अल्पसंख्यकों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अन्य चीनी नागरिकों की तुलना में अधिक व्यापक दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ते हैं। तिब्बतियों के लिए, पासपोर्ट आवेदन में वर्षों लग सकते हैं, और अक्सर अस्वीकृति में समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए रिश्वतखोरी का सहारा लेना पड़ता है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में, एक शोधार्थी को विभिन्न मानक आवश्यक दस्तावेजों के अलावा पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों से हस्ताक्षर युक्त लगभग सात टिकट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

भारत की यात्रा के इच्छुक तिब्बतियों को पासपोर्ट हासिल करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मानवाधिकार प्रथाओं पर अमेरिकी राज्य विभाग की 2016 की प्रांतीय रिपोर्ट में कहा गया है कि "तिब्बतियों और अन्य अल्पसंख्यकों को चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अन्य चीनी नागरिकों की तुलना में अधिक व्यापक प्रलेखन

---

112 "वन पासपोर्ट, टू सिस्टम। तिब्बतियों और अन्य लोगों द्वारा विदेश यात्रा पर चीन का प्रतिबंध" ह्यूमन रईट्स वॉच, 13 जुलाई 2015 https://www.hrw.org/report/2015/07/13/one-passport-two-systems/chinas-restrictions-foreign-travel-tibetans-and-others.

113 वही–

प्रदान करना पड़ता है।"[114] रिपोर्ट के अंत में लिखा है:

तिब्बतियों के लिए पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में वर्षों लग जाते हैं जो अंत में अस्वीकृति में समाप्त होती है। बहुत से तिब्बतियों ने रिपोर्ट दी है कि वे पासपोर्ट केवल पर्याप्त मात्रा में रिश्वत देने के बाद ही प्राप्त कर सके। तिब्बतियों को भारत में धार्मिक, शैक्षणिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए भ्रमण में भारी कठिनाईयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है।व्यक्तिगत लोगों ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा चीन वापिस आने के बाद उनके पासपोर्ट रद्द करने की घटनाओं की भी रिपोर्ट दी है।[115]

भारत में 2017 के कालचक्र के दौरान यात्रा प्रतिबंध

कई तिब्बतियों ने 2017 कालचक्र समारोह, एक तिब्बती धार्मिक अनुष्ठान जो परमपावन दलाई लामा के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, के लिए कानूनी रूप से भारत की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने में वर्षों का समय बिताया था। चीनी सरकार ने श्रद्धालुओं को वहां यात्रा करने से रोकने के लिए गंभीर यात्रा प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।

2017 की अपनी रिपोर्ट में, चीन पर अमेरिकी कांग्रेशनल–कार्यकारी समिति ने कहा:

चीन के तिब्बती क्षेत्रों के अनुमानित 7,000 तिब्बती तीर्थयात्रियों ने जनवरी, 2017 की शुरुआत में बोधगया, भारत में दलाई लामा द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण धार्मिक शिक्षण में भाग लेने का प्रयास किया। नवम्बर 2016 में चीनी अधिकारियों ने पासपोर्ट जब्त कर लिए, धमकियां जारी की और तिब्बतियों को आदेश दिया जो पहले ही भारत और नेपाल की यात्रा शुरू कर चुके थे, वापिस लौट आयें जो धार्मिक स्वतंत्रता और आवाजाही के अधिकारों का उल्लंघन था।[116]

इसके अलावा नेपाल में ट्रैवल एजेंसियों को चीन से एक ट्रैवल एडवाइजरी सर्कुलेशन मिला, जिसमें सभी ट्रैवल एजेंसियों और एयरलाइंस को जनवरी

114 अमिरिका राज्य विभाग, लोकतंत्र ब्यूरो, "मानवाधिकार और श्रम, 2016 की मानवाधिकार प्रथाओं पर देश की रिपोर्ट–चीन https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2016humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_%20id=265330&year=2016#wrapper.

115 वही–

116 "चीन पर कांग्रेस–कार्यकारी आयोग का वार्षिक रिपोर्ट– 2017", 5 अक्टूबर 2017 https://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2017-annual-report.

तक की सभी बुकिंग को रद्द करना था।[117]

कुछ उदाहरणों में, गुआंगज़ौ और कुनमिंग में हवाई अड्डों पर अधिकारियों ने कथित तौर पर तिब्बतियों के पासपोर्ट उनके आगमन पर फाड़ डाले। इन तीर्थयात्रियों को 1 से 15 जनवरी के बीच वापस जाने के लिए मजबूर किया गया था, और जो भी ऐसा करने में विफल रहा, उसके लिए सब्सिडी और नौकरी के नुकसान सहित गंभीर परिणाम सामने आए।[118]

29 मई 2018 को जारी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता में, अमेरिकी विदेश विभाग ने चीन को फिर से चिंता के देश के रूप में सूचीबद्ध किया।

रिपोर्ट में तिब्बती लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और अभ्यास पर राज्य के व्यापक हस्तक्षेप और प्रतिबंधों पर प्रकाश डाला गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रिपोर्ट में कहा है: "चीन में, सरकार अपने धार्मिक विश्वासों का पालन करने के लिए फालुन गोंग के सदस्य, उइघुर मुस्लिम और तिब्बती बौद्ध सहित हजारों लोगों को यातना, हिरासत और जेल में डाल दिया जाता है।"[119]

व्यापक राज्य निगरानी

"सभी गांव किले बन जाते हैं, और हर एक चौकीदार है।" चीन के ग्रिड प्रबंधन टीमों द्वारा प्रयुक्त अधिकारिक नारा।

फ्रीडम हाउस की *फ्रीडम इन द वर्ल्ड* रिपोर्ट 2018 में तिब्बत को सीरिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे कम आज़ादी वाले देश के रूप में स्थान दिया गया है।[120] तिब्बत में स्वतंत्रता की गंभीर कमी को चीन सरकार की व्यापक सीमा और निगरानी की पहुंच से बल मिला है जो तिब्बतियों को

117 अनिल गिरि और संगम प्रसेनः "चीन ने नेपाल के लिए यात्रा प्रतिबंध जारी किया", काठमंडू पोस्ट, 24 दिसम्बर 2016 http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2016-12-24/china-issues-travel-restriction-to-nepal.html.

118 "चीन के हवाई अड्डों पहुंचने पर कालचक्र पूजा से आये तिब्बतीयों का पासपोर्ट फाड डाला", वॉयस ऑफ अमरिका, 24 जनवरी 2017। https://www.voatibetanenglish.com/a/3692184.html.

119 अमेरिकी विदेश विभाग, "चीन (तिब्बत, हांगकोंग और मकाउ शामिल है) 2017 अंतर्राष्ट्रीस धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट" https://www.state.gov/documents/organization/281058.pdf. 122 "विश्व में आज़ादी 2018", फ्रीडम हाउस, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018.

120 वही

व्यक्तिगत रूप से उनकी निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करता है।

2011 में तिब्बतियों की सरकार द्वारा निगरानी तेज हो गई, जब चीन ने "सामाजिक स्थिरता अनुरक्षण" के लिए संदर्भित "ग्रिड सिस्टम" को प्रारम्भ किया था।[121] ग्रिड सिस्टम का उद्देश्य "संभावित परेशानी पैदा करने वालों" की पहचान और निकट निगरानी की सुविधा प्रदान करना है और प्रत्येक क्षेत्र के भीतर तैनात सामुदायिक कर्मचारियों से वास्तविक जानकारी लेना है। निवासियों की हर आवाजाही पर निगरानी कार्यालयों में स्क्रीन द्वारा की जाती है और स्मार्टफ़ोन से लैस ग्रिड स्टाफ सदस्यों द्वारा जियो–टैग की गई तस्वीरों को अपलोड कर कार्यालयों को दी जाती है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा कस्बों और शहरों को छोटे उप–मंडलों में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए, चेनगगुआन जिला, जिसमें ल्हासा और इसके आस–पास का अधिकांश क्षेत्र शामिल है, को चीनी अधिकारियों द्वारा 175 मंडलों में विभाजित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक निगरानी से बच न जाए।

इस प्रणाली के तहत, चीन की सरकार ने सामान्य तिब्बतियों के दैनिक जीवन की निगरानी के लिए उच्च–तकनीक वाले उपकरणों से युक्त "600 सुविधा पुलिस–चौकियों" का निर्माण किया, जिसमें क्षेत्र के "विशेष समूहों"–पूर्व कैदियों और भारत से लौटे तिब्बतियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।[122]

अपनी रिपोर्ट में *चाइनाः नो एंड टू तिब्बत सर्वाइलियानस प्रोग्राम,*[123] में ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) ने ग्रिड–सिस्टम का व्यापक अध्ययन किया। इस रिपोर्ट के अनुसार, निगरानी दल "गाँवों में तिब्बतियों से उनके राजनीतिक और धार्मिक विचारों के बारे में सवाल करना, हजारों की राजनीतिक अनुशासन के अधीन, व्यवहार की निगरानी के लिए पक्षपातपूर्ण सुरक्षा इकाइयों की स्थापना, और ऐसी जानकारी एकत्र करना शामिल है, जिस पर नज़रबंदी या अन्य दंड हो सकते हैं।" 2011 में सरकार ने क्षेत्रीय

121 "चीनः अलार्मिंग न्यू सर्विलांस, तिब्बत में सुरक्षा", ह्यूमन रईट्स वॉच, 20 मई 2013 https://www.hrw.org/news/2013/03/20/china-alarming-new-surveillance-security-tibet.

122 वही –

123 "चीनः तिब्बत निगरानी कार्यक्रम का कोई अंत नही", ह्यूमन रईट्स वॉच, 18 जनवरी 2016 https://www.hrw.org/news/2016/01/18/china-no-end-tibet-surveillance-program.

सरकार के कुल राजस्व के एक–चौथाई से अधिक की लागत से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में 5000 गांवों में से प्रत्येक में, कम से कम 21,000 पार्टी के सिपाहियों को तैनात किया।

"गहन निगरानी कार्यक्रम" चार साल के बाद समाप्त होने वाला था, लेकिन बीजिंग ने कार्यक्रम को अनिश्चित काल तक जारी रखने का फैसला किया है। एचआरडब्ल्यू के चीन निदेशक, सोफी रिचर्डसन ने कहाः "नया सामान्य नियम तिब्बतियों की स्थायी निगरानी में से एक है।"[124] ग्रिड प्रणाली न केवल तिब्बती लोगों के निजता के अधिकार को बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार को भी अन्ततः खारिज करती है।

चीन ने निगरानी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सोशल मीडिया को भी निशाना बनाया है, विशेष तौर से सरकार का ऑनलाइन स्वामित्व वाला बातचीत का मंच जिसे वी चैट कहा जाता है, को भी निशाना बनाया है। एक निजी सूत्र के अनुसारः

> *"वर्तमान में वीचैट तिब्बत में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया मंच है, और प्रत्येक वी चैट समूह में कम से कम एक चीनी खुफिया एजेंट उपस्थित है...और अब उन्होंने निर्वासित तिब्बती समूहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वे निर्वासित तिब्बती समुदाय में सूचना साझा करने पर शायद नियंत्रण कर पाएं पर वे इन सोशल मीडिया मंचों की छानबीन कर अवश्यमेव सूचना एकत्रित कर गलत सूचनाएं फैला सकते हैं।"*[125]

मई 2017 ने रेडियो फ्री एशिया ने बताया था कि "वी चैट के माध्यम से राजनैतिक रूप से संवेदनशील खबरों को मीडिया के द्वारा चीन से बाहर भेजने" के आरोप में कई तिब्बतियों को गिरफ्तार किया गया तथा हिरासत में लिया गया।[126] दो व्यक्ति, अरगया गया तथा भिक्षु लोडोरे को परम पावन दलाई लामा का 80 वां जन्मदिन मनाने के लिये बनाये गए समूह में भाग लेने पर जेल भेजा गया।[127]

---

124 वही–

125 नाम तथा सूत्र का विवरण सुरक्षा कारणों से रोक लिया गया है।

126 "चीनी पोलीस का ध्यान आत्म–दाह के बाद, तिब्बती सोशल मीडिया पर आकर्षित है", रेडिया फ्री एशिया, 30 मई 2017 https://www.rfa.org/english/news/tibet/media-05302017150250.html.

127 "दूसरा तिब्बती दलाई लामा वीचैट ग्रुप पर जेल गया", रेडिया फ्री एशिया, 26 जुलाई 2016 https://www.rfa.org/english/news/tibet/second-07262016170418.html.

सूचना तक पहुंच की कमी

"तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, जैसा कि चीन केंद्रीय तिब्बत को कहता है, में उत्तर कोरिया की तुलना में पत्रकार के रूप में जाना मुश्किल है।" वाशिंगटन पोस्ट, सितंबर, 2016।

चीन की सरकार तिब्बत में और उसके बाहर सूचना के प्रवाह को रोकने में तेजी से प्रभावी हो गई है। अमेरिकी विदेश विभाग की मानवाधिकारों पर 2016 की रिपोर्ट में कहा गया है:

चीनी सरकार ने विदेशी पत्रकारों द्वारा तिब्बती क्षेत्रों में मुफ्त यात्रा को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया।

इसके अलावा, चीनी सरकार ने विदेशी पत्रकारों से बात करने वाले, विदेश में व्यक्तियों को जानकारी देने का प्रयास करने वाले, या सेल फोन, ई–मेल या इंटरनेट के माध्यम से विरोध या असंतोष की अन्य अभिव्यक्तियों के बारे में जानकारी इधर–उधर प्रेषित करने वाले तिब्बतियों को हिरासत में लिया या परेशान किया। राजनयिकों और पत्रकारों द्वारा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के लिए कुछ दौरे जिन्हें अनुमति दी गई थी, उन पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा कड़ाई से नियंत्रण किया गया था।[128]

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरडैब्ल्यूबी) ने शी जिनपिंग को इंटरनेट केशत्रुओं' और "प्रेस स्वतंत्रता के शिकारियों" में सूचीबद्ध किया और कहा है" "शी जिनपिंग द्वारा 2012 के अंत में राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के बाद चीन ने स्वतन्त्रताओं के सम्बंध में उल्लेखनीय गिरावट देखी है।"[129] पिछले एक दशक में केवल सरकार द्वारा आयोजित दौरों अनुमति दी गई थी, और सभी को बारीकी से नियंत्रित किया गया था।[130]

128 अमिरिकी राज्य विभाग, लोकतंत्र ब्यूरो, मानवाधिकार और श्रम, "2016 के लिए मानवाधिकार प्रथाओं पर देश रिपोर्ट–चीन, तिब्बत" https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2016humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_%20id=265330&year=2016#wrapper.

129 "चीनः अभी भी पत्रकारों और नागरिकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जेल", रिपोटर्स विथाउड बॉर्डर्स, 2 जून 2017 https://rsf.org/en/news/china-still-worlds-biggest-prison-journalists-and-citizen-journalists.

130 सिमोन देनयर "उत्तर कोरिया के तुलना में तिब्बत का दौरा कठिन है। लेकिन मुझे जाने को मिला और फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग की, वशिंगठन पोस्ट, 16 सितम्बर 2016 https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/09/16/in-tibet-the-door-cracks-opens-for-foreign-media-and-then-slams-shut-again/?utm_term=.93868bf93c9b.

फ्रीडम हाउस ने *फ्रीडम ऑन दी नेट 2017* में लगातार तीसरे साल चीन को दुनिया का सबसे "सबसे खराब इंटरनेट विरोधी" कहा है, यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें देशों की ऑनलाइन तिकड़मों, विघटनकारी रणनीति का उपयोग, और राजनीतिक कारणों से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध का विश्लेषण करती है।

बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करने या यहां तक कि तिब्बत के अंदर दूसरों के साथ संवाद करने की तलाश में तिब्बतियों को गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और अन्य तिब्बती क्षेत्रों में, कभी–कभी हफ्तों या महीनों के दौरान, अशांति और राजनीतिक संवेदनशीलता के दौरान अधिकारी सेल फोन और इंटरनेट सेवाओं पर अंकुश लगाते हैं। संदिग्ध सामग्री वाले सेल फोन की खोज करने वाले अधिकारियों की खबरें सर्वदा आती रहती हैं। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और अन्य तिब्बती क्षेत्रों में कई व्यक्तियों ने अपने सेल फोन का उपयोग करने के बाद अधिकारिक चेतावनी प्राप्त करने की सूचना दी है कि सरकार जिसे संवेदनशील सूचना मानती है उसका आदान–प्रदान हुआ है।

तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र पार्टी समिति इंटरनेट सूचना कार्यालय के प्रमुख ने जोर देकर कहा है कि "इंटरनेट तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र पार्टी समिति और 14वें दलाई लामा के बीच प्रमुख वैचारिक युद्धक्षेत्र है।" अधिकारी लगातार चीन में उपयोगकर्ताओं को सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाली विदेश–आधारित तिब्बत से संबंधित वेबसाइटों तक पहुँचने से रोकते हैं। चीन से होने वाले सुव्यवस्थित कम्प्यूटिंग हैकिंग हमलों ने चीन के बाहर तिब्बत कार्यकर्ताओं और संगठनों को बार–बार परेशान किया है।

नवंबर 2017 में, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी ने एक साइबर सुरक्षा कानून पारित किया है जो अल्पसंख्यकों को असमान रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अनुच्छेद 12 इंटरनेट के उपयोग को एक राजनीतिक प्रकृति के गैर–परिभाषित अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अपराधी बनाता है, जैसे "राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना" सुरक्षा एजेंसियों को आन लाइन समग्री को नियंत्रित एवं जांज के लिए सुदृढ़ कानूनी प्रक्रिया प्रदान करता है। कुछ विश्लेषकों का मत है कि कानून के प्रावधान जैसे कि अनुच्छेद 12 असमान रूप से तिब्बतियों और जातिय "चरमपंथ का प्रचार करना", "जातीय घृणा को उकसाना," सामाजिक व्यवस्था को परेशान करना" "और" जनहित को हानि पहुँचाना।" "प्रमुख (सार्वजनिक) सुरक्षा

घटनाओं" के जवाब में कानून बड़े पैमाने पर इंटरनेट नेटवर्क बंद करने के अभ्यास को भी संहिताबद्ध करता है, जो कि तिब्बती क्षेत्रों में सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों ने कानून में स्पष्ट आधार के बिना वर्षों तक किया है। ल्हासा में 8 नवम्बर 2017 को आयोजित एक कार्य सम्मेलन ने तिब्बत क्षेत्रों के साथ तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और अन्य प्रांतों से इंटरनेट के प्रबंधन में समन्वय स्थापित करने का आग्रह किया।

निष्कर्ष

तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के सभी पहलुओं को एक अध्याय या एक किताब में शामिल करना संभव नहीं है। मानवाधिकार के मुद्दे और मामले यहाँ लिए गए हैं, चीनी शासन में तिब्बत के अंदर दमनकारी स्थिति का छोटा सा हिस्सा है। लेकिन संचार अव्यवस्था के बावजूद, तिब्बत के अंदर तिब्बती तिब्बत के बाहर सूचना भेजना जारी रखते हैं। वे महान जोखिम लेते हैं, संभवतः जिसमें अपने जीवन की कीमत भी शामिल है, इस उम्मीद में कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हस्तक्षेप करेगा और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में एक जीवन को "गरिमा और अधिकारों में स्वतंत्र और सम्मान" सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

तिब्बत में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तिब्बत में तिब्बतियों के रूप में रहने, उनकी पहचान, संस्कृति को संरक्षित करने के लिए भाषा और परंपरा, चीन सरकार के हालिया नियमो में नए परिवर्तनों के कारण तेजी के साथ सिकुड़ रही है। 19वीं पार्टी कांग्रेस के बाद अति कठिन साइबर–सेंसरशिप कानूनों को लागू करने और राष्ट्रपति पद की अवधि सीमा को कम करने से शि जिनपिंग के सत्ता में बने रहने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, यह आगामी कई वर्षों तक तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता और उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का संकेत देता है।

यह महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तिब्बत के अंदर की स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखता है, जिससे चीनी सरकार पर लोगों के अधिकारों का सम्मान करने और उन्हें बनाए रखने का दबाव बना रहता है, और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। चीन के लिए तिब्बत के लोगों के साथ काम करने के लिए अंतिम उपाय यह है कि तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति को और बिगड़ने के बजाय वह अपने संविधान में निहित कानूनों का पालन करें और स्थायी, ठोस समाधान तैयार करें।

अध्याय चार

तिब्बत में सांस्कृतिक नरसंहार

नरसंहारः शारीरिक और सांस्कृतिक

नरसंहार के अपराध के लिए रोकथाम और सजा पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन निम्नानुसार नरसंहार को परिभाषित करता हैः

वर्तमान कन्वेंशन में, नरसंहार का अर्थ निम्न में से किसी भी कार्य को, पूरे या आंशिक रूप से, एक राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक कुचक्र को नष्ट करने के इरादे से किया जाए, जैसेः

(ए) समूह के सदस्यों को मारना;

(बी) समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना;

(ग) समूह की जीवन स्थितियों को जानबूझकर पूर्ण या आंशिक रूप से क्षति पहुंचा कर उसके भौतिक विनाश के बारे में गणना करना;

(घ) समूह के भीतर जन्म को रोकने के उद्देश्य से थोंपे गए उपाय;

(च) बच्चों को जबरन एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरित करना।[131]

उपरोक्त उल्लेखित नरसंहार की भौतिक–जैविक समझ के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय कानून में यह तर्क देने के लिए वैध कानूनी आधार है कि यह शब्द एक घटक के रूप में सांस्कृतिक नरसंहार में शामिल करने के लिए पर्याप्त और व्यापक है। वास्तव में, जब 1944 में राफेल लेमकिन ने पहली बार नरसंहार शब्द गढ़ा, तो मूल परिभाषा ने सांस्कृतिक नरसंहार[132] की अवधारणा को मान्यता दी।

---

131 नरसंहर के अपराध की निवारण और क्षति पर अधिवेशन, UNGA Res. 260 (III), 9 December 1948, in force in January 1951, 78 UNTS 277.

132 लेमकीन रफयल, यूरोप में व्याप्त धुरी नियमः व्यवसाय, सरकारों का विश्लेषण, निवारण का प्रस्ताव, पब्लिकेशन ऑफ द कार्नेगी एंडॉवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय कानून विभाग, वाशिंगटन, (न्यू यॉर्कः कोलंबिया विश्वविद्यालय प्रेस, 1994)

कनाडा में राज्य–वित्त पोषित आवासीय विद्यालय प्रणाली के माध्यम से देशीय लोगों पर हो रहे अन्याय और उत्पीड़न के बारे में कनाडा में एक उल्लेखनीय अध्ययन ने सांस्कृतिक नरसंहार की यह सर्वव्यापी परिभाषा प्रदान की:

> *सांस्कृतिक नरसंहार समूह को एक समूह के रूप में जारी रखने की अनुमति देने वाली संरचनाओं और प्रथाओं का विनाश है। देश जो लक्षित समूह के राजनीतिक और सामाजिक संस्थानों को नष्ट करने के लिए निर्धारित सांस्कृतिक नरसंहार में संलग्न होते हैं वे भूमि को जब्त कर लेते हैं, और आबादी को जबरन स्थानांतरित कर देते हैं और उनकी आवाजाही प्रतिबंधित होती है। भाषाएं प्रतिबंधित कर दी जाती हैं। आध्यात्मिक नेताओं पर मुकदमा चलाया जाता है, आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए मना किया जाता है, और आध्यात्मिक मूल्य की वस्तुओं को नष्ट कर दिया जाता है। और, इस मुद्दे के लिए सबसे महत्वपूर्ण, परिवार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक मूल्यों और पहचान के प्रसारण को रोकने के लिए बाधित कर दिया जाता है।*[133]

अगस्त 2001 में, पूर्व यूगोस्लाविया (आईसीटीवाई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने कन्वेंशन के तहत नरसंहार के खिलाफ सांस्कृतिक कारकों की प्रासंगिकता को परिभाषित किया। अपने ऐतिहासिक निर्णयों में, आईसीटीवाई ने एक लक्षित समूह के सांस्कृतिक लक्षणों के विनाश नरसंहार के संबंध में मिसाल पेश की। इस सम्बन्ध में कहा गया है:

> *किसी समूह का भौतिक विनाश सबसे स्पष्ट तरीका है (नरसंहार की), लेकिन कोई भी अपनी संस्कृति और पहचान के उद्देश्यपूर्ण उन्मूलन के माध्यम से एक समूह को नष्ट करने की कल्पना कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय से अलग समूह की विलुप्त होने वाली इकाई के रूप में वह रह जाए ... (जहां) भौतिक या जैविक विनाश है अक्सर सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्ति पर लक्षित हमले होते हैं और लक्षित समूह के प्रतीक भी होते हैं, उन हमलों को जिन्हें वैध रूप से समूह को शारीरिक रूप से नष्ट करने के इरादे का सबूत माना जा सकता है।*[134]

---

133 "कनाडा का सत्य और सुलह आयोग, सत्य का सम्मान, भविष्य के लिए पुनर्विचार", मनितोबाः कनाडा का सत्य और सुलह आयोग, 2015, 1 http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Exec_Summary_2015_05_31_web_o.pdf.

134 प्रोसिक्यूटर वी. राधिसालव कृस्तिक, आईटी–98–33–टी, ट्रायल चैंबर, आईसीटीवाई, 2 अगस्त 2001, 574, 580 http://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e.pdf.

उस कानूनी मामले में यह माना गया कि पूर्व युगोस्लाविया में मुस्लिम पुस्तकालयों और मस्जिद के सर्बियाई विनाश, और सांस्कृतिक नेताओं पर हमलों में मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का इरादा स्पष्ट था।

इसके अलावा, सांस्कृतिक अस्तित्व के अधिकार को अन्य ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में मान्यता प्राप्त है, जिसमें 1948 की मानवाधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा [135]शामिल है। बाद में आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक अधिकारों (आईसीईएसआर) पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा–पत्र में इसकी पुष्टि की गई। आईसीएसआर के अनुच्छेद 1 में कहा गया है: "सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। इस अधिकार के आधार पर वे स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक स्थिति का निर्धारण करते हैं और स्वतंत्र रूप से अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाते हैं। "अनुच्छेद 15" सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के अधिकार को मान्यता देता है।"[136] नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा–पत्र (आईसीसीपीआर) भी, विशेष रूप से अनुच्छेद 1 और 27, अल्पसंख्यक सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है।[137]

आज, अंतर्राष्ट्रीय कानून काफी विकसित हो गया है और सांस्कृतिक नरसंहार की सजा के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्थाओं को लागू करने की आवश्यकता की मांग करता है।

सांस्कृतिक विनाश: केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, न्यायविदों, संयुक्त राष्ट्र और विद्वानों द्वारा प्रलेखित

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 60 से भी कम वर्षों में, हजारों वर्षों से संपन्न तिब्बती सांस्कृतिक, धर्म और पहचान को नष्ट कर दिया है।[138] तिब्बत के चीनी आक्रमण और कब्जे के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, 1949 और 1979

135 मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूएनजीए रेस. 217 (3), 10 दिसंबर 1948, अनुच्छेद 271

136 आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कानविनेंट, UNGA Res. 2200 (XXI), 16 December 1966, in force 3 January 1976, 993 UNTS, Articles 1 and 15.

137 नगरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कांविनेंट, UNGA Res. 2200 (XXI), 16 December 1966, in force 23 March 1976, 999 UNTS 171, Articles 1 and 27.

138 सातवीं सदी के बाद की गणना के आधार पर

तक 1 से 2 मिलियन से अधिक तिब्बती लोगों की मृत्यु हो गई।[139] आज, शायद ही कोई एक तिब्बती परिवार ऐसा हो, जिसके कम से कम एक सदस्य को चीनी शासन द्वारा कैद या मार न दिया गया हो।

इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स (आईसीजे) द्वारा प्रकाशित विभिन्न रिपोर्टों में तिब्बती लोगों के खिलाफ नरसंहार के कृत्यों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। 1959 की पहली रिपोर्ट दी क्वेशचन आफ़ तिब्बत एंड दी रूल ऑफ़ लॉ, के निष्कर्ष इस प्रमाण की ओर इंगित करते हैं : "(क) 1948 के नरसंहार सम्मेलन के अनुच्छेद 2 (ए) और (सी) के विपरीत कृत्यों का एक प्रथम दृष्टया मामला; (ख) एक अलग राष्ट्र और तिब्बत के बौद्ध धर्म के रूप में पूरे या आंशिक रूप से तिब्बती को नष्ट करने के लिए इस तरह के कृत्यों और अन्य कृत्यों द्वारा सिलसिलेवार इरादे का एक प्रथम दृष्टया मामला है।"[140]

1960 मे आइसेजे ने अपनी दूसरी रिपोर्ट तिब्बत एंड द चईनिस पीपुल्स रिपब्लिकः ए रिपोर्ट टू द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ ज्यूरिस्ट्स की कानूनी जांच समिति द्वारा तिब्बत पर प्रकाशित की, जिसमें पाया गया कि तिब्बतियों के खिलाफ नरसंहार के कार्य किए गए हैं ताकि उन्हें एक धार्मिक समूह के रुप में नष्ट किया जा सके।[141]

आईसीजे द्वारा तिब्बत पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के बाद, तिब्बत पर तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। सबसे पहले, 1959 में, महासभा ने चीन से "तिब्बती लोगों के मौलिक मानवाधिकारों के लिए सम्मान और उनके विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के लिए सम्मान"[142] सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। 1961 में एक दूसरा प्रस्ताव पारित किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र ने चीन को "तिब्बतियों के आत्मनिर्णय के अधिकार सहित मौलिक मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित रखने वाली प्रथाओं को रोकने की मांग की।"[143] 1965 मे महासभा ने एक तीसरा प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव

139 संदर्भ 3.1 देखें, सीटीए द्वारा संकलित जानकारी के अनुसार तिब्बत के तीनों प्रांतों में 1.2 मिलियन से अधिक तिब्बतियों की मृत्यु के तरीके पर है।

140 अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग, तिब्बत का प्रश्न और कानून के नियम, जिनेवाः अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग, 1959

141 तिब्बत पर अंतर्राष्ट्रीय जांच समिति, 1960

142 संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव संख्या 1354 (ivx), 1959.

143 संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव संख्या 1723 (ivx), 1961.

ने गंभीर चिंता व्यक्त की कि तिब्बत के लोगों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का लगातार उल्लंघन और उनके विशिष्ट सांस्कृतिक और फिर से जारी वर्चस्व के उल्लंघन पर गहरी चिंता व्यक्त की।[144]

इसी तरह, 1991 में, संयुक्त राष्ट्र के भेदभाव और अल्पसंख्यक के अधिकारों के सरंक्षण पर उप–आयोग ने तिब्बत पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें चीनी सरकार के मौलिक अधिकारों और लोगों की स्वतंत्रता के उल्लंघन की आलोचना की गई, जिससे तिब्बती लोगों के सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान को खतरा पहुंचा था। "इसने चीन से "तिब्बती लोगों के मौलिक मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का पूरी तरह से सम्मान करने का आह्वान किया।"[145]

आईसीजे ने तिब्बत पर 1977 में एक तीसरी रिपोर्ट प्रकाशित की, तिब्बतः मानवाधिकार तथा कानून का नियम, आईसीजे के सेक्रेटरी, अडामा डींग, ने इसके बारे में निम्न टिप्पणी कीः

(तिब्बत पर तीसरी रिपोर्ट) तिब्बत में बढ़ते दमन का नया दस्तावेज है, जिसमें मठों में एक 'पुनः शिक्षा' मुहीम, प्रमुख धार्मिक हस्तियों की गिरफ्तारी और दलाई लामा की तस्वीरों के सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता प्रमुख विशेषता है। तिब्बत में चीनी आबादी के हस्तांतरण के माध्यम से तिब्बती पहचान और संस्कृति के पहलुओं के लिए बढ़ते खतरे, तिब्बती भाषा का क्षरण और तिब्बत के वातावरण का ह्रास (...) रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि तिब्बती 'विदेशी अधीनता वाले लोग' हैं। 'लेकिन आत्मनिर्णय के अधिकार के पात्र होने पर भी अधिकार से वंचित हैं।"[146]

इस रिपोर्ट ने तिब्बत के अंदर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निरंतर दमन और तिब्बती संस्कृति और धर्म को खत्म करने की उसकी रणनीतिक योजना को बताते हुए कहा है :

> *तिब्बत में 1994 के बाद तीसरे राष्ट्रीय तिब्बत वर्क फोरम के प्रमुख सम्मेलन के बाद से दमन लगातार बढ़ा है, इस सम्मेलन, वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्वासित दलाई लामा के प्रभाव की पहचान की, जो तिब्बत की अस्थिरता*

144 संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव संख्या 1354 (ivx), 1965.

145 तिब्बत में स्थिति संख्या E/N.4/sub.2/91, 43 Session.

146 अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग, तिब्बतः ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ़ लॉ (जिनेवाः अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग,1997)

के मूल के रूप में तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख व्यक्ति थे, और क्षेत्र के लिए एक नई रणनीति का खाका तैयार किया। फोरम ने तेजी से आर्थिक विकास का समर्थन किया, जिसमें तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) में अधिक चीनियों का स्थानांतरण, और दलाई लामा के प्रभाव को कम करने और असंतोष पर कार्रवाई करने का अभियान शामिल था। फोरम के परिणामों में धार्मिक गतिविधि पर नियंत्रण और संभावित असंतुष्टों के दलाई लामा के अभूतपूर्व सर्वनाश के खिलाफ एक निंदा अभियान शामिल था; और गैर–राजनीतिक विरोधों का दमन बढ़ाना भी शामिल था।[147]

इसके अलावा, आईसीजे ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को "तिब्बत की दुर्दशा पर ध्यान देने और अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों पर जिन्हें रौंद दिया गया है, आगे आने की सलाह दी है।"[148] इसने तिब्बत में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में, जनमत–संग्रह के लिए कहा ताकि अपने जीवन के तरीकों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तिब्बती लोगों के विचारों पर ध्यान दिया जाए।

2013 में, स्पेन के राष्ट्रीय न्यायालय (ऑडीनसीया नेसीयोनल) ने 1980 और 90 के दशक के दौरान तिब्बत में नरसंहार करने के आरोप में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिंताओ का गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी वारंट में कई अन्य प्रमुख चीनी नेताओं के खिलाफ भी आरोप शामिल थे, जिन्होंने उस समय की अवधि में सेवाएं दीं थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति और पार्टी सचिव जिंग जेमिन; पूर्व प्रधानमंत्री ली पेंग; चीनी सुरक्षा के पूर्व प्रमुख और 1980 के दशक के उत्तरार्ध में तिब्बत में मार्शल लॉ की अवधि के दौरान पीपुल्स आर्म्ड पुलिस के लिए ज़िम्मेदार कि़याओशी; तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र चेन कुलन में पार्टी सचिव; और पेंग पे यू यून की योजना बनाने वाले परिवार के पूर्व मंत्री भी शामिल थे।

यह मामला तिब्बत में एक स्पेन में स्थित तब्बत समर्थक ग्रुप कृमाइट डी अपायो द्वारा स्पेन में तिब्बती वादी के साथ दायर किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक सिद्दांत सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र को नियोजित करता है, जिसके अनुसार देशों पर बाध्यता यह है कि गंभीर अपराधों के लिए मुकदमा चलाये, चाहे अपराध का स्थान या अपराधी या पीड़ित की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।

147 वही–

148 वही–

यह जबकि एक महत्वपूर्ण कानूनी मामला था, चीनी सरकार स्पेनिश अदालत के फैसले की निंदा करने और स्पेनिश सांसदों पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए मामले को आगे की कार्यवाही से रोकने के लिए त्वरित रही। चीन ने धमकी दी कि इस तरह की कार्रवाइयों से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को चोट पहुंच सकती है और इसके परिणामस्वरूप, स्पैनिश संसद ने अपने सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार को सीमित करने के लिए मतदान किया, जिससे स्पेन में स्पैनिश या विदेशी निवासी होने की आशंका हो। उच्च न्यायालय ने बाद में नए कानून का पालन करने में विफल रहने से मामले को खारिज कर दिया।

फरवरी 2014 में, एमेनस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने एक खुला पत्र जारी किया, जिसमें गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी स्पेन जैसे देश पर चीन के प्रभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।

तिब्बती बुद्ध धर्म के उन्मूलन के लिए हाल के प्रयासः लारूंग गार और यारचेन गार मठों का विनाश

"रहने के लिए कोई स्थायी जगह नहीं है, भिक्षु अपने दम पर शरण ले रहे हैं" –लारुंग गार के एक छात्र, जो तिब्बत से निर्वासित भारत में भाग गया था, जो वहां रहता ने सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, दिसंबर 2017 में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को बताया।

जुलाई 2016 से, चीनी अधिकारियों ने तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के दो बड़े धार्मिक संस्थानों– लारुंग गार और यारचेन गार से विध्वंस और सामूहिक निष्कासन किया है। लारुंग गार दुनिया के सबसे बड़े बुद्ध केंद्रों में से एक है और यार्चेन गार एक और मठवासी क्षेत्र है। दोनों सेरथार (ची०सेदा) और पल्यूल (ची० बैयु) प्रान्तों में स्थित हैं। कारेज़ (ची० गांजी) तिब्बती प्रान्त, चीन के सिचुआन प्रांत में शामिल है। मानवाधिकार समूहों फ्री तिब्बत और तिब्बत वॉच ने बताया है कि जुलाई 2016 के बाद से, दो भिक्षुणियों–टेरिंग डोलमा और सेमगा– ने अपने आवास में फांसी लगाकर प्राण त्याग दिए। एक दिन बाद, 20 जुलाई को, एक और भिक्षुणी रिगज़िन डोलमा ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

पंद्रह साल पहले, 18 अप्रैल,2001 को, लारुंग गार ने इसी तरह की कार्रवाई

की गयी थी। 7000 से 8000 भिक्षु–भिक्षुणियों की बस्ती को उजाड़ दिया गया और वहां 1400 भिक्षुओं और भिक्षुणियों को रहने की सीमा निर्धारित कर दी गयी। हजारों को निष्कासित कर दिया गया था। दर्जनों मठवासी आवास विहीन हो गए। केंद्र से कुछ भिक्षुणियों को कथित तौर पर 24 डॉलर देकर उनके घरेलू जिलों में वापस जाने की पेशकश की गई थी, लेकिन अतिक्रमण से बड़ी संख्या में पास के पहाड़ों में निराश्रितों को भटकने पर मजबूर किया गया।

एक अति–सम्मानित और प्रभावशाली तिब्बती बौद्ध शिक्षक और लारंग बौद्ध संस्थान के संस्थापक खेंपो जिग्मे फुंटोक को एक साल के लिए हिरासत में ले कर अज्ञातवास में रखा गया था। इसके बाद, 6 जनवरी 2004 की शाम को, खेंपो की मौत सिचुआन प्रांत के चेंगदू शहर के सैन्य अस्पताल "363" में रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई, जहां वह चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे थे। खेंपो 72 वर्ष के थे।

जून 2016 में तिब्बती बौद्ध संस्कृति को कमजोर करने और नष्ट करने के लिए सिलसिलेवार प्रयास में, चीनी अधिकारियों ने एक आठ–सूत्रीय लारिंग गार विध्वंस आदेश जारी किया, जिसमें अभ्यास करने वालों हजारों भिक्षुओं, भिक्षुणियों और जिज्ञासुओं की आवास सुविधाओं को ध्वस्त करने के लिए समय–सीमा के दिशानिर्देशों को निर्धारित किया गया था। उनके इस निष्कासन ने निवासियों की संख्या को 5000 की सरकारी–निर्धारित सीमा तक कम कर दिया। छठे तिब्बत कार्य मंच सम्मेलन और धर्म पर दूसरे राष्ट्रीय कार्य सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए, इस दस्तावेज़ में कहा गया कि विध्वंस आदेश लारुंगगार बौद्ध संस्थान के उचित विनियमन और प्रबंधन के उद्देश्य से था।

शोध रिपोर्टों और प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से ज्ञात हुआ कि संस्थान के "विनियमन और प्रबंधन" की आड़ में लारुंग गार का विध्वंस और विनाश, राजनीति से प्रेरित हैं।

20 वर्षीय लारुंग गार का निवासी, जो निर्वासन में भाग गया था, लारुंग गार में घटनाओं के प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करता है। उन्होंने चीनी अधिकारियों द्वारा 'अधिक आबादी' के कारण तथा "अपर्याप्त आवासीय और सीवरेज प्रबन्धन" के कारण का खंडन किया। इसके बजाय, त्सेरिंग ने दावा किया कि यह संस्थान का बढ़ता प्रभाव है जिससे अधिकारियों को डर लग रहा है।

एक पाश्चात्य विद्वान, जो लारुंग गार में प्रवेश पाने में कामयाब रहे, ने पुष्टि की कि महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र की ओर "अस्थायी आगंतुकों और अध्यात्मिक जिज्ञासुओं" का आकर्षण कम किया जा रहा है। छह निर्माण कंपनियों की कई विशेष बैठकें आयोजित करने के बाद, संस्थान को पर्यटन स्थल में बदलने के लिए चीन के संबंधित प्रयास शुरू हुए।

बेदखल किए गए भिक्षुओं और भिक्षुणियों को संस्थान में वापस नहीं आने या अपने गृहनगर में अपनी प्रथाओं को जारी ना रखने का वचन देते हुए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। "कुछ भिक्षुओं को उनके निष्कासन के बाद अपना वरण भी त्यागने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि कुछ भाग्यशाली अन्य मठों में शामिल होने में कामयाब रहे।"[149]

लारुंग गार का भौतिक विनाश प्रकाश में आया है जो कुल तबाही का केवल मात्र एक हिस्सा है। विध्वंस का पूर्ण प्रभाव बहुत गहरा है, इसने संस्थान के निवासियों और छात्रों को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से "गहराई से परेशान" किया है। त्सेरिंग ने कहा, "जिन लोगों को निकाला गया था, वे अवसाद और कुछ तिब्बती भिक्षुणियाँ और यहां तक कि कुछ चीनी छात्र भी बुरी तरह से अस्त–व्यस्त हो गए थे।" संचार प्रतिरोधों के बावजूद प्राप्त वीडियो फुटेज ने दुनिया भर के तिब्बतियों के बीच गहरा संकट पैदा कर दिया है। भिक्षुणियों को असहाय रूप से कराहते हुए देखा गया है क्योंकि वे अपनी साथी भिक्षुणियों को बसों में जाते हुए देखते थे जिनको अपने गृहनगर वापस भेज दिया जाता है। इनमें से कई बेदखल हुए लोगों को बलात देशभक्तिपूर्ण अभ्यास से गुजरना पड़ता है और वीडियो में तिब्बती भिक्षुणियों को सैन्य वर्दी में कपड़े पहने "चीनी और तिब्बती एक मां की संतान हैं।" गीत गाते हुए दिखाया गया है। एक अन्य वीडियो में सम्भवता लरुंग गार की विस्थापित तिब्बती भिक्षुणियों को लारुंग गार के मंच पर चीनी पॉप गीतों का प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। यह उनकी मठवासी प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन नहीं है, बल्कि अपमान का सबसे बुरा रूप है जिसका एक भिक्षुणी को सामना करना पड़ता है।

149 केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन, "वह हमें कहते थे "आकाश चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का है और जमीन भी': लारुंग गार के निवासी ने बताया," 19 दिसम्बर 2017.http://tibet.net/2017/12/they-would-tell-us-the-sky-belongs-to-the-chinese-communist-party-andso-does-the-earth-larung-gar-resident-speaks/.

लारुंग गार निरंतर कड़ी सुरक्षा में है, जहां पुलिस बलों की वर्दी और सादे कपड़ों दोनों में भारी उपस्थिति हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, विशेष पुलिस बल (पीआरसी की स्वाट इकाइयों को चीनी में टी जिंग कहा जाता है) लारुंग गार में दमन की कार्यवाही करने और डराने वाली प्राथमिक पुलिस इकाई है।

लारुंग गार को पर्यटन केंद्र में बदलने के अलावा, अगस्त 2017 में, कार्दज़ तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी की समिति ने लारुंग गार के दैनिक प्रशासन को संभालने के लिए चीनी कम्युनिस्ट सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की। स्वायत्त ने संस्था के पारंपरिक प्रमुखों के मठाधीशों की प्रशासकीय भूमिका संभालने के लिए छह चीनी कम्युनिस्ट सदस्यों की नियुक्ति की। पार्टी के सदस्यों को नियुक्त करने का निर्णय आठ–सूत्रीय प्रशासनिक आदेश के अनुसार है, जो मठ जुलाई 2016 में आदेश की धारा 7.4 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों में संयुक्त प्रबंधन सरकार को स्वीकार करने के लिए है। कम्युनिस्ट सदस्यों की नियुक्ति चीन के प्रयास को कम्यूनिस्ट सदस्यों और पर्यटक–केंद्र में परिवर्तित इस संस्थान में इसके प्रचार कार्यालय किया गया है।

अक्टूबर 2017 में, मानवाधिकार समूहों फ्री तिब्बत और तिब्बत वॉच ने, अमेरिका स्थित उपग्रह विशेषज्ञ अपोलो मैपिंग की सहायता से, उन उपग्रह चित्रों को ज़ारी किया, जिसमें बौद्ध अकादमी के विनाश के पैमाने का प्रदर्शन किया गया था। लारुंग गार के व्यापक पैमाने पर विध्वंस और भिक्षुओं और भिक्षुणियों के बाद के निष्कासन के इस सबूत ने अंतर्राष्ट्रीय संघ और कार्रवाई को आकर्षित किया। फरवरी 2017 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 34वें सत्र की पूर्व संध्या पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जनादेश धारकों के एक समूह[150] ने चीनी सरकार को बौद्ध संगठनों के विध्वंस के कानूनी आधार के बारे में और भिक्षुओं के आवासों से निष्कासित करने के लिए एक संयुक्त हस्तक्षेप पत्र को सार्वजनिक किया, इसी तरह, यूरोपीय संसद ने एक तात्कालिक संकल्प अपना कर दिसंबर 2016 में लारंग गार

150 समूह में संयुक्त राष्ट्र के छह विशेषज्ञः सांस्कृतिक अधिकारों, विशेष मानवाधिक. ार, सुरक्षित, स्वच्छ, अस्वास्थ्य कर और स्थायी पर्यावरण के अधिकार से संबंधित मानवाधिकार दायित्वों के मुद्दे; शांतिपूर्ण इकट्ठे होने और संगठन की स्वतंत्रता के अधिकारः इस संदर्भ में गैर–भेदभाव के जीवन के पर्याप्त मानक और जीवन के अधिकार के घटक के रूप में पर्याप्त आवास; अल्पसंख्यक मुद्देः और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता शामिल थे।

के विध्वंस की निंदा की।

तिब्बती बौद्ध धर्म (ज़ारी) को मिटाने के प्रयासः मठों का प्रशासन

1962 में, "लोकतांत्रिक प्रबंधन समितियों" (डीएमसी) की स्थापना तिब्बत के आसपास के मठों में की गई थी। हालांकि उनके कई सदस्य अनैतिक व्यवहार में लगे हुए थे, जैसे कि अत्यधिक शराब पीना और वेश्यावृत्ति के साथ जुड़ना, सरकार ने डीएमसी को नियंत्रित किया है, जो कि मठों के पारंपरिक प्रमुखों, मठाधीशों की प्रशासनिक भूमिका को संभालते हैं।

इन समितियों में राज्य–अनुमोदित "देशभक्त" भिक्षु और भिक्षुणियां, पार्टी कैडर और सरकारी अधिकारी होते हैं, और कुछ मामलों में "विश्वसनीय" तिब्बती अधिकारी भी होते हैं। उन्हें मठों के प्रशासन और "देशभक्ति शिक्षा" कार्यक्रम के माध्यम से नियम–कायदे थोपने की जिम्मेदारी दी जाती है और वे चीनी सरकार और तिब्बती बौद्ध मठों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। वे भिक्षुओं और भिक्षुणियों की गतिविधियों और आवाजाही पर निगरानी भी रखते हैं।

7 जुलाई 2004 को चीन की स्टेट काउंसिल द्वारा जारी धार्मिक मामलों के नियमों के तहत डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट कमेटी(डी एम सी) मठों के भीतर आवाजाही को नियंत्रित करता है, मठ की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देता है और मठ के संस्थानों पर छानबीन के अन्य साधनों को लागू करता है। मठों में डी एम सी द्वारा निगरानी के अलावा चीनी सरकार संस्था या इलाके में 'देशभक्ति शिक्षा' का प्रसार करने के लिए "कार्य दल (सरकारी कर्मियों के समूह)" गठित किये हैं। ये कार्यकर्ता विशेषतौर से प्रत्येक भिक्षु अथवा भिक्षुणियों को बलात तिब्बती इतिहास का चीनी संस्करण पढ़ाते हैं, परमपावन दलाई लामा की निंदा करते हैं और उन्हें चीन के धार्मिक कानूनों तथा प्रतिबंधों का अनुसरण करने के लिए बाधित करते हैं। इसके अतिरिक्त, डीएमसी" जांच करने, बैठकें आयोजित करने, निगरानी करने और गिरफ्तारी के लिए उम्मीदवारों की शिनाख्त करने" के विशेष कार्य के लिए मठों और भिक्षुणियों के मठों में प्रवेश कर सकते हैं।

सरकार–समर्थित ये कार्य सामुहिक रूप से धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। वे तिब्बती बौद्ध धर्म को राजनीतिक रूप से सही मायनों में चीन

का प्रतिनिधित्व करने के लिए ढालने का प्रयास करते हैं, और वे बौद्ध संस्थानों को एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्द स्थल में बदलने को मजबूर करते हैं जो सदियों पुराने पारंपरिक रीति–रिवाजों, मान्यताओं और तिब्बती बौद्ध धर्म के मूल्यों की कीमत पर कम्युनिस्ट पार्टी पर तरस करता है।

नवंबर 2015 में निर्वासन में तिब्बतियों द्वारा प्राप्त एक गुप्त दस्तावेज, मठवासी संस्थानों में दमन के एक बिल्कुल नए स्तर को दर्शाता है। धार्मिक संस्थानों की सफाई और सुधार के काम को तेज करने और गहन करने की आवश्यकता पर दरिरु प्रांत पीपुल्स सरकार की अधिसूचना (अस्थाई कार्यान्वयन के लिए)[151] इस दस्तावेज़ का शीर्षक है। यह तिब्बती मठों को चीनी सरकारी कार्यालयों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों में मठवासी आबादी में परिवर्तित करने के सिलसिलेवार प्रयासों का खुलासा करता है। दस्तावेज़ में नियमों का एक समूह होता है जो गतिविधियों की पहचान करता है जिसके माध्यम से धार्मिक संस्थानों में सुधार किया जाएगा और यह बताता है:

> *चीनी अधिकारी धार्मिक संस्थानों की सभी वित्तीय गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे, जिसमें पुर्नअवतार या वरिष्ठ भिक्षुओं को दी गयी भेंट भी शामिल हैं। चीनी अधिकारी सभी मठवासी संपत्तियों का लेखा–जोखा रखेंगे और उनके भंडारण और मरम्मत के बारे में निर्णय लेने के लिए एकमात्र अधिकार बनाए रखेंगे। हर बृहस्पतिवार को, दरीरु प्रांत में सभी धार्मिक संस्थानों के भिक्षुओं और भिक्षुणियों को राजनीतिक शिक्षा सत्रों में जरूरी भाग लेना होगा।*

तिब्बती बौद्ध धर्म पर निरंतर कार्रवाई और भी अधिक बदतर हो गई। 1994 में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने "स्थिरता और विकास" लाने के उद्देश्य के साथ "तिब्बत पर तीसरा राष्ट्रीय कार्य मंच" का आयोजन किया। लेकिन वास्तव में, मंच ने" मठों और भिक्षुणियों के मठों के बेलगाम निर्माण के साथ–साथ समाप्त भिक्षुओं/भिक्षुणियों की बेलगाम भर्ती, "पर चर्चा की और कहा कि"हमारे और दलाई गुट के बीच संघर्ष न तो धार्मिक आस्थाओं का मामला है, और ना ही स्वायत्तता का प्रश्न है, यह हमारे देश की एकता और

151 "दस्तावेज़ संकट तिब्बत देश में राज्य–स्वीकृत धार्मिक दमन के गहनता का प्रस्ताव", तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र, 9 नवम्बर 2015 http://tchrd.org/document-exposes-intensification-of-state-sanctioned-religious-repression-in-troubled-tibetan-county/.

अलगावाद के विरोध का मामला है ... यह जीवन और मृत्यु का संघर्ष है।[152]

इसने यह सुनिश्चित किया कि तिब्बत में अस्थिरता की जड़ "दलाई गुट की विभाजनवादी गतिविधियाँ" हैं, जो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ने का जिक्र करती हैं। हालांकि, परमपावन दलाई लामा ने स्वयं कहा है कि वे स्वतंत्रता नहीं मांग रहे हैं, और 1980 के दशक के उत्तरार्ध से मध्य मार्ग नीति को बढ़ावा दिया है, जो चीन के पीपल्स रिपब्लिक की वास्तविक स्वायत्तता की रूपरेखा चाहता है। (इस रिपोर्ट के अध्याय नौ में इस दृष्टिकोण का विस्तार से विश्लेषन किया जाएगा)। फोरम ने तिब्बती बौद्ध धर्म पर प्रतिबंधात्मक उपायों को लागू किया, जैसे कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों की संख्या को सीमित करना क्योंकि चीन की सरकार ने पाया कि मठ के संस्थानों के सदस्यों ने सबसे अधिक स्वतंत्रता का विरोध किया।

1994 में फोरम के बाद, चीन ने अपने दलाई लामा अभियान को सख्ती से लागू किया। दलाई लामा के चित्र को सरकारी अधिकारियों के निजी घरों में प्रतिबंधित कर दिया गया था और बाहरी स्थानों और सार्वजनिक बाजारों में प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन वर्षों में दलाई लामा के प्रति चीनी शत्रुता बढ़ गई क्योंकि अधिकारियों ने न केवल उनकी धार्मिक शक्ति को कम करने के लिए एक अभियान चलाया, बल्कि कम करने के लिए कड़ाई से निंदा भी की।

मोनलम (प्रार्थना) समारोह पर प्रतिबंध

ल्हासा जोखांग में मोनलम छेनमो(महान प्रार्थना उत्सव) के आयोजन पर 1960 के बाद रोक लगा दी गयी थी और 1986 तक इसका आयोजन नही किया गया, जब तक कि 10वें पंचेन रिंपोछे ने चीन की सरकार को मोनलम छेनमो के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के विषय में नहीं बताया। तब,1989में ल्हासा में सामुहिक विरोधों और प्रदर्शनों के बाद 1990 में इस पर पुनः रोक लगा दी गयी।

शिक्षा और तिब्बती भाषा में क्षति और विनाश

देश भक्तिपूर्ण शिक्षा

---

152 Dus Rabs Gsar par Skyod Pa'i Gser Zam (नए युग के लिए अग्रणी एक गोल्डन ब्रिज) 20–23 जुलाई 1994 में बीजिंग में आयोजित तिब्बत पर तीसरे कार्य मंच के बाद जारी एक दस्तावेज।

देश भक्तिपूर्ण पुर्नशिक्षा या देशभक्ति शिक्षा, प्रारम्भ में 1996 में तिब्बत में "कड़ी मेहनत" अभियान के रूप में चीन में अपराध और भ्रष्टाचार को लक्षित कर शुरू की गई थी। मुहिम उसके बाद फैलती जा रही है और आज सारा क्षेत्र, यहां तक कि तिब्बत के दूरस्थ भाग में भी यह मुहिम पहुंच गई है। अभियान का मुख्य संदेश यह है कि, "राज्य के प्रति वफादारी एक अच्छा भिक्षु या भिक्षुणी बनने के लिए आवश्यक है।" अभियान के तहत, एक कार्य दल (तिब्बतीः लेदोन रूखाग) में, दोनों चीनी और विश्वसनीय तिब्बती अधिकारियों से मिलकर, मठों और भिक्षुणियों के मठों में जाकर भिक्षुओं और भिक्षुणियों को मजबूर करते है कि वह परमपावन दलाई लामा का निंदा और एक परीक्षा के माध्यम से या प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करके कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठ की घोषणा करें। इन अभियानों का भारी प्रतिरोध हुआ हैं, कई बार भिक्षुओं और भिक्षुणियों की गिरफ्तारी और हिरासत और गैर–अनुपालन के लिए अतिरिक्त दंड भी दिया जाता है।

इसके अलावा "नौ अवश्यक सूत्र" कार्यक्रम के तहत, जो देशभक्तिपूर्ण शिक्षा अभियान की अंतर्गत है, सभी मठों और भिक्षुणियों के मठों को चीनी राष्ट्रीय ध्वज और कम्युनिस्ट नेताओं के चित्र प्रदर्शित करने होंगे। सत्र का बहिष्कार करने या कार्य दल की मांगों को धता बताने के किसी भी प्रयास का परिणाम निष्कासन, गिरफ्तारी या यातना हो सकती है।

तिब्बती भिक्षुओं और भिक्षुणियों को चार पुस्तकों का अध्ययन आवश्य करना होगा और उनके संस्मरण और सामग्री के आधार पर परीक्षण होगी, जिसमें विरोधी दलाई लामा विरोधी जानकारी, चीन के तिब्बत के संस्करण, चीन के कानूनी पहलू और धर्म पर प्रतिबंध शामिल हैं। अभियान के तहत, उन्हें यह कहना होगा– "मैं दलाई गुट का विरोध करता हूं; मैं अपने घर में दलाई की तस्वीर नहीं रखूंगा; मेरी सोच दलाई के गुट से प्रभावित नहीं होगी; मैं कम्युनिस्ट पार्टी से प्यार करता हूं; मैं चाहें कुछ भी होजाए पार्टी का अनुसरण करूंगा। "अगर वे विफल रहे या इसके प्रति शत्रुता व्यक्त की, तो उन्हें कठोर परिणाम का सामना करना पड़ेगा जैसे कि निष्कासन या कारावास।

इस क्रूर ज़बरदस्ती और अकर्मण्यता के कारण, कई भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने निंदा से इनकार किया और निर्वासन में भाग गए। तिब्बती बौद्ध मठ परमपावन दलाई लामा को बोधिसत्व अवलोकीतेश्वारा, करणा का देवता की

अभिव्यक्ति मानता हैं, वर्तमान दलाई लामा, विश्व शांति का प्रतीक है, दुनिया भर में उनके अनुयायियों के दिलों के करीब है, और तिब्बत की भीतर एवं बाहर रहने वाले तिब्बतियों का पूजनीय है। हाल के दिनों में, परमपावन दलाई लामा की तिब्बत वापसी के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए 150 से अधिक तिब्बतीयों ने खुद को जला दिया है। तिब्बती पहचान से दलाई लामा को भड़काने के लिए चीन के निरंतर दमनकारी तरीकों के खिलाफ आत्म–दाह विरोध प्रदर्शन एक उग्र रूप है। (विरोध के इन कृत्यों को इस रिपोर्ट के अध्याय एक में पूरे विवरण में संबोधित किया गया है)।

फरवरी 1998 में प्रकाशित तिब्बत पर चीन का दूसरा श्वेत पत्र यह कहता है कि "अपने नागरिकों के धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता अधिकार का सम्मान तथा रक्षा करता है, और यह कहा कि "चीन सरकार ने तिब्बती लोगों को धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता अधिकार को लगातार सम्मान और संरक्षण दिया है।" "इसके अलावा, सत्रह सूत्री समझौते के शर्तों में से एक, तिब्बत पर संप्रभुता को चिन्हित करने वाला अति चर्चित का ऐतिहासिक दस्तावेज, तिब्बती धार्मिक स्थलों और संस्थानों को संरक्षण और सुरक्षा करना था। ये आधिकारिक बयान और घोषणाएं धार्मिक अभियोग के राज्य द्वारा लगाए गए नियमों, भिक्षुणियें और भिक्षुओं के निष्कासन तथा कारावास के साथ कट्टर विरोधाभास में हैं। चीन के धार्मिक नियम तिब्बती बौद्ध धर्म पर दमनकरी चीनी धार्मिक नियमों, सीधे तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपराओं को विकृत और कम कर रहे हैं।

तिब्बती भाषा को नष्ट करने का प्रयास

पूरे इतिहास में और सभी संस्कृतियों में, भाषा को मानव संचार के साधन और सांस्कृतिक पहचान तथा एक कामकाजी समाज और राष्ट्रवाद स्थापित करने के लिए सर्वोपरि माना जाता है।

2000 में प्रकाशित चीनी सरकार का तिब्बत पर तीसरा श्वेत–पत्र, इस विश्वास के प्रति एक प्रकार का दिखावटी प्रेम देता है। यह सरकार की सहायता से तिब्बती संस्कृति को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसमें यहां तक कहा गया है, "बोली जाने वाली और लिखित तिब्बती भाषा का सार्वभौमिक उपयोग किया जाता है।" 1949 के आम कार्यक्रम के चीनी कानूनी ढांचे के तहत, भाषा उत्सवीय अधिकार है जिसमें "अल्पसंख्यकों को अपनी भाषाओं को विकसित करने, और अपनी परंपराओं

को संरक्षित करने या सुधारने की स्वतंत्रता दी गई है।" यहां तक कि सत्रह सूत्री समझौते में भी उल्लेख किया गया है कि तिब्बतियों को "अपनी बोली और लिखित भाषा को विकसित करने और अपने रीति–रिवाजों, आदतों और धार्मिक विश्वासों को संरक्षित या सुधारने की स्वतंत्रता होगी।" खुद चीनी संविधान और क्षेत्रीय स्वायत्तता पर कानून लगातार भाषा की स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं।

हालाँकि, ये घोषणाएँ और दस्तावेज़ बहुत हद तक तिब्बत में जीवन के अभ्यास और वास्तविकताओं से भिन्न हैं। द्वी–भाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के बहाने, चीन की सरकार ने मंडारिन को तिब्बती स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू किया है। वर्तमान भाषा नीतियों ने स्कूलों में तिब्बती भाषा को सीखना ही रोका नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बिना मूल्य और अविक्रेय बना दिया है।

क्षेत्रीय जातीय स्वायत्तता पर चीनी संविधान और कानून अल्पसंख्यकों को अपनी स्वयं की बोली और लिखित भाषाओं का उपयोग करने और विकसित करने का अधिकार प्रदान करता है। कई अन्य प्रावधान हैं जो अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं को भाषा के अधिकार प्रदान करते हैं। इन प्रावधानों के बावजूद, हालांकि, तिब्बती भाषा के अधिवक्ताओं को हिरासत में लिया और राजनीतिक अपराधों के चलते आरोपित किया गया है क्योंकि उन्होनें केवल तिब्बती भाषा के हाशिए पर चिंता व्यक्त करने और चीनी अधिकारियों के खिलाफ अपने स्वयं के कानूनों का पालन करने में विफलता के लिए आवाज़ उठाई थी।

इन भाषा नीतियों के कारण तिब्बती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उदाहरण के लिए, 2010 के अक्तूबर में जब सरकार ने स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली भाषा को पूरी तरह से मंडारिन में बदलने की योजना की घोषणा की, तो हजारों तिब्बती छात्र और शिक्षक विद्रोह के लिए रेब्कोंग, अमदो में अपने भाषाई अधिकारों के लिए सम्मान की मांग करते हुए गलियों में एकत्र हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने तिब्बती भाषा की शिक्षा और अधिक तिब्बती भाषा की कक्षाओं के आरम्भ करने की मांग की। नारों के माध्यम से, और सरकार को एक खुले पत्र में, प्रदर्शनकारियों ने मंडारिन–आधारित शिक्षा की कमियां बताईं, और भाषा नीति की समीक्षा और संशोधन करने का आह्वान किया।

इनमें से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जिससे उन तिब्बतियों के विषय में पता चला, चाहे वे छात्र, लेखक, गायक, शिक्षक या अन्य बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने तिब्बती होने की राष्ट्रीय पहचान का जश्न मनाया और चीनी शासन की आलोचना की। कई तिब्बती स्थानीय भाषा के पाठ्यक्रम चलाकर तिब्बती भाषा को संरक्षित करने का काम करते हैं। परन्तु, वे अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने का जोखिम लेते हैं, जैसा की एक सम्मानित स्थानीय नेता खेनपो कार्टसे के मामले में हुआ, जो तिब्बती भाषा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए वकालत करते थे, और जिन्हें 2013 में ढाई साल तक कैद किया गया था। कई संगीतकारों को उन गीतों को लिखने के लिए जेल में डाल दिया गया है जो तिब्बती मातृभाषा के उपयोग के लिए कहते हैं। इसके संदर्भ में एक तिब्बती केलसांग यारफेल का मामला है जिने चार साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी।

1960 में तिब्बती भाषा के व्याकरण को सरकार द्वारा 'सुधारों' के तहत संशोधित किया गया था। कुछ चीनी शब्दों का इस्तेमाल तिब्बती भाषा में किया गया था, और ज्ञानक (जिसका अर्थ तिब्बती भाषा में चीन था) जैसे कुछ तिब्बती शब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तिब्बतियों के लिए यह आवश्यक बना दिया गया की वह तिब्बती भाषा में चीन के लिए, झंगुओ जैसे चीनी शब्दों को सम्मिलित करें। इसके अलावा, शैक्षिक प्रणाली को इस प्रकार रचा गया की उन्हें {तिब्बती छात्र} अपने स्वयं के इतिहास और भाषाओं को सीखने का अवसर और क्षमता न प्राप्त हो सके तथा" बच्चों को "प्रेरित किया गया" और चीनी संस्कृति के सापेक्ष तिब्बती संस्कृति, धर्म और भाषा के बारे में हीन भावना पैदा की गयी।"[153] न्यू यॉर्क टाइम्स का लेख एक तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) में एक तिब्बती स्कूल का एक धूमिल चित्र प्रदान करता हैः

माओ का एक चित्र लॉबी में टंगा हुआ है। तिब्बती भाषा की कक्षाओं को छोड़कर, सभी कक्षाएं मैंडरिन चीनी में सिखाई जाती हैं। सरकार की अल्पसंख्यक नीतियों के आलोचकों का कहना है कि तिब्बत में शिक्षा प्रणाली अपनी भाषा में तिब्बतियों के प्रवाह को नष्ट कर रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि छात्रों को प्रतिस्पर्धी होने के लिए चीनी को सीखने की आवश्यकता है और इसे कुछ छात्रों ने स्वीकार भी किया है।

153 "चीनः अल्पसंख्यक बहिष्करण, सीमांकन और बढ़ती तनाव", चीन में मानवाधिकार 2007, 28–29।

"मेरी पसंदीदा कक्षा तिब्बती की है क्योंकि हम घर पर सब तिब्बती बोलते हैं, लेकिन हमारे देश की मातृभाषा चीनी है, इसलिए हम चीनी में अध्ययन करते हैं", 13 वर्षीय गेसंग डंडा ने कहा।

एक कक्षा में एक ब्लैकबोर्ड पर, किसी ने हथौड़ा और दरांती के साथ लाल झंडे को हटा लिया था। इसके आगे लिखा था, चीनी और तिब्बती भाषा में एक नारा था: "कम्युनिस्ट पार्टी के बिना, कोई नया चीन नहीं होगा और निश्चित रूप से कोई नया तिब्बत नहीं होगा।"[154]

पहली भाषा के रूप में मंडारिन के साथ तिब्बती भाषा को स्कूलों में दूसरी भाषा के रूप परिभाषित किया गया है ताकि वह हाशिये पर आ सके। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली एक ऐसा मंच है जो तिब्बती छात्रों में वैचारिक मान्यताओं को रोपित कर उनकी पहचान और अस्तित्व को अस्वीकार करवा देता है।

2012 में, किंगहाई, आमदो में मिडिल स्कूल के छात्रों ने वसंत ऋतू की छुट्टियों के बाद नई चीनी भाषा की पाठ्य–पुस्तकों के मिलने पर विरोध प्रकट किया। हजारों छात्रों ने औरों की भांति ही शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में भाग लिया। फिर उस वर्ष के मार्च माह में,गंसु प्रांत के माचू तिब्बती मिडिल स्कूल से एक 19 वर्षीय छात्र, सेरिंग क्यी ने खुद को आग लगा ली, 2009 के बाद से आत्म–दाह करने वाला 24वां तिब्बती बन गया। बताया गया है कि उसने 2010 के भाषा अधिकारों के विरोध में भाग लिया था। तिब्बत के छात्र अपनी मातृभाषा बोल पाने में कठिनाई अनुभव करते हैं, लेकिन जैसा कि चीनी सरकार का इरादा था, वे चीनी भाषा को समाज में संचार और अवसरों के लिए सबसे सुविधाजनक और व्यवहार्य साधन मानते हैं। स्वर्गीय खेंपो जिग्मे फुंत्सोक, लारूंग गार बौद्ध संस्थान के मठाधीश ने इस गंभीर समस्या को निम्न रूप में स्पष्ट किया है:

वास्तव में, वर्तमान तिब्बत में तिब्बती भाषा का कोई मूल्य नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पत्र तिब्बती भाषा में लिखे पते के साथ मेल किया गया था, तो वह तिब्बत के भीतर भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा, बाहर तो बहुत दूर की बात है।

यात्रा के मामले में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तिब्बत में कोई व्यक्ति कितना भी साक्षर हो, वह बस सूची को समझने या टिकट पर सीट संख्या को पढ़ने

154 ऐडवार्ड वोंग, "चीन का पैसा और तिब्बत में बडती प्रवासी", द न्यूयॉर्क टाइम्स, 24 जुलाई 2010 https://www.nytimes.com/2010/07/25/world/asia/25tibet.html.

में सक्षम नहीं होगा। आपातकालीन स्थिति में भी, यदि किसी को प्रान्त के मुख्यालय या शहर में अस्पताल या दुकान की तलाश करनी पड़े, तो तिब्बती भाषा का ज्ञान व्यर्थ होगा। एक व्यक्ति जो केवल तिब्बती जानता है उसके लिए दैनिक आवश्यकताओं की चीजे को खरीदना भी कठिन होगा।

यदि हमारे देश में हमारी भाषा बेकार है, तो इसका और कहीं उपयोग नहीं हो सकता यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही, तो तिब्बती भाषा एक दिन विलुप्त हो जाएगी ....तिब्बत में ऐसे स्कूल दुर्लभ हैं जहां कोई तिब्बती भाषा और संस्कृति का अध्ययन कर सकता है....इसके अलावा, माता–पिता ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की आदत विकसित की है। यह इसलिए है क्योंकि प्राथमिक विद्यालय तिब्बती भाषा के बजाय चीनी सिखाता है। भले ही छात्र मिडिल स्कूल से चीनी और स्नातक हों, तिब्बत में कोई की गुंजाइश रोजगार नहीं है। तिब्बती भाषा सीखने का एक मामूली सा अवसर है परन्तु माता–पिता जानते हैं कि तिब्बती भाषा दिन–प्रतिदिन के जीवन में बेकार है। हालांकि, उनके पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कोई प्रेरणा नहीं है।[155]

2016 में, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने दो लेखों में तिब्बती लोगों के सांस्कृतिक और भाषा अधिकारों के उल्लंघन और ताशी वांगचुक, एक तिब्बती भाषा–अधिकारों के वकील को दिखाते है एक वृत्तचित्र दिखाया था। इसके बाद, वांगचुक को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया और चीनी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक ने तिब्बती भाषा और संस्कृति के समान संरक्षण और संवर्धन से जुड़े अधिकारों और स्वतंत्रता को लागू करने का आह्वान किया था, जो चीनी संविधान के साथ–साथ क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता पर कानून में भी निर्धारित किया गया था। हालाँकि उन पर "अलगाववाद को उकसाने" का आरोप लगाया गया था। वांगचुक ने 4 जनवरी, 2018 को आयोजित चार–घंटे की सुनवाई के दौरान "अलगाववाद को उकसाने" के आरोपों के लिए दोषी नहीं की अपील की थी। 22 मई 2018 तक, उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। (ताशी वांगचुक के मामले के पूर्ण विवरण के लिए, इस रिपोर्ट के अध्याय तीन को देखें

शहरों और देश के मुख्यालय में, लोग तिब्बती भाषा बोलने में असमर्थ हैं, भले ही उनके माता–पिता दोनों तिब्बती हैं। उनमें से सभी ने अपने तिब्बती चरित्र को खो दिया है। अधिक जानकारी के लिए, तिब्बत के अधिकारी शुद्ध तिब्बती भाषा नहीं बोल सकते। एक–पांचवां या दो–तिहाई शब्द जो

155 सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, साम्यवादी चीन के तहत तिब्बतः पचास वर्ष, धर्मशालाः सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, 2001, 41

वह उपयोग करते हैं वे चीनी भाषा से होते हैं जिसके फलस्वरूप, साधारण तिब्बती उनकी भाषा नहीं समझ पाते।

खेंपो जिग्मे फुंत्सोक के पत्र में तिब्बती भाषा के दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य की पुष्टि की गई है, जो सामाजिक संस्थाओं से दूर है और छोड़ दी गई है। जो धारा प्रवाह तिब्बती भाषा बोलते हैं, वे मुख्यधारा की अनिवार्यताओं के अनुरूप नहीं होने के लिए हीन भावना महसूस करते हैं और कई अन्य जो खुद को तिब्बती के रूप में पहचानते हैं, वे चीनी बोलने में स्वयं को अधिक सहज महसूस करते हैं। चीन का तिब्बती भाषा के उपयोग को नीचा दिखाने, भटकाने, कमतर आंकने के प्रयासों से तिब्बती भाषा के अस्तित्व के लिए एक वास्तविक खतरा बन गया है।

आदेश संख्या: 5

2007 में, चीन के धार्मिक मामलों के राज्य प्रशासन ने एक नया नियामक उपाय "तिब्बती बौद्ध में जीवित बुद्धों के पुर्नावतार के लिए प्रबंधन के उपाय" जारी किया, जिसे "आदेश संख्या 5" कहा जाता है। यह आदेश सभी टुलकु (अवतार से उत्पन्न अध्यामिकों) के लिए पंजीकरण करने और सरकारी अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है। विनियमन राज्यों के अनुच्छेद 2, "जीवित बुद्धों को पुर्नावतार देना या किसी विदेशी संगठन या व्यक्ति के प्रभुत्व के अधीन नहीं होना चाहिए" और प्रांतीय या स्वायत्त क्षेत्रीय बौद्ध संघ या चीन के बौद्ध संघ द्वारा अनुष्ठान मान्यता प्राप्त होगा और ऐतिहासिक रूप से स्थापित प्रणालियां के अनुरूप होगा।"[156] इस रिपोर्ट के अध्याय आठ में इस पर चर्चा की जाएगी।

अंतर्जातीय विवाह नीति

चीनी अधिकारियों ने तिब्बतियों और चीनियों के बीच विवाह को प्रोत्साहित करने की अपनी नीति को मजबूत करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अगस्त 2014 में, केनक्वंगो, "तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र" (टीएआर) के प्रभारी ऐसी उच्चतम चीनी अधिकारियों ने स्थानीय समाचार पत्रों में ऐसी कहानियों को प्रकाशित करने का आदेश दिया जिसके अनुसार मिश्रित विवाहों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था। हफ्तों तक टीएआर में सरकार द्वारा संचालित समाचार पत्रों में खुशहाल मिश्रित विवाहों की कहानियां और चित्र

156 अनुच्छेद 7, राज्य धार्मिक मामलों के ब्यूरो आदेश संख्या–पांच, 1 सितंबर 2007।

दिखाए गए, जिसमें बच्चे दोनों संस्कृतियों को प्यार करते और तिब्बती और मैंडरिन में बात करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा एक साक्षात्कार के जवाब में, वाइसर, एक बीजिंग आधारित प्रमुख ब्लॉगर ने कहाः "भिन्न पृष्ठभूमि से आ रहे जोडो के बारे में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से एक साथ आ रहे हैं। हालांकि, जब अधिकारी इसे एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं और इसे प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाते हैं, तो यह गलत लगता है।"[157]

अगस्त 2014 में प्रकाशित एक कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसंधान कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार मिश्रित विवाहों के प्रतिशत में पिछले पांच वर्षों में दोहरे अंक प्रतिशत में, 2008 में 666 जोड़ों से 2013 में 4795 जोड़ों की वार्षिक वृद्धि हुई थी।

चिन क्वांगो, तब टीएआरके पार्टी सचिव जिन्होंने 18 जून 2014 में जातीय अंतरजातीय पारिवारिक मंच की अध्यक्षता की, ने पार्टी और सरकारी अधिकारियों को "रिश्ता जोडने वाले" के रूप में कार्य करने के लिए भी कहा।[158]

खानाबदोश जीवन पद्धति का विनाश

अनुमानित 2.25 मिलियन खानाबदोश लोग तिब्बती पठार पर रहते हैं। इतिहास के अनुसार, खानाबदोशों ने कुशलता से अपने पशुधन को प्रबंधित किया, और भूमि को बनाए रखा,तथा तिब्बत की नाजुक पारिस्थितिक प्रणाली की वास्तविकता के अनुकूल अपने को ढाल लिया।[159] खानाबदोश

157 विलियम वैन एंड जू यंगजिंग, "चीन तिब्बत में मिश्रित शादियों को एकता के रूप में बढ़ावा देता है", वाशिंगटन पोस्ट, 16 अगस्त 2014 https://www.washington-post.com/world/asia_pacific/china-promotes-mixed-marriages-in-tibet-as-way-to-achieve-unity/2014/08/16/94409ca6-238e-11e4-86ca-6f03cbd15c1a_story.html?utm_term=.febb7c80d509.

158 "चीनी पार्टी के अधिकारी ने एकता बनाने के लिए तिब्बत में अंतर–जातीय विवाह को बढ़ावा दिया", इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत, 28 अगस्त 2014। https://www.savetibet.org/chinese-party-official-promotes-inter-racial-marriages-in-tibet-to-create-unity/.

159 परंपरिक तिब्बती पर्यावरण संरक्षण पर विस्तृत रिपोर्ट के लिए, जमयांग नेर्बू, "पूर्व तिब्बत में वन्यजीव और प्रकृति संरक्षण", छाया तिब्बत, 6 दिसम्बर 2009, देखें। जूलिया मार्टिनः परिस्थितिक जिम्मेदारीः बौद्ध धर्म के साथ एक संवादः निबंध और वार्ता का एक संग्रह, नई दिल्लीः तिब्बत हाउस और श्री सतगुरू प्रकाशन, 1997

और किसान दोनों ही आपस में अदला–बदली की प्रणाली में सम्मिलित हो गए जिसमें खानाबदोशों ने जौ, कपड़े और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं के बदले में नमक, मक्खन, मांस, सूखे पनीर और ऊन दिया। हालाँकि जीवन का यह खानाबदोश तरीका धीरे–धीरे ग्राम प्रणाली में बदल गया था लेकिन वर्तमान में तिब्बती खानाबदोश परिवारों के लिए सबसे बड़ा खतरा जबरन पुनर्वास और चरागाहों से खानाबदोशों को हटाने का है। 2006 और 2012 के बीच, लगभग दो मिलियन[160] खानाबदोशों को उनकी जमीन से हटाया गया।

जून 2007[161] में प्रकाशित एक व्यापक रिपोर्ट जिसका शीर्षक था *नो वन हेस द लिबर्टी टू रीफ्युज* में न्यूयॉर्क स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच ने चीन के खानाबदोश पुनर्वास परियोजना के बारे में चौंकाने वाले तथ्य और आंकड़े बताए। चरागाह को बंद करने के कारण के रूप में पर्यावरणीय सुरक्षा का दावा करते हुए, चीनी सरकार ने "खेत को जंगल में बदलें"[162] और "चारागाह को घास स्थल में वापिस बदलें"[163] जैसी नीतियों को प्रारम्भ किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि "2000 के बाद से, चीन सरकार पुनर्वास, भूमि की जब्ती, और चारागाह क्षेत्रों में बाड़ लगाने की नीतियों को मुख्य रूप से तिब्बतियों द्वारा बसाया बसाए गए चरागाह क्षेत्रों में कार्यान्वित कर रहा है, जिससे उनकी आजीविका में भारी कमी आई है। यह नीतियां विशेष रूप से कट्टरपंथी हैं...कई तिब्बती चरवाहों को अपने अधिकांश पशुओं का वध करने की आवश्यकता हुई है तथा पास के कस्बों में अपने पारंपरिक जीवन शैली को छोड़ कर नवनिर्मित आवास कॉलोनियों में चले जाना पड़ा है।"[164]

चरागाहों को बंद करना, रेवड़ों पर लगाई गई सीमाएं और स्थायी बंदोबस्त में स्थानांतरण ने सभी खानाबदोशों को आय के अन्य स्रोतों की तलाश करने के लिए मजबूर किया है, जिसके लिए उनके पास या तो पर्याप्त कौशल

160 ब्रेड एडमस, "वे कहते है कि हमें आभारी होना चाहिएः चीन के तिब्बती क्षेत्रों में सामू. हिक पूर्वाभ्यास और पूनर्वास कार्यक्रम", ह्यूमन राइट्स वॉच, 27 जून 2013 https://www.hrw.org/report/2013/06/27/they-say-we-should-be-grateful/mass-rehousing-and-relocation-programs-tibetan

161 सोफी रिचर्डसन,"अस्वीकार करने के लिए किसी को स्वतंत्रता नहीं है", गन्सु, किंघई, सिचुआन तथा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में तिब्बती चरवाहों को जबरन स्थानांतरित किए गए। ह्यूमन राईट्स वॉच, जून 2007, वॉल्यूम 19, संख्या 8 सी https://www.hrw.org/reports/2007/tibet0607/.

162 पइपक.,17

163 पइपक.

164 वही ,3

या अवसर नहीं हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा एक तिब्बती का साक्षात्कार साझा किया गया कि "चीनी हमें (खानाबदोश) अपना काम नहीं करने दे रहे हैं और हमें चीनी निर्मित शहरों में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो हमें बिना किसी पशु धन के साथ छोड़ देगा और हम अपना अन्य कोई काम करने में सक्षम नहीं होंगे।"[165]

2003 में, पूर्वोत्तर तिब्बत में गोलोक में चराई पर कुल प्रतिबंध लगाया गया था और खानाबदोशों को सरकार द्वारा निर्मित घरों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था। खानाबदोशों को अक्सर उनके पशु धन के लिए एकमुश्त भुगतान किया जाता था, और उन्हें बिना नौकरी की सम्भावना या किसी स्थिर आय के स्त्रोत[166] के बिना घर दिए जाते थे। परिण ाामस्वरूप, वे याट्र्सगुनबू या कैटरपिलर कवच को इकट्ठा करने और बेचने का सहारा लेते हैं, एक चिकित्सा जड़ जिसकी बहुत मांग है और गर्मियों के दौरान बहुत अधिक बाजार मूल्य है, खानाबदोशों में लगभग पूरी आबादी इसके लिए गर्मियों में चरागाहों छानती हितों में बिखरती है।[167] कुछ क्षेत्रों में, स्थानीय नेता पासबुक जारी करते हैं जो लोगों को यह जड़ इकट्ठा करने की अनुमति देते हैं और फिर अधिकारी इसे बेचने के लिए बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं ताकि यह भारी लाभ कमा सके। कुछ अधिकारी पहाड़ों में जड़ इक्कठा करने वालों के लिए वीडियो नाइट आयोजित करते हैं, जिसके दौरान वयस्क फिल्में दिखाई जाती हैं और सस्ती शराब बेची जाती है। व्यापार और बिखराव को लेकर हिंसक और घातक संघर्ष के मामले भी प्रकाश में आए थे। क्योंकि जून 17 के अंक में जूनाथन वाट्स की रिपोर्ट में कहा गया थाः "जुलाई 2007 में आठ लोगों को गोली मार दी गई थी और एक ऐसे संघर्ष में 50 घायल हो गए थे।"[168]

खानाबदोश पारंपरिक मूल्यों और धार्मिक भावनाओं पर एक और हमला चीनी सरकार द्वारा देहाती क्षेत्रों में पशु वध घरों[169] की श्रृंखला का निर्माण

165 वही ,3

166 वही.,57–64

167 वही...,49: यह भी देखें, वांग लिक्सीयोंग और त्सेरिंग शाक्य, द स्ट्रगल फॉर तिब्बत लंदनःवर्सो बुक्स 2009, 160–168, जोनाथन वैट्स, "भूकंप के बाद तिब्बती पठार के पुनर्निमाण में कवक सोने की भीड़", द गर्दडियान, 17 जून 2010, https://www.the-guardian.com/environment/2010/jun/17/fungus-tibetan-plateau.

168 जोनाथन वैट्स, 2010

169 सोफी रिचईसन 2007, 64–71

है और इन घरों में जानवरों को प्रदान करने के लिए प्रत्येक घर के लिए निर्धारित करना है। स्थानीय पशुपालकों को कत्ल करने के लिए पशु देने के आदेश में विफल रहने पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा दंडित किया जाता है। पूर्वी तिब्बत में कार्देज़ में सेरशूल प्रान्त में, लोगों ने स्थानीय अधिकारियों को स्थानीय निर्मित बूचड़खाने के खिलाफ याचिका दी। जब याचिका खारिज कर दी गई, तो कुछ ने बुमनीक मठ के भिक्षुओं और सामान्य लोगों ने एक अपील करते हुए लिखाः "इससे बुद्ध धर्म को कोई अधिक हानि नहीं है। भले ही हम जीवित प्राणियों की रक्षा न करें। दया के बिना उनका वध करना बुद्ध धर्म के खिलाफ है। यह लोगों की इच्छा है"।[170] इसकी आधिकारिक प्रतिक्रिया तीन अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी थी जिन्होंने अपील प्रस्तुत की थी।

2010 में चीन की अपनी यात्रा के बाद, भोजन के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत, ओलिवियर डेस्कुटर, ने 20 जनवरी 2012 को मिशन टू चाईना नाम से एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में तिब्बत में खानाबदोश पुनर्गठन के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, और अपनी पारंपरिक भूमि से तिब्बती खानाबदोश चरवाहों के गैर–स्वैच्छिक पुनर्वास के निलंबन की मांग की गयी। यह कहा कि चीन को "नए समाजवादी" गांवों में रोजगार के अवसरों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना चाहिए, ताकि सभी के लिए पर्याप्त भोजन के अधिकार की प्राप्ति को सक्षम किया जा सके।

इसके अलावा, रिपोर्ट में चीन से आग्रह किया गया कि "सार्थक परामर्श के लिए अनुमति दें, जो कि संपन्न समुदायों के साथ हो, पार्टियों को सभी उपलब्ध विकल्पों की जांच करने की अनुमति दी जाये, जिसमें सीमांत चरागाहों के स्थायी प्रबंधन की हालिया रणनीतियों सहित शामिल हैं।[171]

मार्च 2012 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 19 वें सत्र में जिनेवा में आयोजित एक परस्पर संवादात्मक चर्चा के दौरान, ओलिवर डी शुटर ने तिब्बत में चीन की मजबूर पुनर्वास नीति को चुनौती दी। "मेरा मानना है कि चीन में कई गंभीर समस्याएं हैं और कम से कम तिब्बत में चरवाहों की स्थिति ठीक नहीं है। शुटर ने यह भी तर्क दिया कि पुनर्वास नीतियां

170 वही.,69

171 मानवाधिकार परिषद के उन्नीसवां सत्र, ए/एचआरसी/19/59/Add.1, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-59-Add1_en.pdf.

विफल हो रही थीं क्योंकि मार्च 2011 से इस क्षेत्र में लागू की गई नीतियों के विरोध में तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया था। उन्होंने कहा कि खुद को जलाने वाले 25 में से 18 वास्तव में नए समाजवादी गांवों में जबरन बसाए गए चरवाहे थे। "मेरा कहना है कि यह इस विचार के अनुकूल नहीं है कि ये 'बहुत लोकप्रिय नीतियां" होंगी।[172]

बीजिंग ने तिब्बती खानाबदोशों और उनके जीवन के तरीके को पर्यावरण के लिए खतरा होने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि वे आत्मनिर्भरता की पारंपरिक अवधारणाओं से बंधे हुए "आदिम जीवन" जीते हैं और "अपने घरेलू जानवरों को बेचकर पैसा बनाना नहीं जानते थे"।[173] वास्तव में जीवन के सदियों पुराने खानाबदोश तरीके और दो मिलियन से अधिक खानाबदोशों की सांस्कृतिक पहचान का धमकी दी जा रही है और विलुप्त होने के लिए प्रेरित किया गया है।

निष्कर्ष

पिछले छह दशकों से, चीन ने तिब्बती बौद्धमत और धार्मिक परंपराओं, भाषा, सांस्कृतिक प्रथाओं और जीवन के पारंपरिक तरीके के विनाश के साथ तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत का सिलसिलेवार विनाश किया है।

इन क्षेत्रों में किए गए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नीतियों ने उनकी संस्कृति और भाषा के संदर्भों को छीन लिया है और उनके जीवन के पारंपरिक तरीके को नुकसान पहुँचाया है। सांस्कृतिक नरसंहार के ये कार्य अभी भी किए जा रहे हैं और सांस्कृतिक रूप से आत्मसात किया जा रहा है।

तिब्बत पर चीन की सच्ची शाही मंशा, तिब्बत की बौद्ध सभ्यत्ता के विनाश में परिलक्षित होती है। अब चुनौती यह है कि क्या चीन अंतर्राष्ट्रीय मान दंडों और घरेलू कानूनों का पालन करेगा, और तिब्बत में अपनी विफल नीतियों का पुनः निरीक्षण और संशोधन करेगा?

---

172 केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, संयुक्त राष्ट्र के विशेष संबंध ने तिब्बत में चीन का जबरन पुनर्वास नीति का चुनौति दिया, 7 मार्च 2012, http://tibet.net/2012/03/un-special-rapporteur-challenges-chinas-forced-resettlement-policy-in-tibet/.

173 अधिक देखने के लिए, "खानाबदोश को जोखिम और तिब्बत के देहाती–घुमंतूवादः परंपरा और आधुनिकीारण के बीच", तिब्बती बुलेटिन, सितम्बर–दिसम्बर 2000

अध्याय पांच

तिब्बती पठार तथा इसका बिगड़ता पर्यावरण

परिचय

तिब्बती पठार की पारिस्थितिकीय परिस्थितियां प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों कारणों से चिंताजनक दर से ख़राब होती जा रही है। तिब्बती पठार पर ग्लोबल वार्मिंग का, विशेषतया हाल के दशकों में, गम्भीर प्रभाव पड़ा है। दुर्भाग्य से, कमज़ोर पर्यावरणीय नीतियाँ और चीन सरकार के पर्यावरण संरक्षण के ईमानदार प्रयासों में कमी ने इन परिस्थितियों को और अधिक ख़राब कर दिया है। अंधाधुंध खनन ने तिब्बत के पर्यावरण को गम्भीर नुकसान पहुंचाया है और इसके लोगों को कष्ट में डाला है और विकास के अनथक दबाव ने चीन को मिलावटी मिटी, पानी और हवा युक्त ज़हरीली भूमि बना दिया है। यदि तिब्बती क्षेत्र में पर्यावरण ह्रास की वर्तमान प्रवृति इसी तरह ज़ारी रही तो,चीन के अधिकारी विश्व के सबसे ऊंचे पठार को चीनी प्रान्त के एक अन्य ज़हरीले पठार में बदल देंगे जिससे तिब्बत, चीन और एशिया के लाखों लोगों के लिए तबाही का कारण बन सकता है जो तिब्बत की नदियों पर आश्रित हैं।

तिब्बती पठार की जलवायु गत परिस्थितियों का तिब्बत की संस्कृति और जीवन–चर्या पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से तिब्बतियों ने अपने पर्यावरण का संरक्षण और सम्मान किया है और पठार के बदलते जलवायु को सफलतापूर्वक स्वीकार ही नहीं किया है बल्कि सशक्त सभ्यता के रूप समृद्धि भी प्राप्त की है। तिब्बत की विशिष्ट समृद्ध संस्कृति जो पर्वतों और झरनों में देवताओं की उपस्थिति पर विश्वास करती है,ने तिब्बत के पारिस्थिकीय तंत्र की पवित्रता के विश्वास को जन्म दिया जिसके कारण हज़ारों वर्षों तक इस नाजुक पठार का तदनन्तर संरक्षण होता रहा। 7वीं सदी में तिब्बत के 33वें सम्राट सोंगत्सेन गोम्पो ने अपने शासनकाल में आदेश जारी कर अपनी प्रजा को पशुओं को हानि पहुंचाने और वध ना करने का फ़रमान ज़ारी किया था। तिब्बत में फागमो द्रुपा राजशाही के संस्थापक, ताई सितु जंगचुब ग्यालत्सेन (1302–1364)ने समान शासनादेश ज़ारी कर विभिन्न अवसरों पर शिकार को प्रतिबंधित किया और केंद्रीय तिब्बत में

भारी मात्रा में वृक्षारोपण की सरल नीति को लागू किया। वार्षिक 200,000 रोपित वृक्षों के संरक्षण के लिए वन अधिकारी नियुक्त किये गए। तिब्बत में गादेन फोड़रंग (1642–1959)के शासनकाल में पर्यावरण सरंक्षण प्रयास और अधिक सुदृढ़ हुए। 5 वें और 13 वें दलाई लामा, दोनों ने महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय स्थलों पर आखेट और वृक्षों की कटाई पर कड़ाई से प्रतिबंध का आदेश दिया था। पर्यावरण का संरक्षण परम पावन दलाई लामा की तीन प्रमुख प्रतिबद्धताओं में से एक है, दलाई लामा पर्यावरण सरंक्षण के प्रबल पैरोकार हैं।

तिब्बती पठार का वैश्विक महत्व

तिब्बती पठार का इसका वर्णन करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न नामों से तिब्बती पठार की पारिस्थितिक भूमिका और वैश्विक महत्व स्पष्ट हैः "विश्व की छत", "तीसरा ध्रुव", "एशिया का जल मीनार" और "मौसम निर्माता"। सबसे लोकप्रिय रूप से 'विश्व की छत' के रूप में जाना जाने वाला तिब्बती पठार 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ समुद्र तल से 4000 मीटर से अधिक की औसत ऊंचाई पर स्थित है। केवल 2 प्रतिशत पृथ्वी की भूमि की सतह पर, यह विश्व का सबसे ऊंचा और लम्बा पठार है।[174] 105.000 किमी के क्षेत्र में 46,000 ग्लेशियरों की उपस्थिति, पठार को ब्रहमांड पर उत्तरी ध्रुवों के बाद सुलभ ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत और बर्फ का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय बनाती है। इसी कारण वैज्ञानिक इसे "तीसरे ध्रुव" के रूप में संदर्भित करते हैं।

और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि, पठार एशिया की छह सबसे बड़ी नदियों का मुख्य स्रोत हैः ड्रिचू/यांग्त्से, माचू/पीला, ज़चू/मेकोंग, ग्यालमो न्गुलछु/सलवेन, सेंगकेब/सिंधु और यारलुंग त्संगपो/ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ "वॉटर टावर ऑफ़ एशिया" बनाने में मदद करती हैं, जो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बंगलादेश, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और चीन सहित दुनिया के कुछ सबसे अधिक आबादी वाले देशों में लाखों लोगों को जीवन प्रदान करता हैं। तिब्बत में ग्लेशियर के 12,000 किलोमीटर दूर से आने वाला पानी का पानी एशिया की प्रमुख नदियों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करता है, जो दुनिया की आबादी के पांचवें हिस्से के सामाजिक

174 शिचंग कंग एटी एल, "तिब्बत पठार में जलवायु और कायोस्फेरिक परिवर्तन की समीक्षा", पर्यावरण अनुसंधण पत्र 5 संख्या 1 (2010) 8 https://core.ac.uk/download/pdf/29577783.pdf.

और आर्थिक विकास को बहुत प्रभावित करता है।[175]

भारतीय और पूर्वी एशियाई मानसून का समय और तीव्रता तिब्बती पठार पर जलवायु परिवर्तन से बहुत प्रभावित होती हैः भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून तेज होता है और तिब्बती पठार पर मानव–निर्मित आवृत भूमि परिवर्तन के कारण पूर्वी चीन ग्रीष्मकालीन मानसून कमजोर होता है।[176] इस कारण से, पठार को 'एशिया का मौसम निर्माता' भी कहा जाता है। यहां तक कि यूरोप और उत्तर–पूर्व एशिया में बिगड़ती हवा की लहरें पठारों पर बर्फ की कमी से जुड़ी हैं।[177]

यह स्पष्ट है कि तिब्बती पठार का पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य चीन के स्थिर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। चीन की कुछ सबसे बड़ी संस्कृतियाँ, इतिहास, और अर्थव्यवस्थाएँ पीले और यांग्त्ज़ी नदियों के किनारों पर फली–फूलीं, जो तिब्बत के पिघलने वाले ग्लेशियरों और तुषार भूमि से निकलती हैं और चीन में लाखों लोगों का पोषण करती हैं क्योंकि वे समस्त चीन प्रांत में एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। लेकिन चीन की 40 प्रतिशत से अधिक नदियाँ गंभीर रूप से प्रदूषित हैं कि उनकी और लगभग 20 प्रतिशत नदियाँ इतनी अधिक प्रदूषित हैं कि उनके पानी की गुणवत्ता को भी विषाक्त माना गया है, जो संपर्क में आने के लिए भी विषाक्त है।[178] इसकी झीलों और जलाशयों की तीन चौथाई भाग मानव उपभोग और मछली पकड़ने के लिए अनुपयुक्त हैं।[179]

---

175 टनडन याओ ऐट एल.., "तीसरा ध्रुव पर्यावरण", पर्यावरण विकास 3, (2012):52–64, https://pdfs.semanticscholar.org/6300/f2ba7cd4f6979e214f4b30af-0fe2cce11538.pdf.

176 सुयी यूफेंग ऐट एल, "तिब्बती पठार पर परिवर्तन से मानवजनित भूमि उपयोग के जलवायु प्रभाव", Global and Planetary Change, no. 56 (2006): 33-56, https://pure.mpg.de/rest/items/item_994506/component/file_994505/content.

177 ज़िवे वू ऐट ऐल, "क्या तिब्बत पठार, स्नो कवर यूरेशियन हीट वेव फ्रीकेंसी की अंतर भिन्नताओं को प्रभावित कर सकता है", जलवायु गतिशीलता 46 Climate Dynamics 46, no. 1-12 (2016): 3405-3417,https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-015-2775-y.

178 यंग जियन, "चीन का नदी प्रदूषण" लोगों के जीवन के लिए खतरा है, English.people.cn, Febuary 17, 2012, http://en.people.cn/90882/7732438.html.

179 "चीन का जल संकट भाग 2– जल तथ्य का अवलोकन", चीन जल संकट, मार्च 2010 http://www.chinawaterrisk.org/wp-content/uploads/2011/06/Chinas-Water-Crisis-Part-2.pdf.

तिब्बती पठार पर भूमि के प्रदूषित होने, प्रदूषित हवा और दूषित वाष्पीकरण के कारण इस विकट स्थिति का विस्तार होगा और विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। चीन के कुछ प्रांतों के विपरीत, तिब्बतियों ने अपने पर्यावरण की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित किया है। लेकिन पीआरसी नियम के तहत, पठार पर पर्यावरण की मौजूदा तेजी से बिगड़ती स्थिति के साथ, तिब्बत में घूमने वाले लाखों चीनी पर्यटकों के लिए, ताजी हवा की सांस लेने और प्राचीन पारिस्थितिकी की एक झलक पाना मुश्किल हो जाएगा।

तिब्बती पठार पर जलवायु परिवर्तन का प्रभावः ग्लेशियर पीछे हटना

तिब्बती पठार पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव चरम पर है, जिससे तेजी से ग्लेशियत पीछे हटने, तुषार भूमि क्षरण और व्यापक मरुस्थलीकरण के कारण अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदाएँ हुई हैं।

46,000 ग्लेशियरों के लिए घर, तिब्बती पठार ढो ध्रुवों के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का केंद्र है। हालाँकि, तीसरा ध्रुव कहलाने वाला यह पठार खतरनाक दर पर पिघल रहा है, मुख्य रूप से द्रुततर गति से तापमान गटने के कारण 1950 से वैश्विक तापमान में औसत वृद्धि से दोगुना तिब्बत में 0.3 सेलशियस दशक तक का तापमान वृद्धि दर्ज की गयी है। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप न केवल 80 प्रतिशत से अधिक ग्लेशियर[180] पिघल गए, बल्कि पठार का तापमान भी इस हद तक बढ़ गया कि 1950 के दशक[181] से बर्फ का कोई शुद्ध संचय नहीं हुआ। इसके अलावा ग्रीष्मकाल तेजी से आता है, जो पठार पर पिघलने के मौसम को पहले और अंतिम समय तक शुरू करने के लिए मजबूर करता है।[182] वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि पिघलने की वर्तमान दर जारी रहती है, तो तिब्बती पठार पर दो तिहाई ग्लेशियर 2050[183] तक समाप्त हो जाएंगे। ग्लेशियरों का तेजी से

180 जेन क्विउ, "चाइनाः द थर्ड पोल, क्लाइमेट चेंज इज कमिंग फास्ट ऐंड फ्यूरियस टू द तिब्बतन प्लैटा", नेचर जर्नल 454, (2008): 393–396 https://www.nature.com/news/2008/080723/full/454393a.html.

181 सिचांग कांग और अन्य, 'ड्रामेटिक लॉस ऑफ ग्लेशियर एक्यूमुलेशन एरिया ऑन द तिब्बत प्लैटो रीवील्ड बाय आइस कोर ट्राइटियम ऐंड मर्करी रेकॉर्ड्स', द क्रायोस्फेयर 9, 3 (2015) 1213–1222 https://www.the-cryosphere.net/9/1213/2015/.

182 शू बाइक्विंग ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतन प्लैटो रिसर्च

183 तानडोग (2007), डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतन प्लैटो रिसर्च, तिमोथी गार्डनर, "तिब्बतन ग्लैशियल श्रिंक टु कट वाटर सप्लाई बाई 2050", रायटर्स, 17 जनवरी 2009 https://www.reuters.com/article/us-glaciers/tibetan-glacial-shrink-to-cut-watersupply-by-2050-idUSTRE50F76420090116

पिघलना पूर्वी और दक्षिणपूर्वी तिब्बत के कई हिस्सों को कम बर्फ़ से ढके पहाड़ों के साथ छोड़ देता है। स्थानीय लोगों द्वारा सनातन मानी जाने वाली हिमाच्छादित चोटियाँ अब मौसमी हो गई हैं।

तीव्रगति से पिघलने से नदी के प्रवाह में भी वृद्धि हुई और गर्मियों के दौरान तिब्बत में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। इसने पहाड़ में नई हिमखंड झीलों के निर्माण किया है जो किसी भी समय फट सकती हैं। हिमालय क्षेत्र के नेपाल (भूटान), उत्तर–पूर्व भारतीय राज्यों के कई हिस्सों, भूटानंद के लिए यज ग्लेशियल झीलें गंभीर खतरा बन गई हैं। सौभाग्य से, तिब्बत ने बहुत कम हिमखंड झीलों कि विस्फोड से बाढ़ देखी हैं। लेकिन हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। तिब्बत नीति संस्थान के शोधकर्ताओं ने खम (पूर्वी तिब्बत) में एक पर्वत श्रृंखला के स्माल त्रिज्या के साथ दर्जनों नई ग्लेशियल झीलों के निर्माण का अवलोकन किया। चीनी सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र तिब्बत पर बनी नई ग्लेशियल झीलों की निगरानी में बहुत कम प्रयास या निवेश किया है। चीनी सरकार द्वारा वास्तविक प्रयासों के घटित होने की प्रतीक्षा की जा रही यह आपदा, किसी भी समय अस्थिर प्राकृतिक रूकावटों के बीच ग्लेशियल झीलों के बनने के कारण बन सकती है। आपदा के बाद राहत कार्यों में तेजी लाने के बजाय, जान बचाने और क्षति को कम करने के लिए रोकथाम की कार्रवाई की आवश्यकता है।

तिब्बती पठार पर जलवायु परिवर्तन का और प्रभावः तुषार भूमि

तिब्बती पठार का लगभग 70 प्रतिशत भाग विभिन्न प्रकार की तुषार भूमि वाला है, जिनमें से अधिकतर ऊंची चोटियों वाली तुषार भूमि (इसकी ऊँचाई के कारण) हैं।[184] जब गर्मियों के महीनों में, तुषार भूमि बीच मे पिघलती है, तो यह वर्षा–स्खलित तिब्बती पर वनस्पति के विकास का पोषण करता है। पठार, एक प्रयासरत जिसने तिब्बत के उत्तर और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों के विशाल चरागाहों पर जीवन कायम रखा है। लेकिन 2001 में डेजर्ट रिसर्च की पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 1995 में तिब्बत में 313,000 वर्ग किलोमीटर भूमि का क्षरण हुआ था और संभावित रेगिस्तान भूमि के 30,000 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान की गई थी।

184 पर्यावरण एवं विकास डेस्क, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, तिब्बती पठार पर जलवायु परिवर्तन का प्रभावः हाल की विज्ञान और तिब्बती अनुसंधन का एक संकलन (धर्मशालाः सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग, (2009) http://tibet.net/2009/01/climate-change-report-on-tibet-2009/.

यूएनडीपी की एक रिपोर्ट (2007) में कहा गया है कि तिब्बत के चरागाहों को 2,330 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से रेगिस्तान में बदल दिया जा रहा है।[185] उत्तर–पूर्वी तिब्बत में ज़ोइज वेटलैंड में मरुस्थलीकरण (2012 चीन संवाद) 10 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष बढ़ने की सूचना है। तिब्बती पठार पर ऊंची चोटी के चरागाह सबसे प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो कुल क्षेत्र के 60 प्रतिशत से अधिक पर कब्जा करते हैं, और तेजी से बढ़ रही तुषार भूमि की गिरावट के कारण उत्तर और पूर्वोत्तर तिब्बत के कई हिस्सों में घास के मैदान का तेजी से विघटन हुआ है। यदि यह जारी रहा तो तिब्बत का अधिकांश भाग रेगिस्तान बन सकता है।

चीनी सरकार ने खतरे का एहसास किया है और समस्याओं से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रभाव बनाने, या प्रभावी योजनाओं को लागू करने के लिए बार–बार विफल रही है। यह स्थानीय तिब्बती समुदायों के पारिस्थितिकिय ज्ञान को शामिल करने से इंकार करता है और ज्यादातर मामलों में, स्थानीय तिब्बती समुदायों को पूरी तरह से बताए बिना कि उन्हें इसकी आवश्यकता क्यों है या उनका क्या मतलब है, के बारे में पूरी तरह से जानकारी के बिना नीतियां बनाता और थोपता है।

ऐसा अहंकार आंशिक रूप से चरागाह मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने में ईमानदारी की कमी के कारण है। उदाहरण के लिए, चीनी सरकार ने तिब्बत के एक दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्र कार्दज़े सहित पूरे तिब्बत में सिबाकथार्न, का रोपण लागू किया है, जो चीन के उत्तरी मैदानों में इस्तेमाल की जाने वाली नीति को दोहराता है। लेकिन उत्तरी मैदानी इलाकों के विपरीत, कार्देज़ एक समृद्ध उपजाऊ घाटी है, जिसमें समृद्ध वन आवरण, मध्यम वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में कई नदी घाटियाँ और स्थानीय पर्यावरण के लिए अधिक उपयुक्त एक प्रकार का वृक्ष होना चाहिए, जो कि क्षेत्र में तिब्बतियों को मजबूर करने के बजाय सिबक़थार्न लगाया। यह गुमराह करने वाली नीति के बजाय दोनों लोगों की आजीविका का स्रोत, और भूमि की उर्वरता प्रभावित करती है। यह सामाजिक वास्तविकताओं की परवाह किए

185 किशन खोडे, "क्लाइमेट चेंज ऐंड द राइट टु डेवोलोपमेंट, हिमालयन ग्लैशियल मेल्टिंग ऐंड द फयूचर ऑफ डेवलपमेंट ऑन द तिब्बतन प्लैटो", यूएनडीपी, 7 मई, 2007 https://www. researchgate.net/publication/241759387_Climate_Change_and_the_Right_to_Development_Himalayan_Glacial_Melting_and_the_Future_of_Development_on_the_Tibetan_Plateau.

बिना समान नीतियों को लागू करने और इस क्षेत्र की व्यापक स्थितियों के स्पष्ट मामला था। वनों की कटाई और मौजूदा वनों की सुरक्षा के लिए तिब्बत की पूरी जरूरत है, लेकिन अधिक जानकारी के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण की जरूरत है।

तुषार भूमि के द्रुततर क्षरण से एक और खतरा वायुमंडल में कार्बन की रिहाई है। विश्व की लगभग एक–तिहाई मिट्टी कार्बन, तुषार भूमि क्षेत्रों में संग्रहीत है और यह अनुमान लगाया जाता है कि तिब्बती पठार पर अल्पाइन परमाफ्रोस्ट लगभग 12,300 मिलियन टन कार्बन का भंडार है।[186] यह उष्ण–परमाफ्रॉस्ट, जो जलवायु परिवर्तन के लिए संवेदनशील है। बढ़ते तापमान के लिए अति संवेदनशील है। किसी भी गिरावट से वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन प्रवेश करेगा, जो दुनिया भर में बढ़ते तापमान को और तेज करेगा।

माचेन में हाल ही में हुए भूस्खलन (30 अगस्त 2017) और ज़ातोह (7 सितम्बर 2017) में कीचड़सना भ–ूस्खलन, तुषार भूमि विगलन की दर की गंभीरता का स्पष्ट संकेत हैं। पठार पर बढ़ते तापमान के कारण जमे हुए मैदान तिब्बत भर में जल्दी पिघल जाते हैं, वे बड़ी मात्रा में पिघले पानी को सतह की मिट्टी में छोड़ देते हैं, जिससे कीचड़सना भू–स्खलान पैदा होता है। भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए चीनी सरकार को अभी तक पर्याप्त नीतियों का प्रस्ताव तैयार करना है।

विनाशकारी खननः सार्वजनिक हित की अनदेखी और पर्यावरण के मानदंडों का उल्लंघन

तिब्बत पर कब्जे के बाद से, चीनी अधिकारियों ने विकास के विनाशकारी और गैरजिम्मेदार तरीके को लागू किया, जो तिब्बती लोगों की वास्तविक सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक आवश्यकता को अनदेखा करता है। तिब्बत में आधार उद्योगों के रूप में खनन और पर्यटन की उनकी घोषणा स्पष्ट रूप से "अर्थव्यवस्था, समाज और पारिस्थितिकिय पर्यावरण के सामंजस्यपूर्ण सह–अस्तित्व के साथ निरंतर पथ के अनुपालन के दावे का

186 वही–

खंडन करती है।"[187] विशेष रूप से, तिब्बत के पवित्र पहाड़ों पर सरकार का खनन लोगों की सांस्कृतिक भावनाओं के अनादर के साथ–साथ सांस्कृतिक भावनाओं के लिए अपमानजनक कृत्यों में से एक को उजागर करता है।यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इस शोध में पुष्टि की गई है कि पवित्र स्थलों की पवित्रता में तिब्बती लोगों की मान्यताओं ने प्रमुख पारिस्थितिकिय रूप से प्रमुख क्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण में बहुत योगदान दिया है।[188]

तिब्बत में अनुमानित 132 विभिन्न खनिजों का भंडार है, और ये दुनिया के संसाधनों के भंडार के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिसमें क्रोमियम, नमक, तांबा, चांदी, कोयला, सोना, लिथियम, सीसा, जस्ता, अभ्रक, तेल, गैस, मैग्नीशियम, पोटाश और यूरेनियम शामिल हैं। खनिज अयस्कों और प्राकृतिक संसाधनों की निकासी चीन सरकार द्वारा महंगा आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को ईंधन देने के लिए सख्ती से की गई है।

2007 में चीनी भू–विज्ञान सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया कि तिब्बती पठार में लगभग 30–40 मिलियन टन तांबे का भंडार, 40 मिलियन टन जस्ता और कई मिलियन टन लोहा है। यूलॉन्ग कॉपर माइन में 7.8 मिलियन टन से अधिक तांबे का भंडार है जो इसे चीन में सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा स्थान बनाता है। 2010 की गणना के अनुसार, यहां पर 3,000 से अधिक सिद्ध खनिजों का भंडार है, जिसमें 102 किस्मों के संसाधन अकेले हैं "तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र"(टीएआर) अकेले में हैं।[189]

---

187 चीन जनवादी गणराज्य का राज्य परिषद सूचना कार्यालय, "तिब्बत के विकास का रास्ता, एक अनूठे ऐतिहासिक ज्वार से प्रवाहित है", शिनहुआनेट, 15 अप्रैल, 2015 http://www.xinhuanet.com/english/china/2015-04/15/c_134152612.htm.

188 डैनिका एम. एंडर्सन और अन्य, "कन्जर्विंग द सैक्रेड मेडिसिनी माउंटेन्स वेजेटेशन एनालिसिस ऑफ तिब्बतन सैक्रेड साइट्स इन नॉर्दन यून्नान", बायोडायवर्सिटी ऐंड कन्जर्वेशन, 14, नंबर 13 (2005): 3065–3091, https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-004-0316-9.; साथ ही देखें, सैलिक, जे और अन्य, "तिब्बतन सैक्रेड साइट्स कन्जर्व ओल्ड ग्रोथ थ्रीज ऐंड कवर इन द ईस्टर्न हिमालया", बायो डायवर्सिटी ऐंड कन्जर्वेशन 16, (2007): 693 https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-005-4381-5.

189 "तिब्बत टू सेट अप एक्स्प्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज", चाइना डेली, 13 मार्च, 2010 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-03/13/content_9584983.htm.

चीन की खनन प्रथाओं के विनाशकारी और अनैतिक तरीकों ने पूरे तिब्बत में असंतुलन पैदा और विरोध किया है। 2009 से, तिब्बत में 30 से अधिक ज्ञात बड़े पैमाने पर, खदान से संबंधित विरोध प्रदर्शन हुए हैं। निम्नलिखित मामले, कई मामलों में से कुछ का प्रतिनिधित्व करते हुए, चीनी कब्जे के तहत तिब्बत में विनाशकारी खनन के कारण होने वाली पर्यावरणीय स्थिति को और स्पष्ट करने में मदद करते हैं।

ज़ातो में एक प्रकृति रिजर्व के अंदर खनन

16 अगस्त 2013 को तिब्बत में ज़चेन (मध्य उत्तर) के ज़चेन, अरोड और चीन के 4,500 से अधिक स्थानीय तिब्बती समुदायों ने अपने पवित्र पर्वत पर खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जो कि संजियंग्युआन राष्ट्रीय प्रकृति रिजर्व (एसएनएनआर)[190] के अंदर था।

"मुझे असहाय होने की भावना महसूस हुई, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जिसे हम न्याय की भंग कर सकते थे। "स्थानीय प्रदर्शनकारी सोक चोयडुप ने बताया। लगभग 500 चीनी अर्ध–सैन्य बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और रबड़ की गोलियां दागीं। एक तिब्बती व्यक्ति सोकपो छोहडुप ने खुद को हताशा में चाकू धोंप दिया। चरम असहायता का एक ऐसा ही मामला अन्य उदाहरणों में भी व्यक्त किया गया है।

एसएनएनआर को वर्ष 2000 में चीन सरकार ने यांग्त्ज़ी, पीली और मेकांग नदियों के प्रमुख जल/स्रोत की सुरक्षा के लिए स्थापित किया था। प्रकृति रिजर्व एक विशाल चरागाह के लिए है जहां एक सबसे बड़ा तिब्बती खानाबदोश समुदाय प्रकृति रिजर्व के रूप में क्षेत्र की घोषणा के साथ रह रहा है, कई खानाबदोशों को क्षेत्र से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन विडंबना यह है कि वर्ष 2013 में किंग्हाई प्रांतीय सरकार ने संसाधन विलोपन सराय अरोड और ज़चेन के लिए खनन लाइसेंस जारी किए थे, जो स्पष्ट रूप से एसएनएनआर के हिस्से के रूप में सूचीबद्ध थे,[191] जिससे 13 साल पहले चीनी सरकार के घोषणा के कानून का उल्लंघन

190 केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, "तिब्बती संसद द्वारा खनन के विरोध प्रदर्शन पर चीन के दमन की आलोचना", 22 अगस्त, 2013 http://tibet.net/2013/08/tibetan-parliament-condemns-chinas-repression-on-mining-protest/.

191 "युशू माइन प्रोटेस्ट क्रैकडाउन एक्सपोजेज चाइनाज "नेचर रिजर्व शैम", तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र, 24 अगस्त, 2013 http://tchrd.org/yushu-mine-protest-crackdown-exposes-chinas-nature-reserve-sham/.

हुआ। इस कार्रवाई ने लंबे समय से इस आशंका को मजबूत किया कि चीनी सरकार ने तिब्बत के खानाबदोशों को चरागाह से हटाने की नीति को चीनी खनन कंपनियों के लिए जगह बनाने के लिए प्रेरित किया। हाल के वर्षों में अधिक से अधिक प्रकृति की घोषणा स्वागत योग्य संकेत है, लेकिन चीन सरकार प्रकृति भंडारों की रक्षा के लिए गंभीर प्रयास का अभाव है।

प्रकृति आरक्षित नियमन का एक और उल्लंघन, मुली क्षेत्र के विशाल घास के मैदान पर बड़े खुले गड्ढे वाली कोयला खदानें हैं, जैसा कि ग्रीनपीस चीन ने 7 अगस्त 2014 में अंडर कवर जांच में बताया था।[192] जांच दल ने कहा कि बड़े पैमाने पर मूली कोयला क्षेत्र शामिल थे। पठार पर दो चालु और दो खोलने के कगार पर चार उत्रोपन कास्ट खाना थी। 2013 तक, जियानकांग और जुहेंगेंग खदानों के विस्तार से 42.6 वर्ग किलोमीटर के प्राचीन क्षेत्रों में नुकसान हुआ था। ग्लेशियर और जल संरक्षण के लिए कियान माउंटेन नेशनल इकोलॉजिकल फंक्शनल ज़ोन में जिआंगसांग और जुहेंगेंग खदानें मौजूद हैं, और दो नई खानों ने तीन नदियों (दातोंग, शुल, और बुहा) के स्रोतों के लिए किन्हाई किलियान पर्वत प्रकृति की रिजर्व में अपनी सुविधाएं स्थापित की हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र का मतलब एक सख्त संरक्षण क्षेत्र भी था।

ग्यामा खनन स्थल पर भू-स्खलन।

29 मार्च, 2013 को गयमा खदान में खनन स्थल पर भूस्खलन से 83 मजदूर मारे गए थे। चीनी अधिकारियों ने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाला कि भूस्खलन प्राकृतिक कारकों के कारण हुआ।[193] शिन्हुआ न्यूज ने काई जानों की क्षति के बावजूद, पत्रकारिता की जांच किए बिना आधिकारिक बयान प्रकाशित किया। लेकिन 9 अप्रैल 2013 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट डेस्क (ईडीडी) द्वारा मूल्यांकन की गई एक

192 एक्पोज्ड: कोल माइनिंग ऐट द सोर्स ऑफ चाइनाज येलो रिवर", ग्रीनपीस, 7 अगस्त, 2014 http://www.greenpeace.org/eastasia/news/blog/exposed-coal-mining-at-the-source-of-chinas-y/blog/50394/.

193 "फैटल तिब्बत लैंडस्लाइड कॉज्ड नेचुरल फैक्टर्स: एक्सपर्ट्स", इंग्लिश डॉट पीपल डॉट सीएन English.people.cn, 6 अप्रैल, 2013 http://en.people.cn/90882/8195797.html.

आकलन रिपोर्ट[194] के अनुसार, जिमना खदान के भूस्खलन का वास्तविक कारण खदान के कुप्रबंधन के कारण था।

कम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए जिम्ना में खनन को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया गया है। कई जगहों पर जमीन की पूरी तरह से खुदाई की गई है और कुछ मामलों में खोजबीन, पानी निकालने की प्रक्रिया खनन और सड़क निर्माण में एक पहाड़ का पूरा चेहरा छलनी कर दिया गया है। अभी कुछ ही समय की बात है कि खनन के इतने बड़े पैमाने पर आक्रामक विस्तार से बड़े पैमाने पर आपदा का कारण बन सकता है, रिपोर्ट ने घोषणा की है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि "ग्यामा में भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा के बजाय एक मानव निर्मित घटना है। चट्टानों को खनन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में छोटे टुकड़ों में विघटित किया गया था और ग्लेशियल गतिशीलता के कारण नहीं जैसा कि चीनी अधिकारी दुनिया से विश्वास करने की उम्मीद कर रहे हैं। पर्यावरण एवं विकास देस्क के पास यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि ढीली चट्टान भूस्खलन में बदल गई है और पहाड़ के शीर्ष पर सतह खनन से ऐसा हुआ है जिसे पूर्वी तट पर इकट्ठा किया गया था जहाँ भू–स्खलन की उत्पत्ति हुई थी।[195]

मिन्यांक ल्हांगोंग में नदी प्रदूषण

4 मई 2016 को, लिचू नदी में मछलियों की अचानक सामूहिक मृत्यु, कर्जे में पर मिनयाक लहागोंग के स्थानीय तिब्बती गलियों में प्रदर्शन के लिए निकल आए, जो रोंडा लीथियम कंपनी लिमिटेड[196] नामक एक लिथियम खनन कंपनी के खिलाफ विरोध कर रहे थे। मिनियाक लाहोंग एक तिब्बती क्षेत्र है जो चीनी प्रांत सिचुआन, कार्ज़ तिब्बती स्वायत्त प्रान्त में शामिल है। कंपनी ने खदान के अपशिष्ट (संभवतः लिथियम पानी के भंडारण) को

194 पर्यावरण एवं विकास डेस्क, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, "असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द रीसेंट लैंडस्लाइट इवेंट इन द ग्यामा वैलीः इट्स पॉसिबल कॉज ऐंड इम्पैक्ट्स", 9 अप्रैल, 2013 http://tibet.net/2013/04/assessment-report-of-the-recent-land-slide-event-in-the-gyamavalley/.

195 वही–

196 येशी दोरजी, "चाइनीज पोलिस कैम्प डाउन ऑन तिब्बतन माइनिंग प्रोटेस्ट", वायस ऑफ अमेरिका, 6 मई, 2016 https://www.voanews.com/a/chinese-police-clamp-down-tibetan-mining-protest/3319093.html.

स्थानीय नदी में न्यचू/यालोंग नदी की सहायक नदी में डाल दिया था।[197]

यह पहली बार या नदी के जल प्रदूषण का कोई पृथक मामला नहीं था। 2013 में, उसी नदी को लिथियम खदान के कचरे से प्रदूषित किया गया था, जिससे समुद्री जीवन की मौत हो गई और स्थानीय पेयजल के लिए खतरा पैदा हो गया था।

इसी तरह के एक मामले में, 23 सितंबर 2014 को, ल्हासा के निकट डोकर और ज़िबुक गांवों (लुंड्रुप काउंटी, शिगात्से क्षेत्र) के 1000 से अधिक स्थानीय तिब्बती लोगों ने अपने नदियों में मिलाए जहर के खिलाफ विरोध जताया था। खदान एक धारा के करीब स्थित है जो पीने के पानी, सिंचाई और जानवरों को खिलाने के लिए स्थानीय लोग उपयोग करते है। मुख्य रूप से, स्थानीय अधिकारियों ने घोषणा की कि नदी में जल प्रदूषण प्राकृतिक कारकों के कारण हुआ है न कि खनन कंपनी द्वारा। लेकिन 2010 के एक लेख में, "तिब्बत गयमा घाटी में सतह के पानी की गुणवत्ता पर खनन गतिविधि का पर्यावरणीय प्रभाव" में शियांग ने जोर दे कर कहा है:

> *महान पर्यावरण संबंधी चिंताएं घाटी में कई खनन और प्रसंस्करण जमा हैं, जिनमें भारी मात्रा में भारी धातुएं शामिल हैं, जैसे सीसा, तांबा, जस्ता और मैंगनीज आदि। ये जमाव सीप के पानी और विविक्तों के क्षरण के माध्यम से इसके संदूषण के रिसाव का खतरा है, और इसलिए स्थानीय पर्यावरण के लिए भविष्य का खतरा पैदा होता है और बहने वाले पानी की गुणवत्ता के लिए एक संभावित खतरा है।*[198]

गांव के एक स्थानीय निवासी ने रेडियो फ्री एशिया को बताया, "अतीत में, हमारी नदियाँ खस्ता और स्वच्छ थीं, पहाड़ और घाटियाँ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाती थीं। लेकिन अब नदियों को खानों से निकलने वाले

---

197 येशी छोसांग, "तिब्बतन्स प्रोटेस्ट अगेन्स्ट चाइनीज माइनिंग इन मिन्याक काउंटी, तिब्बत, द तिब्बत पोस्ट इंटरनेशनल, 6 मई, 2016 http://www.thetibetpost.com/en/news/tibet/4998-tibetans-protest-against-chinese-mining-in-minyak-county-tibet.

198 हुआंग एक्स और अन्य, "एनवायर्नमेंटल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज ऑन द सरफेस वाटर क्वालिटी इन तिब्बतः ग्यामा वैली, साइंस ऑफ द टोटल एनवायरमेंट 408, नंबर 19 (2010): 4177–4184 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969710004882?via%3Dihub. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969710004882?via%3Dihub.

जहरीले कचरे से प्रदूषित किया जाता है,[199] स्पष्ट रूप से स्थानीय पर्यावरण के तेजी से विनाश का वर्णन करता है।

अमचोक में एक पवित्र पर्वत पर खनन

31 मई, 2016 को अमचोक में अनुमानित 2,000 स्थानीय तिब्बती अपने पवित्र पर्वत पर गोंग–न्यंग लारी खनन गतिविधियों का विरोध करने के लिए एकत्र हुए। आठ विभिन्न स्थानीय समुदाय पहाड़ को अत्यधिक पवित्र मानते हैं। उस पहाड़ पर खनन ने उन स्थानीय समुदायों और उनकी मान्यताओं को भरी ठेस पहुंचाई था।

अमचोक, अमाडो के लेब्रंग क्षेत्र में है, तिब्बती क्षेत्र गांसु (सेंचू प्रांत, कनलो तिब्बती स्वायत्त प्रान्त) के चीनी प्रांत में शामिल है। प्रदर्शनकारी "पर्यावरण की रक्षा, पवित्र पर्वत की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के संरक्षण" का आह्वान कर रहे थे।

चीनी सरकार ने शांतिपूर्वक सभा को क्रूरतापूर्वक दबा दिया, कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उनमें से छह को हिरासत में ले लिया।

भावनाओं की कुल उपेक्षा और उनके पवित्र पर्वत पर खनन के कारण चिंताओं, त्सेरिंग थोंडुप और कोंचोक त्सेरिंग ने नेतृत्व किया और खुद को 20 नवम्बर 2012 और 26 नवंबर 2012 को खदान स्थल पर आग लगा दी। 19 दिसंबर 2013 को एक तीसरे आत्म–हाह, त्सुलट्रीम ग्यात्सो ने भी उनके बलिदान के कारण के रूप में उनके पवित्र पर्वत पर खनन के कारण भारी पीड़ा व्यक्त की। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गणराज्य के खनिज संसाधन कानून का अनुच्छेद 10 कहता हैः "राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्रों में खनन खनिज संसाधनों में, राज्य को उन क्षेत्रों के हितों पर विचार करना चाहिए और क्षेत्र के आर्थिक विकास और उत्पादन के लिए और स्थानीय अल्पसंख्यक की भलाई अनुकूल व्यवस्था करनी चाहिए।" लेकिन हाल के वर्षों में, खनन की वजह से पर्यावरण के विनाश के मामलों की बढ़ती संख्या और शांतिपूर्ण पर्यावरण विरोध प्रदर्शनों का दमन स्थानीय हितों के लिए

199 "विलैजर्स प्रोटेस्ट इन तिब्बत्स मालड्रो गोंगकार काउंटी ओवर माइन पॉल्युशन", रेडियो फ्री एशिया, 29 सितंबर, 2014 https://www.rfa.org/english/news/tibet/pollution-09292014152011.html.

संरक्षण और सम्मान की अनुपस्थिति को दर्शाता है। तिब्बतियों के बीच इन नीतियों से गहरी निराशा के साथ, चीन सरकार तिब्बत की पर्यावरण, संस्कृति और लोगों के लिए समझ या चिंताओं की कमी दिखाती है।

गैर जिम्मेदाराना बाँध निर्माण : मेगा बांधों ने ग्रामीण पठार को अस्थिर कर दिया और एशिया में लाखों लोगों की जान को खतरा बना है।

तिब्बत ने 1950 के दशक से अपने नदियों पर बांधों का अंधाधुंध निर्माण जारी रखा है। मेगा बांधों के निर्माण की एक नई प्रवृत्ति, हालांकि, दुनिया के सबसे ऊंचे पठार के लिए एक और भी अधिक गंभीर खतरा है, जो कि भूकंपीय गतिविधियों [200] के लिए बहुत अधिक खतरा है जो कि प्रतिस्पर्धा में अधिक से अधिक मेगा बांधों नदियों के समूहों द्वारा बढ़ सकता है। प्रोबे इंटरनेशनल ने अप्रैल 2012 में चेतावनी दी थी कि पश्चिमी चीन में बनाए जा रहे 98.6 प्रतिशत बांध मध्यम से बहुत उच्च भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्रों में स्थित हैं।[201] नवंबर 2017 के महीने में, निंगत्री क्षेत्र [202] में भूकंप की एक श्रृंखला शुरू हुई)। जहां बहुत से बांध यारलुंग त्सांगपो पर बनाये गये हैं।

क्षेत्र के वन्यजीव आवास और नदी के प्रवाह पर मेगा बांधों का प्रभाव स्पष्ट है, लेकिन सबसे भयानक खतरा वेन्चुआन और लुडियन भूकंप जैसी जलाशय–प्रेरित सेस्मिक (आरआईएस) गतिविधियों से है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेगा बांध दोनों ही भूकंप की ट्रीगर और शिकार हो सकते हैं: भूकंप से किसी भी मेगा बांध को नुकसान पहुंचने की संभावना है, जिससे भूकंप की प्रतिक्रिया फैलने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया हो सकती है। फैन जिओ के अनुसार, 2008 के वेन्चुअन इयरक्वाक, जिसने युन्नान में 80,000 लोग मारे गए थे और 2014 के लुडियन भूकंप दोनों ही मेगा बांधों से प्रेरित

200 देंग क्वी–दोंग और अन्य, "सीस्मिक एक्टिविटीज ऐंड अर्थक्वेक पोटेंशियल इन द तिब्बत प्लैटो", चाइनीज जर्नल ऑफ जियोफिजिक्स 57, नंबर 5 (2014): 678–697, 2014. http://html.rhhz.net/Geophy_en/html/20140506.htm.

201 "प्रेस रिलीजः फेवरिश चाइनीज डैम बिल्डिंग कुड ट्रिगर सुनामी", प्रोब इंटरनेशनल, 3 अप्रैल, 2012 https://journal.probeinternational.org/2012/04/03/press-release-feverish-chinese-dam-building-could-trigger-tsunami/.

202 यांग यी, संपादित, "नो कैजुअलिटीज फ्रॉम 2 तिब्बत अर्थक्वेक्स", शिनहुआनेट, 20 दिसंबर, 2017 http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/20/c_136839848.htm.

थे, जिनमें जिपिंग्पु डैम और ज़िल्लोडु डैम शामिल थे।[203] वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञात जोखिम और स्पष्ट चेतावनी के बावजूद, चीनी सरकार तिब्बत के अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र पर मेगा बांध बनाना जारी रखती है, इनमें शामिल हैं: मध्य तिब्बत के ग्यात्सा क्षेत्र में यारलुंग त्सांग्पो पर 510– मेगावॉट ज़मू हाइड्रोपावर बांध, 2015 में आए विनाशकारी नीप भूकंप के दोष रेखा से बहुत दूर नहीं; न्यारचोंग क्षेत्र में न्याचू नदी पर 295 मीटर ऊंचा लियांगेखो बांध, पूर्वी तिब्बत में, लुडियन और वेन्चुआन भूकंपों से बहुत दूर नहीं; और दक्षिण–पूर्व तिब्बत के मार्खम और बाथंग क्षेत्रों की सीमा पर यांगज़े नदी के हाल ही में घोषित 1.2 मिलियन किलोवाट सुवालोंग जलविद्युत स्टेशन।

रिकॉर्ड पर अपनी तरह के शक्तिशाली भूकंप में से एक, 1950 में असम–तिब्बत में आए 8.6 तीव्रता के भूकंप ने दक्षिण–पूर्व तिब्बत के हेट निंगिंग्री, चमडो और जायउल क्षेत्रों में लोगों को मौत की नींद सुला दिया। भूकंप की तीव्रता के कारण भूस्खलन हुआ और मेटोक में येदोंग गांव को यारलुंग त्सांगपो में फिसलने के कारण बह गया। इस शक्तिशाली भूकंप ने भारत में भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, जहां बड़े भूस्खलन ने अरुणाचल और असम में सुबनसिरी नदी अवरुद्ध हो गयी। यह प्राकृतिक बांध आठ दिन बाद टूट गया, जिससे 23 फीट ऊंची लहर पैदा हुई, जिसमें कई गाँव बह गए और 536 लोग मारे गए।[204] अगर आज भी भू–स्खलन का एक समान परिदृश्य सामने आता है, तो यह बांध की दीवारों को कमजोर कर सकता है, या भूस्खलन बांधों को तोड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप तिब्बत के भीतर और निछले हिस्से के देशों के लिए एक अकल्पनीय तबाही हो सकती है। जाहिर है, तिब्बती नदियों पर जल्दी से जल्दी मेगा बांध बनाने की मौजूदा प्रवृत्ति गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।

चूंकि, तिब्बत एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसमें बड़ी नदियों के जल के क्षेत्र हैं, इसकी ऊर्जा की जरूरत कुशल, स्माल हाइड्रोपावर स्टेशनों या विशाल सौर ऊर्जा क्षमता का उपयोग करके पूरी की जा सकती है।

---

203 जेन क्विउ, "चाइनीज डेटा हिंट ऐट ट्रिगर फॉर फैटल क्वेक", नेचर, 10 सितंबर, 2014, https://www.nature.com/news/chinese-data-hint-at-trigger-for-fatal-quake-1.15883.चीफ इंजीनियर फैन शियाओ, रीजनल जियोलॉजिकल टीम, सिचुआन जियोलॉजी एवं मिनरल ब्यूरो, चेंगदू

204 "हिस्टोरिक अर्थक्वेक्स, असम–तिब्बत 1950, 15 अगस्त," https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/official19500815140934_30/impact

हालांकि, पीआरसी खनन और शहरीकरण के तेजी से विस्तार का समर्थन करने के लिए इन बांधों का निर्माण जारी रखे हुए है। उदाहरण के लिए, चमोडो क्षेत्र में गुओदुओ हाइड्रोपावर स्टेशन (उस समय तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन) के निर्माण के लिए नवंबर में आयोजित एक समारोह में, "तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के उपाध्यक्ष" "पेमा त्सावांग, ने कहा कि स्टेशन युलोंग कॉपर माइन के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।[205] यूलोंग का चीन में सबसे बड़ा तांबा जमा है। यहां तक कि प्रस्तावित ल्हासा–छलपदह–ट्राई–चेंग्दू लाइन एक लंबी चक्कर लगाकर एक असामान्य मोड़ लेती है। खनन शहर यूलोंग तक पहुँचने के लिए इसके नामचीन शहरों के बीच सबसे सीधा रास्ता है।[206]

बांध उन्माद के पीछे एक और मकसद तिब्बत के कुछ हिस्सों में चीनियों के व्यापक प्रवास का समर्थन करना है, जैसे कि दक्षिण–पूर्वी तिब्बत में निंगट्री, एक संसाधन संपन्न क्षेत्र जो कि वन क्षेत्र के साथ समशीतोष्ण जलवायु का आनंद देता है। चीनी सरकार ने पहले ही राजमार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों और मेगा बांधों के तेजी से निर्माण में निवेश किया है ताकि तिब्बती क्षेत्र में चीनी के व्यापक जन प्रवास को आसान बनाया जा सके।

व्यापक बांध निर्माण का लक्ष्य चीन सरकार के कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करना भी है। कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए और 2030[207] तक पुनर्नवीकरण संसाधनों के लिए अपनी कुल ऊर्जा खपत का 20 प्रतिशत स्रोत के लिए पीआरसी की प्रतिबद्धता एक स्वागत योग्य प्रयास है, लेकिन तिब्बती पठार को नष्ट करने और तिब्बती लोगों को विस्थापित करने की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। लगभग 6,000 तिब्बतियों को अपने पूर्वजों के घरों से बाहर दक्षिण पूर्वी तिब्बत के न्याचू क्षेत्र में लियांगखेऊ

---

205 गुओदो पनबिजली केंद्र का निर्माण शुरू करने की तैयारियां, चाइना तिब्बत ऑनलाइन, 30 नवंबर, 2009 http://chinatibet.people.com.cn/6827895.html.

206 छेओदोन, "दारत्सेदो से न्यींगत्री तक चेंगदू–तिब्बत रेलवे स्टेशन लाइन का निर्माण अगले साल शुरू होगा, चाइना तिब्बत ऑनलाइन, 9 नवंबर, 2016 http://tb.tibet.cn/2010news/xzxw/lyjt/201611/t20161109_4132682.html.

207 ग्रैस मोन्ग, "नो नीड टु सैक्रिफाइस एशियाज रिवर्स टु पावर चाइनाज डेवलपमेंट", चाइना, वाटर रिस्क, 10 फरवरी, 2015 http://www.chinawaterrisk.org/opinions/china-no-need-to-sacrifice-rivers-for-power/.

बांध के निर्माण के लिए विस्थापित होने के लिए मजबूर किया गया था।[208]

घुमन्तु तिब्बतियों का बलात निष्कासन : चरागाहों के संरक्षकों को गरीबी में धकेला

तिब्बत में चराग़ाह अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग 70 प्रतिशत है। उच्च ऊंचाई पर अल्पाइन घास का मैदान, बदले में, कुल तिब्बती रंगभूमि का 60 प्रतिशत। तिब्बती पठार पर देहातीवाद में खेती की सीमा से अधिक ऊंचाई पर ठंड वातावरण का अनुकूलन शामिल है। पुरातात्विक क्षेत्रवाद के अनुसार, देहाती खानाबदोशों में चरागाहों की गतिशीलता और पशु चिकित्सा ज्ञान की गहरी समझ विकसित की है, और 8000 से अधिक वर्षों से एक अद्वितीय देहाती संस्कृति को बनाए रखते हुए तिब्बती पठार का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है।

आज तक, तिब्बती खानाबदोश एक आश्वस्त विशाल पठार पर पर्यावरण मित्र के रूप में आत्मनिर्भर जीवन जीते हैं। लेकिन चीन की सरकार ने दो मिलियन से अधिक तिब्बतियों[209] को अपनी जमीन से हटा दिया है और उन्हें बड़े पैमाने पर बस्तियों में धकेल दिया है, जहां कोई चिकित्सा, शैक्षिक या व्यावसायिक अवसर नहीं हैं, जो एक सम्मानजनक जीवन का समर्थन करते हैं और अपनी पहचान बनाए रखते हैं।

चीन की सरकार चरागाहों को पुनः प्रारम्भ करने की बात चराई पर प्रतिबंध लगा कर इस गलत अनुमान से करती है कि चरागाहों का क्षरण का केवल एक मात्र कारण चराई है। चीनी वैज्ञानिकों सहित बहुत से वैज्ञानिकों ने ईको–तंत्र का स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिये मध्यम चराई की आवश्यकता पर व्यापक रूप से लिखा है। तिब्बती खानाबदोशों, जिन्होंने नाजुक चरागाहों का संरक्षण किया है, के बलात निष्कासन से वास्तव में इनके संरक्षण को बढ़ावा मिला है। तिब्बती खानाबदोशों का बलात पुनर्वास स्पष्टतया चीन की ओर से गैर जिम्मेदाराना प्रशासन का स्पष्ट मामला हैः पहले घुमन्तुओं

208 "चाइनाज ड्राइव टु बिल्ड डैम्स फॉर ग्रीन पावर थ्रीटेन्स होम्स ऐंड सैक्रेड माउंटेन्स", साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, 26 जून, 2017 https://www.scmp.com/news/china/society/article/2099970/chinas-drive-build-dams-green-power-threatens-homes-and-sacred.

209 "चाइनाः एंड इन्वॉल्युन्ट्री रीहाउसिंग, रीलोकेशन ऑफ तिब्बतन्स", ह्यूमन राइट्स वॉच, 27 जून, 2013 https://www.hrw.org/news/2013/06/27/china-end-involuntary-rehousing-relocation-tibetans.

पर पर्याप्त प्रमाणों के बिना चरागाहों के क्षरण का आरोप लगाया, तब उन्हें उनकी परम्परागत जीवन–चर्या से अलग किया और अंततः उन्हें जीवन जीने के लिये खेतों, पशु–धन और पर्याप्त रोजगारों के बिना बुरी तरह से अनियोजित पुनर्वास बस्तियों में तब्दील कर दिया।[210]

बलात निष्कासित घुमन्तुओं के साथ किये गए स्कूल, अस्पतालों और रोजगारों के वायदे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तिब्बती घुमन्तु, जो कभी स्वस्थ और आत्म–निर्भर जीवन बिताते थे, को अचानक विस्थापन और गरीबी में धकेल दिया। अंततः यह सरकार द्वारा संस्कृति और जीवन–चर्या को तबाह करने की चाल है।

भारी कूड़ा: कचरा प्रबंधन सुविधाएं केवल शहरों में उपलब्ध हैं

चीनी सरकार ने बढ़ती गतिविधियों के साथ सामना करने के लिए आवश्यक कचरा प्रबंधन में ज्यादातर सरकारी निवेश कुछ चुनिंदा पर्यटन केंद्रों और शहरों में केंद्रित है, जैसे कि गृह शासन के अधिकारी, जैसे कि ग्यालथंग, डार्टडेडो, ल्हासा, शिगात्से, काईगूडो और ज़िटसडेग। जैसे ही कोई इन कस्बों और शहरों से बाहर जाता है, कूड़े का ढेर लग जाता है और कचरा प्रबंधन लगभग न के बराबर हो जाता है। स्थिति ने स्थानीय समुदायों को अपने स्वयं के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया है: स्वैच्छिक पर्यावरणीय समूहों ने आसपास के पहाड़ों से कचरे के ट्रक लोड को इकट्ठा करने के लिए गठित किया है। कचरे से निपटने के लिए अधोसंरचनात्मक प्रावधानों के अभाव में, स्थानीय लोग कचरे को जलाते हैं, अनजाने में अधिक पर्यावरणीय खतरे पैदा करते हैं। स्थानीय तिब्बतियों ने उनकी मदद के लिए आवाज़ उठाई है क्योंकि सरकार उन्हें कचरा परिवहन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा ट्रक भेजने या भवन में कचरा उपचार स्थल बनाने जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफल रही है।

बढ़ती प्राकृतिक आपदा: एक खतरे की अनदेखी और बुरी तरह से प्रबंधित

वर्ष 2016 में अल्पावधि में अप्रत्याशित संख्या में प्राकृतिक आपदाएं देखी गयीं। 9 जुलाई को, उत्तरी पूर्वी तिब्बत के तसोल्हो में किचड–स्खलन और

210 फाछुन डू, "इकोलॉजिकल रीसेटलमेंट ऑफ तिब्बतन हर्डर्स इन द सान्जियानगुअयान: अ केस स्टडी इन मडोई काउंटी ऑफ क्विंघई, नौमैडिक पीपल्स 16, नंबर 1 (2012): 116–133.

भू–स्खलन हुआ जिसमें दो व्यक्ति मारे गए और 30 से अधिक ज़ख्मी हुए। 17 जुलाई को, पश्चिमी तिब्बत में नगारी के रूथोक प्रांत में एक ग्लेशियर के खिसकने से 9 व्यक्ति मारे गए और 110 याक व 350 भेड़ें दब गयीं।[211] 22 अगस्त को उतर–पूर्वी तिब्बत में बाढ़ से भारी मात्रा में सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

तिब्बत में 2017 के दौरान और अधिक प्राकृतिक आपदाएं घटित हुई जिसमें 15 जून को रोगद्रेक में 6000 से अधिक घर बाढ़ से ग्रसित हो गए जिसमें 30,000 अधिक लोग प्रभावित हुए; 6 जुलाई को देगे की बाढ़ में कई घर क्षतिग्रस्त हुए ;और जुलाई मास में पूर्वी तिब्बत की जोमदा की बाढ़ों ने तीन व्यक्ति मारे गए थे और कई घर क्षतिग्रस्त हुए थे। स्थानीय तिब्बती बार –बार प्राकृतिक आपदाओं के आने की प्रवृति से चिंतित थे, एक प्रवृति जिसका तिब्बत के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्थानीय जनता के अनुसार "तिब्बत में एक नया सामान्य" होने का भय है।[212]

दुर्भाग्य से चीन की सरकार ने इन प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबले के लिए बहुत कम किया है। बाढ़ों और भूस्खलनों से जान और माल की क्षति को बहुत कम कार्य किया जा सकता था यदि चीन की सरकार बचाव के कदम उठाती और यथोचित नीतियों को लागू करती। यहां तक कि नदी के किनारे बसे गांव और कस्बों में तट बन्धनों का साधारण कार्य से बहुत सारे नुकसान से बचा जा सकता था।

यद्यपी चीन की विज्ञान अकादमी ने 2015 की रिपोर्ट[213] में भूस्खलन, तेज़ बारिश, हिम आपदाएं तथा वनों की आग[214] सहित प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने की चेतावनी दी है, चीन की सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है

---

211 "मैसिव ऐंड मिस्टीरियस आइस अवालान्च इन तिब्बत", अर्थ ऑब्जर्वेटरी, 7 सितंबर, 2016 https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=88677.; यह भी देखें, "अ सेकंड मैसिव आइस अवालान्चे इन तिब्बत," नासा https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=88953.

212 जामल्हा, तेम्पा ग्यालत्सेन, "नेचुरल डिजास्टर्स इन तिब्बतः इज इट द न्यू नॉर्मल?", तिब्बत पॉलिसी इंस्टीट्यूट, 8 अगस्त, 2016 https://tibetpolicy.net/comments-briefs/natural-disasters-in-tibet-is-itthe-new-normal/.

213 "रिपोर्ट ऑन साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ एनवयार्नमेंटल चेन्जेज इन तिब्बत प्लैटो", चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज, 18 नवंबर, 2015 http://www.cas.cn/yw/201511/t20151117_4465636. shtml#rdss.

214 वही

या इस चुनौती का सामना करने के लिए कोई नई नीति बनाई है।

तिब्बत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव संसाधनों के दोहन और बांध–निर्माण से और भी तेज हो गया है। खनन तिब्बत के लोगों और धरती के लिए भारी चिंता का विषय बन गया है जिसके कारण भूस्खलन, चरागाह क्षरण तथा जल–प्रदूषण हो रहा है। तसोल्हो के स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में बेतहाशा खनन और पर्वतों के बीच सुरंगें बनाने से हाल की किचडी–बाढ़ का आरोप लगाया है।

जलवायु परिवर्तन के गम्भीर प्रभावों के बावजूद निर्देशों और जागरूकता कार्यक्रमों की कमी अभी भी है और चीन की सरकार तिब्बती पठार को प्रभावित करने वाले खतरनाक जलवायु गत परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रही। इसकी अपेक्षा इसकी बहुत सी पर्यावरण से सम्बंधित नीतियां जो हाल के वर्षों में बनाई गई हैं केवल शहरी तटीय प्रदूषण समस्याओं के समाधान के लिये लक्षित की गई हैं जबकि तिब्बत तथा शिनजियांग के जातिगत क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण के सरंक्षण के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिये।

निष्कर्ष

2015 में नये पर्यावरण सरंक्षण क़ानून को लागू करना एक स्वागत योग्य क़दम है क्योंकि यह क़ानून के कार्यान्वयन को सुदृढ बनाता है और चीन में शक्तिरहित पर्यावरण संरक्षण अधिकारियों का पुनर्नवीनीकरण करता है। लेकिन नए पर्यावरण कानून निष्पक्ष और सुदृढ़ कार्यान्वयन अभी तिब्बत में दिखाई नहीं देता। हाल ही में बड़े बांधों के निर्माण में वृद्धि, संसाधनों के उत्खनन का विस्तार और शांतिपूर्ण पर्यावरण से सम्बंधित विरोध नए पर्यावरण कानून के विपरीत हैं।

इस तरह के विरोधाभासों और गैर–ईमानदारी के मामले बहुत सारे हैं। एक मामले में परमपावन दलाई लामा के परामर्श पर वर्ष 2006 के बाद तिब्बतियों ने सामुहिक रूप से पशुओं के बालों और चमड़ी से बने कपड़ों की परंपरा त्याग दी। यह प्राचीन और उच्च मूल्यों की परंपरा को त्याग कर तिब्बतियों ने पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर भी चीन की सरकार तिब्बती कर्मियों को पशुओं के बालों के कपड़े पहनने के लिए बाध्य और विवश करते हैं जो स्पष्टतया अपने ही कानून के विपरीत है जिसमें

वन–पशुओं की 125 प्रजातियों को राज्य–संरक्षण प्रदान किया गया है।

चीनी सरकार को तिब्बती पठार पवित्र पर्वतों, झीलों और नदियों की पवित्रता सम्बन्धी तिब्बती लोगों की सांस्कृतिक आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके अधिकारों का संरक्षण करना चाहिये। चीन की सरकार द्वारा तिब्बत में खनन परमिट के लिए प्रतिस्पर्धात्मक विश्वसनीय पर्यावरण प्रभाव अनुमानों तथा सामाजिक प्रभावों के अनुमानों के आधार पर पारदर्शी, बिना समझौते वाली सुदृढ़ प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिये। चीन की सरकार को कड़ाई से खनन कम्पनियों की निगरानी करनी चाहिए और खान के ख़तरनाक अपशिष्ट को समीपवर्ती क्षेत्रों या नदियों में डालने से रोकना चाहिए।

तिब्बत के चरागाही खानाबदोश ऊंची चरागाहों के विशेषज्ञ अभिभावक हैं और उनके ज्ञान और अनुभव को जलवायु शमन और अनुकूलन अभ्यासों में अवश्य शामिल किया जाना चाहिये। निर्णय करने वाली प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इसमें सभी हित धारकों विशेषतया तिब्बती घुमन्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए। तिब्बती घुमन्तुओं का अपनी ज़मीन से बलात निष्कासन रोक दिया जाना चाहिये और जो चरागाहों में वापिस जाना चाहते हैं उन्हें अनुमति दी जानी चाहिये। चीन की सरकार को अतिशीघ्र तिब्बती घुमन्तुओं के लिए घटिया ढंग से नियोजित पुनर्वास कार्यक्रमों को ठीक करना चाहिये। अपनी पारम्परिक आत्म–निर्भर जीवन चर्या को खोने पर, चीन सरकार को नए स्थापित पुनर्वास घुमन्तुओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य देख–रेख सेवाएं प्रदान करनी चाहियें सकारात्मक दृष्टि से, हाल के वर्षों में चीन की सरकार ने तिब्बत के गिर्द अधिक राष्ट्रीय पार्कों और नेचर रिज़र्व की घोषणा की है। भविष्य में, ऐसे कानूनों और नीतियों के गठन के समय तिब्बती लोगों की सांस्कृतिक भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त स्थानीय ज्ञान को शामिल किया जाना चाहिये, और लोगों की आवाज़ और ज़रूरतों को सुना जाना चाहिये तथा उन पर विचार किया जाना चाहिये। नेचर रिज़र्व घोषित किये गए क्षेत्रों में रहने वाले तिब्बतियों का जीवन कम नहीं आंका जाना चाहिये।

शहरों और कस्बों के द्रुततर विस्तार ने तिब्बत के नाजुक पारस्थितिकीय तंत्र पर गहरा परस्तिथिकीय दबाव डाला है। स्पष्ट शहरी नियोजन दिशा निर्देश स्थापित किये जाने चाहिए और चीन सरकार द्वारा कड़ाई से पालन किया

जाना चाहिये। चीन के प्रमुख भागों के शहरीकरण की गलती तिब्बती पठार में दोहराई नही जानी चाहिये। तिब्बत में पर्यटकों की आवाजाही को अवश्य नियमित किया जाना चाहिए ताकि पठार के नाजुक पारिस्थितिकीय तंत्र को संरक्षित किया जा सके। तिब्बत में किसी भी प्रमुख विकासात्मक परियोजना के लिए चीन सरकार द्वारा तिब्बती जनसंख्या को भी साथ लेना चाहिये। शहरी नियोजन में भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तिब्बत में 2016 के बाद प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ने और तदनन्तर जान–माल का नुकसान अनियमित तथा बिना सोच–समझ के शहरीकरण के कारण हुआ है। जैसे ही जलवायु परिवर्तन बढ़ता है, प्रभाव तिब्बती पठार से बाहर तक फैलेगा जिससे करोड़ों लोगों की जलापूर्ति में परिवर्तन आएगा और आधे ग्रह पर वातावरणीय चक्र बदल जायेगा। बीजिंग, पेरिस जलवायु समझौते में प्रमुख देश था और अब अपनी मंशा कागज़ों पर ही नहीं अभ्यास में भी दिखाने की आवश्यकता है। इसे तिब्बती पठार की वैश्विक पर्यावरणीय महत्ता को समझने की आवश्यकता है। तिब्बत के लोगों का और उनकी पर्यावरणीय चिंता का सम्मान करना चाहिये।

परमपावन दलाई लामा निरन्तर इस बात पर बल दिया है कि पर्यावरण संरक्षण एक सार्वभौमिक मुद्दा है और राजनीतिक चिंताओं से ऊपर है। चीन की सरकार को तिब्बतियों के साथ मिल कर इकट्ठे विश्व के सबसे ऊंचे पठार को और अधिक श्रतिग्रस्त और क्षरित होने से बचाना चाहिए।

अध्याय छह

तिब्बत में आर्थिक विकास का वास्तविक स्वरूप

परिचय

2015 में चीनी सरकार ने तिब्बत पर एक श्वेत पत्र जारी करने के तुरंत बाद, 6 सितंबर 2015 को चाइना डेली ने रिपोर्ट में दावा किया था कि तिब्बत "अब अपने सुनहरे युग में है,"[215] जो क्षेत्रीय जातीय स्वायत्तता की पीआरसी की नीति से लाभान्वित हो रहे हैं। उसी दिन शिन्हुआ के एक रिपोर्ट में कहा गया था कि "शहरी और ग्रामीण निवासियों के रहने की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है।" श्वेत पत्र की ओर संकेत करते हुए, यह कहा जाता है कि "तिब्बत की जीडीपी 1965 में 327 मिलियन युआन से बढ़कर 2014 में 92.08 बिलियन युआन (डोलर 14.5 बिलियन), 281 गुना वृद्धि हुई है ...."[216] इसी प्रकार, हालही में चीन डेली ने 29 जुलाई 2017 को एक रिपोर्ट दी, जिसमें उसने "मजबूत आर्थिक विकास" का आनंद लेने के लिए "तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र" को घोषित किया, और वर्ष की पहल छह माहिने में जीडीपी की वृद्धि दर 10.08 प्रतिशत तक स्थिर रही।[217]

दूसरे शब्दों में, चीनी सरकार ने तिब्बत की उदात्त छवि को चित्रित किया है जो अब "स्वर्ण युग" में रह रहा है।

इस क्षेत्र में उल्लेखनीय जीडीपी वृद्धि एक मीट्रिक है जिसने चीन को अपनी उपलब्धियों की घोषणा करने में अच्छा काम किया है। जैसा कि उपर्युक्त श्वेत पत्र में कहा गया हैः "1994 के बाद से, तिब्बत की जीडीपी औसतन 12.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है, जो लगातार 20 वर्षों तक दोहरे

215 "चाइना इशूज व्हाइट पेपर ऑन तिब्बत," चाइना डेली, 6 सितंबर, 2015 http://usa.chinadaily.com.cn/china/2015-09/06/content_21796167.htm.

216 "तिब्बत्स जीडीपी इनक्रीज्ड बाय 281 टाइम्स इन 50 ईयर्सः व्हाइट पेपर", शिन्हुआ नेट, 6 सितंबर, 2015 http://www.xinhuanet.com/english/2015-09/06/c_134593930.htm.

217 "तिब्बत रिपोर्ट्स रोबस्ट जीडीपी ग्रोथ इन एच1", चाइना डेली, 29 जुलाई 2017, http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-07/29/content_30288305.htm.

अंकों में वृद्धि दर्ज करती है।" निस्संदेह, एक बड़ा राज्य–प्रेरित आर्थिक परिवर्तन, तिब्बत में मौजूद है। हालाँकि, चीन ने शोधकर्ताओं और पत्रकारों के लिए स्वतंत्र रूप से तिब्बत की जांच, रिपोर्ट और अध्ययन करना कठिन बना दिया है, विशेष रूप से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) में, तिब्बत की अर्थव्यवस्था पर निष्पक्ष, मापा और वैज्ञानिक अध्ययन ढूंढना और चीन की विकासशील नीतियां बेहद चुनौतीपूर्ण हैं।

यह चुनौती कुछ हद्द तक इसलिए भी है क्योंकि पीआरसी ने जिस प्रकार तिब्बत को बढ़ाया है। 1965 में चीन ने टीएआर स्थापित किया था। चीन की 2010 जनगणना रिपोर्ट के अनुसार तिब्बतियों की टीएआर में संख्या तीन मिलियन से थोडा ज्यादा है। बाकि के 6.3 मिलियन तिब्बती, तिब्बत के अन्य भागों में रहते हैं जो सिचुआन, यूनान, गांसू तथा किंगहाई[218] जैसे प्रान्तों में मिलाया गया हैं। इससे तिब्बत की अर्थव्यवस्था पर सम्पूर्ण, सही एवं एक वैज्ञानिक अध्ययन असंभव न भी हो पर कठिन हो जाता है। तिब्बत की अर्थव्यवस्था का स्तर समझने के लिए शोधकर्ताओं को हर प्रकार की जानकारी के टुकड़ों को जोड़ना होगा।

शोधकर्ताओं और पत्रकारों पर इस तरह के निहित और लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, चीन के विकास परियोजनाओं और तिब्बत में नीतियों पर कुछ रोशन, स्वतंत्र अध्ययन पिछले कुछ दशकों में प्रकाश में आए हैं। इन अध्ययनों में से कई चीनी सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर उनके निष्कर्षों पर आधारित हैं। इन आँकड़ों और अन्य व्यापक आर्थिक रुझानों के बारे में एक महत्वपूर्ण पढ़ने से तिब्बत में चीन की विकास नीतियों के बारे में कुछ परेशान और प्रासंगिक सवाल उठते हैं।

तिब्बती अर्थव्यवस्था की नब्ज को पढ़ने के लिए केवल जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों को देखने वालों के लिए, इस प्रकार गुमराह होना आसान है। तिब्बत की जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों को पीआरसी की भारी सब्सिडी से बल मिलता है। हालाँकि आज क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की स्थिति, विशेष रूप से जब तिब्बती लोगों की भलाई के लेंस के माध्यम से देखा गया है, यह दर्शाता है कि सकारात्मक आर्थिक विकास बनाने के लिए नकदी के संचार

218 सी एन्ने–मैरी ब्लोन्डेयू ऐंड कातिया बफरट्रिले, ईडीएस., "पॉपुलेशन", ऑथेन्टिकेटिंग तिब्बतः आन्सर्स टु चाइनाज वन हंड्रेड क्वेश्चंस (बर्कलीः यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, 2008) 133–158, साथ में देखें, शियावेई जॉन्ग, एथनिसिटी इन चाइनाः अ क्रिटिकल इंट्रोडक्शन (चाइना टुडे) कैम्ब्रिजः पॉलिटी, 2015)

से अधिक समय लगता है। विकास को बढ़ावा देने और "तिब्बतियों के लिए स्वर्ण युग के प्रयास के बजाय, चीनी सरकार के दृष्टिकोण ने ज्यादातर अपने हितों की सेवा की है।

तिब्बत में पीआरसी की विकास नीतियों के इतिहास पर एक नज़र इस क्षेत्र की वर्तमान अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को रोशन करने में मदद करेगी।

1950–1980: तिब्बत का समाजवादी परिवर्तन

1950 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने छमदो और खाम और आमदो के अन्य हिस्सों के तिब्बती क्षेत्रों पर कब्जे के बाद माओ त्सेतुंग ने तिब्बत को समाजवादी परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित किया था। हालाँकि, माओ ने चीनी और तिब्बतियों के बीच के जातीय मतभेदों को पहचाना, और यह तथ्य कि दोनों के बीच संबंध पिछले शताब्दियों में सीमांत से अशांत तक रह चुके थे। वे मध्य तिब्बत में तिब्बती लोगों द्वारा चल रहे प्रतिरोध से भी परिचित थे। इसलिए तिब्बत मे अपने पाँव जमाने के लिए तथा तिब्बती अभिजात वर्ग की वफादारी पर जीत हासिल करने के लिए उन्होंने मध्य तिब्बत को 1950 से 1958 तक समाजवादी सुधारों के सभी रूपों से छूट दी थी। फिर भी यह नीति लोगों पर जीत हासिल करने में विफल रही, जैसा कि 1959 में ल्हासा में बड़े पैमाने पर हुए विद्रोह में परिलक्षित हुआ था।

इसके परिणामस्वरूप, बीजिंग ने एक अलग निष्कर्ष निकालाः कि राष्ट्रीयता के बीच मूलभूत सुधार संबंध प्रत्येक के भीतर श्रमिक वर्ग की पूर्ण मुक्ति पर निर्भर थे। वर्ग संघर्ष के माध्यम से, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ने खुद को चीनी लोगों की पार्टी नहीं, बल्कि चीन के सभी गरीब लोगों का नेता और प्रवक्ता घोषित किया। वर्ग संघर्ष का उद्देश्य गरीबों और निम्न–वर्ग के तिब्बतियों को उनकी राष्ट्रीय और धार्मिक निष्ठाओं से कुलीन वर्ग के लिए जीतना था।[219]

अंततः 1959 के बड़े पैमाने पर जन आंदोलन के बाद, पीआरसी ने सख्ती से तिब्बत को परिवर्तित करना, विशेष रूप से केंद्रीय तिब्बत को बदलना शुरू कर दिया, इसे चीन के समाजवादी परिवर्तन का एक समान हिस्सा

219 वांग लिक्सियोंग ऐंड त्सेरिंग शाक्य, द स्ट्रगल फॉर तिब्बत (लंदन, वेर्सो बुक्स, 2009)

बनाने का प्रयास किया गया। माओ युग के दौरान चीन की आर्थिक विकास नीतियों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू कृषि सुधार, औद्योगीकरण, बुनियादी ढांचा विकास, पारस्परिक सहायता और ग्राम संस्था प्रणाली थे।

इन समाजवादी परिवर्तनों के अनुसार, संपत्ति और अन्य चीजें जो अमीर और कुलीन परिवारों तथा मठों की अन्य संपत्ति जब्त कर ली गई थी। सैद्ध ांतिक रूप से, उनकी भूमि को जब्त कर लिया गया था और समान रूप से वितरित किया गया था, लेकिन बाद में इसे सामूहिक कर दिया गया था। ग्राम संस्था प्रणाली का और मजबूर मैनुअल श्रम के साथ सुधार समय मुख्य उद्देश्य यह था की एक छोटी अवधि के भीतर राष्ट्रीय कुल उत्पादन में वृद्धि करना था। आपसी सहायता समूहों और ग्राम संस्था प्रणाली के माध्यम से, किसानों को नहरों और बांधों के निर्माण और बंजर भूमि पर खेती करने के लिए निर्देशित किया गया था। सिंचाई प्रणाली में भी सुधार हुआ। एक अच्छी 1959 की फसल को इन नई तकनीकों का परिणाम माना गया, अर्थात् बेहतर सिंचाई प्रणाली और मजदूरों की मेहनत। हर सदस्य ने औसतन 15 घंटे एक दिन या उससे अधिक काम किया। प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रतिवर्ष कमाए गए ग्राम प्रणाली श्रमिकों को भुगतान आवंटित करने के लिए औसत कार्य बिंदु–राज्य की माप 3500 पर आई। प्रत्येक कार्य बिंदु पर 100 युआन के साथ 100 फेन के साथ आठ फेन की कमाई हुई, इसलिए प्रत्येक सदस्य की वार्षिक आय लगभग 288 युआन थी। अप्रैल 1960 तक, 100,000 किसान परिवारों को 186,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि वितरित की गई थी।[220]

इस पारस्परिक सहायता प्रणाली के दौरान निजी स्वामित्व अभी भी मौजूद था। लेकिन 1965 में, चीनी अधिकारियों ने आपसी सहायता टीम नीति को चरणबद्ध किया और एक ग्राम संस्था प्रणाली की शुरुआत की, जो माओ की कट्टरपंथी विचारधारा के अधीन है, "कम खाओ और अधिक उत्पादन करो" जो भूमि के स्वामित्व का अंत ला रही है।"[221] 1966 से पूर्व ल्हासा में 1200 से अधिक के निजी स्वामित्व में खुदरा विक्रेता थे, लेकिन 1975 तक, केवल 67 ही रह गए थे। जालुंग काउंटी में, 3000 निजी स्वामित्व वाले ऊन करघे

220 दावा नोर्बू, "चेन्जेज इन तिब्बत इकोनॉमीः 1959–76", चाइना रिपोर्ट 24, नंबर 3 (1988): 221–236

221 दावा नोर्बू, "इकोनॉमिक पॉलिसी ऐंड प्रैक्टिस इन कन्टेम्पररी तिब्बत", बैरी साउटमैन ऐंड जून तेउफेल ड्रेयर्स (ईडीएस.) कन्टेम्पररी तिब्बतः पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट ऐंड सोसाइटी इन डिस्प्यूटेड रीजन, (एबिन्गटन, राउतलेज, 2006) 157.

और कताई पहियों को "पूंजीवादी प्रथाओं को समाप्त करने" [222] के नाम पर नष्ट कर दिया गया था। 1979 की विनाशकारी फसल के कारण अनुचित फसल विकल्पों के साथ एक गहन खेती तकनीक का विकास हुआ।

तथाकथित सुधारों के अलावा, कई अवसंरचना विकास परियोजनाएं शुरू की गईं, जैसे राजमार्ग और सड़क निर्माण। सड़क से जुड़ने वाले विशेषणः डारत्सेदो और ल्हासा, चेंग्दू और नाबा, और ल्हासा और शिगात्से चीन की पहली पांच साल की योजना का हिस्सा थे। माओ के युग के अंत तक, पीआरसी ने कुल 15800 किमी के 91 हाईवे का निर्माण किया था, और अकेले टीएआर में 300 स्थायी पुल बनाये थे।

लेखक दावा नोरबू ने तर्क दिया कि चीनी सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों और विकास का मूल उद्देश्य न तो "मुक्ति" था और न ही "प्रगति" थी, अपितु रणनीतिक विकास था।[223] उन्होंने आगे तर्क दिया कि राजमार्ग 1950 व् 1960 के दशक की शुरुआत में यद्यपि परिवहन तथा संचार उद्देश्य के लिए बनाये गए थे, वह कब्ज़ा करने तथा लम्बी–अवधि की मुक्ति परियोजना के लिए समान रूप से मूल्यवान थे"[224] लेखक जून टूफ़ेल का तर्क है कि सड़क और राजमार्ग निर्माण चीनी के साथ तिब्बती क्षेत्र के एकीकरण को सरल करने के लिए थे।[225] इसी तरह, राजनीतिक वैज्ञानिक एलीज़बेथ फ्रंड लार्स और विद्वान एलन कार्लसन ने तर्क दिया कि उपर्युक्त नीतियों का उद्देश्य तिब्बत को एकीकृत करना और राज्य के खेतों के संबंध में तिब्बत और मुख्य भूमि चीन[226] के बीच स्पष्ट अंतर को कम करना था। जिनमें से अधिकांश सीधे सैन्य नियंत्रण में थे। एमिली येह ने अपने नॉवंश विज्ञान अध्ययन में तर्क दिया है कि वे राज्य प्रादेशिकता और राज्य निगमन के तरीके थे।[227]

---

222 वही, 66

223 दावा नोर्बू, चाइनाज तिब्बत पॉलिसी (होवः साइकोलॉजी प्रेस, 2001), 347

224 वही

225 जून तेउफेल ड्रेयर, चाइनाज पॉलिटिकल सिस्टमः मॉडर्नाइजेशन ऐंड ट्रेडिशन (हारलोः लॉन्गमैन, 2005)

226 एलिजाबेथ फ्रेउंड लारुस, पॉलिटिक्स ऐंड सोसाइटी इन कन्टेम्पररी चाइना (कोलोरा. डोः लिन्ने रिएनर पब्लिशर्स, 2012), 229, एलेन कार्लसन, बीजिंग तिब्बत्स पॉलिसीः सेक्योरिंग सॉवर्निटी ऐंड लेजिटिमैसी (वाशिंगटनः ईस्ट वेस्ट सेंटर, 2004)

227 येह एमिली टी., टेमिंग तिब्बतः लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन ऐंड द गिफ्ट ऑफ चाइनीज डेवलपमेंट (इथाका ऐंड लंदनः कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, 2013)

1979–1988: आर्थिक सुधार और उदारीकरण

माओ के युग के अंत में तिब्बत में चीन की विकास नीतियों में बदलाव देखा गया। मार्च 1980 में पहली तिब्बत कार्य मंच को छोड़कर, हू याबोंग की तिब्बत की यात्रा के साथ मिलकर, बीजिंग ने घरेलू जिम्मेदारी प्रणाली लागू की। इस प्रणाली ने भूमि को विभाजित किया और इसे घरों में आवंटित किया। केंद्रीय नियोजकों से दूर बुनियादी उत्पादन प्रबंधन को विकसित किया, पहले कृषि के लिए और फिर अन्य क्षेत्रों के लिए।[228] हालांकि 1980 में तिब्बत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण शुरू हुआ, यह चीनी सरकार के कड़े नियंत्रण में रहा तथा इसे चीन के साथ तिब्बत को एकीकृत करने के लिए एक प्रमुख नीति के रूप में देखा गया।[229]

इस अवधि के दौरान लागू की गई दो महत्वपूर्ण नीतियां "समर्थन–बांधने" की नीति और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली थीं। "समर्थन–बांधने" ने निर्णय लिया कि मुख्य भूमि में विकसित प्रांतों और शहरों को कम विकसित क्षेत्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे। जिसके साथ उन्हें वित्त, कुशल श्रमिकों और परियोजनाओं सहित जोड़ा गया।[230] हालाँकि 1960 में इसे शुरू तथा और लागू किया गया था, लेकिन 1980 में इस नीति को प्रमुखता मिली, जब इसमें "जनसंख्या हस्तांतरण" और "राज्य वित्तीय सहायता" दोनों शामिल थे। चीनी सरकार के अनुसार, इस विशेष नीति का मुख्य उद्देश्य अन्य क्षेत्रों से कुशल चीनी को प्रोत्साहित करना था ताकि तेज गति से तिब्बत को विकास करने में मदद मिल सके।[231]

1983 में, चीनी सरकार ने प्रवास पर प्रशासनिक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया और तिब्बत में वर्क परमिट प्राप्त किया और इसके परिणामस्वरूप, 50,000 चीनी श्रमिकों ने तिब्बत में प्रवास किया। 1984 में टार के कुछ

---

228 मा रोन्ग, पॉपुलेशन ऐंड सोसाइटी इन कन्टेम्परारी तिब्बत (हॉन्गकॉन्गः हॉन्गकॉन्ग यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011)

229 वारेन डब्ल्यू स्मिथ जूनियर, चाइनाज तिब्बत?: ऑटोनॉमी ऑर एसिमिलेशन (लैनहैमः रोमैन ऐंड लिटिलफील्ड, 2009)

230 जिन वेई, "तिब्बत ऐज रेसिपिएन्ट ऑफ असिस्टेंस ऐंड इट्स सस्टेनबल डेवपलमेंट", चाइना पॉलिसी इंस्टीट्यूट पॉलिसी पेपर, संख्या 9 (2015) https://www.nottingham.ac.uk/iaps/documents/cpi/policy-papers/cpi-policy-paper-2015-no-9-jin-wei-final-051015.pdf.

231 चीन सरकार द्वार प्रकाशित विभिन्न श्वेत पत्र देखें, जिसमें नीति के बारे में इसी तरह के तर्क दिए गए हैं.

शहरी क्षेत्रों में, पड़ोसी प्रांतों से 10,000 चीनी परिवारों बसें और केवल मई में ही बीस चीनी प्रांतों और शहरों से लगभग 60,000 "पैदल यात्री और शिल्पकार" तिब्बती शहरी क्षेत्रों में नयी परियोजनाओं में काम करने के लिए पहुंचे।[232]

जहां तक राज्य सब्सिडी का संबंध था, 1984 में दूसरे तिब्बत वर्क फोरम ने 0.48 बिलियन युआन के निवेश के साथ 42 प्रमुख निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। 1991 में, 8 वीं पंच वर्षीय योजना के तहत, नदियों की परियोजनाओं की लागत 2.189 बिलियन युआन राज्य की।[233] 1980 से केंद्र सरकार ने राज्य सब्सिडी के माध्यम से कुल आर्थिक उत्पादन में वृद्धि की, जो पहले की ही प्रवृति की निरंतरता थी, जैसे कि 1960 में राज्य सब्सिडी [234]के कारण औद्योगिक और कृषि उत्पादन का दोगुना होना।

1980 की शुरुआत में पर्यटन ने पीआरसी के तिब्बत के विकास के दृष्टिकोण में एक प्रमुख भूमिका निभाई। ल्हासा को 1981 में पर्यटन के लिए एक खुला क्षेत्र घोषित किया गया था, और उस वर्ष, 1059 विदेशी पर्यटकों ने 1959–79 से बीस वर्षों में पर्यटकों की कुल संख्या की तुलना में चार गुना अधिक यात्रा की। राजनीतिक कारणों से, पर्यटकों की संख्या सीमित थी 1500–2000 लोगों को प्रत्येक वर्ष।[235]

1984 में, दूसरे तिब्बत वर्क फोरम के तहत, टीएआर के पर्यटन निगम को आर्थिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र था और अपने स्वयं के मुनाफे और नुकसान के लिए जिम्मेदार था। 1985 में, राज्य–परिषद के सामान्य मामलों ने राज्य पर्यटन प्रशासन और टीएआर की सरकार द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक था, "तिब्बत के पर्यटन विकास कार्यक्रम पर रिपोर्ट", सभी संबंधित विभागों से अनुरोध किया गया है कि तिब्बत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन का समर्थन प्रदान करें। 1987 में दो साल के बाद, पर्यटन उद्योग को औपचारिक रूप से तिब्बत में आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना में

---

232 दावा नोर्बू, "इकोनॉमिक पॉलिसी ऐंड प्रैक्टिस इन कन्टेम्परारी तिब्बत", कन्टेम्परारी तिब्बतः पॉलिटिक्स, डेवपलमेंट ऐंड सोसाइटी इन डिस्प्यूटेड रीजन, बैरी साउतमैन ऐंड जून तेउफेल ड्रेयर (ईडीएस), (एबिन्गटनः राउतलेज, 2006), 157.

233 जिन वेई (2015)

234 जून तेउफेल ड्रेयर (2005).

235 ड्रेयर 2005, सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, तिब्बत अंडर कम्युनिस्ट चाइनाः 50 ईयर्स (धर्मशालाः सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग, 2001) 41.

शामिल किया गया था, साथ ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व पर जोर दिया गया। 1986 में, पर्यटन निगम टीएआर का नाम बदलकर तिब्बत पर्यटन प्रशासन कर दिया गया।

वैज्ञानिकों का कहना है कि 1985 और 1987 के बीच, 88902 विदेशी पर्यटकों ने तिब्बत का दौरा किया, जिससे 96,807 मिलियन युआन का राजस्व प्राप्त हुआ। 1987 में, चीन ने तिब्बत[236] पर आने वाले 43000 पर्यटकों से 130 मिलियन युआन कमाए। 1980 के बाद से तिब्बत में पर्यटन उद्योग अपने संबंधित राजस्व–वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। माओ की प्रारंभिक अवधि के दौरान प्रचलित "जातीय संवेदनशीलता" के बारे में दृष्टिकोण कम समसामयिक नीति द्वारा विस्थापित किया गया था जिसमें तिब्बत का आधुनिकीकरण और "आधुनिक" तिब्बतियों की एक नई नस्ल का निर्माण किया गया, जो पूर्व में लिया गया था।[237]

जो इन नीतियों का समर्थन करते हैं, तर्क देते हैं की यह तिब्बत की आर्थिक स्थिति को जल्द से जल्द सुधारने के इरादे से बनी थी, ताकि यह चीन के अन्य हिस्सों की बराबरी कर सकें। इसके अतिरिक्त वह मानते हैं की सरकार की जनसँख्या स्थानातरण की नीति का इरादा यह नहीं था की चीनी भरी संख्या में तिब्बती व्यापार अवसरों पर कब्ज़ा जमा सकें बल्कि यह की तिब्बत का कौशल कारीगरों के माध्यम से विकास हो सके।[238] परन्तु अन्य लोगों का तर्क है की यह आर्थिक नीतियां वास्तव में चीनी अंधराष्ट्रीयता[239] में तिब्बत के मेल के लिए बनी थी। यह विद्वान यह मानते है की चीन का तिब्बत में बिना निशेधात्मक नियमों के आने से तिब्बत का हाँ भी अंदरूनी मंगोलिया अथवा शिनजियांग जैसा ही हो जायेगाः अल्पसंख्यक क्षेत्र जो क्षेत्रीय और आर्थिक रूप से चीन में एकीकृत हो चुके हैं। इन नीतियों का प्रभाव आज भी है जब चीनियों की संख्या स्थानीय आबादी से अधिक हो गयी है तथा बाज़ार अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा प्रवासी

---

236 लुओ ली, द इकोनॉमी ऑफ तिब्बतः ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ ट्रेडिशनल टु अ मॉर्डन इकोनॉमी (बीजिंगः फॉरने लैंग्वेज प्रेस, 2008)

237 हुआंग, याशेंग, "चाइनाज कैडर ट्रांसफर पॉलिसी टुवर्ड्स तिब्बत इन 1980" मॉर्डन चाइना 21, नंबर 2 (1995): 184–204

238 वही

239 मा रोन्ग, पॉपुलेशन ऐंड सोसाइटी इन कन्टेम्परारी तिब्बत (हॉन्गकॉन्गः हॉन्गकॉन्ग यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011)

चीनियों के हित में जाता है।

1990–2000: स्थिरता व् विकास का युग

1990 में चीन की अर्थव्यवस्था की विकासत्मक नीतियों में तीसरा बड़ा बदलाव आया। कई परिस्थितियां जैसे 1987–1990 चीन के विरोध में प्रदर्शन, चीन तिब्बत वार्ता, तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान में तेज़ी तथा परमवावन दलाई लामा की लोकप्रियता में बढ़ोतरी ने विशेष रूप से इन आर्थिक नीतियों के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्टूबर 1989 में उन्होनें कम्युनिस्ट पार्टी की पोलितब्यूरो की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया, तिब्बत की स्थिति पर एक विशेष मीटिंग की तथा पार्टी की क्षेत्रीय समिति के सचिव, हू जिन्ताओ ने बैठक के कार्यवृत जारी किये। इस दस्तावेज़ के अनुसार केन्द्रीय सरकार का तिब्बत में विशेष कार्य वहां की अर्थव्यवस्था में स्थिरता तथा उसका विकास करना था। परन्तु दस्तावेज़ ने यह माना की सामाजिक स्थिरता का आधार आर्थिक विकास है,[240] तथा "स्थिरता और विकास"[241] और दलाई लामा की सार्वजनिक निंदा की जुड़वाँ नीतियों को क्रियान्वित किया गया। 1994 में केंद्रीय सरकार ने तीसरा तिब्बत वर्क फोरम आयोजित किया जहाँ इन नीतियों को और प्रभावी रूप से अपनाया गया।

आर्थिक विकास में चार प्रमुख उद्देश्य सम्मिलित हैं: आर्थिक विकास, राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा, अलगाववाद को मिटाना, तथा सामाजिक स्थिरता को सम्भालना तथा तिब्बत के जीवन स्तर का विकास करना।[242] इसमें तीन प्रमुख नीतियां भी सम्मिलित थीः राज्य द्वारा छूट प्रदान करना, आबादी का स्थानान्तरण, तथा आधारिक संरचना का विकास।[243] बाद के विकास की स्थिति में परिवहन सुविधाएं और संचार, बिजली, कृषि के लिए तकनीकें तथा पशुपालन इसके साथ ही खादानी, व्यापी, शिक्षा तथा अन्य सेवाएं इत्यादि थे। परिणामस्वरुप केंद्रीय सरकार ने 62 नयी परियोजनाओं के

240 बो झियुए, "चाइनाज एलीट पॉलिटिक्सः गवर्नेंस ऐंड डेमोक्रेटाइजेशन", द चाइना जर्नल, संख्या 68 (2012): 207–209

241 देखें बी. पिटमैन पॉटर, लॉ, पॉलिसी ऐंड प्रैक्टिस ऑन चाइनाज पेरिफेरी, सलेक्टिव एडाप्शन ऐंड इंस्टीट्यूशनल कैपिसिटी (लंदनः राउतलेज कन्टेम्परी चाइना सिरीज, 2011), रॉबर्ट बारनेट, "रेस्ट्रिक्शन्स ऐंड दियर एनोमलीजः द थर्ड फोरम ऐंड द रेगुलेशन ऑफ रिलीजन इन तिब्बत", करेंट चाइनीज अफेयर्स 41, संख्या 4 (2012): 45–107

242 बी. पिटमैन पॉटर (2011), 124

243 देखें जून तेउफेल ड्रेयर (2005), बी. पिटमैन पॉटर (2011), रॉबर्ट बारनेट (2012)

निर्माण के लिए उस अवधि (जून तयूफेल डायर, 2005, जिन वेई, 2015) में 4.86 बिलियन युआन प्रदान किये। कुल मिलाकर केंद्रीय सरकार की नयी नीति की आधार–शिला आर्थिक विकास तथा आधुनिकीकरण है।[244]

चीन की पिछली आर्थिक नीतियों का संचयी प्रभाव

पिछले छह दशकों में तिब्बती अर्थव्यवस्था में सबसे बुनियादी बदलाव खेती–बाड़ी से सेवा क्षेत्र की ओर का परिवर्तन है। चीन की सांख्यिकीय वार्षिक पुस्तकों में तिब्बत पर दिए गए आंकड़े अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र (मुख्य रूप से कृषि और देहाती गतिविधियों में शामिल) में श्रम भागीदारी में तीव्र गिरावट दिखाते हैं जो पहले तिब्बती अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थाः 1959 में यह देश में कर्मचारियों की संख्या का 73.6 प्रतिशत था तथा 2008 में यह गिरकर 15.3 प्रतिशत पहुँच गया था।[245] इसके विपरीत सेवा–सुविधाएं आधारित सेक्टर ने इसी अवधि में काफी वृद्धि हुई, 1959 में 15.8 प्रतिशत कर्मचारी संख्या से लेकर 2008 में 55.5 प्रतिशत तक।

अपने आप में यह संख्या आधुनिकीकरण का संकेत थी तथा अन्य अर्थव्यवस्थाओं के विकासशील पदचिन्हों पर चल रही थी। परन्तु तिब्बती सन्दर्भ में यह ऊपर की संख्याएँ सही कहानी नहीं बताती। इसी समयावधि में चीनियों द्वारा तिब्बतियों का पूर्ण रूप से भेदभाव नहीं परन्तु आर्थिक हाशिए पर ले जाना देखा गया है। जैसा की ऊपर देखा गया है की तिब्बत में आर्थिक शोध कठिन होने के चलते इस प्रकार के भेदभाव पर किसी भी प्रकार की जानकारी पाना कठिन हो जाता है तथा तिब्बतियों को विकास के इस क्षेत्र का लाभ मिल पाना भी कठिन हो जाता है।

इस नुकसान का मुख्य कारण, भर्ती में किसी भी संभावित प्रत्यक्ष भेदभाव को अलग करना, बस शिक्षा का है। तेज़ी से बढते हुए तृतीयक स्तर और माध्यमिक क्षेत्र में तिब्बत की भागीदारी को बनाए रखने और सुधारने के लिए, तिब्बतियों को एक निश्चित स्तर की शिक्षा और कौशल प्राप्त करना चाहिए। साक्षरता, जो कई बार सेवा प्रदाता क्षेत्र के लिए आवश्यक है अपने आप में विकास के विषय में बताती है तथा तिब्बत में यह काफी कम है।

---

244 गोल्डस्टीन, 1997, Dus Rabs Gsar par Skyod Pa'i Gser Zam (नए युग की ओर ले जाने वाला स्वर्ण पुल). "तिब्बत पर तीसरे कार्य मंच" के बाद जारी दस्तावेज जो कि बीजिंग में 20 से 23 जुलाई 1994 को आयोजित हुआ।

245 देखें फिशर (2001). हर सेक्टर में तिब्बत की भागीदारी का विस्तृत विश्लेषण, यह देखना महत्वपूर्ण है कि दूसरे दरजे के सेक्टर में एक ही तरह का रुख पाया गया।

अधिकारिक साक्षरता दर टीएआर के निवासियों, के चीनी भाषा पढने के सन्दर्भ में देखी जाती है 2015 में केवल 37.33 प्रतिशत थी।[246] यह पीआरसी में अब तक की सबसे बुरी, किंगहाई प्रान्त से दुगनी जहाँ तिब्बती जनसँख्या इसके बाद सबसे अधिक है। अधिकारिक साक्षरता दर तिब्बती भाषा की निरक्षरता के स्तर को नहीं बताते, परन्तु परिस्थितियां, और यह तथ्य की तिब्बत के अधिकांश विद्यालय चीनी माध्यम हो रहे हैं यह बताते हैं की तिब्बती भाषा में साक्षरता निरंतर घट रही है।

इस लगातार साक्षरता का एक भाग इसलिए है की तिब्बती विद्यालय नहीं जा रहे हैं। चीन की जनगणना के अनुसार 2000 में तिब्बत के अलग अलग भागों में तिब्बतियों की संख्या 5.4 मिलियन थी तथा 2010 तक 6.3.मिलियन हो गयी। जनसँख्या वृद्धि के बावजूद स्कूलों में छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। उदहारण स्वरुप नाबा में छात्रों का नामांकन 2006 में 98,994 से 2014 में 74,995 पहुँच गया। टीएआर में वर्ष 2000 तक 38 प्रतिशत युवाओं ने शिक्षा नहीं प्राप्त की थी। वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार, शिक्षा प्रणाली से लाभ पाने वाले तिब्बतियों की संख्या राष्ट्रीय औसत से नीचे है: 45.5 प्रतिशत तिब्बती जनसँख्या (6 वर्ष या उससे अधिक) ने 7.7 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत की तुलना में किसी प्रकार की शिक्षा नहीं प्राप्त की। यह अपने आप में असाधाराण ऊंची संख्या है।

इन आँकड़ों को अंतर्निहित करती सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक भाषा ही है। तिब्बती भाषा का उपयोग व्यापार तथा व्यावसायिक जीवन में कम होने से हताश तथा अपने बच्चों को अधिकांश रूप से मंडारिन न पढ़ाने के चलते परिवार अपने बच्चे को विद्यालय ही नहीं भेजना चाहते, तथा यदि अच्छी नौकरियों में मंडारिन भाषा की आवश्यकता होगी तो जो उससे बोलता होगा उससे तिब्बती भाषा बोलते है बड़ा होने वाले से अधिक लाभ मिलेगा।

पार्टी कैडर रोज़गार एक अन्य प्रवृति है जिसने तिब्बतियों व चीनियों के बीच पिछले कुछ समय में आर्थिक भेदभाव सामने लाया है। 2003 में टीएआर में कार्य कर रहे कैडर औसत वार्षिक आय 26,931 युआन पा रहे थे जो 14,040 की राष्ट्रीय औसत से दुगना था तथा केवल शंघाई में ही इससे अधिक 27,304 था। इस प्रकार की आय के चलते चीन के अन्य भाग से

246 चीन का नेशनल सांख्यिकी ब्यूरो, चीन सांख्यिकी वार्षिकी 2016। http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm.

कैडर तिब्बत आने के लिए आकर्षित होते हैं। राज्य रोज़गार के इस नकदी समृद्ध क्षेत्र में तिब्बतियों के प्रतिनिधित्व में भी अकस्मात बदलाव आया हैः 2001 से 2003[247] में राज्य की स्वामित्व वाली इकाइयों में तिब्बती कर्मचारियों की संख्या भी काफी नीचे गिर गयी जबकि चीनी कर्मचारियों की संख्या इसी अवधि में काफी बढ़ गयी थी।

यह प्रवृति केवल राज्य स्वामित्व वाली इकाइयों में ही सीमित नहीं था परन्तु तिब्बतियों की कैडर लेवल पर नियुक्ति में भी देखा गया था। 2003 में कैडर स्तर की नियुक्तियां राज्य स्तर के स्थायी रोज़गार का दो तिहाई भाग थी– वर्ष 2000 में पदों की संख्या 69,927 से जाकर अब 88,734 तक पहुँच गयी है। परंतु इस स्तर पर तिब्बतियों की संख्या 50,039 (सारे का 72 प्रतिशत) से गिरकर तीन साल के बाद 44,069 (कुल 50 प्रतिशत) तक पहुँच गयी। आधिकारिक कर्मचारियों पर मिन्जु जानकारी के विभाजन को 2004 में वापिस ले लिया गया था अतः सही संख्या को फिलहाल पाना असंभव सा है।

पीआरसी द्वारा प्रकाशित जीडीपी के आंकड़ों को संदेहास्पद रूप से देखने का कारण यह भी है की संभावना है की वह थोड़ा वास्तविक अंतर्निहित विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, और तिब्बत की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बीजिंग द्वारा दी गयी छूट से चलती है। उनके अपने आंकड़ों के अनुसार, बीजिंग द्वारा 1952 से 2013 तिब्बत को कुल मिलाकर 542,343 बिलियन युआन की आर्थिक छूट दी गयी। जो की क्षेत्र के 91.45 प्रतिशत कुल राजस्व में से था। खर्च के अनुसार, केंद्र सरकार ने तिब्बत के कुल खर्चों का 92.3 प्रतिशत आर्थिक छूट के रूप में प्रदान किया ताकि समाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके तथा तिब्बत के कार्यों को चलाया जा सके।[248]

पश्चिम और केंद्रीय चीन के कुछ भागों में से तिब्बत सबसे अधिक सरकारी छूट पाता है। यदि दी जा रही छूट को तिब्बत की जनसँख्या में समान रूप से बांटा जाए तो 2010 तक हर तिब्बती को प्रतिवर्ष 17,105 युआन मिलते। उसी वर्ष सभी प्रान्तों में प्रति व्यक्ति सब्सिडी केवल 2,481 युआन थी। 2013 के एक अध्ययन से पता चला है कि बीजिंग की सब्सिडी ने

247 तिब्बत सूचना नेटवर्क, "तिब्बतन्स लूज ग्राउंड इन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इन द टीएआरः स्ट्रीमलाइनिंग इफेक्टिवली डिस्क्रिनेट्स अगेन्स्ट तिब्बतन्स", 22 जनवरी, 2005.

248 जिन वेई (2015)

स्थानीय अर्थव्यवस्था को बौना कर दिया है, जो क्षेत्र के आर्थिक उत्पादन के 112 प्रतिशत के बराबर तिब्बत में राशि खर्च करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सब्सिडी न केवल विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं या सुरक्षा बलों पर खर्च करने के रूप में हैं–वे स्वास्थ्य देखभाल, आवास, भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को भी शामिल करती हैं। चीनी सरकार की तरफ से सब्सिडी ही तिब्बती अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। उसके बिना इसका अपने पैरों पर खड़ा हो पाना असम्भव था।

मुख्य कार्यात्मक ज़ोनिंग: चीन का वर्तमान आर्थिक विकास दृष्टिकोण

आज के तिब्बत में चीनी सरकार के द्वारा आर्थिक नीतियां कार्यान्वित करने हेतु मुख्य उपकरण मुख्य कार्यात्मक ज़ोनिंग है। सीधे शब्दों में कहें, एमएफजेड कुछ आर्थिक गतिविधियों के लिए कुछ भौगोलिक क्षेत्रों का पदनाम है। इसने 2006 से चीनी राज्य योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जब इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना[249] का केंद्रीय हिस्सा बनाया गया था।

जैसा की 13वें पांच वर्षीय कार्यक्रम में बताया गया है की पीआरसी के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एनडीअरसी) ने तिब्बत के लिए गरीबी उन्मूलन के बारे में अपने लक्ष्य निर्धारित किए:

> *हम बोर्ड भर में गरीबी से लड़ने के लिए लक्षित माप के साथ आगे बढ़ेंगे। हम गरीब क्षेत्रों में विकास और गरीबी कम करने का समर्थन करेंगे। हम सीमावर्ती क्षेत्रों और जातीय अल्पसंख्यक क्षेत्रों में गरीबी को कम करने के लिए समर्थन भी बढ़ाएंगे। हम सिचुआन, युनान, गांसु और क्विंगहाई प्रांतों में शिंजियांग, तिब्बत और तिब्बती जातीय क्षेत्रों के विकास का समर्थन करना जारी रखेंगे, इन क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार का समर्थन बढ़ा रहे हैं, और एक–से–एक सहायता कार्यक्रम 250 तक बढ़ा रहे हैं।*[250]

249 पर्यावरण और विकास पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए चीनी परिषद, "पश्चिमी चीन में पर्यावरण एवं विकास पर रणनीति और नीतियां", पर्यावरण एवं विकास पर पॉलिसी रिसर्च रिपोर्ट: क्षेत्रीय संतुलन एवं हरित विकास, 2012 https://www.iisd.org/pdf/2013/CCICED_annual_report.pdf.

250 राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग, राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 2015 की योजना और राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए 2016 की प्रारूप योजना को लागू करने पर रिपोर्ट, इसे 5 मार्च, 2016 को 12वीं राष्ट्रीय जन कांग्रेस के चौथे सत्र के दौरान पेश किया गया, 41। http://online.wsj.com/public/resources/documents/NPC2016_NDRC_English.pdf.

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में, व्यक्तियों को स्थानांतरित करना तथा उनके प्रमुख कार्यक्रमों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

> *सरकारी सहायता के लिए पंजीकृत असहाय परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा और आवास प्रदान किया जाएगा। हमनें 2 मिलियन लोगों को इस वर्ष स्थानांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्थानीय जगहों पर गरीबी हटाने के लिए गरीब जगहों पर स्थित सभी स्त्रोतों का उपयोग उद्योगों का विकास की सहयोग विशेष खेती–बाड़ी और वनिकी, ग्राम दर्शन, तथा सौर उर्जा। इस वर्ष हमनें उद्योगों द्वारा की गयी पहल से छह मिलियन लोगों को गरीबी से हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।*[251]

तिब्बती पठार पर, तिब्बती जीवन और भूमि प्रबंधन में अधिकारिक हस्तक्षेप के लिए इन प्रमुख उद्देश्यों को एमएफजेड के आधार पर, अलग–अलग क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। कार्यात्मक क्षेत्रों में तिब्बत के रीमैपिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तिब्बत के देहाती परिदृश्य को "अधिक घास उगाने के लिए गश्त बंद करने" के नाम पर उत्पादन से बाहर निकालने का उद्देश्य है, यह 2003 से प्रभावी आधिकारिक नारा है। इस पर अनडीआरसी स्पष्ट व् विशिष्ट है :

हम नए सिरे से सीमांत खेती योग्य भूमि को जंगल अथवा घास स्थलों में वापिस परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे तथा राष्ट्रीय वनीकरण नीति को क्रियान्वित करने के प्रयासों में तेज़ी लायेंगे। हम राष्ट्रीय उद्यानों की एक प्रणाली की स्थापना के साथ लगातार आगे बढ़ते हैं। हम प्रमुख जल क्षेत्रों में जल पर्यावरण के व्यापक शासन और प्रमुख क्षेत्रों में पर्यावरण को आगे बढ़ाते रहेंगे, जैसे कि बीजिंग और तियानजिन को प्रभावित करने वाले धूल के तूफानों के स्रोत, पथरीले रेगिस्तानों के प्रसार से प्रभावित क्षेत्र और चराई वाले क्षेत्र भूमि को चारागाह में वापस कर दिया गया है। एक प्रमुख जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू की जाएगी। हम झीलों और आद्रभूमि के पारिस्थितिक संरक्षण को आगे बढ़ाएंगे और जंगलों, घास के मैदानों, आर्द्रभूमि और समुद्र के लिए पारिस्थितिक लाल रेखाओं की स्थापना करेंगे।[252]

यह चार उद्देश्य आपस में परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा एक दूसरे को समर्थन करते हैंः खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए भी

---

251 वही

252 वही

गरीबों की आय में वृद्धि होती है; इसी तरह, दुनिया भर में नाजुक झीलों की सुरक्षा अभिभावकों, रेंजरों और पुनर्वसन और पुनर्वास के कार्यक्रमों के स्थानीय आबादी को बढ़ाती है, जो पानी की आपूर्ति और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर सभी चार लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जाना है, तो मानव और पशु आबादी भूमि पर बने रहेंगे, सक्रिय रूप से इसके जीर्णोद्धार और उत्पादक उपयोग में लगे रहेंगे। याक लगातार चरते रहेंगे, एक झुंड चरवाहों को झुंड में ले जाता रहता है, जबकि घास को भी तबाह करने के लिए नियोजित किया जाता है। जहां बहुत वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि यह सबसे अच्छी रणनीति है, न केवल मानव आजीविका के लिए, बल्कि जैव विविधता के लिए भी।[253]

परन्तु चीन के केंद्रीय योजनाकारों ने इन चार उद्दश्यों की प्राप्ति को प्रादेशिक रूप से अलग कर दिया है। गरीबी उन्मूलन को स्पष्ट रूप से लोगों को स्थानांतरित कर दिया जायेगा क्योंकि अधिकारिक रूप से तिब्बती लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि वह तिब्बत में रहते हैं, एक ऐसी उदासीन तथा कठिन जगह जहाँ गरीबी अपरिहार्य है, स्थानिक रूप से सन्निहित है तथा जिससे मिटाना असंभव दिखता है। अभी यह स्पष्ट नहीं है की उन्हें कहाँ ले जाया जायेगा, तिब्बत के ही कस्बों और शहरों में या और आगे। खाद्य सुरक्षा, तिब्बत में एक आधिकारिक चिंता का विषय है, इसे शहरीकृत कृषि पर फिर से हासिल किया जा सकता है, शहरी इलाकों में फिर से, शहरी बाजार की मांग के करीब खेत और फीडलष्ट में। चीन के सभी क्षेत्रों के रूप में, एमएफजेड औद्योगिक विकास खाद्य उत्पादन के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रत्येक शहर के चारों ओर एक रिंग के साथ, विकास ध्रुव के रूप में शहरीकरण को बढ़ावा देगा। जैसा कि एमएफजेड आगे फैलता है, यह विशाल पठार को प्रकृति के आरक्षित और राष्ट्रीय उद्यान के रूप

253 लि वेनजुन और कॉन्गपो सेरिंग (गोन्गबोजुरेन), "पैस्टोरलिज्मः द कस्टोडियनन ऑफ चाइनाज ग्रास–लैंड्स, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, 2013, http://pubs.iied.org/pdfs/10042IIED.pdf.; यानबो लि, गोन्गबोजुरेन और वेनजुन लि, "अ रीव्यू ऑफ चाइनाज रेंजलैंड मैनेजमेंट पॉलिसीज", अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, 2014, http://pubs.iied.org/pdfs/10079IIED.pdf.; जूलिया ए क्लेइन, जॉन हार्ते और शिन–कुआन झाओ, "एक्सपेरिमेंटल वार्मिंग, नॉट ग्रेजिंग, डीक्रीजेज रेंजलैंड क्वालिटी ऑन द तिब्बतन प्लैटो", इकोलॉजिकल अप्लीकेशन्स 17, संख्या 2 (2007): 541–557, https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1890/05-0685.; जूलिया ए. क्लेइन, जॉन हार्ते और शिन–क्युआन झाओ, "डिक्लाइन इन मेडिसिनल ऐंड फॉरेज स्पेसीज विद वार्मिंग इज मेडिकेटेड बाइ प्लांट ट्रेट्स ऑन द तिब्बतन प्लैटो", इकोसिस्टम्स 11, संख्या 5 (2008): 775–789।

में नामित करेगा, जलवायु शमन और पानी की आपूर्ति के नाम पर क्षेत्र के अनुसार, एमएफजेड ने पहले से ही ज़िबू डा कैफा के लिए सबसे बड़े क्षेत्र को "चरने से निर्बाध रूप से बढ़ने वाली घास" के लिए प्रेरित किया है।

इन योजनओं को अलग क्षेत्रों में अलग रूप से क्रियान्वित करना थोडा महंगा, अप्रभाविक तथा इन चार उद्देदशें का प्राप्त करने में अवश्य लग सकता है परन्तु राज्य पार्टी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यहाँ एक आंतरिक तर्क भी है।

ये नीतियां कुछ विशिष्ट चरित्रों को साझा करती हैं। ये सभी तिब्बतियों की आबादी को अलग करती हैं। ग्रामीण भूमि उपयोग कर्ताओं के लिए दशकों पहले लागू किए गए घरेलू जिम्मेदारी प्रणाली के तहत भूमि के टुकड़े करने के उपरांत, वे सभी तिब्बतियों को केवल राज्य कल्याण प्राप्तकर्ताओं तक ही सीमित कर देते हैं जो परोपकारी केंद्रीय नेतृत्व के लिए आभारी रहेंगे। सभी पार्टी–राज्य को पूरी तरह से घास के मैदानों के प्रभारी के रूप में स्थापित करते हैं, जैसा पहले कभी नहीं किया गया हो। सभी राज्य को एहसान फैलाने में सक्षम बनाते हैं, जैसे कि भूमि के अधिकार, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण या शहरी बाजारों तक पहुंच को आवंटित करना।

संक्षेप में यह सभी नीतियां तिब्बत को और स्पष्ट रूप से अधिकारिक जांच के लिए गोचर तथा अधिक, संवेदनशील बनायेंगीः सुरक्षा ग्रिड प्रबंधन की निरंतर निगरानी के तहत एक नया पूर्वनिर्वाचन, शायद ही कभी कैमरे की नज़र से हटे। इन तरीकों से, जो पहले कभी चार अलग अलग नीतियां लगती हैं, चार अलग मूल्यांकनों के साथ, अलग–अलग दिशाओं में खींचते हुए, वास्तव में एक आम आधार साझा करते हैं।

चीन का एमएफजेड इन नीतियों को चलाने वाला मूल आधार है जो ग्रामीण तिब्बत की जनसँख्या को हटाता है और शहरी आबादी पर तिब्बत ग्रामीण की आबादी को केंद्रित करता है, जबकि सुरक्षा नाम पर, ग्रिड प्रबंधन उनके पूरी तरह से शहरी बनने के उनके अधिकार को प्रतिबंधित करता है। इन सभी नीतियों को एकजुट करता है, और पहले के उत्पादवादी नीतियां जो अब एमएफजेड के उदय से अमान्य हो गयी हैं तथा तिब्बत के अधिकांश भाग को "नाजुक पारिस्थितिकी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो पूरे तिब्बत में प्रकट रूप से प्रभारी होने की राज्य की इच्छा है।

चेंगडु से ल्हासा रेलवे : एक केस स्टडी

जब उत्तरी तिब्बत के परमाफ्रोस्ट से ल्हासा तक की सिंगल ट्रैक रेल लाइन 2006 में संचालित होने लगी, तो चीन ने अपनी इंजीनियरिंग उपलब्धि के लिए खुद को बधाई दी।

दुनिया की छत के पार आसमानी ट्रेन पहली बार थीः दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली ट्रेन लाइन। प्रॉपागैंडा ने चीन को सभी प्राकृतिक बाधाओं का विजेता घोषित किया, और ग्लेशियल चोटियों और विशाल, खाली उत्तरी मैदान पर महारत हासिल की नई लाइन द्वारा जंगतंग–ट्रैवर्स, जो कि कनाडा के बॉम्बार्डियर द्वारा निर्मित 361 विशेष रूप से डिजाइन की गई गाड़ियां हैं।

तब से एक दशक बाद, आय दिन बेजिंग, शंघाई, छेंगदू तथा अन्य मुख्य शहरों से ट्रेन आई हैं तथा चीन के तिब्बत में पर्यटकों को लायी हैं, जिन्हें एक राज्य के स्वामित्व वाली देखने योग्य जगह से दूसरी में मान्यता प्राप्त टूर गाईडों द्वारा घुमाया जाता है। उसके उपरांत वह उस्सी वातानुकूलित ट्रेनों में 48 घंटे के अन्दर बीजिंग या शंघाई चले जाते हैं।

बहुत से यह रास्ता लन्ज़हौ वाया शिनिंग तथा गोरमो से ल्हासा नहीं लेते। सीमित माल यातायात में आता है (ज्यादातर सड़क मार्ग से आता है), यह देखते हुए कि चीन तिब्बत की देहाती अर्थव्यवस्था को समाप्त करने में विफल रहा है, और ल्हासा के पश्चिम और पूर्व दोनों में तांबे की खदानें बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण संचालन में विफल रही हैं।

2006 के बाद से, चीन ने उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम दोनों में, विशेष रूप से उच्च गति वाले मार्गों में, गहरी लिंकेज और आर्थिक उत्तेजना पैदा करते हुए, शक्तिशाली रूप से निवेश करना जारी रखा है। चीन को इन उपलब्धियों पर गर्व है, भले ही वे भविष्य की पीढ़ियों से भारी पूंजी उधार लेने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हों। लेकिन हाल ही में निर्मित रेल लाइनों में से किसी को भी ल्हासा लाइन के उद्घाटन के रूप में नहीं मनाया गया है। तिब्बती पठार के सबसे उत्तरी पहाड़ों के पार एक तेज़ गति की लाइन के उद्घाटन ने थोड़ा ध्यान आकर्षित किया।

परन्तु चीन ने कहा है की वह 2020 तक 13वीं पंच वर्षीय योजना के हिस्से

के रूप में, यह निंग्ट्री के मध्य से ल्हासा से सिचुआन प्रांत की राजधानी छेंगदू से एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी रेल लाइन के लिए निधि देकर और आगे बढ़ेगा। यह रेल लाइन जो खाम से पुल व् सुरंग बनाती हुई पूर्वी तिब्बत, और केंद्रीय तिब्बत में गहरी में जाएगी कम से कम तीन पंच वर्षीय योजनाओं में बनेगी। इंजीनियरों के लिए, अल्पाइन रेगिस्तानों में मौजूदा लाइन की तुलना में एक बड़ी चुनौती है। शिन्हुआ ने घोषणा की किः "नई रेलवे लाइन लगभग 1629 किमी लंबी होगी, और ल्हासा और छेंगदू के बीच यात्रा करने वाली ट्रेनों से केवल 15 घंटे का समय लगेगा।"[254] यह मार्ग उत्तरी तिब्बती रेगिस्तान मार्ग की तुलना में थोड़ा छोटा है, और ट्रेनें औसतन 108 किमी/घंटा होगी।

इस नयी रेल लाइन का सबसे अधिक लाभ प्रत्यक्ष रूप से चीन के पार्टी राज्य को ही मिलेगा। परन्तु जो जाहिर नहीं है वो यह है की छेंगदू से ल्हासा रेल लाइन बनाने वाले खर्च का लाभ कम नहीं है। इसे बनाने का कोई आर्थिक औचित्य नहीं है, कोई व्यापार नहीं होगा, किसी भी प्रकार के लाभ का विश्लेषण अथवा निवेश पर कोई प्रतिफल मिलेगा। यह केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि लायेगा क्योंकि चीन के स्थानीय पर्यटक पूर्वी तट से ल्हासा जाने को अत्यंत ही आकर्षक मानते हैं। यद्यपि राज्य सभी देखने योग्य जगहों का स्वामित्व नियंत्रण अपने पास रखता है, और उनकी व्याख्या को नियंत्रित करता है, परन्तु शायद ही बड़े पैमाने पर पर्यटन राज्य को पर्याप्त राजस्व देता है।

खाम के पार एक रेल लाइन का दूसरा संभावित आर्थिक भुगतान तिब्बतके सबसे बड़े तांबे प्रांत तक पहुंचता है, जोमदा के आसपास, डेरगे और छमदो के बीच, आमतौर पर युलोंग कहा जाता है। यहाँ पर तांबा, सोना, चांदी और अन्य मूल्यवान धातुओं का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है और दशकों से भूवैज्ञानिकों के संदर्भ में सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाता है। जब तक वे बाजारों से नहीं जुड़ते हैं और शुरू में स्मेल्टरों के साथ होते हैं जो साइट पर उत्पादित सांद्रता को अलग, शुद्ध में बदल सकते हैं धातु, अथवा वह फंसे हुए संपत्ति रहेंगे। युलोंग में जमा खनिज के आकार और पैमाना, उनकी पृथकता तथा चीन की ताम्बेव् सोने पर निर्भरता, सभी

254 "तिब्बत को आंतरिक भूमि से जोड़ने के लिए चीन दूसरा रेलमार्ग बनाएगा", शिनहुआ नेट, 7 मार्च 2016. http://www.xinhuanet.com/english/2016-03/05/c_135157349.htm.

इस रेलवे लाइन की आवश्यकता की और इशारा करते हैं। छेंगदू से खाम और मध्य तिब्बत को दो हाईवे आपस में जोडते हैं। अधिक पूर्वी, राजमार्ग ज़ी–317, तांबा खदानो के करीब से गुजरता है। नियोजित रेलवे इन दोनों मार्गों के अधिक दक्षिण से गुज़रती है, तांबे खदानों के दक्षिण में राजमार्ग ज़ी–318,200 किलोमीटर के साथ, यह इलाका काफी बीहड़ है तथा यहाँ दोनों राजमार्ग केवल एक गंदी सड़क से आपस में जुड़ रहे हैं।

इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है कि छेंगदू को ल्हासा लाइन से यूलोंग के तांबे के दरकिनार करने के लिए निवेश की गई पूंजी पर बहुत कम आर्थिक वापसी होगी। यूलोंग ड्रिछु (यांग्त्ज़े) के पश्चिम में टीएआर के भीतर है, और इस तरह से बीजिंग से मिलने वाली सब्सिडी पर पूरी तरह से निर्भर सरकार के राजस्व में योगदानकर्ता है।

चीन की पार्टी–राज्य के अनुसार तिब्बत की सभी कठिनाइयों का हल विकास है, तथा सम्पूर्ण चीन में आर्थिक विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। फिर भी तिब्बत की बीजिंग पर निर्भरता बढती जा रही है तथा मध्य तिब्बत में आर्थिक उड़ान का कोई भी संकेत नहीं दिखाई दे रहा। जैसा की अर्थशास्त्री एंड्रू फिश्र ने दिखाया है, निर्भरता और भी गहरी होती जाएगी यदि रेलवे लाइन के पास तिब्बत के देहाती पशुधन को चीनी अर्थव्यवस्था में नहीं मिलाया जायेगा। पेकिंग विश्वविद्यालय में समाजशास्त्री के प्रोफेसर मा रोंग ने सबसे पहले मध्य तिब्बत को एक निर्भर अर्थव्यवस्था 1993 में बताया था और उसके बाद से यह निर्भरता केवल बढती गयी है।[255]

पार्टी राज्य के लिए पे–ऑफ, निर्भरता और नियंत्रण है, जो देश भर में और तिब्बतियों के जीवन में सबसे बडे राज्य की उपस्थिति का वर्णन करता है। समाजशास्त्री मा रोंग ने लंबे समय से तर्क दिया हैः टीएआर को आर्थिक रूप से मुख्य में नहीं जोड़ा गया है। एक नया आर्थिक और प्रशासनिक गठन स्थापित किया गया था, जो पुराने (तिब्बती) शासन से बिल्कुल अलग था। यह नया व्यवस्था बाहर से आयात गया था और देशी मिट्टी से नहीं निकला था। न ही यह नया तत्व जोड़ने का प्रयास था जिसे पुरानी नींव पर जोड़ा जा सकता है"[256]

255 मा रोन्ग, "इकोनॉमिक पैटर्न्स, माइग्रेशन ऐंड एथनिक रिलेशनशिप्स इन द तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन, चाइना", पॉपुलेशन, एथनिसिटी ऐंड नेशन बिल्डिंग, काल्विन गोल्डशेइडर एड (बोल्डरः वेस्टव्यू प्रेस, 1995)

256 मा रोन्ग, पॉपुलेशन ऐंड सोसाइटी इन कन्टेम्परारी तिब्बत, (हॉन्गकॉन्गः हॉन्गकॉन्ग यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011): 180–183

कद्र्ज़े से ल्हासा के इस रेलवे का शिलालेख इस प्रवृति को पलट सकते हैं तथा तिब्बती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बना सकते हैं तथा यह देहाती पशुधन उत्पादन में मूल्य भी जोड़ सकता है, और शहरी बाज़ार को भी खोल सकता है जैसे अंदरूनी मोंगोलिया डायरी आधारित चीज़ों के सम्पूर्ण चीन में आवंटन का आधार बन गया है।[257] परन्तु वास्तविकता में यह रेलवे, पार्टी स्टेट के अन्य परियोजनाओं की तरह ही इस भूमि पर राज्य की उपस्थिति को प्रकट करते हैं, और आबादी के जीवन में, दुनिया को आधुनिक ट्रेनों को तिब्बती ग्रामीण इलाकों के माध्यम से गति से जाते है की छवियों के प्रदान करते हैं।

यह चकलम, तिब्बतीयों को रेलवे (लौह रास्ता) गरीब तिब्बतियों को पृथकता तथा उनकी बाज़ार न पहुँच पाने की अक्षमता को दूर कर एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा, यह तभी संभव है यदि बीजिंग विकास के नरम बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना होगाः व्यावसायिक प्रशिक्षण, माइक्रो–क्रेडिट, कृषि विस्तार, पशुधन बीमा, स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर रसद। लेकिन बीजिंग में मेगा बुनियादी परियोजनाओं पर कठोर बुनियादी ढाँचा तय किया जाता है, जो सभी राज्य की स्थापना करते हैं। प्राधिकार, जहाँ पारंपरिक रूप से किसी राज्य का अधिकार नहीं था। इस तरह की परियोजनाएं स्थानीय आबादी को सुरक्षा स्थिति के लिए दृश्यमान और सुगम बनाती हैं।

यदि कोई 13वीं पंच वर्षीय योजना परियोजनाओं की आधिकारिक सूची को देखता है, विशेष रूप से तिब्बत को लक्षित करता है, तो कोई यह तर्क दे सकता है कि रेलवे को छोड़कर, कोई भी, तिब्बत की देहाती उत्पादन परिदृश्य में अंतर्निहित, तिब्बती अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग बनने की क्षमता नहीं रखता है। 13वीं योजना की पांच प्रमुख परियोजनाएं जो सबसे सीधे प्रभाव वाली तिब्बती प्राथमिकता वाले ऑडर में हैं, सिचुआन–तिब्बत रेलवे : 60,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले नए पनबिजली संयंत्र; तिब्बत और अन्य क्षेत्रों में बड़े जलाशय; मध्य और पश्चिम चीन में 100 मिलियन लोगों का शहरीकरण; और तिब्बती पठार और अन्य पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पारिस्थितिक बहाली उल्लेखनीय यह है कि कोई भी तिब्बती अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करता है, वास्तव में, पारिस्थितिक

257 जूलिया ए. क्लीन, मारिया ई. फर्नांडीज–गिमेनेज ऐंड हान वेई आदि, "अ पार्टिसिपेटरी फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रेसिलेंट सोशल–इकोलॉजिकल पैस्टोरल सिस्टम्स", रेस्टोरिंग कम्युनिटी कनेक्शन्स टु द लैंडः बिल्डिंग रेसिलेंस थ्रू कम्युनिटी बेस्ड रेंजलैंड मैनेजमेंट इन चाइन ऐंड मंगोलिया (वालिंगफोर्डः सीएबीआई, 2012)

बहाली, गरीबी उन्मूलन, डैम या रेलवे भवन के नाम पर, तिब्बती समुदायों को हटाने, स्थानांतरण और विस्थापन की आवश्यकता होती है। उत्पादकता और बाजारों तक पहुंच, इन सभी बड़ी परियोजनाओं के साथ, उनके बड़े बजट और बड़े आप्रवासी निर्माण कार्यबल के साथ, तिब्बत को आधुनिक अर्थव्यवस्था के आधार पर और अधिक चरम निर्भरता की और ले जाते है।

निष्कर्ष

पीआरसी की आर्थिक विकास नीतियां तभी दिलचस्प हैं यदि उनसे यह उम्मीद लगायी जाये की वह स्पष्ट रूप से तिब्बतियों की आर्थिक स्थिति ठीक करेंगी। आत्म निर्भरता, शिक्षा और स्वास्थ्य में बडे सुधार अथवा फैली हुई अर्थव्यवस्था का न होना ये बताता है की पीआरसी का प्रथम और मुख्य उद्देश्य तिब्बतियों का उभाड़ना नहीं है। बल्कि तीन व्यापक सिद्धांत पीआरसी की तिब्बत में आर्थिक नीतियों के संचालक हैंः आर्थिक विकास का प्रसार मूल्य, चीनी राज्य सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लाभ, और आर्थिक निर्भरता द्वारा प्रदान की गई राज्य सुरक्षा।

1992 से, चीनी सरकार के राज्य परिषद के सूचना कार्यालय ने तिब्बत पर लगभग 14 श्वेत पत्र प्रकाशित किए हैं।[258] इन पत्रों में पृष्ठ–दर–पृष्ठ पारम्परिक तिब्बती अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के बारे में विस्तार से बताया गया है और चीन के आधिपत्य के बाद जो अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है उसका वरण है। आधिकारिक आँकड़ों की सराहना करते हुए, चीनी अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों ने तिब्बती अर्थव्यवस्था के विषय पर कई पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं, जिनमें अन्यों के अतिरिक्त शामिल हैंः शुज़िशेंग द्वारा लिखे तिब्बत अतीत और वर्तमान (2008), एक पारंपरिक से आधुनिक समाज में तिब्बत अर्थव्यवस्था का परिवर्तन लुओ लिई (2008) और आप तिब्बत के बारे में क्या जानते हैंः विदेशी भाषा प्रेस (2011) द्वारा प्रश्न और उत्तर। ये पुस्तकें और श्वेत पत्र तिब्बत पर अंतर्राष्ट्रीय व्याख्या को परिभाषित करने और तिब्बत के प्रति चीन की राय को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रकाशनों के माध्यम से, चीन सरकार, कुछ हद तक, चीन के भीतर और दुनिया भर में तिब्बत पर अपने नियंत्रण को वैध बनाने में सक्षम रही है। 2008 में तिब्बत में बड़े पैमाने पर विरोध के बाद से, तिब्बत

258 तिब्बत पर कुछ हालिया श्वेत पत्र इस प्रकार हैंः "तिब्बत में क्षेत्रीय नस्लीय स्वायत्तता का सफल दस्तूर (सितंबर, 2015)", "तिब्बत के विकास का रास्ता, एक अनूठे ऐतिहासिक ज्वार से प्रवाहित है (अप्रैल, 2015) और "तिब्बत का विकास और प्रगति" (2014)

के अधिकांश आधिकारिक श्वेत पत्र सीधे तिब्बत के विकास से संबंधित हैं।

इसके अतिरिक्त, तिब्बत के कई राजमार्गों, रेलमार्गों और हवाई अड्डों ने चीन की सीमाओं को रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डावा नोरबू ने तर्क दिया कि, चीन के लिए, तिब्बत उसके पिछला दरवाज़ा हैं। यह चीन में सभी प्रकार के विदेशी प्रभावों और हस्तक्षेपों के लिए एक प्रवेश द्वार बना हुआ है। "इसलिए जब एक बार पिछले दरवाजे के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया तब कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत को महसूस करना शुरू कर दिया था, खासकर 1970 के दशक के दौरान चीन के दक्षिण–पश्चिम में साम्राज्यवाद, संशोधनवाद प्रतिक्रिया के खिलाफ चौकी के रूप में," ऐसे शब्द जो चीन द्वारा–तत्कालीन सोवियत संघ और भारत के लिए शत्रुतापूर्ण माने जाते थे।"[259] इसलिए जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, तिब्बत की भौगोलिक स्थिति चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

बुनियादी ढांचे में तिब्बत में चीनी प्रवासियों के स्थानांतरण की सुविधा भी है। चीनी प्रवासियों की इस आमद को समाप्त करने के लिए बीजिंग की अनिच्छा, निश्चित रूप से, राजनीतिक और रणनीतिक रूप से प्रेरित है। तिब्बत में रहने और काम करने वाले गैर–तिब्बतियों की बड़ी संख्या बीजिंग को एक नया दुर्जेय समर्थक चीन संबल प्रदान करती है जो उनकी व्यापकता को बढ़ाती है।

अंत में, तिब्बती अर्थव्यवस्था की मजबूत निर्भरता के साथ–साथ कई व्यक्तिगत तिब्बती–चीनी सरकार की सब्सिडी, पार्टी–राज्य को भारी लाभ देती है। यह नियंत्रण का एक उपकरण है और इसका उपयोग राज्य द्वारा तिब्बतियों के साथ जबरदस्ती करने के लिए किया जाता है। 2012 के बाद से, पीआरसी ने भारत के बोधगया में परमपावन दलाई लामा के कालचक्र शिक्षाओं की यात्रा करने का प्रयास करने पर तिब्बतियों को सब्सिडी और नौकरियों के नुकसान के साथ धमकी दी है। इस तरह के आर्थिक खतरे तब तक एक शक्तिशाली राजनीतिक उपकरण बने रहेंगे जब तक कि तिब्बती अर्थव्यवस्था और कई तिब्बती परिवार पीआरसी से महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। अब उनकी भूमि या स्वतंत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था के बजाय पीआरसी पर काफी हद तक निर्वाह, करने वाले तिब्बतियों ने स्वायत्तता की एक और मात्रा खो दी है।

---

259 दावा नोर्बू, "चाइनीज स्ट्रटेजिक थिंकिंग ऑन तिब्बत ऐंड द हिमालयन रीजन", सामरिक विश्लेषण 12, संख्या 4 (1988): 374

अध्याय सात

चीन का तिब्बत में शहरीकरण

परिचय

चीनी सरकार का तिब्बतियों को शहरीकरण की ओर धकेलना अनगिनत लोगों को उनके परंपरागत रहन सहन से दूर ले गया है तथा इससे तिब्बत में कई चीनी प्रवासी कामगारों को ले कर आया है जो तिब्बत में आकर रहने लगे है। सरकार की इन नीतियों के चलते तिब्बती लोगों की ज़मीन चीनी निवेशकों के हाथों में फिसल जाती है, जो वहा बुनियादी ढांचे का विकास करते हैं तथा ऐसे में तिब्बती निरन्तर बदलते शहरों में स्वयं को पाते हैं। यद्यपि पीआरसी यह दावा करती है, की शहरीकरण एक नई विकासात्मक नीति है जो क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों जगहों को विकासशील एवं सभ्य बनती है, वास्तव में यह नीति तिब्बती अस्तित्व को धीरे धीरे मिटा रही है।

चीन की राज्य परिषद् ने 2014 में नेशनल न्यू टाइप अरबनइज़ेशन प्लान या राष्ट्रीय नवीन शहरीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की जिससे शहरी लोगों की संख्या वर्ष 2012 में 52.6 प्रतिशत से 2020 में 60 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। नागरिक जिन के पास शहर में रहने हेतु अनुमति, अर्बन हुकोऊ, होगी उनका अनुपात 35.3 प्रतिशत बढ़ कर 45 प्रतिशत हो जायेगा। कई साल के विचार विमर्ष व् बदलाव में रूकावट के उपरांत से लेकर एक कडे शहरी हुकोऊ प्रणाली तक चीनी सरकार ने अपनी प्रक्रिया में ग्रामीण प्रवासियों को शहरी क्षेत्रों में अपने घरेलू पंजीकरण को स्थानांतरित करने के लिए ढील दी है। इस नयी नीति का तिब्बत पर अलग ही प्रभाव पड़ा है जहाँ शहरी–करण एक दबाव बन गया है। चीन के घने आबादी वाले तटीय प्रान्तों के चीनी प्रवासियों ने तिब्बत की और जाना शुरू कर दिया है तथा सुधारित हुकू प्रणाली ने उन्हे अपने घरेलु पंजीकरण को स्थानांतरित करना और आसान बना दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कई तिब्बतियों ने अपनी ज़मीन ज़ब्त होने के चलते गवा दी है। जैसा की एमिली टी येह ने अपनी पुस्तक टेमिंग तिब्बत में लिखा

है, यह चीन के तिब्बत[260] को अपनी प्रादेशिकता का रूप देने का हिस्सा है। जेम्स लेइबोल्ड, जो ला त्रोब विश्वविद्यलय मेलबोर्न में चीनी राजनीति तथा एशियाई मुद्दों के वरिष्ट विख्याता हैं, उनके अनुसार, चीन ने अपने प्रतिक्रियाओं के शस्त्रागार के भाग के रूप में शहरीकरण को और अधिक तेज़ कर दिया है इस उम्मीद के साथ की आर्थिक विकास एवं सांस्कृतिक संपर्क अस्मिता और स्थिरता को जन्म देगा।[261]

इस नीति ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया है जैसा की तिब्बती शहरों के विकास में देखा जा रहा है। 2018 तक, ल्हासा, शिगात्से, छमदो, न्यिन्गत्री, ल्होका और नागछु को प्रांत स्तर के शहर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) में कहा गया है। अधिक तिब्बती जनसंख्या वाले अन्य शहरों का भी टीएआर क्षेत्र के बाहर निर्माण किया गया हैः युनान प्रान्त में ग्याल्थंग (जोंगदियन, जिससे शांग्री–ला या शंगलीला); सिचुआन में दरत्सेदो (कांगडिंग); किंगहाई में त्सोशर, सीलिंग तथा युशु; और गांसू में त्सोए (हेजुओ) को पिछले दस सालों में "उन्नत" बनाया गया।[262]

बावा फुन्त्सोक वांग्याल, तिब्बत में एक उच्च स्तरीय कम्युनिस्ट अधिकारी ने अपनी किताब में लिखा की शहर चीन की क्षेत्रीय स्वायत्त जगहों[263] के केंद्र होने चाहिए।

क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्वायत क्षेत्रों के शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों को इन क्षेत्रों की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषता होनी चाहिए। इन जगहों में सुधार और बदलाव के चलते वास्तव में यह विशेषताएं धीरे–धीरे मिट गयी हैं तथा राष्ट्रीय वा क्षेत्रीय स्वायत्ता केवल नाम के लिए ही रह गयी है। अधिकांश रूप से इन तिब्बती क्षेत्रों के शहरों

---

260 यह एमिली टी. (2013)

261 जेराल्ड रोच, बेन हिलमैन और जेम्स लीबॉल्ड, "चीनी शहरों में इतने सारे तिब्बतियों क्यों जा रहे हैं", चीन फ़ाइल, 26 जून 2017 http://www.chinafile.com/reporting-opinion/viewpoint/why-are-so-many-tibetans-moving-chinese-cities.

262 कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं कांग्रेस के रूप में चीन की तिब्बत नीति में नए घटनाक्रम शुरू", तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान, 17 अक्टूबर 2017 https://www.save-tibet.org/new-developments-in-chinas-tibet-policy-as-communist-partys-19th-congress-begins/.

263 वॉंग्याल बावा फुंत्सोक, राष्ट्रीय मुद्दा और राष्ट्रीयताओं पर काम करना, ट्रांस (धर्मशालाः खावा करपो, 2013)

और कस्बों में चीनी प्रवासी रहते हैं।

चीनी जनसंख्या का तिब्बत में स्थानांतरण

1952 में, तीन साल के चीनी गणराज्य के बनने के उपरांत, माओ त्सेदुंग ने कहा, "तिब्बत एक बड़ी ज़मीन पर है परन्तु यहाँ की जनसँख्या बहुत कम है.... इसकी जनसँख्या को 2 या 3 मिलियन से बड़ा कर पांच या छह मिलियन तक ले जाना चाहिए तथा आगे इसे 10 मिलियन तक ले जाना चाहिए"। [264] उस समय तक यद्यपि तिब्बत को चीनी कम्युनिस्टों का कब्जा हुआ है किन्तु 1951 से ही, माओ ने तिब्बत में चीनी प्रवासिओं को बसने का इरादा बना चुके थे।

1955 में, लू शओखी जो की नवीन गणराज्य के राष्ट्रपति थे, उन्होनें दिवंगत पंचेन लामा को बताया की तिब्बत एक आज़ाद देश है तथा चूंकि चीन की अधिक जनसँख्या थी जो वहां बस सकती है।[265] अगस्त 1957 में, चाओं एनलाई, जो चीन के प्रधानमंत्री थे उन्होनें अपने भाषण में गैर चीनी क्षेत्रों का चीन में समावेश के राष्ट्र कार्यक्रम के विषय में बताया, तथा उन्होनें चीनी जनसँख्या वाले क्षेत्र में ज़मीन की कमी तथा भूमिगत प्राकृतिक स्त्रोतों की कमी और भ्रात्र अल्पसंख्यकों की आबादी वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक स्त्रोतों के विकास पर औद्योगीकरण हेतु ज़ोर दिया है। ज्होऊ ने कहा अल्पसंख्यक क्षेत्रों में श्रम शक्ति व् तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के चलते प्राकृतिक स्त्रोतों को अप्रयुक्त छोड़ दिया गया है। "बिना परस्पर सहायता के, विशेषतः चीनी लोगों से सहायता, ज्होऊ एनलाई ने कहा की, "अल्पसंख्यक लोग स्वयं को महत्वपूर्ण रूप से प्रगति करना कठिन होगे"।

जिन स्थानान्तरणों के चलते आमदो (छ :किंगहाई) में चीनियों की आबादी पचास प्रतिशत से साठ प्रतिशत तक बड़ी तथा छह से चालीस प्रतिशत तक शिनजियांग में बढ़ी, यह केवल कट्टर माओवाद के समय में 1950,1960 तथा 1970[266] के दशक की शुरुआत में हुआ। यद्यपि आमदो का अधिकांश क्षेत्र तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से आता है, यहाँ प्रान्त की

264 सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, कम्युनिस्ट चीन के तहत तिब्बतः 50 वर्ष (सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, 2001) 45

265 तिब्बत पर कानूनी जाँच समिति, न्यायविदों का अंतर्राष्ट्रीय आयोग, तिब्बत और चीनी लोगों के गणतंत्र, (जिनेवाः न्यायविदों का अंतर्राष्ट्रीय आयोग, 1960)

266 किंगहाई ब्यूरो का आंकड़ों (फठै), किंगहाई सांख्यिकीय वर्ष पुस्तक 3 (बीजिंगः चीन स्टेटिस–टिकल प्रेस, 2003), तालिका 3–3

अधिकांश आबादी चीनी है यद्यपि दोनों एक दूसरे पर अतिव्याप्त नहीं होते। प्रान्त को आठ प्रशासकीय क्षेत्र में बनता गया है जिसमें से पांच तिब्बती स्वायत्ता वाले जनपद हैं तथा एक तिब्बती–मंगोल स्वयत्ता वाले जनपद। यह छह मिल कर प्रान्त का 97.2 प्रतिशत क्षेत्र बनाते है।[267]

चीनी प्रवासी श्रमिकों की अधिक मात्रा सामान मांग को बढाती रही और इसके चलते दाम बढने लगे। तिब्बतियों की ज़मीन एवं जीवन पर दबाव इतना स्पष्ट दिखने लगा की तिब्बती स्वायत्ता क्षेत्र एक उच्च स्तरीय तिब्बती ने 1992 में कहा, "यहाँ एक छोटा और बड़ा दरवाज़ा है। यह छोटा दरवाज़ा बहरी दुनिया की ओर खुलता है तथा बड़ा दरवाज़ा चीन की ओर.....बड़ा दरवाज़ा छोटे दरवाजे को दबा देता है तथा तिब्बत पर निगले जाने का खतरा सबसे अधिक है"।[268]

सरकारी एवं सेना के अधिकारियों को तिब्बत भेजने के अलावा अत्यधिक आर्थिक सहायता और तिब्बत में बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के कारण चीनी श्रमिकों के एक बडे ताँता तिब्बत में लगा है। चीनी श्रमिक जिन्हें अपने गृह क्षेत्र में नौकरी के अवसर नहीं मिल पाते वह तिब्बत में नौकरी एवं व्यवसाय करने के लिए आकर्षित होते हैं। चीन से तिब्बत जाने वाली जनसँख्या वही नीति का पालन कर रही है जो किंग साम्राज्य के दौरान चीन अधिकृत मंगोलिया (आज का अंदरूनी मंगोलिया) में कार्यान्वित की गयी, जहाँ मंगोल 19वीं सदी के अंत में अल्पसंख्यक बन गए थे। यह जनसँख्या का स्थानान्तरण अधिकांश रूप से खेती–बाड़ी सम्बंधित था जिससे अधिकांश चीनी श्रमिक् ग्रामीण इलाकों में बस गए। परन्तु अंत में वह ग्रामीण वा शहरी दोनों ही प्रकार ही जनसँख्या में प्रभावी होने लगे। तिब्बती इलाकों में समकालीन प्रवास पूर्ण रूप से शहरी होई रहा है।[269]

2004 के कार्य पत्रों में एंड्रयू मार्टिन फिशर ने तिब्बत में शहरीकरण की विशेषताओं को इस प्रकार बताया है :

---

267 गुडमैन और डेविडे. एस. जी. "किंगहाई और पश्चिम का उद्भवः राष्ट्रीयता, सांप्रदायिक संपर्क और राष्ट्रीय एकीकरण", चीन तिमाही, संख्या 178 (2004): 379–99

268 एंडर्स होजमार्क एंडर्सन, नया बहुमतः चाइनीज पॉपुलेशन ट्रांसफर इन टिबेट (लंदनः टिबेट सपोर्ट ग्रुप, यूके, 1995), 55

269 एंड्रयू मार्टिन फिशर, "शांग्री ला की शहरी गलती की रेखाएंः पश्चिमी चीन के तिब्बती क्षेत्रों में अंतर–जातीय संघर्ष की जनसंख्या और आर्थिक नींव", संकट राज्य कार्यक्रम काम करने वाले कागजात, DESTIN विकास अध्ययन संस्थान (LSE), जून 2004

इन जनसंख्या की गति के साथ बातचीत करते हुए, शहरी क्षेत्रों में हाल के तेजी से आर्थिक विकास में ध्रुवीकरण हुआ है, बड़े पैमाने पर शहरी प्रशासनिक विस्तार और कुछ हद तक बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं को चीन में कहीं और नहीं देखा गया है। विकास दर के पुनर्जीवन के अलावा मध्य –1990 के दशक में मुख्य रूप से सब्सिडी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, तिब्बती इलाकों में शहरी–ग्रामीण असमानताएं अन्य पश्चिमी क्षेत्रों सहित चीन में हर जगह की तुलना में काफी अधिक हैं। इसने स्थानीय ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीबों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ तेजी से विकासशील शहरी क्षेत्रों पर दबाव डाला है, जबकि इस तरह के तेजी से विकास बल्कि अनन्य हैं, अर्थात् कम कुशल श्रम को अवशोषित करने के लिए किसी भी महत्वपूर्ण सहायक माध्यमिक उत्पादक गतिविधियों के बिना, उच्च–मजदूरी और उच्च–कौशल श्रम में केंद्रित है।[270]

राज्य परिषद् के पश्चिम क्षेत्रीय विकास ऑफिस ने सलाह दी है की कोई भी सरकारी अधिकारी तिब्बत में अपने हुकोउस को लाने वाले लोगों से शहरी जनसंख्या अधिभार या इस प्रकार का अन्य कुछ नहीं ले सकता।[271] इस सलाह ने चीनी प्रवासियों को प्रोत्साहित किया है की वह तिब्बती शहरों में आकर बसें। आने वाले दशकों में तिब्बत में लाखों की संख्या में चीनी प्रवासियों की जनसंख्या में वृद्धि देखी जा सकेगी।

ग्रामीण तिब्बतियों का शहरों और कस्बों की ओर पलायन

तिब्बती के शहरीकरण ने कई ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे तिब्बतियों को प्रोत्साहित किया है की वह तिब्बती शहरों में आकर गैर कृषि वाले व्यवसाय चुनें। चूंकि उनके पैत्रिक ज़मीनें ड़ेवेलोपेर्स को बेच दी जाती हैं जो उद्योगों का निर्माण करते हैं जो तिब्बत में और भी प्रवासियों को आकर्षित करती हैं। जैसा की स्ट्रेट्स टाइम्स ने हाल ही में लिखा, "चीन के 31 प्रान्तों, क्षेत्रों और नगर पालिकाओं में केवल तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र ही ग्रामीण एवं शहरी नागरिकों में भेद कर पाता है।"[272] ग्रामीण/शहरी वर्गीकरण के इस कार्यक्रम के कारण ही चीनी प्रवासी जो तिब्बत के बाहर से आते हैं तिब्बती शहरों में

270 एंड्रयू मार्टिन फिशर (2004)

271 राज्य परिषदों का परिपत्र, पश्चिमी क्षेत्र के विकास से संबंधित नीतियों और उपायों के कार्यान्वयन पर सुझावों के वितरण पर सामान्य कार्यालय। राज्य परिषद के पश्चिमी क्षेत्र विकास कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया, 29 सितम्बर 2001।

272 "बीजिंग सुधारों में हओको शहरीकरण को आगे बढ़ाता है", तनाव का समय, 22 सितंबर 2016 https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/beijing-finally-adopts-hukou-reforms.

फिर से बसने के लिए प्रोत्साहित होते हैं जहाँ उनकी पहुँच सामाज कल्याण योजनाओं पर होती है।

प्राकृतिक प्रवास के उदाहरणों के अतिरिक्त ग्रामीण इलाकों से सरकार की जबरन पुनर्वास नीति के चलते कई तिब्बतियों को शहरों में भेजा जा रहा है। यह नीति देहाती तिब्बतियों को जो ग्रामीण पहाड़ों और घाटियों में अपने झुण्ड के साथ रहते हैं, उन्हें छोटे कस्बों में स्थानांतरित करती है। ये नीति सरकार को अनुमति देती है की वह ग्रामीण निवासियों के गमनागमन को सामाजिक स्थिरता के नाम पर नियंत्रित करे।

जैसे की सोफी रिचर्डसन, ह्यूमन राइट्स वॉच की चीन निदेशक का कथन है, "तिब्बतियों का उन नीतियों को बनाने में कोई हाथ नहीं है जो उनके जीवन को बदल रही हैं और एक अत्यंत ही दबाव के सन्दर्भ में उससे चुनौती देने का भी कोई तरीका नहीं है। अधिकारों का हननं इस दौरान परामर्श की कमी से लेकर पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने में विफलता तक जाता है, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार निष्कासन को वैध ठहराने के लिए आवश्यक हैं। इस कदम के बाद खानाबदोश जीवन से शहरों की ओर अचानक बदलाव ने तिब्बत में बेरोज़गारी बढ़ा दी है।

तिब्बती शोधकर्ता, गोंगबो ताशी (गोंपो तशी) तथा मार्क फोग्गिन द्वारा 2009 में किया गया एक क्षेत्र अध्ययन लोका प्रान्त में पारिस्थितिक पुनर्वास का अनुभव जन्य प्रभाव दिखाता है।

300 से अधिक लोगों के साक्षात्कार के उपरांत पता चला की शोधकर्ताओं ने पाया है कि जबरन बसाने के चलते देक्यी गाँव के वासी अपने पशुधन से वंचित हो जाएगी जो उनके जीवन का प्रमुख हिस्सा था। जिन नए कस्बों में ग्रामीण दुबारा से बसे थे वहां पशुधन चरने की जगह कम थी। और यद्यपि दुबारा से बसे तिब्बतियों को खेती का प्रशिक्षण दिया जाना था परन्तु उनमें से अधिकतर ने शिकायत की उनको इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप उनके पशुधन की संख्या बहुत कम हो गयी जिसके चलते पहले से आत्म निर्भर ग्रामीण तिब्बतियों को बहुत अधिक रूप से सरकारी छूट पर निर्भर होना पड़ा।

नीचे दिये गए टेबल में पशुधन की तिब्बत स्वायत्ता वाले क्षेत्र द्रानांग और

त्सोना प्रान्तों में कम होती संख्या का पता चलता है।[273]

टेबल नः1 द्रानांग तथा त्सोना प्रान्तों में औसत पशुधन संख्या, पूर्व और पोस्ट पुनःस्थापन, स्त्रोत :गोंपो तशी, 2009 सर्वे

Original county	Yak and cattle		Sheep and goats		Donkeys and horses	
	Before	After	Before	After	Before	After
Dranang County	1320	255	876	107	267	0
Tsona County	2457	126	1260	32	253	0
N=42 households (over 300 individuals)						

2005 से 2009 में किंगहाई की दो बस्तियों में निवासियों को चीनी शोधकर्ता क्सु जून द्वारा अन्य शोधकर्ताओं के साथ इंटरव्यू लिया गया जिन्होनें हर साल एक महीना युशुल तथा ना–गोरमो प्रान्तों में एक महिना बिताया। अपने शोध में जहां पुनर्स्थापन हुआ क्सु ने बताया की पुनर्स्थापित खानाबदोश अंत्यंत ही गहरे रूप से विस्थापन की भावना का सामना करते हैं।

> *हमने उनके नव जीवन के संघर्ष को नज़दीक से देखा जब वह नयी जगह पर बस रहे थे तथा अपने भविष्य के बारे में असमंजस में थे। कई मायूस थे। कई अपमान जनक अनुभव कर रहे थे क्योंकि उनको अपने जीवन यापन हेतु अपने रिश्तेदारों पर निर्भर करना पड़ रहा था जो घास के मैदानों में रहते थे। कुछ को अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए घास के मैदानों में लौटना पड़ रहा है। पांच साल की जांच से पता चलता है की सान जियांग युन संरक्षण की अवधि के दौरान आस पास के शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग बिना घास के मैदानों के स्त्रोतों का उपयोग किये बिना जीवन यापन नहीं कर पाए हैं। दूसरी ओर इस प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है की इस प्रकार के प्रवास से घास के मैदानों को कुछ सहायता मिली है, जिससे स्थानान्तरण का मुख्य कारण बताया गया था।*[274]

273 ताशी निमा, "तिब्बती पठार पर विकास के चर्चाः दरत्सेदो में शहरीकरण और खेती का विस्तार", हिमालय 30, संख्या 1 (2011)

274 शु जून, "चुनौतियांः किंघाई प्रांत में खानाबदोशों का पुनर्वास", https://case.edu/affil/tibet/tibetanNomads/documents/Challenges-Resettlementof-NomadsinQinghaiProvince.pdf. The detailed paper was presented at SLTP Conference, Leipzig, December 2-3, 2009.

2014 से चीनी सरकार ने जानबूझ कर पशुधन का दाम कम कर दिया है। पहले बाज़ार में एक बधिया भेड़ 1200 युआन दिलवा सकती थी परन्तु अब यह राशी केवल घटकर 500 युआन रह गयी है। यह गिरावट पशुधन को खरीदने और बेचने के बाज़ार को नष्ट करने से आई है। यह अनुमान लगाया जा सकता है की खानाबदोश पुनः स्थापन नीति को क्रियान्वित करने के लिए चीनी सरकार ने पारंपरिक तिब्बती खानाबदोश बाज़ारों को गैर फायदेमंद बना कर उन्हें निशाना बनाया है तथा खानाबदोशों को अपना पारंपरिक जीवन छोड़ कर नयी बस्तियों में जाने पर विवश किया है। वर्तमान में 56 प्रान्तों में तिब्बती खानाबदोश तथा 68 में अर्द्ध तिब्बती खानाबदोश हैं। पशुधन में गिरावट ने तिब्बतियों के लिए 124 प्रान्तों में आय को औसतन आधे पर ला दिया है जिस से 84.35 प्रतिशत तिब्बत की जनसँख्या प्रभावित हुई है।

तिब्बत में चीनी प्रवासी श्रमिकों की भीड़ के चलते, चीनी भाषा ने भी बाज़ार में अपना महत्व बना लिया है। विशेष रूप से चीनी सरकार ने तिब्बत के सभी सरकारी कार्यालयों में चीनी भाषा को अधिकारिक भाषा के रूप में अपना लिया है। अधिक रूप से चीनी भाषा लोगों के आय दिन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा अधिक चीनी श्रमिकों के चलते कई तिब्बती शहरों में वाणिज्य की भाषा बन गयी है। कई सरकारी नेता एवं अधिकारी ये मानते हैं की चीनी भाषा सीखना तिब्बतियों को बाज़ार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा।[275]

इसीलिए तिब्बती भाषा का तिब्बती अस्तित्व और संस्कृति में उपयोग घट रहा है।

शहरीकरण कार्यक्रम की नाममात्र परोपकारी आकांक्षाओं के बावजूद पीआरसी के दृष्टिकोण का ग्रामीण तिब्बतियों को अधिक फायदा नहीं होने वाला था। तशी न्यीमा इस मुद्दे को अपने हिमालय में दिये गए लेख में उठाते हैं :

> *टॉप–डाउन कार्यक्रम ग्रामीणों को योजना बनाने में उनकी भागीदारी से वंचित रखते हैं। ग्रामीणों को 'विकासात्मक समस्याओं' के रूप में चित्रित किया गया है। विडम्बना से कार्यान्वन ने इस परियोजना को साथ ही गैर राजनीतिक बना दिया है तथा इसका चित्रण तकनीकी रूप से कई कारणों के लिए महत्वपूर्ण बताया है विशेषतः राजनीतिक स्थिरता। जिन ग्रामीणों को अधिकारिक रूप से*

275 शियोंग वेंग, "चीन के तिब्बती क्षेत्रों में स्थानीय विकासात्मक दृष्टिकोण" एशियाई हाई लैंड परिप्रेक्ष्य 28, (2013):129–154

पिछड़ा हुआ व् आदिम माना गया था उन्हें विकास का केंद्र बनाया जाना था। परन्तु उनका विकास का अपना अनुभव आधिकारिक वर्णन से बिलकुल अलग था। मौजूदा सशक्त संबंधों के कर्ण परियोजना को अपनी शर्तों पर परिभाषित करना अधिक सफलतापूर्ण नहीं रहा था। अधिकारिक वचन के भीतर उपर्युक्त लक्ष्य और विकास विचारधारा ग्रामीणों की वास्तविक इच्छाओं से आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम प्रासंगिकता है।[276]

शहरीकरण तथा सामाजिक स्थिरता

लम्बी सामाजिक स्थिरता, क्षेत्रीय विकास तथा "पिछडे क्षेत्रों" के आधुनिकीकरण जैसे लक्ष्यों द्वारा चीनी सरकार के आधिकारिक प्रवचन में विकास को परिभाषित किया गया है।

तिब्बत के पिछडे इलाकों को छोड़ कर शहरों में लोगों के आने जाने संपर्को पर पीआरसी के ग्रिड मोनिटोरिंग सिस्टम के अंतर्गत विशेषकर अधिक आसानी से नज़र रखी जा सकती है। चीन ने अपना प्रथम शहरी ग्रिड प्रबंधन प्रयोग बीजिंग के दोंगछेंग जिला में अक्टूबर 2004 में किया।[277] यदि चीन किसी भी प्रकार की लोकतान्त्रिक जांच और संतुलन से रहित रहा तो ग्रिड प्रबंधन के निरंतर विकास से तिब्बत में केवल एक आधुनिक पुलिस राज्य का मॉडल बनेगा। पीआरसी के लिए यह शहरीकरण कार्यक्रम का मुख्य लाभ है।[278]

ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2013 में एक रिपोर्ट में बताया की किस प्रकार शहरी ग्रिड प्रबंधन प्रणाली तिब्बत की राजधानी, ल्हासा में निवासियों के आने जाने पर नज़र रखने के लिए प्रभावी साबित हो रही है।[279] शहरी प्रशासन के इस ज़मीनी स्तर में शहरों में प्रत्येक "पड़ोस" या "समुदाय" को तीन या अधिक इकाइयों में विभाजित किया जायेगा। ल्हासा में अप्रैल 2012 में कम से कम आठ पायलट इकाइयाँ स्थापित की गयी और सितम्बर में उनके "उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त" करने की घोषणा कर दी गयी। उसी वर्ष अक्टूबर में क्षेत्रीय सचिव ने कहा क्योंकि "ल्हासा अभ्यास ने सामाजिक

276 ताशी नीमा (2011)

277 वू क्येंग, "चीन में शहरी ग्रिड प्रबंधन और पुलिस राज्यः एक संक्षिप्त अवलोकन" चीन बदले, 12 अगस्त 2014 https://chinachange.org/2013/08/08/the-urban-grid-management-andpolice-state-in-china-a-brief-overview/.

278 वही

279 वही

प्रबंधन (यानि बडे पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने) को मज़बूत बनाने और उसमें आविष्कार करने के लिए ग्रिड प्रबंधन को लागू करने की प्रभावशीलता को पूरी तरह से साबित कर दिया है" तथा इसे तिब्बती स्वायत्ता क्षेत्र के कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों और मंदिरों में इस प्रणाली को सर्वभौमिक बनाया जाना चाहिए।

तिब्बत के वातावरण के विशेषज्ञ, गेब्रियल लाफित्ते, कहता हैं की तिब्बत का प्रतिभूति करण अंतत्तः उसके शहरीकरण पर निर्भर करता है।

> *आधुनिक तकनीकों के साथ भी लाखों चलनशील ग्रामीणों पर नज़र रखना जो एक पश्चिमी यूरोप से बडे पठारी चरागाह में फैले हैं, संभव नहीं है। यह कोई दुर्घटना नहीं हो सकती कि पार्टी–राज्य ने लम्बे समय तक विकास को सभी तिब्बती समस्याओं के दीर्घकालिक उत्तर के रूप में और शहरीकरण को विकास के सार के रूप में तथा बिजली से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के लिए सभी केंद्रीकृत सेवाओं के वितरण के लिए आवश्यक शर्त के रूप में लिया है। शहरीकृत जनसँख्या एकाग्रता भी अधिक सुपाठ्य और संप्रभु राज्य के लिए सुलभ है।*[280]

भूमि की निकासी

आस पास के कस्बे और गाँव अब तिब्बत में शहरों से जुड़ रहे हैं। भूमि जो वास्तव में खेती के लिए उपयोग होनी थी, उस पर अब विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ साथ आवासीय और वाणिज्यिक भवनों का निर्माण हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, "ग्रामीण और औद्योगिक उपयोग (चीन में) के लिए अपेक्षित रूपांतरण विशेष रूप से अक्षम रहा है क्योंकि निर्णय बाज़ार की मांग के बजे प्रशासनिक निर्णयों द्वारा बडे पैमाने पर संचालित किये गए हैं।[281]

चीन के शहरीकरण ने एक बड़ी मात्र में भूमि को स्त्रोत के रूप में कब्ज़ा लिया है चूंकि शहरी सीमाएं बढती हैं और शहरों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भी बढ़ता है मुख्य रूप से आसपास के ग्रामीण भूमि के विस्तार और

280 गेब्रियल लाफित्ते, "निष्कपटता को अनिवार्य बनानाः चीन सभी नागरिकों के व्यवहार की सही निगरानी और सुधार का सपना देखता है", 15 जुलाई 2017 http://rukor.org/making-sincerity-mandatory/.

281 "चीनः नई निगरानी, तिब्बत में सुरक्षा", ह्यूमन राइट्स वॉच, 20 मई 2013 https://www.hrw.org/news/2013/03/20/china-alarming-new-surveillance-security-tibet.

एकीकरण के माध्यम से।[282] जैसा की नीचे दिए ग्राफ में बताया गया है की शहरीकरण परियोजना के कारण चीन में पिछले कुछ वर्षों में शहरी भूमि की मांग बढ़ी है।

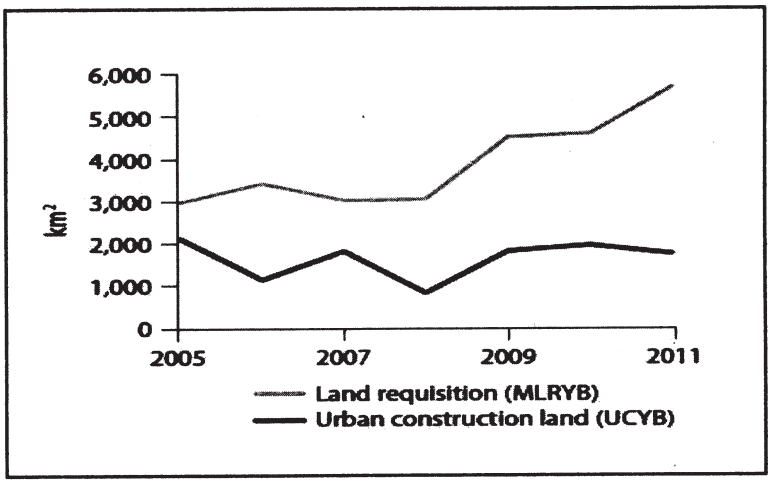

2001 से 2011 में चीन में शहरी निर्माण भूमि के रूप में वर्गीकृत भूमि की मात्र 17600 वर्ग किलोमीटर (वर्ग किमी) से बढ़ कर 2011 में 41805 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र तक पहुँच गयी जो की एक दशक में 58 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी। शहरी भूमि की मांग का लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण भूमि के नियमन के माध्यम से पूरा किया गया, जबकि अविकसित शहरी निर्माण भूमि के मौजूदा भंडार से केवल 10 प्रतिशत की आपूर्ति की गई थी। इस प्रवृत्ति के बाद, जैसे कि तिब्बती शहरों में ग्रामीण भूमि बढ़ती है, तिब्बत को चीनी सरकार द्वारा तेजी से विकसित किया जाएगा।

सरकार ने उन लाखों किसानों या ग्रामीणों पर तेजी से शहरीकरण के प्रभावों को नजरअंदाज कर दिया है, जिन्हें आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्षों से भूमिहीन (कानूनी या अवैध रूप से) बनाया गया है।[283] चीन में हर साल तीन मिलियन लोग भूमिहीन किसान बन जाते हैं। शहरीकरण की वर्तमान गति के कारण 2020 में कुल संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है।[284]

282 विश्व बैंक और विकास अनुसंधान केंद्र, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाईना, "चीन का शहीकरण और भूमिः सुधार के लिए एक रूपरेखा," शहरी चीनः कुशल, समावेशी और सतत शहरीकरण, (वशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक, 2014)

283 ताशी नीमा (2011), 79

284 विश्व बैंक तथा विकास अनुसंधान केंद्र, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2014

शहरों की वृद्धि का एक और परिणाम है। उनकी किताब टेमिंग तिबेट, एमिली टी येह ने कहा कि क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता (एलआरएनए) के चीन के कानून के अनुसार, जब क्षेत्र, प्रान्त, और काउंटी शहरों में उन्नत होते हैं, तो इन क्षेत्रों की स्वायत्त स्थिति खो जाती है। उराद्यन बुलाग, एक मानवविज्ञानी, जो आंतरिक मंगोलिया पर शोध करते हैं, ने तर्क दिया कि प्रान्त से शहर तक एक प्रशासनिक पदोन्नति का लाभ, विशेष रूप से स्थानीय नेताओं के लिए, जातीय संवेदनशीलता को जातीय स्वायत्ता के नुकसान के विषय में बताता है।

निष्कर्ष

चीन द्वारा तिब्बत शहरीकरण (और पूरे देश में) चीन की धीमी अर्थव्यवस्था का उपाय के रूप में लक्षित है। यह लाखों चीनी प्रवासी श्रमिकों को तिब्बत में व्यवसाय बसाने और लागू करने के लिए एक नीति बनाने का लक्ष्य है। इस प्रक्रिया के तहत, तिब्बत के शहर जनसांख्यिकीय बदलावों से गुज़रे हैं, जिसके परिणामस्वरूप चीनी संस्कृति का अक्सर तिब्बती भाषा और प्रथाओं की कीमत पर मजबूत प्रभाव पड़ता है।

आने वाले कुछ दशकों में तिब्बत में 30 प्रतिशत शहरीकरण की अनुमानित दर का अर्थ यह होगा कि तिब्बत के सभी शहर चीनी बन जाएंगे। नतीजतन, तिब्बती भाषा स्वायत्त स्थिति से जुड़े भाषा के अधिकारों को खो देगी। इसके बाद, सरकार जब भी आवश्यक समझेगी तो शहरी क्षेत्रों में प्रत्यारोपित किए गए निवासियों की गतिशीलता और संचार की सख्त निगरानी की जाएगी।

शहरों की वृद्धि से निपटने के लिए, ग्रामीण भूमि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) और विदेशी कंपनियों द्वारा खरीदी जाती है। भूमि एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो कई ग्रामीण तिब्बतियों को अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। और न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के तिब्बती अपनी भूमि खोते हैं साथ ही साथ, इसके बाद उन्हें अकुशल, आमतौर पर अस्थायी काम देखने होंगे। यदि चीनी सरकार द्वारा शहरी भूमि की मौजूदा दर की गणना जारी रहती है, तो तिब्बत में कई क्षेत्रों में भूमि का स्वामित्व, चीनी प्रवासियों, व्यवसायों और राज्य को हस्तांतरित किया जाएगा। तिब्बत के शहरीकरण हेतु दिया जा रहा जोर, जो ऐतिहासिक रूप से ग्रामीण रहा है, सरकार का एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रचा गया है,

लेकिन चीन गणराज्य में तिब्बतियों को एकीकृत करने के राजनीतिक एजेंडे के साथ, इस "जातीय स्वायत्तता" को कम करके और शीर्ष से नीचे तक का नियंत्रण (टॉपडाउन) सुनिश्चित करना है। अधिकारिक मीडिया ने बताया है कि, 2020 तक किंगहाई में सात नए शहर होंगे (तिबःआमदो) क्योंकि चीनी अधिकारी कम से कम पांच लाख लोगों का शहरीकरण करने की इच्छा रखते हैं तथा परिवहन और संचार अवस रचना के नेटवर्क का निर्माण करने की इच्छा रखते हैं।[285]

तिब्बत में शहरीकरण जिससे की तिब्बत में पारंपरिक जीवन को क्षति पहुंचना, तिब्बतियों के दिल नहीं जीत सकता जैसा की शी जिनपिंग ने तिब्बत में हुई पिछली वर्क फोरम में बताया।[286] इस से केवल तिब्बती प्रतिरोध ओर मज़बूत होगा।

285 "कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं कांग्रेस के रूप में चीन की तिब्बत नीति में नए घटनाक्रम", तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान, 17 अक्टूबर 2017 https://www.savetibet.org/new-developments-in-chinas-tibet-policy-as-communist-partys-19th-congress-begins/.

286 बी. झाओ, "भूमि–खो चुके किसानों की समस्या का समाधान कैसे करें?" रेनमिनवांग, 9 दिसंबर 2005 http://theory.people.com.cn/GB/40553/3929253.html.

अध्याय आठ

चीन का तिब्बत के लिए मास्टर प्लान: अवतार द्वारा शासन

परिचय

तिब्बत के बौद्ध मानते हैं की सभी संवेदनशील प्राणी इस वर्तमान जीवन में एक पूर्व अस्तित्व से आते हैं तथा मृत्यु के उपरांत भी पुनर्जन्म लेते हैं। यही कुछ भिक्षुओं के पुनर्जन्म, जिन्हें टुल्कु कहा जाता है की अनोखी परंपरा को पहचाने का आधार है, यह 13वीं सदी में आरम्भ हुआ। तिब्बत में तिब्बती बौद्ध धर्म के चार विभिन्न संप्रदाय हैं तथा हर एक ने टुल्कु को पहचानने का अपना तरीका विकसित कर लिए है।

दलाई लामा तथा पंचेन लामा सबसे प्रसिद्ध वंश (टूल्कु) हैं जो अभी क्रमशः अपने 14वें तथा 11वें अवतार में हैं। परमपावन 14वें दलाई लामा की पहचान पवित्र झील ल्हामो ल्हत्सो में प्रकट दृष्टि से हुई। कुछ लामाओं की पहचान उनके द्वारा विश्वसनीय रूप से याद किये गए उनके पुनर्जन्मों से भी की जाती है। अन्य अवतरित लामा अन्य लामाओं के नए अवतारों को पहचान जाते हैं जैसे की 11वें पंचेन लामा की पहचान 14वें दलाई लामा द्वारा की गयी।

लामाओं के उतराधिकारी को पहचानने के कई महतवपूर्ण तरीके हो सकते हैं जिसमे से एक मृत्यु पूर्व की इच्छा भी हो सकती है। उत्तराधिकारी अपने पूर्व जीवन के विषय में विश्वसनीय उपाख्यान बता सके, अपने पूर्वज की चीज़ों को पहचान सके तथा उन लोगों का पता कर सके जिसने उसको सेवा की थी। अन्य तरीकों में विश्वसनीय अध्यात्मिक गुरुओं से अटकलें लगाना तथा देववाणी पर आधारित भविष्वाणी करना हैं। अभी तक पुनर्जन्म, अवतार समदींग दोरजे फाग्मो को छोड़कर अधिकांश रूप से पुरुष ही रहे हैं।

तिब्बती बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म प्रणाली और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है चूंकि इन लामाओं को उच्च स्तर के अध्यात्मिक व् राजनीतिक अधिकार दिये जाते हैं, जैसे की परमपावन दलाई लामा ने दर्शाया है। चीनी गणराज्य,

तिब्बत पर पूर्ण कब्जे की होड़ में लामाओं के पुनर्जन्म को मान्यता देना के अधिकार पर हक जताता आया है। यह परे हटाते हुए की यह सरकार के लिए कितना हैरतंगेज़ है की वह पुनर्जन्म के महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दों पर अपना हक जताए, चीनी गणराज्य के कार्य व् वक्तव्य अपने आप में एक अवसर बन कर उभरते हैं की किस प्रकार हिसाब बराबर कर लिया जाये तथा इस क्षेत्र का इतिहास तथा अद्वितीय तिब्बती संस्कृति को अधिक श्रोताओं तक पहुँचाया जाये। इस ध्येय को मस्तिष्क में रख, यह अध्याय दलाई लामा की पुनर्जन्म प्रणाली, जो वर्तमान दलाई लामा की पहचान तथा भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालती है, पर चर्चा करेगा।

दलाई लामा वंशावली का आरम्भ

वर्तमान टुल्कु पुनर्जन्म प्रणाली वास्तविक रूप में केवल तिब्बती बौद्ध प्रणाली में ही अभ्यास किया जाता था तथा बाद में इसे मोंगोलों ने भी अपना लिया। और कोई भी बौद्ध देश, यहाँ तक की चीन भी इस संस्कृति का पालन नहीं करते। बुद्ध धर्म के आने से पूर्व, तिब्बत का अपना बॉन धर्म पुनर्जन्म के आधार को मानता था तथा यह बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ और गहरा होता गया। टुल्कु को पहचानने की प्रथा 13वीं सदी में कर्मा पक्षी को कर्मपा दुसुम खेंपो के अवतार के रूप में मान्यता मिलने के साथ आरम्भ हुई। तब से कर्मपों के 17वें अवतार हो चुकें हैं। गेंदून द्रुब, जो ज़े त्सोंखापा, जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग संप्रदाय का संस्थापक भी कहा जाता है उनकी मृत्यु 1474 में तशी ल्हुन्पो मठ स्थापित करने के उपरांत हुई। 1476 में संगे छोएग्यल नमक युवा जो त्सांग तनक में पैदा हुआ था उससे गेंदून द्रुब के अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, जब उसने अपने पूर्व जनम के विषय में सही जानकारी प्रदान की। पुनर्जन्म की इस पंक्ति में, सोनम ग्यात्सो को दलाई लामा की पदवी प्रदान की गयी। तब से लबरंग की परंपरा चली आ रही है तथा गदेन फोद्रंग की सरकार, दलाई लामा कार्यालय, दलाई लामा के आने वाले अवतारों को ढूँढता है तथा उन्हें मान्यता प्रदान करता है।

14वें दलाई लामा की खोज के दौरान तिब्बत-चीन सम्बन्ध

1933 में 13वें दलाई लामा की मृत्यु के बाद, तिब्बत की सरकार ने तीन जगह उनके अवतारों को खोजने के लिए दल भेजे। केवत्संग रिन्पोछे के नेतृत्व में एक दल ने एक लडके को ढूँढा जिसका नाम ल्हामो थोंडुप

था तथा उसका जनम तिब्बती सौर कैलेंडर के पांचवें महीने के पांचवें दिन (जुलाई 6, 1935) आमदो के तकत्सेर में कुम्बुम के निकट जन्म हुआ था। यह बालक देवी देवताओं तथा लामाओं की भविष्यवाणियो तथा ल्हामो ल्हुत्सो झील में देखे गए दिव्य दृष्टान्तों से मेल खाता था। परन्तु सिपहसालार माँ बुफेंग, जिसका उस समय इलाके पर खासा दबदबा था, के दखल से बचने के लिए, केवत्संग रिन्पोछे ने अपनी पहचान आरम्भ में छुपाये रखी।

चीनी सरकार तिब्बत में हो रहे इस घटनाक्रम से वाकिफ थी। यह हमें शी अन के एक गुप्त तार सन्देश से पता चला जो उस समय वहां राष्ट्रवादी सरकार की सैन्य समिति के निदेशक थे तथा जेंग डिंगवेन, जो क्षेत्रीय सैन्य कमान के प्रमुख थे, जो उन्होनें वू जोंगज़िन को किया था जो मंगोलिया तथा तिब्बती मामलों की समीति (एमटीएसी) के निदेशक थे। तार के अनुसार :

तिब्बती ल्हासा सरकार ने पिछले साल (1937) में सर्वोच्च लामा केवत्संग लामा तथा क्हेयमे सोनम वांगदु तथा अन्य को त्सोंगोन में दलाई लामा के अवतार की खोज में भेजा। लगभग आधे साल के उपरांत उन्होनें कुम्बुम के निकट एक जहो चीनी परिवार में ढूँढा। दलाई लामा का अवतार ल्हासा भविष्यवाणियों तथा पंचेन लामा की जांच के उपरांत बिना किसी शक के सत्यापित हो गया।

सन्देश के अंत में जियांग दिगवेन सुझाव देते हैं किः

केंद्रीय सरकार के सरहद के इलाकों को सुरक्षित करने की नीति के अंतर्गत, में यह सलाह देता हूँ की यह आवश्यक है की दलाई लामा की तिब्बत वापसी के विषय में एक सही निर्णय लिया जाये अथवा एक प्रतिनिधि को जिम्मेदार लोगों की सहयता के लिए नियुक्त किया जाये ताकि वह अपना कार्य व्यवस्थित रूप से कर सकें। अथवा त्सोंगोन सरकार को आदेश दिया जाये की वह दलाई लामा को कुम्बुम मठ में अस्थायी रूप से रखें जब तक की उनकें आगे के सफ़र अथवा वही रहने पर कुछ निर्णय न लिया जाये। [287]

287 13वें दलाई लामा की प्रार्थना सेवा तथा 14वें दलाई लामा के सिंहासन होने के दस्तावेज़ों का संग्रह, चीनी भाषा, 134 (यहाँ से प्रार्थना सेवा तथा सिंहस्नारुद होने के दस्तावेज़ों का संग्रह)। इस अध्याय में दिये गए कई सन्दर्भ वह उल्लेख चीनी सरकार द्वारा समर्थित चाइना तिब्बत ओलोजी अनुसन्धान संस्थान से आये हैं। यह नोट किया जाना चाहिए की चीन अक्सर अपनी सामग्री को तोड़ मरोड़ कर प्रकट करता है। उदहारण के लिए चीनी अधिकारीयों ने तिब्बत सरकार के सन 1950 से पूर्व के दस्तावेज़ों के संग्रह, जो तिब्बती भाषा में थे तथा जिसमें चित्र भी थे का अनुवाद चीनी भाषा में किया है उसमें महतवपूर्ण शब्दों को अपने अनुसार बदल डाला है। जैसेः चीनी सरकार की जगह केंद्रीय

वू जोंगज़िन ने तब प्रधानमंत्री कार्यालय को 26 अप्रैल 1936 एक तार भेजा जिसमे लिखा था :

> *दलाई लामा की खोज से जुडे मुद्दे की जाँच से हमें पता चला है, हमारी जानकारी में यह लाया गया है की केवत्संग रिन्पोछे तथा कुछ अन्य को त्सोंगोन (आमदो) में अवतार की खोज के लिए भेजा गया है तथा यद्यपि अब एक साल से ऊपर हो गया है खोजी दल ने हमें इस विषय में टेलीग्राम से कोई जानकारी नहीं दी है।*[288]

जैसा की यह संवाद दर्शाते हैं कि तिब्बती खोजी दल अपना कार्य गुप्त रूप से, बिना चीनी सरकार के परामर्श के रीजेंट रेटिंग रिन्पोछे के अनुदेशों पर कर रहे थे।

14 अगस्त को माँ बुफेंग ने एमटीएसी के एक गुप्त टेलीग्राम सन्देश का उत्तर देते हुए कहा कीः केवत्संग रिन्पोछे ने रेटिंग हुतुक्तु को एक टेलीग्राम देकर इस इलाके से 14वें दलाईलामा के लिए तीनों बालक उम्मीदवारों पर किसी निर्णय हेतु इच्छा व्यक्त की। अभी तक कोई अनुदेश प्राप्त नहीं हुआ है।"[289] इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद एमटीएसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को 18 अगस्त 1938 को सलाह दी की स्वर्ण कलश को प्रान्त की सरकार को प्रदान करने की आवश्यकता है।[290] इसी वर्ष 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कार्यालय को एक और पत्र में, एमटीएसी ने अवतार की पहचान हेतु तीन और तरीकों का सुझाव दिया। यह थेः

1. राष्ट्रीय सरकार उच्च स्तरीय अधिकारियों को ल्हासा में प्रतिनिधि के रूप में भेजेगी ताकि स्वर्ण कलश में से चित्रण का कार्य रेटिंग हुतुक्तु के साथ पूर्ण किया जा सके।

2. राष्ट्रीय सरकार उच्च स्तरीय अधिकारियों को ल्हासा में प्रतिनिधि के रूप में भेजेगी ताकि स्वर्ण कलश में से चित्रण का कार्य रेटिंग हुतुक्तु के साथ

प्राधिकरण तथा "ल्हासा शहर" की जगह, "तिब्बत राष्ट्र की जगह", "नोर्लिंग केलसंग महल" की जगह" नोर्बुलिंग्का केलसंग पैलेस, ल्हासा में स्थित यह रिकॉर्ड फिर भी काम के स्त्रोत सिद्ध हो सकते हैं चूंकि इनसे प्रथम दृष्टा समय की जानकारी मिलती है, परन्तु इस प्रसंग पर इन शब्दों को उच्च मूल्य देने से पूर्व अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए।

288 प्रार्थना सेवा तथा सिंहासनारूढ़ होने के विषय में दस्तावेज़ों का संग्रह, चीनी भाषा,135

289 वही 140

290 वही –

न केवल पूर्ण किया जा सके बल्कि इन कार्यों के प्रबंधन हेतु प्रतिनिधि भी नियुक्त करेगी।

3. राष्ट्रीय सरकार उच्च स्तरीय अधिकारियों को ल्हासा में प्रतिनिधि के रूप में भेजेगी ताकि स्वर्ण कलश में से चित्रण का कार्य रेटिंग हुतुक्तु के साथ न केवल पूर्ण किया जा सके बल्कि राष्ट्रपति दूत नियुक्त करेंगे ताकि कार्यवाही का प्रबंधन सही प्रकार से हो सके।

यह पत्र हर तरीके का फायदा व् नुकसान भी बतलाता हैः

> *पहला तरीका राष्ट्रीय सरकार का अवतार के विषय में उच्च सम्मानीय विचारों को तो बतलाता ही है परन्तु एक क़ानूनी जनादेश वहन करता है। परन्तु इस दल की राजकोश को 20,000 से 30,000 युआन लागत आएगी। इसके साथ साथ इस दल को तिब्बत आने पर विरोध भी झेलना पढ़ सकता है। ऐसी स्थिति आने पर सम्बन्ध बिगड़ने का भी खतरा है। दूसरा तरीका इस से अधिक सावधानी भरा दृष्टिकोण है तथा साथ ही साथ कानून व्यवस्था को भी सुरक्षित बनाये रखता है। इसमें लागत भी कम आएगी। माध्यम से तिब्बती पक्ष की ओर से कोई शक भी उत्पन नहीं होगा क्योंकि केंद्रीय सरकार के उच्च नेतृत्व का निर्णय हमारे द्वारा स्थानीय ब्यूरो अधिकारी को नियुक्त करने से पूर्व ही लिया जा चुका होगा। यदि नियुक्त दूत सहयोग करेंगे तो व्यय में और बचत होगी।*[291]

चूंकि यह ध्यान रखते हुए की ये मुद्दा अत्यंत महत्व का था, प्रधानमंत्री कार्यालय ने सावधानी पूर्वक चलते हुए तिब्बत वासियों से परामर्श करने का निर्णय लिया। एमटीएसी ने एक स्थानीय चीनी सरकार के अधिकारी चांग वाईबी को 25 अक्टूबर को ल्हासा में दो टेलीग्राम भेजे। एक टेलीग्राम के अनुसार तीन तरीकों में से "प्रथम तरीका सबसे सही था परन्तु इस विषय में पूर्ण चर्चा होनी चाहिए थी। यदि तिब्बत वासी इस पर राज़ी नहीं होते हैं तो दूसरा या तीसरा तरीका उपयुक्त किया जा सकता था। तिब्बती सरकार से हुई चर्चा को टेलीग्राम के माध्यम से बताया जा सकता है।"[292]

इसी दौरान ल्हासा में अवतार के स्वागत में पहले से व्यस्त तिब्बती तरफ से 12 दिसम्बर 1938 को एमटीएसी नें सिक्योंग रीजेंट के नाम एक तार भेजा जिसमे कहा गयाः

> *केंद्रीय अधिकारियों द्वारा व्यक्ति नियुक्त करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री तथा कशाग ने एक साथ चर्चा की तथा निर्णय लिया की नियुक्त व्यकित स्वर्ण*

291 वही,146

292 वही, 150

कलश समारोह में हिस्सा ले सकता है जो तीन उम्मीदवारों के समक्ष होगा ताकि आम जनता का विशवास जीता जा सके तथा अफवाहों से बचा जा सके। परन्तु तिब्बत के केंद्रीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि चांग वाईबी का वहां पहले से होना काफी होगा अन्यथा वहां एक और प्रतिनिधि को तिब्बत भेजना होगा। कौन सा तरीका इसमें से ज्यादा उचित होगा इस विषय में चर्चा एक सही समय पे होगी तथा उत्तर दे दिया जायेगा। देवताओं व् लामाओं की दिव्यदृष्टि व् भविष्यवाणियों के अनुसार यदि तीनों बालक तिब्बत नहीं पहुँच पाते तो दलाई लामा के लिए यह व्यक्तिगत रूप से अशुभ संकेत प्रकट करेंगे। चूँकि ये मुद्दा अति महत्वपूर्ण है हम किसी ऐसी घटना के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते अतः हम आशा करते हैं की आरंभिक कदम के तौर पर आप त्सोंगों मैं सरकार को आदेश देंगे की वह त्सोंगोन से उमीदवार को केवत्संग रिन्पोछे वा उनके समूह के साथ तिब्बत के लिए कूच कर सके। धन्यवाद।[293]

छह दिन बाद, दिसम्बर 18 को राजदूत नवांग सम्तेन तथा अन्य जो बीजिंग की तिब्बती दूतावास में थे, उन्होने एमटीएसी को टेलीग्राम भेजा तथा कहाः" स्वर्ण कलश समारोह के विषय में तीन सुझाये गए तरीकों में से तीसरे के अनुसार, तिब्बती पक्ष चीनी–तिब्बत द्विपक्षीय मैत्री हेतु चांग वाईबी को एमटीएसी के राष्ट्रपति के दूत के रूप में कार्यवाही प्रबंधन हेतु स्वीकार करता है।"[294]

तिब्बत वासी तीसरे तरीके के लिए राज़ी हो गए क्योंकि यह सबसे कम दखल वाला था। तिब्बती सरकार ने चांग वाईबी, जो ल्हासा स्थित चीनी अधिकारी थे, उसे एमटीएसी के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया ताकि ल्हासा में वू जोंगज़िन के आने से बचा जा सके। परन्तु संभव अवतार को ल्हासा लाने के प्रयासों में देरी हुई तथा आगे किसी भी प्रकार की कठिनाईयों से बचने के लिए तिब्बती राजदूत नवांग सम्तेन तथा अन्य ने एमटीएसी को टेलीग्राम भेजकर कहा किः "ल्हासा से टेलीग्राम के अनुसार, तिब्बती सरकार अभी के लिए वू जोंगज़िन के ल्हासा आने का स्वागत करती है। परन्तु उन्हें समुद्र के रास्ते आना होगा तथा उनके निकलने से पूर्व केंद्रीय प्राधिकरण को त्सोंगोन में टेलीग्राम भेजना होगा ताकि केवत्संग रिन्पोछे व उनके सहयोगी संभावित उमीदवार को तिब्बत ला सकें। वू जोंगज़िन के तिब्बत से निकलने से पहले एक टेलीग्राम तिब्बत भी भेजा जाना चाहिए।[295]

293 वही, 158–159

294 वही, 160

295 वही, 188

जैसे ही तिब्बती सरकार ने वू जोंगज़िन की यात्रा को मंजूरी दी चीनी सरकार ने अंग्रेजी भारत सरकार से वीसा के लिए आवेदन किया। अंग्रेजी भारत सरकार ने यात्रा की तिथि, दल के सदस्यों के विषय में जानकारी की मांग की। यह भी साफ़ किया गया की तिब्बती सरकार से पहले से मंजूरी की भी आवश्यकता होगी। यह समझते हुए की अंग्रेजी भारत की स्थिति को स्वीकार करना चीन की तिब्बत पर संप्रभुता को कमज़ोर करेगा तथा कोई और समाधान न देखते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने लंदन दूतावास को गुप्त टेलीग्राम 22 मई 1939 को भेजा।

> *वू जोंगज़िन, एमटीएसी के अध्यक्ष का भारत से तिब्बत का दौरा केवल 14वें दलाई लामा के स्वर्ण कलश समारोह हेतु है तथा इसका कोई अन्य राजनीतिक महत्व नहीं है। हमारे सहयोगी की सुविधा हेतु तथा चूंकि दौरे में केवल राष्ट्रीय सरहद को केवल पार ही किया जायेगा हमें अंग्रेजी विदेश मंत्रालय द्वारा मांगी गयी जानकारी देना आवश्यक नहीं प्रतीत होता। भारत सरकार को केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के अनुरोध हेतु एक अन्य तार भेजे।*[296]

जब चीनी सरकार के प्रतिनिधि तिब्बत से मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, मॉ बुफेंग ने एमटीएसी टेलीग्राम भेज सुनिश्चित कियाः" संभावित उम्मीदवार आज चला गया।"[297]

वू जोंगज़िन तथा उनके दल के लिए यह अत्यंत ही आवश्यक था चूंकि उनकी अनुपस्थिति का अर्थ यह निकलता की चीनी का तिब्बत में कोई प्रभाव नहीं है। अतः उन्होनें गोंग जिन्गज़ोंग, एमटीएसी में तिब्बत विभाग के प्रमुख को ज़मीनी मार्ग से भेजा। तिब्बती राजदूत नवांग सम्तेन तथा अन्य अभी भी केवत्संग रिन्पोछे तथा दल के बारे में अनभिग्य थे तथा उन्होनें एमटीएसी को यह कहते हुए 27 जुलाई को तार भेजा किः

> *कशाग की ओर से तार के अनुसारः 1) पूर्वी तिब्बत के गवर्नर जनरल ने आदेश दिया है की गोंग जिन्गज़ोंग की यात्रा के लिए सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक कदम उठा जायें। 2)चूंकि अभी हमें सीलिंग से केवत्संग रिन्पोछे का टेलीग्राम नहीं मिला है जो संभावित उम्मीदवार के जाने की तिथि को निश्चित रूप से बतलाये, सत्य अभी भी स्पष्ट नहीं है। हम आशा करते हैं की केंद्रीय सरकार इस मामले पर ठीक से ध्यान देगी तथा एक कडे शब्दों में टेलीग्राम से पता लगाएगी की असल में वह कब निकलेंगे।*[298]

---

296 विदेश मंत्रालय के दस्तावेज़ों का संग्रह, तिब्बती सेक्शन, वॉल्यूम वी, ताइवान, चीनी भाषा, 205

297 प्रार्थना सभा तथा सिंहासनारूढ़ होने के विषय में दस्तावेज़ों का एक संग्रह, 213

298 वही – 217

केवत्संग रिन्पोछे के त्सोंगोन से अपनी यात्रा की तिथि सुनिश्चित करने के बाद, तिब्बत सरकार के कशाग ने 20 अगस्त को वू जोंगज़िन को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें चीनी दल के प्रतिनिधिमंडल के आकार पर सख्त प्रतिबंध लगाया। टेलीग्राम के अनुसारः

हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सितम्बर महीने के आरम्भ में आप तथा पांच सहायक को मिलाकर चौदह अधिकारी भारत के माध्यम से नवम्बर में तिब्बत आयेंगे। दल के आकार के विषय में, हम निवेदन करते हैं की आवश्यक सदस्यों के अतिरिक्त अधिक लोगों को लाने से बचा जाये। इस आदेश की अवमानना भिक्षुओं तथा अन्य लोगों में संदेहास्पद स्थिति को जन्म देगा। मैं आशा करता हूँ की आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे।[299]

यद्यपि वू जोंगज़िन व् उनके सहयोगियों के वीसा हेतु प्रक्रिया अप्रैल 1939 में आरंभ कर दी गयी थी पर तिब्बत सरकार ने अपनी मंजूरी का पत्र अंग्रेजी भारत सरकार को सितम्बर में भेजा।

1 सितम्बर को सिक्योंग रेटिंग ने वू को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें लिखा थाः" आश्वस्त रहें की मैने तथा कशाग ने अंग्रेजी भारतीय सरकार को टेलीग्राम भेज कर निवेदन किया है की आप के 19 सदस्य दल को सभी प्रकार की सहयता प्रदान की जाये जब आप भारत से तिब्बत आयें।"[300] टेलीग्राम 31 अगस्त को भेजा गया। वीसा को अंततः 5 अक्टूबर को मंजूरी मिली तथा दल तिब्बत जाने के लिए चोंगक्यींग को 21 अक्टूबर को छोड़, हांगकांग, बर्मा व् भारत से तिब्बत जाने के लिए निकला। पहले चरण के लिए दल ने हवाई यात्रा की परन्तु बाद में ल्हासा के लिए भारत से सड़क मार्ग से निकला तथा 15 जनवरी 1940 को ल्हासा पहुंचा। उनका स्वागत रेटिंग रिन्पोछे ने व्यक्तिगत रूप से नहीं अपितु उनके प्रतिनिधियों ने किया। वू जोंगज़िन ने अपनी डायरी में इस विषय में लिखाः "18 जनवरी को मौसम साफ़ था तथा 11 बजे प्रातः हमने रेटिंग हुतुक्तु से मिलने की इच्छा व्यक्त की, हमनें परस्पर एक दूसरे को खता दिया। मेरे अन्य सहकर्मियों ने भी इसी प्रकार उन्हें सम्मान दिया।"[301]

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि चीन और तिब्बत के बीच सम्बन्ध केंद्रीय तथा क्षेत्रीय सरकारों मे से एक होते तो स्थानीय अधिकारी (सिक्योंग

299 वही, 233–234

300 वही, 238

301 तिब्बत असाइनमेंट के निष्कर्ष पर एक रिपोर्ट, चीनी भाषा, 245

रेटिंग रिन्पोछे) को केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधियों का वू जोंगज़िन के आवास पर स्वागत करना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ बल्कि वू तथा उनके दल को रेटिंग रिन्पोछे के पास मिलने के लिए आना पड़ा।

14वें दलाई लामा का चयन

28 जून 1939, पृथ्वी–खरगोश वर्ष को तिब्बती राष्ट्र असेंबली ने दलाई लामा के निजी कक्ष, पोटाला देदेंख्यी में मिली तथा ल्हामो थोंडुप को पूर्व दलाई लामा का अवतार घोषित किया। शकाब्पा वांगचुक देदेन अपनी पुस्तक द पालिटिकल हिस्ट्री आफ तिब्बत में लिखते हैंः ल्हामो थोंडुप नाम का बालक वुड–पिग वर्ष के पांचवें महीने के पांचवें दिन, छोक्योंग त्सेरिंग तथा माता सोनम त्सो (देक्यी त्सेरिंग) के छिजा नाम के परिवार में एक खेती–बाड़ी वाले गाँव तकत्सेर में डोमी, आमदो इलाके में कुम्बुम मठ के निकट पैदा हुआ था। रिन्पोछे तथा उनके सहयोगियों ने कुम्बुम मठ की महान गद्दी को छोड़ दिया है तथा वह अब तिब्बत की धरती पर पहुँच गए हैं।"[302]

यह 13वें दलाई लामा के अवतार की पहली आधिकारिक पुष्टि थी जो सार्वजानिक की गयी थी।

हालाँकि, पीआरसी द्वारा प्रकाशित एक श्वेत पत्र के अनुसारः "चीनी गणराज्य (1912–1949) की केंद्रीय सरकार ने 5 फरवरी,1940 को अध्यादेश नः 898 द्वारा पांच वर्षीय बालक ल्हामो थोंडुप जो किजचुन, हुयनजोंग प्रान्त, किंग्हाई में पैदा हुआ था को 13वें दलाई लामा के अवतार के रूप में स्वीकृत किया...." यह कथन तथ्यों के आधार पर सही नहीं है। वास्तविकता में तिब्बती सरकार ने तकत्सेर से उम्मीदवार का चयन गुप्त रूप से उसके ल्हासा आने से पहले ही कर लिया था। जैसे की, एमटीएसी को भेजे गए एक गुप्त तार में 31 मार्च 1938 को जनरल जेंग डिंगवन ने लिखाः

> *तिब्बती सरकार ने पिछले वर्ष केवत्संग रिन्पोछे को दलाई लामा के अवतार को त्सोंगोन इलाके में ढूँढने का कार्य सौंपा था। खोजी दल ने अवतार को कुम्बुम के निकट पाया तथा छह महीने से अधिक के बाद भविष्यवाणियों तथा दिवंगत पंचेन लामा द्वारा जांच के बाद दलाई लामा के अवतार को पहचाना गया।*[303]

---

302 वांगचुक देदेन शकाब्पा, अ पालिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ तिब्बत, वोल. 2, तिब्बती भाषा, 360–361

303 प्रार्थना सभा तथा सिंहासनारूढ़ होने के विषय में दस्तावेज़ों का संग्रह, चीनी भाषा, पृष्ठ 134

या हंज्हंग द्वारा लिखी गयी द दलाई लामास बायोग्राफी, की प्रस्तावना में लेखक कहते हैं कि: "संघर्ष के हित में दल चाहता था की में तिब्बत के इतिहास पर पुस्तक लिखूं"। यह पुस्तक चीनी सरकार के रुख के अनुसार लिखी गयी है तथा दावा करती है की:" दिसम्बर 1939 को वू जोंगज़िन को कशाग तथा आम जनता ने ल्हासा पहुँचने पर भव्य स्वागत पाया। ल्हासा पहुँचने के बाद यह बदलाव आया की संभावित तीन उम्मीदवारों में से केवल एक ही बचा।[304]

सचिव ज्हू–शाओ यी, जो वू जोंगज़िन के दल के सदस्य थे उन्होनें अपने संस्मरण, एन आईविटेनस अकाउंट इन ल्हासा में लिखा:

> *दोनों पक्षों के नेताओं के बीच काफी विचार विमर्ष होने के बाद, स्वर्ण कलश को उपयोग न करने के लिए यह पूर्व शर्तें रखी गयी। (पहली) वू जोंगज़िन व्यक्तिगत रूप से बालक की जांच करेंगें की क्या वह वास्तविक रूप में दिव्यदृष्टि रखता भी है या नहीं। (दूसरा) रेटिंग होतुक्तु केंद्रीय प्राधिकरण को एक याचिका लिखेंगे जिसमें स्वर्ण कलश के उपयोग की परम्परागत प्रथा से मुक्ति मिलेगी। रेटिंग होतुक्तु इन दोनों शर्तों के लिए मान गए।[305]*

वू जोंगज़िन का ल्हासा में रहना भी अप्रिय था। यह वू की डायरी प्रविष्टियों तथा उस समय की तेलेग्रामों से स्पष्ट हो जाता है। वू तिब्बतियों पर विशवास नहीं करते थे तथा तिब्बती भी अवतार की कार्यवाही में स्वर्ण कलश के उपयोग के खिलाफ थे। वू का बचाव करते हुए तथा और अधिक देरी से बचने के लिए तिब्बती सरकार ने चीनी सरकार को पत्र लिख कर कहा की वह कलश का उपयोग नहीं करेंगे। अतः 26 जनवरी 1940 को सिक्योंग रेटिंग ने युवा अवतार के विषय में विस्तारपूर्वक पत्र लिखा। पत्र अंत में कहता है :

> *जैसे की लोग संतुष्ट हैं तथा उन्होनें अपनी मंजूरी दे दी है, स्वर्ण कलश के उपयोग की अब कोई आवश्यकता नहीं है। टुल्कु के मुकुट पर बाल कटने के सदियों पुराणी प्रथा पूर्ण की जा चुकी है तथा केंद्रीय प्राधिकरण को इस विषय में अवगत कराया जा चुका है। महँ नेचुंग ओरेकल की भविष्यवाणी के अनुसार यह निर्णय ले लिया गया है की आयरन ड्रैगन वर्ष के पहले महीने के चौदहवें दिन सिंहसनारूढ़ करने का समारोह होगा। कृपया देखें की यह सूचना चीनी केंद्रीय प्राधिकरण तक कैसे पहुंचे।[306]*

---

304 या हंज्हंग, द दलाई लामास बायोग्राफी, तिब्बती भाषा, 876

305 वही

306 प्रार्थना सेवा तथा सिंहासनारूढ़ होने के विषय में दस्तावेज़ों का संग्रह, 282–286

यह स्पष्ट है की यह पत्र का उद्देश्य चीनी सरकार को यह बताना था की तिब्बतियों नें सिंहासनारूढ़ होने के विषय में स्वयं निर्णय लिया है। यह भी आवश्यक है की वास्तविक पत्र वू को तिब्बती भाषा में लिखा गया थाः इसका चीनी भाषा में अनुवाद वू के कनिष्ठ कर्मचारियों ने किया था। एक 13वें दलाई लामा की प्रार्थना सभा तथा 14वें के सिंहासनारूढ़ होने के विषय में दस्तावेज़ों का संग्रह नमक प्रकाशन में, लेखक के कुछ वाक्यों में फुटनोट्स तिब्बती भाषा के वास्तविक पत्र से मेल नहीं खाते। जैसे की, "स्वर्ण कलश को उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है का अनुवाद किया गया "डोऊ बॉल विधि का उपयोग कर अटकल का संचालन करने की आवश्यकता नहीं"। वू रेटिंग के पत्र से प्रसन्न नहीं थे तथा जनवरी 26 को उन्होनें अपनी डायरी में लिखाः

> *काफी देरी के बाद अधिकारिक पत्र आज ही प्राप्त हुआ। आश्चर्य की बात है की पत्र न केवल उल्टा पुल्टा है परन्तु एक अधिकारिक पत्र होने के नाते काफी असावधानी पूर्ण भी हैं। में पत्र को देख कर बहुत चकित था तथा पत्र वाहक को मैने काफी गुस्से में उत्तर दिया। यह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए अत्यंत ही असम्मान तथा निष्ठाहीनता थी। में अपना सामान बंद कर के जाने के लिए तैयार था। यह पत्र में किसी भी हाल में चीन नहीं भेज सकता था अतः मैने अपने अधिकारी चांग वईबी को पत्र के साथ भेजा ताकि पत्र को ढंग से पढ़ा जा सके तथा उसका अंत सही दिखे और उसमें रेटिंग रिन्पोछे की मुहर लगे।*[307]

फिर भी, 28 जनवरी को वू ने केंद्रीय सरकार को एक गुप्त टेलीग्राम भेजा जिसके अनुसारः

> *में, वू जोंगज़िन, ने संभावित उम्मीदवार के द्वारा दिखाए गए विशेष संकेतों को जांचा है तथा उन सब को सही पाया है। अतः मैं केंद्रीय सरकार से आग्रह करता हूँ की वह एक आधिकारिक फरमान भेजें। ल्हामो थोंडुप को 14वें दलाई लामा के रूप में नियुक्त करने की आज्ञा उनके सिंहासनारूढ़ होने के समारोह को आयोजित करने का पर्याप्त समय देगा। चूंकि महत्वपूर्ण मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, यह मुद्दा उठाया जा रहा है।*[308]

अपने इस विशेष कार्य की सफलता दिखाने हेतु, वू ने स्वर्ण कलश का उपयोग न करने के निर्णय का विषय में कुछ नहीं बताया। वू यह भी दावा करते हैं की उन्होनें "संभावित उम्मीदवार की दुबारा जाँच की" परन्तु उस

307 तिब्बत कार्य के निष्कर्ष पर एक रिपोर्ट, चीनी भाषा, 247

308 प्रार्थना सभा तथा सिंहासनारूढ़ होने के विषय में दस्तावेज़ों का संग्रह, 287

समय वह अवतार से मिले ही नहीं थे।

या हानज़ाँग लिखते हैं :

बालक की जांच करने के मुद्दे के आगे कई रुकावटें आई क्योंकि वू जोंगज़िन को नोर्बुलिंग्का आने की आज्ञा नहीं मिली। जब इसका सबसे प्रमुख अधिकारी के समक्ष उठाया गया तो उनका कथन था की न केवल वू को दलाई लामा के केलसंग महल में सिंहासनारूढ़ होने के समारोह में श्रोता के रूप में आने की इच्छा व्यक्त करनी होगी परन्तु उन्होंने यह भी बताया की यह समारोह केलसंग महल में आयोजित करने का निर्णय तिबेटी नेशनल असेम्बली का था तथा यह एक परंपरागत तिब्बती प्रथा है की वहां सब श्रोता होने की इच्छा व्यक्त करें। उन्होनें बताया की कोई भी बदलाव संभव नहीं है चूँकि नेशनल असेंबली ने यह निर्णय लिया था। इसका अर्थ यह था की वू जोंगज़िन के पास बालक को जांचने का कोई अधिकार नहीं था। जब हमनें श्री वू को प्रमुख अधिकारी से अपनी मुलाकात के विषय में बतलाया वह काफी निराश है तथा उन्होनें कुणचोक जुगने को बुलाया। एक दमदार आवाज़ में उन्होनें इस महत्वपूर्ण मुद्दे के विषय में बतलाया तथा जल्द ही रेटिंग हुतुक्तु के पास जाकर यह समझाने को कहा की पूर्व निर्णय मन जाना चाहिए। उन्होनें कहा यदि वह ऐसा नहीं कर पाते तो केंद्रीय प्राधिकरण के सभी अधिकारी बिना किसी खेद के तिब्बत छोड़ कर चले जाएंगे। इसके उपरांत रेटिंग हुतुक्तु का स्वाभाव काफी नर्म हो गया तथा अगले ही दिन उन्होनें एक नेता को भेजकर क्षमा व्यक्त की कि प्रमुख अधिकारी को कुछ गलत समझ आया था तथा उससे वास्तविक स्तिथि का ज्ञान नहीं था। श्री वू को दर्शकों के लिए तिथि व् स्थल निर्दिष्ट करने के लिए कहने के बाद उन्होनें फरवरी 1 को नोर्बुलिंग्का में जांच करने का निर्णय लिया।

या हानज़ाँग आगे लिखतें हैं, "फिर भी जाँच केवल गुओमिनतन्ग सरकार के प्रति निष्ठां का केवल दिखावा ही थी तथा वास्तव में उनके पास अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं था।"[309]

ज्हू–शाओ यी की पुस्तक एन आई विटनेस एकाउंट इन ल्हासा के अनुसार वू की प्रथम जांच की तिथि 1 फरवरी थी जबकि वू अपनी डायरी में इससे 31 जनवरी लिखतें हैं। वू लिखतें हैं की उनका दर्शन 10 मिनट से अधिक नहीं चला। यह सोचनीय मुद्दा है की केवल इतने समय में कितनी जांच हो पाई होगी।

उपरोक्त जानकारी चाइना तिबेतोलोजी रिसर्च सेंटर के चीनी भाषा के संग्रहों

309 या हंज्हंग, द दलाई लामास बायोग्राफी, तिब्बती भाषा, 877–878

से मिलती है। दिवंगत न्गाबो नवांग जिग्मे जिन्होनें पुराने दस्तावेज़ों को पढ़ा था उन्हें सरकार द्वारा समर्थित केन्द्रों के इन दस्तावेज़ों के प्रति ग़लतफ़हमी थी। अपने एक भाषण में उन्होनें कहाः

गुओमिन्तंग सरकार ने इस कृपी किये पत्र को एक अमूल्य गहने की तरह संग्रह में संभाल कर रखा था। ऐसा निकल कर आया है की गुओमिन्तंग सरकार ने इस कृपी किये गए पत्र को तिब्बती सरकार के वास्ताविक पत्र की तरह ही माना तथा इससे 13वें दलाई लामा के अवतार को ढूँढने हेतु प्रगति से अवगत कराया। परन्तु सत्य यह था की कृपी किया गया पत्र न ही वास्तविक रिपोर्ट थी न ही उससे सांस्कृतिक तिब्बती हस्तनिर्मित कागज़ पर लिखा गया था। यही नहीं दस्तावेज़ पर मुहर भी नहीं थी जिससे यह केवल एक सामान्य कृपी किये गए पत्र के सामान ही बनता था। इस दावे के विषय में की इस मुद्दे पर दो और भी वास्तविक रिपोर्ट हैं, मैने पहले से ही दो पत्रों को संदर्भित किया है.... यह दो दस्तावेज़ बतलाते हैं की 13वें दलाई लामा के अवतार की पहचान हेतु उमीदवार त्सोंगोन इलाके में ढूँढ लिया गया है तथा जहाँ खोजी दल, अवतरित उमीदवार के साथ तिब्बत वापिस आने की तैयारी कर रहा है, मा बुफेंग कई प्रकार के विघन अड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको देखते हुए दल ने तिब्बती व् चीनी संबंधों के महत्व को प्राथमिकता देते हुए गुओमिन्तन्ग सरकार से सहायता की इच्छा व्यक्त की।

समारोह के सभी अवतरण से जुडे आवश्यक संस्कारों पर निर्णय तथा प्रदर्शन तिब्बतियों ने पूर्ण किया। चीनियों का उसमें कुछ हिस्सा नहीं था। अतः गोंग जिज़ोंग ने एक टेलीग्राम में 26 नवम्बर 1939 को एमटीएसी को लिखाः "हम ल्हासा 25 को पहुंचे..... 24 को एक भिक्षु के रूप में त्सोंगोन की पुनर्जनम समन्वय समारोह तिब्बतियों द्वारा पूर्ण किया गया। रेटिंग ने टुल्कु के मुकुट पर बाल काटने की प्रथा पूर्ण की। चूंकि हम एक दिन देर हो चुके थे हम इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए।[310]

वू जोंगज़िन तथा दलाई लामा की सिंहासनारूढ़ होने का समारोह

राष्ट्रवादियों पर अपनी विजय के चलते, चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत पर आक्रमण किया। आरम्भ में, कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिन्तंग शासन को एक झूठे प्रतिक्रियावादियों का समूह बताया। परन्तु आज वह कुओमिन्तंग को तिब्बती अवतरण प्रणाली को बनाये रखने का श्रेय देते हैं।

कुओमिन्तंग द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का एक स्पष्ट

310 प्रार्थना सभा तथा सिंहासनारूढ़ होने के विषय में दस्तावेज़ों का संग्रह, 275–276

उदहारण एमटीएसी द्वारा सिंहसनारूढ़ समारोह से चार दिन पूर्व एक प्रेस वार्ता का है जहाँ नौं चीनी अख़बारों को एक प्रेस विज्ञप्ति दी गयी की 22 फरवरी को यह भव्य उत्सव होगा। समाचार पत्रों को यह निर्देश दिया है कि समारोह में सम्मिलित तथा व्यापक प्रचार प्रदान करें। यह लिखित आदेश तीन अनुबंधों के साथ आये।

पहला अनुबंध, "14वें दलाई लामा के सिंहासनारूढ़ होने के उत्सव को स्मरण करने का मूल कारण", ध्यान दिया जाये," राष्ट्रवादी सरकार नें स्पष्ट रूप से मंगोलिया तथा तिबेतन अफेयर्स कमीशन के अध्यक्ष, वू जोंगज़िन को रेटिंग हुतुक्तु के साथ समारोह में सभापति के रूप में बुलाया था।

दूसरा अनुबंध, "दलाईलामा के अवतार को पहचानने की प्रक्रिया" अन्य कार्यों के अलावा बतलाता है, "विशिष्ट रूप से नियुक्त मंगोलिया तथा तिबेतन अफेयर्स कमीशन के अध्यक्ष, वू जोंगज़िन, रेटिंग हुतुक्तु के साथ दलाई लामा के अवतार से जुडे मुद्दों पर कर्त्तव्य निवारण के लिए आवश्यक हैं।

तीसरा अनुबंध, "दलाई लामा का पुनर्जन्म तथा राष्ट्र का भविष्य एवं दृष्टि" बतलाता हैः "इस महान सदी के आज ही के दिन एक नए देश का निर्माण हुआ था जब हम जापान से प्रतिरोध के युद्ध से विजयी होकर आये थे, 14वें दलाई लामा को केंद्रीय सरकार की देख–रेख में ही सिंहासनारूढ़ किया गया था"।[311]

इस समारोह की प्रेस रिपोर्ट पूर्ण रूप से अधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों पर आधारित है तथा इन्हें आज एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ के रूप में दिखाया जाता है।

वू जोंगज़िन सिंहासनारूढ़ होने के समारोह में नहीं आये जैसा की चीनी सरकार द्वारा दावा किया जाता है। परन्तु इस दावे का ऐतिहासिक दस्तावेज़ों द्वारा खंडन किया जाता है जिसमें वू की स्वयं के डायरी की प्रविष्टियाँ तथा वहां मौजूद तिब्बती तथा चीनी अफसरों के लेख भी सम्मिलित हैं। वू व् उसके साथी वहां केवल साधारण मेहमान थे। शकाब्पा वांगचुक देदेन जो वहां उपस्थित थे लिखते हैंः

> *आयरन–ड्रैगन वर्ष, 1940 के पहले महीने के 13वें दिन, एक जुलूस के चलते दलाई लामा को परंपरा के अनुसार नोर्बुलिंग्का से पोटाला महल आना पड़ा।*

311 वही, 156–157

चौदहवें दिन (फरवरी 22,1940), वह दिन जिस दिन दलाई लामा को सत्ता में स्थापित किया गया था, उसी दिन सर्वोच्च प्रभु अवतार रिन्पोछे को ऊँचे स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाया गया, जिसे सिज़ी फुंत्सोक स्वागत हॉल में निडर प्रभु महादेव के आठ भगवानों द्वारा बनाया गया था। साथ ही नमग्यल मठ के भिक्षुओं द्वारा शुभ कार्य हेतु प्रर्थना वर्णन किया। सिंहासन पर बैठाने की प्रथा के अनुसार भिक्षु आभूषण पहन के दलाई लामा को आठ शुभ संकेतों, आठ शुभ पदार्थों तथा शाही प्रतीक के सात प्रकारों का चढ़ावा भेंट करते हैं। धार्मिक सेवाएं एवं गंभीर प्राथनाएं की गयी। संरक्षक राज प्रतिनिधि रट्रेंग ने मंडाला का मौखिक स्पष्टीकरण दिया। निवेश के लेख दलाई लामा को भेंट करने के बाद, रीजेंट, प्रधानमंत्री, शिक्षक, होठुक्तु, मंत्रिमंडल, आम सहयोगी, भिक्षु तथा गंदेन, सेरा और ड्रेपुंग मठ से अवतार तथा सरकारी अधिकारों ने दलाई लामा का आशीर्वाद पाया। चीनी सरकार के उपहार वू जोंगज़िन, जाओ गुन्दीन, गोंग जिनज़ोंग, चांग वईबी और इन्हीं सब द्वारा दिये गए। अधिकारिक उत्सव हेतु पाठ पुन्नावत्री, विवादकर्ता, चढ़ावा वितरकों, नृतकों, संगीतज्ञों, आम जनता और अन्य लोग, पिछले उत्सव की तरह इकट्ठे हुए।[312]

वू की 22 फरवरी की डायरी की प्रविष्टियों तथा सचिव ज्हू–शाओ (एक उपहार वाहक) अपनी पुस्तक "एन आई विटनेस एकाउंट इन ल्हासा" में समारोह की कार्यवाही की पूर्ण जानकारी देते हैं। वह ऐसा कोई संकेत नहीं देते की वू ने समारोह की अध्यक्षता की। उन्हें केवल एक खता ही प्रदान करने का अवसर मिला और कुछ नहीं। प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें तिब्बती सरकार के उच्च अधिकारियों तथा उच्च पदस्थ भिक्षुओं का ही पालन करना था। वू समारोह से पहले पहुंचे तथा अन्य अतिथियों की तरह अपनी आवंटित सीट पर बैठ गए तथा आधे घंटे तक प्रतीक्षा की। यह तिब्बतियों ने ही युवा टुल्कु को सिंहासनारूढ़ किया।

समारोह का अन्य महत्वपूर्ण तथा विवादस्पद पक्ष बैठने की व्यवस्था से जुदा था। वू अपनी डायरी में लिखते हैंः "मैं पश्चिम की और दलाई लामा के बाएँ में बैठा था। अधिकांश चीनी दस्तावेज़ यह दावा कारते है की वू की सीट दलाई लामा के साथ ही थी। जवाब में शकाब्पा वांगचुक देदेन "द पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ तिब्बत" में लिखते हैं :

और आगे वू के यह कथन की सिंहासनारूढ़ होने का समारोह उन्होंने आयोजित किया, उन्होंने दलाई लामा को सिहासन पर बैठाया तथा दलाई लामा ने कृतज्ञता के चलते बीजिंग की और सिर झुकाया भी झूठे हैं तथा

312 त्सेपोन वांगचुक देदेन शकाब्पा, वन हंड्रेड थाउजेंड मून्सः अन एडवांस्ड पालिटिकल हिस्ट्री आफ तिब्बत (न्यूयॉर्कः हार्पर कॉलिंस,1988) 885–886

निराधार हैं। यद्यपि में उस समय एक उच्च अधिकारी नहीं था तथा केवल त्सीपा के पद पर था (राजकोश अधिकारी), मैं उन अधिकारियों में से था जिन्हें अलंकरणों किया गया था और जिसने धूप उठाया। अतः जब दलाई लामा अपने कक्षा से बाहर निकले तो मैने उनका स्वागत धुप उठाते हुए किया। पूरे समारोह के दौरान मुझे सिहासन के आगे ही बैठे रहना था। दलाई लामा जब अपने कक्षा से आये तो केंद्रीय मंत्री लामा तेंपा जम्यंग तथा मुख्य परिचारक नवांग तेनजिन ने उनके हात पकडे। जब वह सीढ़ी चढ़ कर सिहासन पर विराजमान हुए तो मठाधीश खेनरब तेनजिन ने उन्हें अपनी बाँहों में उठा लिया। चूंकि वू जोंगज़िन भी आमंत्रित थे उन्हें सिहासन कक्ष में जाने की अनुमति थी। उसके अतिरिक्त न तो उन्होनें दलाई लामा को छुआ अपितु उन्हे सिहासन के पास जाने की अनुमति भी नहीं थी। यदि किसी ने सिहासन के करीब आने का प्रयास किया होता तो अन्य लोग भी अवश्य ही देखते।[313]

"एन आई विटनेस एकाउंट इन ल्हासा" में सचिव ज्हू–शाओ के लेख की ख़ास जांच की जानी चाहिए वे लिखते हैं:

फरवरी 22, तिब्बती कैलेंडर के प्रथम महीने का चौदवा दिन, पूर्व–निश्चित टुल्कु उम्मीदवार को सिहासनारूढ़ करने का दिन था। पहले से चर्चित, सिहासनारूढ़ समारोह से जुडे शिष्टाचार एवं प्रोटोकॉल के अनुसार अध्यक्ष वू तथा रेटिंग के प्रतिनिधियों के दोनों ही पक्षों ने पुरातन तिब्बती परम्पराओं से इस समारोह का संचालन करना माना। परन्तु वू के बैठने की व्यवस्था को लेकर कुछ विवाद था। आरम्भ में तिब्बती पक्ष ने वू को रेटिंग के सामने बिठाने की इच्छा जताई थी तथा उनके आसन को प्रधानमंत्री के बराबर ही बड़ा रखा था परन्तु वू बैठने की व्यवस्था को वैसे ही चाहते थे जैसे की मांचू अम्बांस के समय में रखा जाता था जो तिब्बत में रहते थे। वे चाहते थे की उनका आसन दलाई लामा के बराबर ही बाएँ तरफ दक्षिण को मुख कर रखा जाये। क्योंकि इस कार्यक्रम की अधिकारिक प्रधानता थी, उनके प्रतिनिधियों ने कहा की वू चूंकि राष्ट्रीय सरकार के प्रतिनिधि हैं जो दलाई लामा के सिहासनारूढ़ होने के समारोह की ज़िम्मेदारी उठाये हुए है तथा वह ही मुख्य प्रभारी भी हैं और तिब्बत एवं मंगोलिया मामलों के प्रमुख भी वह इस बात पर राज़ी नहीं है, कई बार चर्चाओं के उपरांत ही तिब्बती पक्ष राज़ी हुआ।[314]

परन्तु यद्यपि "माना गया" जैसे शब्द का चर्चा के हिस्से के रूप में उपयोग किया गया है परन्तु यह दिखाने हेतु कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा बैठने की व्यवस्था का मानचित्र दिखता है की टुल्कु का सिंहासन तथा वू का आसन एक दूसरे के बराबर नहीं रखे गए हैं। सचिव ज्हु शाओ यी द्वारा बनाये गए इस मानचित्र में टुल्कु के सिंहासन को सभा में

313 वही, 888–889

314 जू–शाहू यी; ऐन आई विटनेस एकाउंट इन ल्हासा, चीनी भाषा, 77

सबसे ऊपर दिखाया गया है जिसके साथ उनके निजी शिक्षक उनके दायें में तथा उनके माता–पिता उनके बाएँ में दक्षिण की ओर बैठे थे। सिंहासन के नीचे दायें की और रेटिंग रिन्पोछे की अगुवाई में सभी उच्च लामा जिनके पूर्वज रीजेंट थे, आसनातीत थे। मठों के टुल्कु एवं मठाधीश तथा सभी भिक्षु अधिकारी जो चौथे श्रेणी के थे रेटिंग रिन्पोछे के पीछे बैठे थे। सभा के बायें हाथ में वू और उनके सहयोगियों के लिए 16 सीटें थीं, ग्यारह सीटें नेपाली दल के लिए थी तथा 7 भूटान के दल के लिए थी। दलाई लामा के भिक्षु सहयोगी सभागार के मध्य में बैठे थे। कलोन दक्षिण दिशा की ओर बैठे थे। उनके पीछे अन्य अधिकारी थे जो चतुर्थ श्रेणी के नीचे थे तथा इसके बाद विदेशी थे। मानचित्र सभी पूर्व रीजेन्ट् के नाम भी बताता है।

आगे 1989 में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पिपल्स कोंग्रेस में, दिवंगत नाबो नवांग जिग्मे विस्तारपूर्वक बताते हैं :

> *वास्तविकता में इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई जहाँ यह कहा जा सके की वू जोंगज़िन ने 14वें दलाई लामा के सिंहासनारूढ़ होने के समारोह की अध्यक्षता की। फिर भी तिब्बती राष्ट्रीयता के सहयोगी जब उस युग के विषय में लिखते हैं तो यह दावा करते हैं की वू जोंगज़िन ने सिंहासनारूढ़ होने के समारोह की अध्यक्षता की थी। किसी के लिए यह लिखना तब तक असंभव सा है जब तक वह तिब्बती प्रथाओं के बारे में कुछ न जानता हो। यहाँ बैठे कई लोगों में से कई वह हैं जो पुराने तिब्बत में रईस थे। जैसा की आप सभी को ज्ञात है, दलाई लामा के सिंहासनारूढ़ होने के समारोह की अध्यक्षता कोई नहीं करता। यह चीनी लोगों की परस्पर मुलाकात की तरह नहीं है जहाँ कोई अध्यक्षता करने के लिए चाहिए... पिछले वर्ष इंस्टिट्यूट ऑफ तिबेतोलॉजी की मुलाकात में मैने इस विषय पर बात की तथा बताया की मैने किस प्रकार इससे जुडे प्रासंगिक अभिलेख देखे हैं। हम कम्युनिस्टों के पास गुओमिंदांग की ही तरह इस मुद्दे पर लगातार झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है।*

वू का बैठने की व्यवस्था को लेकर झूठा लेख जो की साफ़ तौर पर चीनी सरकार के मान को बचाने के लिए लिखा गया था, यह बताता है की वह अपनी अधिकारिक कर्तव्यों को निभाने में सफल रहे थे। परन्तु चीनी सरकार इस बात का कितना भी दावा करे की वू ने 14वें दलाई लामा की सिंहासनारूढ़ समारोह की अध्यक्षता की थी इस दावे को समर्थित करता कोई भी इतिहासिक प्रमाण नहीं है। बल्कि वू के साथ अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की तरह ही व्यवहार किया गया तथा उन्हे कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया।

सुनहरा कलश तथा टुल्कु के अवतार को चयन करने का विधि

पीआरसी ने दलाई लामा को चुनने के लिए सुनहरे कलश के उपयोग को विशेष महत्व दिया है। यह तिब्बती लामाओं के पुनर्जनम को चुनने की शक्ति का दावा करने के उनके प्रयास का हिस्सा है। जैसा की ऊपर नोट किया गया है वह 14वें दलाई लामा के चयन में सुनहरे कलश के उपयोग से "छूट" की ओर इशारा करते हैं जो इस बात का प्रमाण है की यह इस नियम का अपवाद है। परन्तु इस दावे में कोई सत्य नहीं है की सुनहरा कलश तिब्बती बुद्ध प्रथा का अंदरूनी हिस्सा है, वास्तव में सुनहरे कलश का उपयोग एक विदेशी विचार है जिसे तिब्बत में मंचु द्वारा उन्नातीस संपादक लेख अथवा 1793 के तिब्बत से जुडे नियमों के अंतर्गत तिब्बत में लाया गया (जैसा की इस रिपोर्ट के इतिहास से जुडे अध्याय में बताया गया है)। वंशानुगत वंशावली के अतिरिक्त–जैसे साक्य गोंगमा, मिंलिन्ग त्रिछेंस तथा तकलुंग शंद्रुंग अवतार को पहचानने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार हैः

1) यदि पिछले अवतार ने भविष्यवाणियों अथवा कुछ निर्देशों को छोड़ा है तो उन्हे अवतार चुनने के लिए आधार बनाया जाता है तथा कोई और तरीकों की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार करमापा की पहचान की जाती है।

2) यदि कोई भविष्वाणी नहीं है, दिशा–निर्देश तथा खोजी दल के आगे बढने के लिए देवी देवता तथा ल्हामो ल्हुत्सो झील की सहायता ली जाती है। यदि उम्मीदवार सही प्रकार से अपने पूर्व जन्म के अवतार से जुडी चीज़ों को पहचान पाते हैं तथा अपने पूर्व जन्म से जुडी घटनाओं को विश्वसनीय रूप से बता पाते हैं तो उन्हें पहचान लिया जाता है। कोई अतिरिक्त परीक्षण की अवश्यकता नही है। परमपावन 14वें दलाई लामा का चयन इसका उदाहरण है।

3) यदि उम्मीदवार पूर्व अवतार के केवल कुछ गुण ही दिखा पता है तो अथवा यदि एक से अधिक उम्मीदवार हैं तो दिव्य शीषे, भविष्वाणी से परामर्श का उपयोग किया जाता है। जब सभी देवी देवताओं द्वारा की गयी भविष्यवाणियाँ संतोषजनक रूप से मेल खाती हैं तो अवतार को मान्यता दे दी जाती है। इसी माध्यम को 13वें दलाई लामा को चयन के लिए उपयोग किया गया था।

4) यदि अवतार की पुष्टि करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है

तो भविष्यवाणी (ज़नरिल ड्रिल) हेतु डोख–बॉल प्रक्रिया का उपयोग करना पड़ता। यह मांचू साम्राज्य द्वारा सुनहरे कलश में से पर्चियां निकालने से भिन्न है जो तिब्बतीयों के लिए एक अनजानी प्रक्रिया थी। डोख–बॉल और चित्रण प्रक्रिया में काफी समानताएं हैं तथा तिब्बतियों ने कई अवसरों पर दोनों का ही उपयोग किया है जब अन्य माध्यमों के परिणामों से कोई नतीजा नहीं निकल सका।

11वें और 12वें दलाई लामा तथा 8वें और 9वें पंचेन लामा का चयन सुनहरे कलश के माध्यम से हुआ था परन्तु यह माध्यम अन्य किसी भी दलाई लामा के चयन में उपयोग नहीं किया गया। 1791–93 के गोरखा आक्रमण में सेना की सहायता का आभार जताने के लिए मंचुओं को यह बताया गया की 10वें दलाई लामा के चयन में सुनहरे कलश का उपयोग किया गया था परन्तु चयन कर्ताओं ने ऐसा नहीं किया था क्योंकि उनका इस प्रक्रिया में विश्वास नहीं था तथा उन्होनें ऐसा केवल उपकार पाने के लिए किया।

फिर भी, 18 जुलाई 2007 को राज्य धार्मिक मामलों के प्राधिकरण के तत्वाधान में पीआरसी ने "तिब्बती बौद्ध धर्म में जीवित बुद्ध के पुनर्जन्म के लिए प्रबंधन के उपाय" जारी किया, जिसे "आदेश न. 5' भी कहा जाता है। इसके अनुसार तिब्बती टुल्कु की पहचान सुनहरे कलश में से पर्ची निकल कर की जा सकती है तथा इसमें चीनी सरकार की अनुमति होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से ही राजनीति से प्रेरित पहल है ताकि तिब्बती बौद्ध नेताओं के चयन को नियंत्रित करने का बहाना दिया जा सके।

पीआरसी तथा परमपावन 14वें दलाई लामा

नास्तिक और धर्म विरोधी शासन के रूप में चीनी कम्युनिस्ट सरकार के पास तिब्बती बौद्ध धर्म की टुल्कु प्रणाली के साथ हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं था। इसी प्रकार चीनी सरकार का आग्रह समान रूप से पूर्वगामी है की 14वें दलाई लामा को उनकी शर्तों के अनुसार अवतरित होना चाहिए। अवतार मानव शरीर के रूप में पहले वाले की मृत्यु के बाद उत्पन्न होता है; इसका प्रयोजन केवल बुद्ध धर्म में की जा रहे दया के कार्यों को जारी रखना तथा सभी लोगों का कल्याण करना है।

चीनी सरकार अक्सर परमपावन दलाई लामा को चीनी राष्ट्र की एकता को सबसे बड़ा अकेला खतरा मानती है। वह कहते हैं की दलाई लामा

का "मानवीय चेहरा व् राक्षस का ह्रदय है" तथा वे "भिक्षु के कपड़ों में छिपे भेडिये हैं"। वह इस बात का भी दावा करते हैं की दलाई लामा एक "ऐसे अलगाववादी है जो अपनी मात्रभूमि की एकता को भंग करने पर उतारू हैं।"

यदि चीनी सच में इन सभी बातों पर विशवास करते है तो वह दलाई लामा को अवतरित करवाने पर क्यों विवश कर रहे हैं?

फिर भी, पीआरसी असाधारण रूप से आगे बढ़ कर अवतरण की प्रक्रिया पर अपना नियंत्रण जमाना चाहता था। इसका सबसे नाटकीय उदहारण 11वें पंचेन लामा का अपहरण मना जा सकता है जिसे बाद में उन्होनें बीजिंग के पक्षधर लडके से बदल दिया।

पीआरसी ने दशकों से 14वें दलाई लामा के अवतार के चयन की प्रक्रिया के अधिकार को निर्मित करने का दिखावा किया है। 1969 में परमपावन दलाई लामा ने कहा की अवतार की प्रक्रिया को जारी रखना है या नहीं यह तिब्बत के लोग ही निर्णय लेंगे। यह कथन चीनी सरकार के लिए अत्यधिक संवेदनशील था। पिछले कुछ वर्षों में चीनी अधिकारियों ने परमपावन दलाई लामा के कथनो का खंडन यह कहते हुए किया है की अवतरण की प्रक्रिया जल्द ही समाप्त होगी।

1992 में किंगहाई राज्य में चीनी सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र के भाग ने एक "किंगहाई में तिब्बती बौद्ध अवतार प्रणाली के टुल्कु की पहचान व् उन्हें तलाशना" नमक कानून पारित किया। इस कानून के चौथे लेख के अनुसार : यद्यपि यह तीसरे लेख में आता है उस अवतार को मान्यता नहीं दी जाएगी जो बच कर विदेश चला गया है तथा मात्रभूमि को क्षति पहुँचाने की किसी प्रकार की करवाई में संलिप्त पाया जाता है"। यह स्पष्ट रूप से 14वें दलाई लामा की धार्मिक प्राधिकार को चुनौती देने का तथा 15वें दलाई लामा को नियंत्रित करने का प्रयास है।

2007 में धार्मिक मामलों के चीनी राज्य प्राधिकरण ने "आदेश संख्याः 5 कार्यान्वित किया जो तिब्बती बौद्ध धर्म में जीवित बुद्धाओं के अवतरण के प्रबंधन को लेकर था।" प्राधिकरण के निदेशक यी शओवेन ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किये।

बीजिंग में मार्च 2015 में आयोजित चीनी नेशनल पीपल कांग्रेस TAR प्रान्त के गवर्नर, पदमा छोलिंग ने कहाः "दलाई लामा अवतार की प्रक्रिया को

रोकना चाहते हैं या नहीं यह निर्णय उन तक भी नहीं है। जब वह 14वें दलाई लामा बने तो यह निर्णय उनका भी नहीं था। उनका चयन धार्मिक नियमों तथा इतिहासिक प्रथाओं तथा केंद्रीय सरकार की अनुमति से हुआ था। क्या वो निर्णय ले सकते है की कब अवतरण समाप्त होगा? यह संभव नहीं हैं"[315]

परमपावन दलाई लामा ने लम्बे समय से कहा है की वह चीन नियंत्रित तिब्बत में पुनर्जन्म नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ वह तिब्बती लोगों की सेवा स्वच्छंद रूप से नहीं कर पते। इसके उत्तर में 2011 में धार्मिक मामलों के चीनी राज्य प्राधिकरण ने एक कानून पारित किया जिसके अंतर्गत अलग दलाई लामा केवल चीन नियंत्रित धरती पर ही पुनर्जन्म ले सकता है। न केवल यह बल्कि चीनी तिबेतोलॉजी अनुसन्धान केंद्र के एक निदेशक ने आदेश दिया की अगले दलाई लामा को दलाई लामा के गृह प्रान्त किंगहाई जो चीनी जमीन पर है इतिहासिक प्रथाओं व् धार्मिक नियमों के अनुसार पेश किया जाना चाहिए।

अवतरण की इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के इस अपमानजनक प्रयास के अतिरिक्त चीनी सरकार ने "तिब्बती बुद्ध तुल्कु तलाश इनजन" आरंभ किया, यह एक ऑनलाइन डेटाबेस था जिसमें 1311 तुल्कुओं की जानकारी थी। इस डेटाबेस के सभी नामों को सरकार दवारा मंजूर किया जाना था। विशेष रुप से दलाई व तेनज़िन ग्यत्सो को www.tibet.cn सरकर दवारा समर्थित वेबसाइट पर बंद कर दिया गया।

परमपावन 14वें दलाई लामा का उनके पुनर्जन्म पर कथन

परमपावन 14वें दलाई लामा अगले दलाई लामा के प्रश्न पर अत्यंत ही दृढ हैंः "उन्होनें पीआरसी की स्थिति को अत्यंत ही बेवकूफी भरा बताया तथा कहा, "जहाँ तक मेरे जन्म का प्रश्न है इस पर अंतिम अधिकार केवल मेरा है किसी और का नहीं"

सितम्बर 2011 में एक सार्वजनिक बयान में परमपावन दलाई लामा ने कहाः

315 स्टीफैन मैक्डोनल, "चीन ने दलाई लामा को "अपवित्र" का आरोप करते संकेत किया कि बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म का समाप्त। एबीसी न्यूज, 10 मार्च 2015 http://www.abc.net.au/news/2015-03-10/china-attacks-dalai-lama-over-bid-to-cease-reincarnation/6296420.

जब में 90 वर्ष का हो जाऊंगा, मैं तिब्बती बुद्ध प्रथाओं के अन्य उच्च लामाओं तथा तिब्बती लोग एवं अन्य लोग जो तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं से बातचीत कर, इस बात का मूल्यांकन करूंगा की क्या दलाई लामा की संस्था को रहना चाहिए या नहीं। इस आधार पर ही हम कोई निर्णय लेंगे। यदि यह निर्णय लिया जाता है की दलाई लामा के अवतार की प्रथा को चलते रहना चाहिए तथा 15वें दलाई लामा को मान्यता देने की आवश्यकता है तो ऐसा करने की जिम्मेवारी दलाई लामा के फोद्रांग ट्रस्ट से जुडे अधिकारों पर आ जाएगी। उन्हें तिब्बती बुद्ध प्रथाओं के विभिन्न प्रमुखों तथा विश्वसनीय शपथ बाध्य धर्म रक्षकों से बातचीत करनी चाहिए जो दलाई लामा के वंश से जुडे हैं। उन्हें इनसे जुडे लोगों से सलाह व् निर्देश लेने चाहिए तथा तलाश व् पहचानने का कार्य प्रथाओं के अनुरूप करना चाहिए। मैं इसके लिए एक स्पष्ट लिखित निर्देश लिख कर छोड़ दूंगा। आपके दिमाग में यह ख्याल रहना चाहिए की इन कानूनी तरीकों द्वारा पहचान किये गए अवतार के अतिरिक्त, किसी राजनीतिक मतलब से जुडे उम्मीदवार चाहे वह सीपीसी[316] से भी हो को मान्यता नहीं दी जाएगी।

तीन साल के उपरांत सितम्बर 2014 में परमपावन दलाई लामा ने विस्तार पूर्वक बतायाः "मेरे उत्तराधिकारी को तलाश करने हेतु प्रक्रिया में भविष्यवाणियों का उपयोग नहीं किया जायेगा क्योंकि चीन उन्हें प्रभावित कर सकता है। मैं एक निर्वाचिका सभा के प्रकार का कुछ सोच रहा हूँ जैसे की कैथोलिक चर्च पोप के चयन में उपयोग करता है अथवा मेरी मृत्यु के बाद एक लिखित निर्देश होगा।"[317]

परमपावन दलाई लामा ने ये भी कहा की उनका अगला अवतार एक महिला के रुप में भी हो सकता है अथवा तिब्बती लोग इस विषय में वोट भी दाल सकते हैं की दलाई लामा की संस्था आगे चलती रहनी चाहिए या नहीं। परमपावन ने ये भी कहा की वह अपना अवतार का चयन अपने जीवित रहते भी कर सकते हैं–एक धार्मिक मोड़ जिसे मधे टुल्कु कहा जाता है–जो उन्हें अपने उतराधिकारी को सिखाने का अवसर देगा तथा नेतृत्व में आने

316 रंजित एस. कलहा, "चीन भारत संबंध में पुनर्जन्म अगली राजनीतिक संकट होगी", द वायर, 14 अप्रैल 2017 https://thewire.in/external-affairs/dalai-lama-china-india-tibet.

317 दलाई लामा की सीपीसी को चुनौतीः माओ के अवतार को ढूँढ लें तो आप मेरा उत्तराधिकारी भी ढूँढ सकते हैं", एशिया न्यूज़, 13 मई 2016, http://www.asianews.it/news-en/Dalai-Lama-challenges-CPC:-Find-Mao%E2%80%99s-reincarnation-and-you-can-choose-my-successor-37487.html.

वाले अंतराल, जो तिब्बती लोगों को अस्थिरता देते हैं से मुक्ति देगा।[318]

केवल एक चीज़ निश्चित है, परमपावन दलाई लामा ने सार्वजनिक रूप से कहा की उनका उत्तराधिकारी चीनी नियंत्रित तिब्बत के बाहर से ढूँढा जाये।

निष्कर्ष

दलाई लामा संस्था का भविष्य चीनी और तिब्बती समाज में एक विचार का मुद्दा है। किसी के लिए भी अपने सर्वोच्च धार्मिक गुरु के उत्तराधिकारी के विषय में सोचना एक चुनौती सिद्ध हो सकता है। तिब्बतियों के लिए इस मुद्दे में पीआरसी की दखल और भी इससे गंभीर बना देती है। तिब्बत की ज़मीन और शासन के अधिग्रहण से असंतुष्ट पीआरसी उनके धार्मिक प्रथाओं पर भी नियंत्रण पाना चाहती है।

सौभाग्य से परमपावन दलाई लामा की इस विषय पर स्पष्टता तथा टुल्कु प्रथाओं का इतिहास, इस उलझन को दूर करता है की अवतरित लामाओं को चुनने का अधिकार किसी है। 1969 से परम पावन ने यह स्पष्ट किया है की दलाई लामा संस्था का भविष्य तिब्बती लोगों के हाथ में है। किसी भी देश की सरकार, चाहे वह चीन हो या कोई अन्य देश अगले दलाई लामा या अगले टुल्कु के विषय में नहीं बता सकता। यह पवित्र एवं सबसे अलग तिब्बती बुद्ध प्रथाओं को तिब्बती बुद्ध लोग और संस्था ही आगे ले जाएंगे जैसे इन्हें इनके बनने के बाद से ले जाया गया है।

318 दलाई लामा, "पुनर्जन्म" https://www.dalailama.com/the-dalai-lama/biography-and-daily-life/reincarnation.

अध्याय-9

मध्यम मार्ग दृष्टिकोण : आगे का रास्ता

मध्यम मार्ग दृष्टिकोण (एम डैब्लूय ए), तिब्बत की भाषा में "उमय–लम", परमपावन दलाई लामा द्वारा तिब्बत के लोगों की वास्तविक स्वायत्तता तथा चीन के नेतृत्व के साथ संलग्नता, के लिए एक नीति बनाई है जो चीन और तिब्बत के लोगों दोनों के लाभदायक है। मध्यम मार्ग दृष्टिकोण बौद्ध दर्शन के सिद्धान्त अति को नकार कर मध्यमार्ग की खोज पर आधारित है। अतः यह एक दृष्टिकोण है जो यथावत स्थिति और स्वतंत्रता के बीच मध्य मार्ग की तरह फैला हुआ है। यह तिब्बती लोगों के प्रति चीनी सरकार की वर्तमान दमनकारी और औपनिवेशिक नीतियों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है, लेकिन यह पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पी आर सी) से स्वतंत्रता भी नहीं चाहता है। वार्ता के माध्यम से, मध्यम मार्ग दृष्टिकोण तिब्बती और चीनी लोगों के बीच सहअस्तित्व प्राप्त करना चाहता है, जहां तिब्बतीयों पीआरसी के संवैधानिक ढांचे के भीतर वास्तविक स्व–शासन का आनंद ले सके और एक ही बार में अद्वितीय तिब्बती भाषा और सांस्कृतिक विरासत को बहाल करने और प्राचीन वातावरण को संरक्षित करने में सक्षम रहें।

1968 के पास, विश्व की राजनैतिक परिस्थितियों, विशेषतया चीन की दृष्टिगत, परमपावन दलाई लामा ने उस समय निर्णय–लेने वाली संस्था कशाग और तत्कालीन तिब्बत के पीपल्ज़ डेप्टीज़ के चेयरमैन तथा वाईस–चेयरमैन के मध्य विचार–विमर्ष की श्रृंखलाएं आयोजित कीं।

परिणामस्वरूप, 1974 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के बजाय, अवसर मिलने पर चीन सरकार के साथ औपचारिक संपर्क तथा संवाद प्रारंभ करने का आंतरिक निर्णय लिया गया था। इसलिए 1979 में जब चीन के सर्वोपरि नेता डेंग शियोपिंग ने परमपावन दलाई लामा के बड़े भाई ग्यालो थोंडुप से कहा कि, "स्वतंत्रता को छोड़कर हर चीज पर चर्चा की जा सकती है"। तब हम तुरंत संपर्क स्थापित कर सकते हैं क्योंकि हम उन्हें जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे।

परमपावन दलाई लामा ने मध्यममार्ग दृष्टिकोण की औपचारिक घोषणा 1987

में यू. एस. कांग्रेशनल ह्यूमन राइट केकस में पांच सूत्रीय शांति योजना तथा वर्ष 1988 में यूरोपीयन संसद में स्टार्सबर्ग प्रस्ताव प्रस्तुत करके की।

1997 में निर्वासित तिब्बतियों में किये गए जनमत सर्वेक्षण में 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने परमपावन दलाई लामा के दृष्टिकोण पर अपना समर्थन व्यक्त किया। उस समय, अधिकांश राय तिब्बत के भीतर बहुसंख्यक तिब्बतियों ने भी मध्यम मार्ग दृष्टिकोण का समर्थन किया। इस परिणाम के दृष्टिगत, तिब्बत की निर्वासित संसद ने इस दृष्टिकोण के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया और आज तक, मध्यम मार्ग नीति को सबसे यथार्थवादी और व्यावहारिक तरीके के रूप में शांति से तिब्बत की स्थिति को हल करने के रास्ते के रूप में चुना। आगामी दशकों में, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) ने बार–बार तिब्बती लोगों द्वारा इस नीति के पालन की पुष्टि की है।

मध्यम मार्ग दृष्टिकोण एक जीत–भरा प्रस्ताव और व्यावहारिक स्थिति है जो सभी संबंधित पक्षों के महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा करती है। तिब्बत के लोगों के लिए, यह उनकी पहचान और सम्मान की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है; चीन के लिए, मातृभूमि की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता प्रदान करता है। तिब्बती स्व–शासन का एक रूप चाह रहे हैं जो उन्हें उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देता है, लेकिन चीन गणराज्य की एकता और स्थिरता को चुनौती नहीं देता है। वे एक एकल प्रशासनिक इकाई के तहत और अधिक कुशलता से और प्रभावी ढंग से अद्वितीय तिब्बती विशेषता को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। वर्तमान में, तिब्बतियों को "तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र" और तिब्बती स्वायत्त परिपूर्ण और किन्गहाई, सिचुआन, गांसु और युन्नान के पड़ोसी प्रांतों के काउंटियों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक बहुसंख्यक चीनी हैं। चीनी अधिकारियों का दावा है कि यह तिब्बती नेतृत्व का तिब्बती क्षेत्रों से "सभी चीनी" को निष्कासन करने का इरादा है। लेकिन वास्तव में, तिब्बती लोगों[319] के लिए वास्तविक स्वायत्तता पर ज्ञापन जो 8वें दौर की वार्ता के दौरान अक्तूबर 2008 में पीआरसी नेतृत्व को प्रस्तुत किया, वह स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हुए कि मामला यह नहीं है;

319 केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, "तिब्बती लोगों के लिए वास्तविक स्वायत्तता पर ज्ञापन।", http://tibet.net/important-issues/sino-tibetan-dialogue/memorandum-on-geniune-autonomy-for-the-tibetan-people/.

"हमारा उद्देश्य गैर–तिब्बतियों को निष्कासित करना नहीं है। हमारी चिंता मुख्य रूप से चीनी, बल्कि कुछ अन्य राष्ट्रीयताओं, जैसे कई तिब्बती क्षेत्रों में प्रेरित जन गमनागमन है, जो बदले में मूल तिब्बती आबादी को हाशिए पर डाल देता है।

ज्ञापन में तिब्बती क्षेत्रों को अद्वितीय तिब्बती पहचान और 11 बुनियादी जरूरतों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए तिब्बती बहुसंख्यक होने का आह्वान किया गया है:

1. भाषा: भाषा तिब्बती लोगों की पहचान की सबसे बड़ी विशेषता है। तिब्बती भाषा संचार का प्राथमिक साधन है, वह भाषा जिसमें साहित्य, आध्यात्मिक ग्रंथ और तिब्बतियों के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक कार्य लिखे जाते हैं। पीआरसी का संविधान, अनुच्छेद 4 में, सभी राष्ट्रीयताओं की स्वतंत्रता की गारंटी देता है "अपनी स्वयं की बोली और लिखित भाषा का उपयोग करने और विकसित करने के लिए ....." अपनी भाषा का उपयोग और विकसित करने के लिए, तिब्बती को क्षेत्र की बोली और लिखित भाषा के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए– यह तिब्बती स्वायत्त क्षेत्रों की सिद्धांत भाषा होनी चाहिए। इस सिद्धांत को मोटे तौर पर अनुच्छेद 121 में संविधान में भी मान्यता दी गई है, जिसमें कहा गया है, "राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्रों के स्व–शासन के अंग, स्थानीय स्तर पर सामान्य उपयोग में भाषा व बोली जाने वाली तथा लिखित भाषा को इस्तेमाल करते हैं।" क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता (LRNA) पर कानून के अनुच्छेद 10 में यह प्रावधान है कि ये अंग "इन क्षेत्रों में राष्ट्रीयताओं की स्वतंत्रता की गारंटी देंगे कि वे अपनी बोली और लिखित भाषाओं का उपयोग और विकास कर सकें ...।"

तिब्बती क्षेत्रों में मुख्य भाषा के रूप में तिब्बती की मान्यता के सिद्धांत के अनुरूप, एलआरएनए (अनुच्छेद 36) स्वायत्त सरकार के अधिकारियों को शिक्षा के संबंध में "निर्देशों और नामांकन प्रक्रियाओं में प्रयुक्त भाषा" पर निर्णय लेने की अनुमति देता है। इसका तात्पर्य इस सिद्धांत से है कि शिक्षा का मुख्य माध्यम तिब्बती होना चाहिए।

2. संस्कृति: राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता की अवधारणा मुख्य रूप से अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं की संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से है। मुख्य रूप से, पीआरसी के संविधान में अनुच्छेद 22, 47 और 119 के साथ–साथ

एलआरएनए का अनुच्छेद 38 सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ हैं। तिब्बतियों के लिए, तिब्बती संस्कृति हमारे धर्म, परंपरा, भाषा और पहचान से निकटता से जुड़ी हुई है, जो कई स्तरों पर खतरों का सामना कर रही हैं। चूंकि तिब्बती पीआरसी के बहुराष्ट्रीय राज्य के भीतर रहते हैं, इसलिए इस विशिष्ट तिब्बती सांस्कृतिक विरासत को उपयुक्त संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से संरक्षण की आवश्यकता है।

3. धर्म: धर्म तिब्बतियों के लिए मौलिक है, और बौद्ध धर्म हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। चर्च और राज्य के अलगाव के महत्व को पहचानते हुए, इस सिद्धांत को विश्वासियों की स्वतंत्रता और अभ्यास को प्रभावित नहीं करना चाहिए। तिब्बतियों के लिए अपनी आस्था, विवेक और धर्म का अभ्यास करने की स्वतंत्रता के बिना व्यक्तिगत या सामुदायिक स्वतंत्रता की कल्पना करना असंभव है। संविधान धर्म के महत्व को पहचानता है और इसे लागू करने के अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 36 सभी नागरिकों को धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। कोई भी दूसरे धर्म में विश्वास करने के लिए दूसरे को मजबूर नहीं कर सकता है, और धर्म के आधार पर भेदभाव करना मना है।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रकाश में इस संवैधानिक सिद्धांत की व्याख्या भी विश्वास या पूजा के तरीके की स्वतंत्रता को कवर करेगी और इसमें मठों के बौद्ध भिक्षु परंपरा के अनुसार संगठित होने और चलाने का अधिकार शामिल है; शिक्षाओं और अध्ययनों में शामिल होना; और इन नियमों के अनुरूप किसी भी आयु वर्ग के भिक्षुओं और ननों की संख्या को दर्ज करने के लिए। बड़ी सभाओं के साथ सार्वजनिक शिक्षाओं और सशक्तिकरण समारोहों को आयोजित करने की सामान्य प्रथा इस स्वतंत्रता द्वारा कवर की जाती है। इसके अलावा, राज्य को धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जैसे कि एक शिक्षक और उसके शिष्य के बीच संबंध, मठवासी संस्थानों का प्रबंधन और पुनर्जन्म की मान्यता।

4. शिक्षा: पीआरसी के केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सहयोग और समन्वय में अपनी शिक्षा प्रणाली विकसित करने और प्रशासन करने की तिब्बती की इच्छा निहित सिद्धांतों द्वारा समर्थित है जैसा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में संलग्न और योगदान करने के लिए है। संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार, राज्य अपने नागरिकों के लिए शिक्षा प्रदान

करने के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेता है, लेकिन, अनुच्छेद 119 ने इस सिद्धांत को मान्यता दी कि "राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्रों के स्व–शासन स्वतंत्र रूप से शैक्षिक ...उनके संबंधित क्षेत्रों में मामलों का प्रबंधन करते हैं ..." यह सिद्धांत एलआरएनए के अनुच्छेद 36 में भी परिलक्षित होता है।

वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में संलग्न होने और योगदान करने की आकांक्षा के लिए, संविधान (अनुच्छेद 119) और एलआरएनए (अनुच्छेद 39) स्पष्ट रूप से ऐसा करने के लिए स्वायत्त क्षेत्रों के अधिकार को पहचानते हैं। हम यहां बौद्ध मनोविज्ञान, तत्वमीमांसा, मन की समझ और ब्रह्माण्ड विज्ञान द्वारा किए गए आधुनिक विज्ञान के योगदान के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय द्वारा बढ़ती मान्यता को ध्यान में रखते हैं।

5. पर्यावरण संरक्षण: तिब्बत एशिया की महान नदियों का प्रमुख स्रोत हैं। यह पृथ्वी के सबसे ऊँचे पहाड़ों, इसके सबसे व्यापक और सबसे ऊँचे पठार के साथ–साथ प्रचुर खनिज संसाधन, प्राचीन वन और गहरी घाटियाँ भी रखती हैं जो मानवों से अछूती हैं। युगों के माध्यम से, इस क्षेत्र के पर्यावरण के संरक्षण को तिब्बती लोगों के जीवन के सभी रूपों के लिए पारंपरिक सम्मान से बढ़ाया गया है, और संवेदनशील प्राणी, मानव या जानवर को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ प्रतिबंध है। आमतौर पर, तिब्बत एक विशिष्ट प्राकृतिक पर्यावरण युक्त अभेद्य जंगल अभयारण्य था। लेकिन आज, तिब्बत के एक बार संरक्षित पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो रही है, विशेषकर घास के मैदान, फसल, जंगल, जल संसाधन और वन्यजीव, भले ही अनुच्छेद 45 और 66 के एलएनएआरए तिब्बती लोगों को पर्यावरण के प्रबंधन और पारंपरिक रूढ़िवादी प्रथाओं का पालन करने का अधिकार देता है।

6. प्राकृतिक स्त्रोतों का उपयोग: प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में, संविधान और एलआरएनए केवल स्वायत्त क्षेत्रों के स्व–शासन के अंगों के लिए एक सीमित भूमिका को स्वीकार करते हैं (देखें एलआरएनए का अनुच्छेद 27,28,45,66 और संविधान के अनुच्छेद 118, जो यह प्रतिज्ञा करता है कि राज्य "राष्ट्रीय स्वायत्तता क्षेत्रों" के हितों पर उचित ध्यान देगा। "एलआरएनए स्वायत्तता क्षेत्रों की रक्षा के महत्व को पहचानता है और वन और घास के मैदानों को विकसित करना (अनुच्छेद 27) और प्राकृतिक संसाधनों के तर्कसंगत दोहन और उपयोग को प्राथमिकता देना, जो कि स्थानीय अधिकारियों को विकसित

करने के लिए हकदार हैं, "लेकिन केवल राज्य योजना और कानूनी शर्तों की सीमा के भीतर। वास्तव में, केंद्रीय भूमिका इन मामलों में राज्य संविधान (अनुच्छेद 9) में परिलक्षित होता है।

एक अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों, करों और राजस्व का विकास भूमि के स्वामित्व पर आधारित होता है, लेकिन गठन में स्वायत्तता के सिद्धांत इस दिशा में वास्तव में नेतृत्व नहीं करते हैं। यदि वे प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि खनिज संसाधन, जल, जंगल, पहाड़, घास के मैदान इत्यादि के उपयोग पर निर्णय लेने में तिब्बती अपने स्वयं के भाग्य के स्वामी नहीं बन सकते हैं, तो यह आवश्यक है कि केवल राष्ट्रीयता स्वायत्त क्षेत्र के पास भूमि को हस्तांतरित करने या पट्टे देने के लिए कानूनी अधिकार होता है, (राज्य के स्वामित्व वाली भूमि को छोड़कर)। उसी तरह, स्वायत्त क्षेत्र में स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए और राज्य के समवर्ती विकास योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण।

7. आर्थिक विकास और व्यापार: चीनी संविधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि स्वायत्त अधिकारियों की स्थानीय विशेषताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके क्षेत्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है; संविधान का अनुच्छेद 118, एलआरएनए में भी परिलक्षित अनुच्छेद 25)। संविधान प्रशासन और वित्त के प्रबंधन (अनुच्छेद 117, और एलआरएनए अनुच्छेद 32) में स्वायत्तता के सिद्धांत को भी मान्यता देता है। इसी समय, संविधान राज्य के वित्त पोषण और विकास को गति देने के लिए स्वायत्त क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के महत्व को पहचानता है (अनुच्छेद 122, एलआरएनए अनुच्छेद 22)।

इसी तरह, एलआरएनए के अनुच्छेद 31 में स्वायत्त क्षेत्रों की क्षमता को मान्यता दी गई है जो विदेशी देशों की सीमा पर, साथ ही साथ सीमा पर व्यापार करने के लिए विदेशी देशों के साथ व्यापार करते हैं। इन सिद्धांतों की मान्यता तिब्बती राष्ट्रीयता के लिए महत्वपूर्ण है जो विदेशी देशों के साथ अपनी निकटता को देखते हैं। सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय और आर्थिक संबंध हैं। तिब्बत PRC के भीतर सबसे अधिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, और आर्थिक विकास का भी स्वागत करता है। लेकिन केंद्र सरकार और अन्य प्रांतों द्वारा प्रदान की गई सहायता का केवल अस्थायी लाभ है और लंबे समय में, यह तिब्बतियों के लिए दूसरों पर निर्भर होना

हानिकारक है। स्पष्ट रूप से, आर्थिक आत्मनिर्भरता तिब्बती स्वायत्तता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

8. सार्वजनिक स्वास्थ्यः चीनी संविधान स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं (अनुच्छेद 21) प्रदान करने के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी से बाहर करता है। अनुच्छेद 119 यह मानता है कि यह स्वायत्तता क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी का क्षेत्र है। LRNA के 40 क्षेत्र यह भी मानते हैं कि यह सम्मान का क्षेत्र है। स्वायत्त क्षेत्रों के। एलआरएनए का अनुच्छेद 40 स्वायत्त क्षेत्रों के स्वशासन के अंगों के अधिकार को "स्थानीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने की योजनाओं पर स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीयताओं की आधुनिक और पारंपरिक दोनों दवाओं को आगे बढ़ाने के लिए" के अनुसार मान्यता देता है। उपर्युक्त कानूनों के सिद्धांतों के अनुसार, क्षेत्रीय स्वायत्त अंगों को संपूर्ण तिब्बती लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दक्षताओं और संसाधनों का होना आवश्यक है। उन्हें पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा और ज्योतिषीय प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, पारंपरिक अभ्यास के अनुसार कड़ाई करने की आवश्यकता है। हालांकि, मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से ग्रामीण तिब्बती आबादी की जरूरतों को पूरा करने में विफल है।

9. सार्वजनिक सुरक्षाः स्वायत्त क्षेत्रों की आंतरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी स्वायत्तता और स्व–शासन के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान (अनुच्छेद 120) और एल आरएनए (अनुच्छेद 24) स्थानीय भागीदारी के महत्व को पहचानता है और सुरक्षा के तहत "राज्य की सैन्य प्रणाली और व्यावहारिक जरूरतों को राज्य कौंसिल के अनुमोदन के बाद" व्यवस्थित करने के लिए स्वायत्त क्षेत्रों को अधिकृत करता है लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि अधिकांश सुरक्षा कर्मियों में स्थानीय राष्ट्रीयता वाले सदस्य शामिल हों, क्योंकि वे लोग हैं जो तिब्बती क्षेत्रों में स्थानीय रीति–रिवाजों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं, हालांकि, स्थानीय तिब्बती अधिकारियों के हाथों में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।

10. प्रवासी जनसंख्या का विनियमः राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता और स्वशासन का मूल उद्देश्य अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता की पहचान, संस्कृति और भाषा को संरक्षित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि यह अपने स्वयं के मामलों का स्वामी है। जब एक विशेष क्षेत्र पर लागू किया जाता है जिसमें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता एक केंद्रित समुदाय या समुदायों में रहती

है, तो राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता का बहुत सिद्धांत और उद्देश्य बड़े पैमाने पर है। यह समझा जाता है कि हान राष्ट्रीयता और अन्य राष्ट्रीयताओं के एक बड़े पैमाने पर प्रवास और निपटान को न केवल अनुमति दी जाती है, बल्कि प्रोत्साहित भी किया जाता है। इस तरह के बड़े पैमाने पर प्रवासन के परिणामस्वरूप, जिन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का परिणाम होगा, वे तिब्बती राष्ट्रीयता को हान राष्ट्रीयता में एकीकृत करने के बजाय आत्मसात करने का प्रभाव डालेंगे–और इसके अलावा, तिब्बतियों के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हान और अन्य राष्ट्रीयताओं की बाढ़ क्षेत्रीय स्वायत्तता के अभ्यास के लिए मूल रूप से सिद्धांतों को बदल देगी; स्वायत्तता के अभ्यास के लिए संवैधानिक यह है कि अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता एक विशेष क्षेत्र में काम्पेक्ट समुदायों में रहती है। प्रवासन, स्थानान्तरण और बस्तियां अनियंत्रित ज़ारी हैं, तिब्बती अब एक कॉम्पैक्ट समुदाय में नहीं रह पायेंगे और इसके परिणामस्वरूप, अब संविधान के तहत, राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायतता के लिए हकदार नहीं होंगे। यह संविधान के बहुत सिद्दांतों का अपने दृष्टिकोण में प्रभावी ढंग से उल्लंघन करेगा।

राष्ट्रीयताओं का मुद्दा, पीआरसी में नागरिकों के चाल–चलन या निवास पर प्रतिबंध के लिए मिसाल है और "क्षणिक आबादी" को नियंत्रित करने के उपायों पर काम करने के लिए स्वायत्त क्षेत्रों के अधिकार की बहुत सीमित मान्यता है। स्वायत्तता के सिद्धांत की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए, उन व्यक्तियों के निवास, निपटान, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार होना आवश्यक है जो पीआरसी के अन्य हिस्सों से तिब्बती क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि अनुसंधान का अन्वेषण गैर–तिब्बती स्थायी रूप से तिब्बत में बस गए, बड़े हुए और काफी समय तक वहाँ रहे। इसके बजाय हम मुख्य रूप से हान के जन–आंदोलन के बारे में चिंतित हैं, लेकिन कुछ अन्य राष्ट्रीयताओं, तिब्बत के कई क्षेत्रों में, मौजूदा समुदायों को परेशान कर रहे हैं, स्थानीय तिब्बती आबादी को हाशिए पर रखते हुए और नाजुक प्राकृतिक वातावरण को खतरे में डाल रहे हैं।

11. अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक, शैक्षिक और धार्मिक आदान-प्रदानः स्वायत्त क्षेत्रों और अन्य राष्ट्रीयताओं, प्रांतों और पीआरसी के क्षेत्रों में तिब्बती राष्ट्रीयता के बीच आदान–प्रदान और सहयोग का महत्व, साथ ही साथ विदेशी देशों के साथ इस तरह के आदान–प्रदान करने की शक्ति, ये क्षेत्र,

एलआरएनए (अनुच्छेद 42) में मान्यता प्राप्त हैं। राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता कानून और चीन लोक गणराज्य दोनों के संविधान में चीन अल्पसंख्यकों के जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण सम्मान प्रदान करते हैं।

मध्यम मार्ग नीति का प्रभाव व समर्थन

मध्यम मार्ग नीति को अपनाने से परमपावन दलाई लामा और पीआरसी नेतृत्व के बीच सीधा संपर्क हो गया है। पहला सीधा संपर्क 1979 में शुरू हुआ, जिससे परम पावन के लिए चार तथ्य खोजने वाले प्रतिनिधिमंडल भेजना संभव हुआ, एक के बाद एक, 1979 से 1985 के बीच और इन प्रतिनिधिमंडलों के लिए पूरे तिब्बती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्रा करना और बीजिंग में चीनी नेतृत्व के साथ मिलना। अधिक महत्वपूर्ण रूप से दो खोजपूर्ण टॉक मिशन 1982 और 1984 में पीआरसी नेतृत्व बेजिंग से मिलने के लिए भेजे गए थे। फिर 2002 से 2010 तक, परमपावन दलाई लामा के दूतों ने नौ दौर की वार्ता की और एक अनौपचारिक बैठक चीनी नेतृत्व के प्रतिनिधियों के साथ की।

तथ्यन्वेषण–प्रतिनिधि खोज मिशन और पीआरसी नेतृत्व के साथ सीधी बैठकों में तिब्बत के विवादित मुद्दे का समाधान नहीं हुआ। हालाँकि, इन यात्राओं की बैठकों ने हमें तिब्बती लोगों की वास्तविक स्थिति को देखने, चीनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और परमपावन दलाई लामा और तिब्बती लोगों की स्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम किया, कि चीन की लोहे की पकड़ की दबाव संबंधी चिंताओं को कैसे हल किया जाए। अगर चीनी नेताओं को वास्तव में अपने शासन के कारण होने वाली समस्याओं को हल करने की इच्छाशक्ति थी, तो वे स्पष्ट रूप से समझेंगे कि परम पावन और तिब्बती लोग इसे प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं।

मध्यम मार्ग का दृष्टिकोण तिब्बत के अंदर नेताओं और बुद्धिजीवियों, चीन के भीतर और बाहर दोनों चीनी समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों से काफी समर्थन प्राप्त करता है।

तिब्बत के अंदर के कुछ प्रमुख समर्थकों में 10वीं पेनचेन लामा शामिल हैं, जिन्होंने मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के लिए खुले तौर पर समर्थन व्यक्त किया, साथ ही वरिष्ठ नेताओं जैसे नाबोए नवांग जिग्मे, बापा फुंत्सोग वांगयल, डोरजी त्सेतेन, सांगे येशी (तियान बाओ), ताशी त्सेरिंग और यांगलिंग।

दोरजी।

चीन के भीतर और बाहर, दोनों के लिए नीति का समर्थन लगातार बढ़ रहा है, खासकर चीनी बुद्धिजीवियों और कलाकारों में, जैसे लियू शियाओबो, नोबेल पुरस्कार विजेता जोकि कैद और अब स्वर्गवास हुआ है, जिन्होंने 2008 में एक खुले पत्र में परमपावन दलाई लामा की शांति पहल का समर्थन व्यक्त किया। तब से, चीनी विद्वानों और लेखकों द्वारा 1,000 से अधिक लेख और राय के टुकड़े लिखे गए हैं, जो तिब्बत के मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत के लिए समर्थन व्यक्त करते हैं। मध्यम मार्ग दृष्टिकोण का समर्थन वैंग लिशियोंग जैसे बुद्धिजीवियों से आया है, जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं; चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज तथा संवैधानिक विशेषज्ञ झांग बोशू; सिचुआन सहित्यिक आवधिक के रेन युनफई; चीन कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य तथा बीजिंग स्थित कानूनी विशेषज्ञ यू हाओचेंग; चीनी समामजिक विज्ञान अकादमी में पूर्व अर्थशास्त्री सु शओज़ी; पूर्व सीसीपी सचिव झाओ ज़ियांग के निकट सहयोगी यान जियाकी, सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन (सीएसओ) ने भी पीआरसी नेतृत्व से तिब्बतियों के लिए अपनी नीति की समीक्षा करने का आह्वान किया है और बातचीत की शुरुआत का आग्रह किया है। बेजिंग–आधारित कानूनी सीएसओ, गोंगमेंग संवैधानिक पहल की एक रिपोर्ट, जिसमें तिब्बती लोगों की शिकायतों का वर्णन किया गया है और पीआरसी द्वारा एक नीति समीक्षा की मांग की गई है। 2012 में 15 देशों में स्थित 82 चीनी सीएसओ ने संयुक्त राष्ट्र, द यूरोपियन यूनियन और विभिन्न संसदों और सरकारों को एक याचिका भेजी, "जिससे उन्हें जल्द से जल्द वार्ता शुरू करने के लिए चीनी सरकार से आग्रह करना चाहिए।"

व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय में, मध्यम मार्ग के दृष्टिकोण ने कई सरकारों को एक समाधान उन्मुख दृष्टिकोण का समर्थन करने और अपने द्विपक्षीय समझौते और चीनी नेतृत्व के साथ व्यवहार में तिब्बत के मुद्दे को उठाने में सक्षम बनाया है। नीति के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय समर्थन कई सरकारों द्वारा आयोजित विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है कि यह तिब्बत के अंदर मौजूदा स्थिति को संबोधित करने के लिए सबसे ज्वलंत विकल्प है।

जिमी कार्टर, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा सहित संयुक्त राज्य अमेरिका के सफल राष्ट्रपतियों ने तिब्बत

में संकट का समाधान करने के लिए पीआरसी नेतृत्व तक पहुंचने के लिए परम पावन की पहल का समर्थन किया है। राष्ट्रपति ओबामा की परमपावन दलाई लामा के साथ बैठक के बाद, व्हाइट हाउस ने चीन के साथ एक संवाद और मध्यम मार्ग दृष्टिकोण का अनुसरण करने के लिए परम पावन की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए बयान जारी किए। राष्ट्रपति ओबामा ने संबंधित पक्षों को "लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को सुलझाने के लिए सीधी बातचीत" में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और परमपावन दलाई लामा के मध्यम मार्ग के दृष्टिकोण के लिए समर्थन व्यक्त किया।

कई अन्य प्रमुख वैश्विक नेताओं ने अतीत में मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के बाद बातचीत के लिए सराहा, जिसमें मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त नवी पिल्ले, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, डोनाल्ड टस्क, यूरोपिय संघ के विदेश मामलों के उच्च प्रतिनिधि/सुरक्षा नीति/यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष लेडी कैथरीन एश्टन; ब्रिटिश प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन; फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी; जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, कैनेडियन प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबोट; ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन रुड; और ताइवान के राष्ट्रपति मा यिंग–जेउ आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, कई संसदों और सरकारों ने आधिकारिक तौर पर मध्यम मार्ग के दृष्टिकोण के लिए अपना समर्थन दिया है, जिसमें अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में, यू.एस., यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और लक्ज़मबर्ग में मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के लिए घोषणा, संकल्प और समर्थन के प्रस्ताव अपने राष्ट्र की संसद में पारित किए गए हैं।

मध्यम मार्ग के दृष्टिकोण को दक्षिण अफ्रीका के आर्कबिशप डेसमंड टूटू, अमेरिका के एली विसेल और जोडी विलियम्स, लाइबेरिया के लेमाह गॉबी, पोलैंड के लेछ वलेसा, ईरान के शिरीन इबादी, गोटीमाला के रिगोबेरता मेनचू तुम, पूर्वी तिमोर के जोस रामोस होर्ता, अर्जेंटीना के अडोल्फ़ पेरेज़ एस्क्विवेल, आयरलैंड के मारीड कोरिगन मगुइरे और यूके के बेट्टी विलियम्स सहित कई नोबेल शांति पुरस्कारों का समर्थन मिला है।

वर्ष 2012 में चीनी राष्ट्रपति हू जिन्ताओ को संबोधित एक खुले पत्र में, नोबेल शांति लौरेट्स के समूह ने लिखाः

'तिब्बत के लोगों की सुनी जाने की कामना। उन्होंने लंबे समय से सार्थक स्वायत्तता की मांग की है और इसे प्राप्त करने के अपने साधन के रूप में बातचीत और मैत्रीपूर्ण मदद को चुना है। चीनी सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए, उनके दुख–दर्द को समझना चाहिए और अहिंसक समाधान खोजना चाहिए। उस समाधान की पेशकश हमारे मित्र और भाई परमपावन दलाई लामा ने की है, जिन्होंने कभी अलगाव नहीं चाहा, और हमेशा एक शांतिपूर्ण रास्ता चुना। हम चीन सरकार से आग्रह करते हैं कि वह सार्थक वार्ता के लिए जो अवसर प्रदान करता है, उसे जब्त करे। एक बार बन जाने के बाद, यह चैनल खुला, सक्रिय और उत्पादक बना रहना चाहिए। यह उन मुद्दों को संबोधित करना चाहिए जो वर्तमान तनाव के केंद्र में हैं, तिब्बती लोगों की गरिमा और चीन की अखंडता का सम्मान करते हैं।

इसलिए, यह देखते हुए कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था, मध्यम मार्ग दृष्टिकोण लंबे समय से चली आ रही चीन–तिब्बत समस्या को हल करने का सबसे व्यवहार्य उपाय है।